PART-1

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935

(बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम 6, 1935)

बिहार [------] राज्य में सहकारी सोसाइटी संबंधी विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिये अधिनियम।

प्रस्तावना—चूँकि कृषकों तथा सामान्य आवश्यकता वाले अन्य व्यक्तियों के बीच मितव्ययिता, स्वयं साहाय्य एवं उक्त साहाय्य की उन्नति के लिए सहकारी सोसाइटी का गठन, कार्यान्वयन तथा समेकन को आसान करना एवं आपसी प्रयोजनार्थ बिहार एवं उड़ीसा राज्यों में सहकारी समिति संबंधी विधि को समेकित तथा संशोधित करना शामिल है, और चूँकि इस अधिनियम को पारित करने के लिए भारत अधिनियम की धारा 80 (क) की उपधारा (3) के अधीन राज्यपाल की पूर्व अभिमत मिल चुकी है अतः एतद्वारा यथा निम्न रूप में अधिनियमित किया जाता है।

टिप्पणी

[जहाँ अत्यधिक संख्या में जलकरों की बन्दोबस्ती करनी हो, ऐसे मामलों में पचास प्रतिशत जलकरों की बन्दोबस्ती अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत निबन्धित समितियों के साथ की जा सकती है। शेष बची पचास प्रतिशत की अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबन्धित समितियों के बीच उनके सदस्यों की संख्या के अनुपात में की जानी चाहिए। फिर भी अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत निबन्धित समितियाँ जलकरों की बन्दोबस्ती के मामले में अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबन्धित समितियों पर अपनी अधिमानता का दावा नहीं कर सकती हैं। सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहकारी समिति सीमित बनाम बिहार राज्य, 2005 (3) पी०एल० जे०आर० 681]

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार (1) इस अधिनियम को' खबिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935, कहा जायेगा ।

(2)[1] [इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।]

टिप्पणी

[सहकारी सोसाइटी विधि—सम्मत है। **शेख मुहम्मद अली बनाम बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड**, 1989 पी०एल० जे०आर० 447: 1989 बी०एल० जे० 613: **डा० गीता सिंह बनाम बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड**, 1989 बी०एल० जे० 613 ।]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 81 (1) (ग) के प्रावधानों के तहत् सहकारी सोसाइटी के उस आय को कर मुक्त किया गया है जो समिति के सदस्यों द्वारा समिति कार्य हेतु विपणन कार्य हेतु परिलक्षित है। जो समिति के कार्यकलाप को प्रोत्साहित करता है। (1989) 2 एस०सी०सी० 679।

2. **परिभाषा**—इस अधिनियम में, अन्यथा विषय अथवा प्रसंग प्रतिकूल न हो—

(क) "उपविधि'' से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त निबंधित उपविधि एवं उसमें उपविधि का निबंधित संशोधन शामिल है;

(ख) "सहकारी परिसंघ'' से अभिप्रेत है वह निबंधित सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य निबंधित सोसाइटियों के कार्यकलापों को समन्वित तथा आसान बनाना तथा सहकारी आन्दोलन के विकास को समन्वित करना है;

[2] [(खख) **"सहकारी वर्ष**'' से अभिप्रेत है[1] [1 अप्रील, से प्रारम्भ होनेवाला और [31 मार्च'' को समाप्त होनेवाला वर्ष];

1. बिहार अधिनियम 5, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. बिहार अधिनियम 39, 1982 द्वारा अन्तःस्थापित ।

[6][(ग) ''**वित्तदाता बैंक**'' से अभिप्रेत है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, राज्य सहकारी बैंक, कन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जानेवाला कोई अन्य बैंक, जिसको उद्देश्य हैं ऐसे निधि का निर्माण करना जिससे सहकारी सोसाइटी या अन्य संस्था अथवा दोनों को धन का कर्ज दिया जाय];

[4][''2 (ग ग) ''**सरकार**'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार''];

(घ) ''**परिसमापक**'' से अभिप्रेत है निबंधित सोसाइटी के कामकाज के परिसमापनार्थ धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त एक या अधिक व्यक्तिय;

[5][(ङ) ''**बोर्ड**'' से अभिप्रेत है निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय अथवा प्रबन्ध समिति, चाहे जो भी इसका नाम हो, जिसे सहकारी समिति के कामकाज का प्रबन्धन सौंपा गया हो।;

(च) ''**सदस्य**'' में शामिल हैं सोसाइटी के निबंधनार्थ आवेदन में सम्मिलित होनेवाला व्यक्ति एवं ऐसी सोसाइटी की नियमावली तथा उपविधियों के अनुसार निबन्धन के पश्चात् सदस्य रूप में प्रविष्ट व्यक्ति;

[1][(चच) ''**बहुबंधी सहकारी सोसाइटी**'' वह प्राथमिक सोसाइटी है जिसका गठन अपने सदस्यों को एक से अधिक प्रकार की सेवायें प्रदान करने के लिये किया गया हो और इसमें ईख उत्पादक सहकारी सोसाइटो के रूप में निबंधित कोई सोसाइटी शामिल है];

2[(चचच) ''**नाममात्र या सह–सदस्य**'' से अभिप्रेत है वह सदस्य जो सोसाइटी के सदस्य का वैसा विशेषाधिकार या अधिकार रखता हो और जो सदस्य के मात्र वैसे दायित्वों के अधीन रहे जो उप–विधियों द्वारा विहित किये जायें];

(छ) ''**पदाधिकारी**'' में शामिल है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति का सदस्य अथवा सोसाइटी के कारबार के संबंध में निदेश देने के लिए इस अधिनियम अथवा सोसाइटी की नियमावली या उपविधियों के द्वारा या अधीन अधिकार प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति;

[5][''(छछ) ''**पदधारी**'' से अभिप्रेत है सहकारी समिति के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष तथा किसी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा निर्वाचित कोई अन्य व्यक्ति।''

(छछछ) ''**प्राथमिक सोसाइटी**'' वह सोसाइटी है जिसका कोई सदस्य निबन्धित सोसाइटी न हो];

2 [(छछछछ) ''**प्राथमिक कृषि साख (क्रेडिट) सोसाइटी**'' से अभिप्रेत है ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसानों, ग्रामीण कारीगरों और कृषि मजदूरों को आर्थिक या अन्य सहायता देना है और इसमें कृषक सेवा सोसाइटी और बहुद्देशीय सहकारी सोसाइटी भी शामिल है];

(ज) ''**निबन्धित सोसाइटी**'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निबन्धित अथवा पंजीकृत मानी जानेवाली सोसाइटी;

(झ) ''**निबन्धक**'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन सहकारी सोसाइटियों के निबन्धक के कर्त्तव्य पालन के लिए नियुक्त; एवं

(ञ) ''**नियमावली**'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली।

[3] [(ट) ''**परिवार**'' से अभिप्रेत है पति, पत्नी एवं उनके आश्रित पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों की इकाई।

टिप्पणी

[किसी भी संयुक्त परिवार के एक से अधिक बालिग सदस्य सहयोग समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ऐसा होने से सभी सदस्य समिति से कर्ज लेने का प्रयास करेंगे जिसके कारण समिति के निधि को नुकसान पहुँच सकता है। लालजी भगत बनाम हंसदीन सहयोग समिति, एल०पी०ए० सं० 14, 1942, दिनांक 28—10—1942, पटना।]

4[(ठ) ''**अल्पकालीन सहकारी साख संरचना**'' में शामिल है राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी;

1. बिहार अधिनियम 39, 1982 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. बिहार अधिनियम 21, 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. बिहार अधिनियम 18, 2008 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. बिहार अधिनियम सं० 6, 2013 दिनांक 22—5—2013 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. बिहार अधिनियम 39, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ड) ''**राष्ट्रीय बैंक**'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम 61, 1981) की धारा 6 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक;

''**रिजर्व बैंक**'' से तात्पर्य है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम 2, 34) के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक;

(ण) ''**सम्बद्धक सोसाइटी**'' से अभिप्रेत है निबंधित सोसाइटी जिसका दूसरी निबंधित सोसाइटी सदस्य है, और सम्बद्ध सोसाइटी का अर्थ है निबंधित सोसाइटी जो सम्बद्धक सोसाइटी का सदस्य है।

(त) ''**पंचायत**'' से अभिप्रेत है बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 एवं समय–समय पर उक्त में संशोधन के द्वारा अधिसूचित ग्राम पंचायत।]

[1]["(थ) ''**सामान्य निकाय**'' से अभिप्रेत है उस सहकारी समिति के सम्मिलित रूप से सभी सदस्य अथवा सभी सदस्यों के प्रतिनिधि।"

[1][''(द) ''**कृत्यकारी निदेशक**' 'से अभिप्रेत है उस नियमावली अथवा सहकारी समिति के उपविधियों में विनिर्दिष्ट समिति के कृत्यकारी कार्यपालक निदेशक।"

[1][''(ध) ''**पिछड़े वर्गों** '' से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है ''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991''

(बिहार अधिनियम सं०–3, 1992) की अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के नागरिकों की सूची, समय–समय पर यथासंशोधित;

[1]['' (न) ''**अति पिछड़े वर्गों**'' से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित हैं ''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991'' (बिहार अधिनियम सं०–3, 1992) की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के नागरिकों की सूची, समय–समय पर यथासंशोधित।]

3. भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 लागू नहीं होगा–(1) निबन्धित सोसाइटी पर भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (7 सन् 1913)] [2] लागू नहीं होगा।

4. विद्यमान सोसाइटी की व्यावृत्ति–(1) इस समय विद्यमान प्रत्येक सोसाइटी जो सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम, 1904 (10 सन् 1904) के अधीन अथवा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (2 सन् 1912) के अधीन निबन्धित हुई है, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत मानी जायगी और इसकी उपविधियाँ, जब तक परिवर्त्तित या समाप्त न हों उस हद तक प्रवृत्त रहेंगी जिस हद तक वे इस अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों से असंगत नहीं हों।

(2) उक्त अधिनियम के अधीन की गई सारी नियुक्तियाँ, निर्मित नियमावली और आदेश, निर्गत अधिसूचनाएँ तथा सूचनायें, किये गये सारे संव्यवहार, संस्थित वाद एवं अन्य कार्यवाहियाँ, यथाशक्य इस अधिनियम के अधीन क्रमशः निर्मित, निर्गत किये गये तथा संस्थित माने जायेंगे ।

टिप्पणी

[''आदेश'' शब्द से अभिप्रेत है नियमानुसार पारित आदेश। **केदारनाथ लाल बनाय शिवनारायण राम**, ए०आई०आर० 1957 पटना 4081।]

5. अधिनियम में सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के निदेशों का अर्थ लगाया जाना– भारत में किसी प्राधिकार द्वारा निर्मित तथा बिहार एवं उड़ीसा के प्रदेशों में तत्समय प्रवृत्त अधिनियम में किये जानेवाले सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के सारे निर्देश उक्त राज्यों के वैसे किसी अधिनियम के प्रयोग में इस अधिनियम के निर्देश वैसे ही लागू माने जायेंगे।

अध्याय 2

सोसाइटियों का पंजीयन

6. निबन्धक–(1) राज्य सरकार राज्य अथवाउसके किसी भाग में सहकारी सोसाइटियों के लिए किसी व्यक्ति को निबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उस निबन्धक के सहायतार्थ अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेंगी।

1. बिहार अधिनियम 6,2013 दिनांक–22–05–2013 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अब देखें–कम्पनी अधिनियम, 1956

(2) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निम्नांकित शक्ति सौंप सकेगी–

(क) निबन्धक के सहायतार्थ उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन धारा 26 के अधीन शक्तियों को छोड़कर निबन्धक की सारी अथवा कोई शक्ति, तथा

(ख) किसी सहकारी परिसंघ अथवा वित्तदाता बैंक को घारा 20, धारा 28 की उपधारा (3) तथा ख्भाग 34, धारा 35 और धारा 36, के अधीन निबन्धक की सभी अथवा कोई शक्ति ।

[2][(3) जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि कार्यों के शीघ्र निबटारे के लिए निबन्धक को अपर निबन्धक की सहायता अपेक्षित है वहाँ वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उतने अपर निबन्धक, नियुक्त कर सकेगा जितना वह उचित समझे ।

(4) अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी निबन्धक, अपर निबन्धक को थे शक्तियाँ, कृत्य और कर्त्तव्य प्रत्यायोजित, अन्तरित या समनुदेशित कर सकेंगा जो वह आवश्यक समझे जिसमें धारा 26 और 56 के अधीन की शक्तियाँ भी शामिल है। तब, अपर निबन्धक को इस प्रकार प्रत्यायोजित, अन्तरित या समनुदेशित मामलों में निबन्धक की शक्तियाँ होगी।]

अधिसूचना, दिनांक 20–11–1991 बिहार गजट (असाधारण) दिनांक 27–11–1991 में प्रकाशित)– बिहार को–ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1935 की धारा 6 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में निम्नांकित पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 3 में वर्णित शक्तियों, स्तम्भ 4 में वर्णित शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं बिहार सहकारी समिति नियमावली (बिहार को–ऑपरेटिव सोसाइटीज नियम), 1959 के अन्तर्गत निबंधक, सहयोग समितियों की शक्तियाँ प्रदान की जाती–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	शक्तियाँ	शक्ति सीमा
1.	श्री सुभाष शर्मा, भा०प्र०से, अपर निबन्धक, सहयोग समितियाँ (औद्योगिक) बिहार, पटना ।	उक्त अधिनियम की धारा 26 एवं 56 तथा बिहार को–ऑपरेटिव सोसाइटीज (औद्योगिक) नियम, 1956 के एतद् संबंधी नियम को छोड़कर अधिनियम और नियम की सारी शक्तियाँ।	सभी स्तर की सहकारी समितियों के संबंध में।

उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग उनके पदस्थापन क्षेत्र के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

टिप्पणी

[निबंधक की शक्तियाँ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर भूतलक्षी प्रभाव से सहायक निबंधक को नहीं सौंपी जा सकती है। अच्युतानन्द सिंह बनाम राज्य, 1972 बी०आर०एल० जे० (रेभन्यु) 15 : ए०आई०आर० 1971 एस०सी० 2001: 1972 पी०एल० जे०आर० 146।

निबन्धक के सहायतार्थ नियुक्त व्यक्ति, धारा 26 के सिवाय, अधिनियम के अधीन निबन्धक की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने का हकदार है, ऐसे सहायक कानून के द्वारा अभिव्यक्ततः अपवर्जित विस्तार के सिवाय राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्ति का कानून की क्रिया द्वारा, प्रयोग करने के हकदार हैं। **योगेन्द्र प्रसाद बनाम अपर निबन्धक**, 1992 (1) पी०एल० जे०आर० 9 (एस०सी०)।

अधिनियम के अधीन निबंधक का केवल यह कार्य है कि वह इस बात को देखे कि अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है कि नहीं और यदि अनुपालन किया गया है उसे निबंधित करने के अलावा और कोई विवेकाधिकार नहीं है। सरकार इसमें किसी प्रकर का काट–छाँट अथवा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, न ही वह किसी विपरीत कार्यकारी निदेशों के द्वारा उसे विशेषित कर सकती है। इस आशय की अधिसूचना कि आपवादिक मामलों में अधिनियम के अधीन निबंधक को किसी सहकारी समिति का निबंधन मंजूर करने के पूर्व सरकार का अनुमोदन

1. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. विहार अधिनियम 39, 1982 द्वारा अन्तः स्थापित ।

लेना चाहिए, बिना किसी क्षेत्राधिकार के है तथा गलत ढंग से निर्गत किया गया है। अधिनियम सरकार को ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जो निबंधक को अधिकार से वंचित कर सके, तथा उसे सरकार के अनुमोदन के अधीन बना सके। तरडीह प्रखंड मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहकारी समिति बनाम बिहार सरकार, 2008 (1) पी०एल० जे०आर० 667 1,

7. सोसाइटी जो निबन्धित हो सकती है–' ख(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, समय–समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित सहकारी समिति, जिसका उद्देश्य सहकारिता सिद्धान्त के अनुरूप सदस्यों के समान हित की अभिवृद्धि करने के साथ भारत–संविधान के खण्ड।ट में निहित किसी या सभी निर्देशों की पूर्ति सुनिश्चित करना है, को इस अधिनियम के अधीन, सीमित या बिना सीमित दायित्व के रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा ।,

(2) जहाँ सोसाइटी का दायित्व सीमित होगा वहाँ सभी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की सम्पत्ति का दायित्व में परिसमापन की दशा में उसके सदस्य द्वारा धारित अंशों पर असंदत्त राशि तक यदि हो, अथवा जहाँ दायित्व गारंटी के द्वारा सीमित होगा वहाँ वैसी गारंटी की राशि तक अथवा जहाँ किसी अन्य रीति से सीमित होगा वहाँ धारा 32 के प्रावधानों के अध्वधीन नियमावली अथवा उपविधियों में जिस प्रकार से विनिश्चित हो सकेगा उस प्रकार से सीमित होगा ।

(3) जहाँ सोसाइटी का दायित्व असीमित होगा वहाँ प्रत्येक सदस्य, भूतपूर्व सदस्य तथा मृत सदस्यों की सम्पत्ति, परिसमापन की स्थिति में धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रभारों के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक् पृथक् दायी होंगे ।

8. **पंजीकरण की शर्तें**–(1) कोई भी सोसाइटी, उस सोसाइटी को छोड़कर जिसका एक सदस्य पंजीकृत सोसाइटी हो, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं की जायगी जो अठारह वर्ष से ऊपर की आयु के कम–से–कम दस व्यक्तियों की नहीं होगी एवं जिस सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए निधियों का सृजन करना होगा, जब तक वैसे व्यक्ति–

(क) एक ही शहर अथवा ग्राम दल के निवासी न होंगे, अथवा

(ख) एक ही जनजाति, वर्ग अथवा धंधा के सदस्य न होंगे, किन्तु निबन्धक का अन्यथा निदेश अपवाद होगा ।

2 [(1–क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सहकारी सोसाइटी के किसी विशिष्ट वर्ग के लिये इन व्यक्तियों की न्यूनतम सदस्य संख्या घटा सकेगी।]

3 ख(ख) बिहार सरकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 अथवा किसी अन्य बिहार अधिनियम अथवा उसके तहत् गठित नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की उपविधि अथवा राज्य सरकार या निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी, एक प्रखण्ड में मात्र एक निबन्धित मत्स्यजीवी सहयोग समिति होगी, जिसका कार्यक्षेत्र प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा तक विस्तारित होगा ।

9. **पंजीकरण हेतु आवेदन**–(1) सोसाइटी के निबन्धन हेतु आवेदन–पत्र निबन्धक के पास दिया जायगा, तथा उसके साथ सोसाइटी की प्रस्तावित उपविधियों की एक प्रति रहेगी और जिन व्यक्तियों के द्वारा अथवा के तरफ से वैसा आवेदन–पत्र दिया जायगा वे सोसाइटी के संबंध में वैसी जानकारी देंगे जैसा निबन्धक अपेक्षा करे ।

(2) आवेदन–पत्र पर निम्नांकित हस्ताक्षर करेंगे–

[4] [(क) यदि आवेदक में कोई भी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी नहीं हो, तो धारा 8 की उप–धारा (1) या उप–धारा (क) की अपेक्षानुसार अर्हता प्राप्त कम–से–कम दस या इससे भी कम व्यक्तियों द्वारा।]

1. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. बिहार अधिनियम 39, 1982 द्वारा अन्तःस्थापित ।

3. बिहार अधिनियम 22, 2010 द्वारा अन्तःस्थापित ।

4. बिहार अधिनियम 39, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][परन्तु यह कि आवेदक पृथक परिवारों के पुरुष अथवामहिला होंगे।]

(ख) यदि आवेदकों में कोई निबंधित सोसाइटी हो तो वैसी प्रत्येक निबंधित सोसाइटी की ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, एवं यदि सोसाइटी के सभी सदस्य निबन्धित सोसाइटी में हो तो दस अन्य सदस्य अथवा, यदि दस अन्य सदस्यों से कम सदस्य हों तो वे सभी सदस्य ।

[1][(3) प्रत्येक ऐसा आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किया जायेगा–

(क) संप्रवर्त्तक सदस्यों द्वारा यथा अंगीकृत सहकारी समिति की प्रस्तावित उपविधि की चार प्रतिक,

(ख) सदस्यों के नामों की सूची, उनका पता, पेशा एवं हिस्सा भागीदारी,

(ग) संप्रवर्त्तक सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रथम बोर्ड के व्यक्तियों के नामों की सूची,

(घ) अध्यक्ष द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उस बैठक के संकल्प की सच्ची प्रतिलिपि, जिसमें उपविधि अंगीकृत की गयी हो।,

10. कतिपय प्रश्नों पर निबन्धक द्वारा निर्णय लेने की शक्ति–जब प्रश्न उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अमुक व्यक्ति कृषक है अथवा गैर कृषक, या कोई व्यक्ति अमुक नगर या ग्राम या ग्राम दल का निवासी है, अथवा दो या अधिक ग्राम मिलाकर एक दल समझा जाय अथवा कोई व्यक्ति किसी विशेष जनजाति, वर्ग या धंधा का है तो उस प्रश्न का निर्णय निबन्धक करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

11. पंजीकरण–[2] [(1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि समिति ने इस अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमावली का अनुपालन किया है और उसकी प्रस्तावित उपविधियाँ इस अधिनियम अथवा नियमावली के प्रतिकूल नहीं है तो वह समिति एवं उसकी उपविधि को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा तथा समिति के संगठनकर्ताध्संप्रवर्तक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र एवं स्वयं द्वारा सम्यक्रूप से हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद रजिस्ट्रीकृत उपविधियों की मूल प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज देगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार की राय में उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन अनुबद्ध शर्तों को पूरा किया गया प्रतीत न हो तो इन्कार करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर समिति का रजिस्ट्रेशन करने से वह इन्कार कर देगा और संगठनकर्त्ताध्संप्रवर्तक को निबन्धित डाक से अपने निर्णय को प्रेषित करेगा। नियत अवधि के भीतर इनका प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति में सहकारी समिति रजिस्ट्रीकृत समझी जायेगी और ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार एक माह के भीतर रजिस्ट्रीकृत समझे जाने का प्रमाण–पत्र और स्वहस्ताक्षरित एवं मुहर सहित रजिस्ट्रीकृत उपविधि की मूल–प्रति निबन्धित डाक से प्रेषित करेगा ।

(3) जहाँ उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का आदेश संगठनकर्त्ताध्संप्रवर्त्तक को प्राप्त हो गया हो अथवा विहित अवधि के भीतर समझा गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र संगठनकर्ताध्संप्रवर्त्तक को प्राप्त नहीं हुआ हो, तो यदि ऐसा आदेश धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो वह सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकेगा और यदि ऐसा आदेश सहकारी समिति के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया हो तो, राज्य सरकार के पास अपील संस्थित किया जाएगा ।

परन्तु ऐसी अपील इन्कार आदेश के प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर अथवा समझा गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के संसूचन हेतु विहित की गई अवधि के समाप्ति से साठ दिनों के भीतर की जा सकेगी।

(4) यदि रजिस्ट्रार की राय में सोसाइटी के संगठनकर्त्ताध्संप्रवर्त्तक द्वारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन छल या गलती से करा लिया गया है तो रजिस्ट्रार उक्त रजिस्ट्रेशन को रद्द करने हेतु राज्य सरकार के पास अपील कर सकेंगे,

परन्तु वह अपील रजिस्ट्रेशन आदेश के साठ दिनों के भीतर ही की जा सकेगी ।,

टिप्पणी

[आवश्यकता नहीं होने पर किसी कर्मचारी को तीन माह पूर्व एतदर्थ सूचना देकर या तीन माह का वेतन देकर पदच्यूत किया जा सकता है। **चतुर्भुज सहाय बनाम चेयरमैन, निदेशक पर्षद, बिहार राज्य को–ऑपरेटिव बैंक लि०,** ए०आई०आर० 1955 पटना 223।

उप विधियों जो अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुकूल न हो। अविधिमान्य समझी जायेगी। 1959 बी०एल० जे०आर० 38 ।

निबंधक को पूर्व में दिए गए अधिकार से वंचित करने संबंधी अधिसूचना के बाद सहायक निबंधक द्वारा निर्गत सहकारी समिति के निबंधन का प्रमाण–पत्र। सहकारी समिति को स्वीकृत निबंधन तकनीकी तौर पर गलत हो सकता

1. बिहार अधिनियम 10,2002 द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. प्रतिस्थापित तत्रैव ।

है, लेकिन कानूनी तौर पर गलत नहीं है, क्योंकि निबंधन के लिए निबंधक के पास आवेदन दिया गया था तथा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त उसने सहायक निबंधक को उक्त निबंधन करने का निर्देश दिया। इसका प्रभाव यह है कि गलत व्यक्ति ने सक्षम व्यक्ति के निर्देशन में अपने अधिकार का प्रयोग किया। निबंधक द्वारा अपने वैधानिक कार्य करने में असफल रहने के लिए सहकारी समिति को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। **तरडीह प्रखंड मत्स्यजीवी स्वावलम्बी सहकारी समिति बनाम बिहार सरकार**, 2008 (1) पी०एल० जे०आर० 6671,

1[''11–क. सहकारी समितियों का निबन्धन जो इस अधिनियम द्वारा निबंधित नहीं है। जहाँ बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा 5 के अन्तर्गत निबंधित समिति इस अधिनियम के अधीन सहकारी समिति के रूप में सम्परिवर्तित करने का निर्णय लेती है, इस प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन लिखित प्रावधानों एवं सरकार के निर्णय के अनुरूप निबंधन हेतु आवेदन करेगी।'',

[2][11.ख. बिहार अधिनियम ट५ 1935 या किसी अन्य अधिनियम अथवा उसके तहत् गठित नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की उपविधि अथवा राज्य सरकार या निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सभी विद्यमान प्रखण्डस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिनका कार्यक्षेत्र प्रखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो, एक समिति में संविलित माने जाएँगे तथा बिहार अधिनियम ट५ 1935 के अन्तर्गत एक नई समिति स्वतः निबन्धित समझे जाएँगे एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा,

परन्तु, ऐसा पुनर्गठन होने पर विद्यमान सहयोग समिति अथवा बिहार अधिनियम ट५ 1935 अथवा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी समिति के सभी सदस्य पुनर्गठित समिति के सदस्य समझे जाएँगे एवं सदस्यों को वैसे समिति के सदस्यों के सभी अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होंगे ।

परन्तु, यह और कि, वैसे पुनर्गठन के बाद, निबंधक ध्सरकार, पुनर्गठित समिति एवं वैसे सम्बद्ध समितियों, जिसके मत्स्यजीवी सहयोग समिति सदस्य हो, के कार्य संचालन हेतु तदर्थ प्रबन्ध समिति गठित करेगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से अनधिक होगी तथा जिसके अधीन निर्वाचन के बाद नई प्रबन्ध समिति का गठन किया जाएगा।

12. **रजिस्ट्रार का साक्ष्य**– जबतक यह सिद्ध न हो कि सोसाइटी का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है तब तक निबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित पंजीकृत प्रमाण–पत्र इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि उसमें कित सोसाइटी विधिवत् पंजीकरण है।

अध्याय 3

पंजीकृत सोसाइटी के निगमन–कार्य एवं विशेषाधिकार

13. **सोसाइटी निगम निकाय होगी**– सोसाइटी का पंजीकरण जिस नाम से वह पंजीकृत होगी उसके अधीन शाश्वत् उत्तराधिकार तथा सामान्य मुहर एवं सम्पत्ति अर्जित तथा धारित करने, संविदा करने, वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित तथा प्रतिरक्षित तथा जिन प्रयोजनों के लिये इसका गठन हुआ है उनके लिये सब आवश्यक कार्य करने की शक्ति के साथ उसे निगम निकाय बना देगा।

[3] [13–क. राज्य सरकार के द्वारा सहकारिता आन्दोलन का उन्नयनः ख'' (1) राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रवन्धन को

प्रोत्साहित एवं उन्नय करना और इस ओर ऐसे कदम उठाना, जिसकी आवश्यकता हो, राज्य सरकार का दायित्व होगा ।

[4][(2) उप–धारा (1) के प्रावधानों के अधीन सहकारी समिति के प्रोत्साहन एवं उन्नयन हेतु राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझे तो–

(क) किसी सामान्य या निबंधित सहकारी समिति के किसी वर्ग के विकास में सहायता के विचार से सहकारी समिति की हिस्सा–पूँजी में सीधे अंशदान दे सकेगीय

(ख) किसी सहकारी समिति की हिस्सा पूँजी के निर्माण एवं सम्बर्द्धन के लिए सहायता कर सकेगीय

(ग) सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दे सकेगी या सहकारी समिति के द्वारा निर्गत डिबेंचर पर मूल धन के पुनर्भुगतान और सूद के भुगतान की गारंटी दे सकेगी या किसी सहकारी समिति को दिये गये ऋण या अग्रिम के मूलधन के पुनर्भुगतान औरसूद के भुगतान की गारंटी दे सकेंगी।'',

1. बिहार अधिनियम 18, 2008 द्वारा अन्तः स्थापित ।

2. बिहार अधिनियम 22, 2010 द्वारा अन्तःस्थापित ।

3. बिहार अधिनियम 5, 1989 द्वारा अन्तः स्थापित ।

4. बिहार अधिनियम 6, 2013 दिनांक–22–05–2013 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[13–ख. नाम का संप्रदर्शन (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन अपने रजिस्ट्रोकृत कार्यालय का नाम एवं पता सुपाठ्य अक्षरों में तथा ऐसे प्रत्येक कार्यालय के स्थान पर जहाँ इसका कारबार होता हो, सहज दृश्य स्थानों और निम्नलिखित में भी संप्रदर्शित करेगा –

(क) प्रत्येक सूचना एवं प्राधिकृत प्रकाशन में,

(ख) अपने सभी सविया, कारबार के पत्रों, माल के लिए आदेश, बीजक, लेखा–विवरणी, रसीद एवं प्रत्यय–पत्रों पर,

(ग) सभी विनिमय–पत्रों, वचन–पत्रों, पृष्ठांकन, चेकों एवं भुगतान आदेश पर जिन पर उसकी या उसकी ओर से हस्ताक्षर किया जाता हो,

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी अपने नाम में, राजभाषा में ''कोआपरेटिव'' तथा ''लिमिटेड'' अनलिमिटेड'' अथवा राज्य–सूची में मान्यता प्राप्त अन्य भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों को अवश्य रखेगी।,

14. **पंजीकृत सोसाइटी के पास प्रबन्ध समिति आदि होंगे**–(1) प्रत्येक निबंधित सोसाइटी का नियमावली के अनुसार एक निबन्धित पता होगा जिस पर सारी सूचनायें तथा संचार प्रेषित किए जा सकेंगे एवं उक्त पता में कोई परिवर्तन होने पर इसकी लिखित सूचना निबन्धक को, उस किसी वित्तपोषक बैंक को, जिसका वह शेयरधारक, हो, तथा सहकारी परिसंघ को, यदि रहे वैसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर प्रेषित करनी होगी।

[2][(2) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का प्रबन्धन इस अधिनियम एवं इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावलीध उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति में निहित होगा।

इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाई गई सोसाइटी नियमावलीध्उपविधियों के किसी प्रावधान में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में पदधारक या पदधारकों सहित शीर्ष एवं राज्य स्तरीय समिति में अधिकतम सत्तरह, केंद्रीय सहकारी सोसाइटी में पन्द्रह तथा प्राथमिक सोसाइटी में तेरह सदस्य होगा।

3 ["परन्तु यह कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए दो स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए दो स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए दो स्थान आरक्षित होगाः

परन्तु और यह कि उपर्युक्त परन्तुक में यथाविहित स्थानों के आरक्षण के ध्येय से राज्य सरकार, सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा, वैसी समितियों अथवा समितियों के वर्ग को जिनमें सदस्यों के रूप में व्यष्टि अन्तर्विष्ट नहीं हैं अथवा जिनमें उपर्युक्त आरक्षण श्रेणियों से सदस्य नहीं हैं, को अपवर्जित कर सकेगीः

परन्तु और यह कि उपर्युक्त के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कुल स्थानों के पचास प्रतिशत से अनधिक होगा :

परन्तु और भी कि उपर्युक्त के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे :

परन्तु यह और भी कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों पिछड़े वर्गों एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे :

परन्तु यह और भी कि इस प्रकार महिलाओं के लिए आरक्षित कुल स्थानों की संख्या दो से अन्यून होगीः

इस प्रकार आरक्षित स्थान, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्यों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा महिलाओं के बीच से, निर्वाचन या/और सहयोजन द्वारा भरे जायेंगे। यह प्रावधान प्राथमिक सोसाइटी से शीर्ष सोसाइटी तक की सभी सोसाइटियों पर लागू होगा :

परन्तु और भी कि प्राथमिक समिति तथा शीर्ष समिति तक ऐसा आरक्षण इस प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा शासित होगा।''

[4][(3) जब राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी किसी निबंधित सोसाइटी में प्रबंध निदेशक, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उसका उस तरह के किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्त होता है तो वह मुख्य कार्यपालक होगा और प्रबन्ध समिति के सामान्य निदेश एवं नियंत्रण के अध्यधीन उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे–

1. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित ।

3. बिहार अधिनियम सं०–6, 2013 दिनांक–22–05–2013 द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. बिहार अधिनियम 5, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) निबंधित सोसाइटी के प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण रखनाय

(ii) प्रबंध समिति की बैठक आहूत करनाय

(ii) निबंधित सोसाइटी की ओर से सभी रुपये तथा प्रत्याभूति प्राप्त करना तथा निबंधित सोसाइटी के नगद शेष तथा अन्य सभी सम्पत्तियों के संधारण एवं अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना।

(iv) निर्बोधत सोसाइटी की ओर से प्रोमिसरी नोट, सरकारी तथा अन्य प्रत्याभूतियों का पृष्ठांकन एवं अन्तरण करना और चेकों तथा अन्य नेगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेंट का पृष्ठांकन, उसपर हस्ताक्षर तथा पराक्रमण करनाय

(v) निबंधित सोसाइटी के दैनिक कारोबार एवं कार्यकलापों का सामान्य संचालन, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होनाय

(vi) बैंकों में निबन्धित सोसाइटी का लेखा संचालन करना तथा सभी प्राप्तियाँ तथा जमा पर हस्ताक्षर करनाय

(vii) निबन्धित सोसाइटी के पक्ष में सभी बन्ध—पत्रों तथा अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करनाय

(viii) निबन्धित सोसाइटी के कर्मचारियों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करनाय

(ix) निबन्धित सोसाइटी की उप—विधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति में निहित शक्तियों को छोड़कर निबन्धित सोसाइटी के किसी वेतनभोगी कार्मिक को नियुक्त, पदोन्नत, स्थानान्तरित, दंडित, निलम्बित, सेवामुक्त अथवा बर्खास्त करनाय

(x) निबन्धित सोसाइटी के विरुद्ध अथवा पक्ष में मुकदमा दायर करना अथवा किसी मुकदमें या अन्य न्यायिक कार्यवाही का संचालन करना, प्रतिवाद करना समझौता करना एवं वापस लेना तथा किसी दावा के भुगतान अथवा पूत्ति के लिए समय स्वीकृत करना या समझौता करनाय

[(xi) उनके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में निबंधित सोसाइटी के किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों को सभी अथवा कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना ।

[1][(4—क) इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी जहाँ रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी में राज्य सरकार तीस लाख रुपये से अधिक हिस्सा पूँजी सीधे निवेश की हो उस दशा में उस सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार तीन व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नाम निर्देशित कर सकेगीः

परन्तु उन नाम निर्देशित सदस्यों में दो सरकारी सेवा से एवं तीसरा सोसाइटी के क्रियाकलापों से सम्बन्धित सहकारीधवित्तीय संस्थान का पदधिकारी होगा :

परन्तु और कि सोसाइटी की उपविधियों में यथा उपबंधित पदेन सदस्यों की गणना नाम निर्देशन हेतु उपबंधित कोटाधनियत संख्या में की जायगी :

परन्तु और भी कि ऐसे नाम निर्देशित सदस्य इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई नियमावली या समिति की उपविधि के अनुसार आहूत की गई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की प्रबन्ध समिति की किसी बैठक और अथवा शेयरधारकों की सामान्य बैठक में भाग ले सकेंगे और प्रबन्ध समिति की बैठक में मत दे सकेंगे, किन्तु शेयरधारकों की सामान्य बैठक में मत देने के हकदार नहीं होंगे ।,

[2][''(4) (ख) इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समिति के बोर्ड में बैकिंग, प्रबन्धन, वित्त अथवा समिति के उद्देश्यों और कार्यकलाप के अनुरूप दूसरे क्षेत्रों के विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सदस्य के रूप में समिति द्वारा सहयोजित किये जा सकेंगे;

परन्तु इस प्रकार सहयोजित सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी और यह उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट बोर्ड की अधिकतम संख्या के अतिरिक्त होगीय

परन्तु और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में ऐसी सदस्यता के अधीन मत देने का अधिकार नहीं होगा और न वे बोर्ड में पदधारी के रूप में निर्वाचित होने के पात्र होंगेय

परन्तु और भी कि सहकारी समिति के कृत्यकारी निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्याकी गणना के प्रयोजनार्थ ऐसे सदस्य अपवर्जित किये जायेंगे ।

1. बिहार अधिनियम सं०–6,2013 दिनांक–22–05–2013 द्वारा पुर्नसंख्यांकित ।

2. अन्तःस्थापित तत्रैव ।

1 [(5) इस अधिनियम के किसी प्रावधान, इसके अधीनबनायी गयी नियमावली एवं सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में मनोनीत सदस्य एवं पधारी इस संशोधन अधिनियम, 2002 के गजट में प्रकाशन की तिथि से नब्बे दिनों के अन्दर पदमुक्त हो जायेंगे, और वह रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी रिक्त पदों पर अपनी पदावधि की अवशेष अवधि के लिए निर्वाचन करायेगी।

परन्तु और कि अवक्रमित समितियों में सोसाइटी के प्रशासक इस संशोधन अधिनियम, 2002 के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बारह महीने के भीतर निर्वाचन द्वारा नई प्रबन्ध समिति का गठन करायेंगे अन्यथा रजिस्ट्रार अगले तीन महीने के लिए उस सोसाइटी के लिए एक नया प्रशासक नियुक्त करेगा और निर्वाचन द्वारा नई प्रबन्ध समिति गठित करायगा ।,

(6) [2][xxxx],

[1][(7) उप–धारा (9) के प्रावधानों के होते हुए भी प्रबंध समिति का नाम निदेशित सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

(8) [2][xxxx],

3 ['' (9) किसी सहकारी समिति के नियमों या उपविधियाँ में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, किसी सहकारी समिति की बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से पाँच वर्षों की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड के पदावधि के सह–विस्तारी होगी,

परन्तु बोर्ड आकस्मिक रिक्ति को उसी वर्ग के सदस्यों से, मनोनयन द्वारा भर सकेगा, जिससे संबंधित आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई हो, यदि बोर्ड की मूल अवधि के आधे से कम की बाकी होय

परन्तु यह और यदि बोर्ड की अवधि उसकी मूल अवधि के आधे से अधिक बाकी हो, और यदि सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए चाहे जिस किसी कारण से कोई भी रिक्ति उत्पन्न होती है तो शेष अवधि के लिए, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार उप–निर्वाचन कराकर रिक्ति को भरेगा।''

ख(10) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार किसी सहकारी समिति, जहाँ राज्य सरकार ने हिस्सापूँजी अथवा ऋण अथवा वित्तीय सहायता अथवा कोई सरकारी गारंटी दी हो, में बोर्ड का निर्वाचन संचालित करने में यदि कारणवश असफल हुआ हो तो बोर्ड अवधि की समाप्ति की तिथि से स्वतः अधिक्रमित समझा जायेगा तथा निबन्धक, सहयोग समितियाँ, विधि के अनुसार नये बोर्ड के गठन हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति को प्रशासक के रूप नियुक्त करेंगे। इस प्रकार नियुक्त प्रशासक बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निर्वाचन के संचालन में हर संभव सहायता करेगा। यह व्यवस्था पूर्णतः अन्तरिम व्यवस्था होगी और प्रशासक, विहित अवधि के भीतर, निर्वाचन के उपरान्त नये बोर्ड को समिति का प्रबन्धन सौप देगा,

परन्तु जहाँ सरकार हिस्सा–पूँजी अथवा ऋण अथवा वित्तीय सहायता अथवा किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी हो और जहाँ बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार बोर्ड की अवधि की समाप्ति के पूर्व निर्वाचन संचालित करने में असफल रहता है, तो निबंधक, सहकारी समितियाँ निर्वाचन संचालन करने के प्रयोजनार्थ एक तदर्थ बोर्ड की नियुक्ति के लिए सदस्यों की एक विशेष आम सभा आयोजित करने का आदेश दे सकेंगे,

परन्तु यह और कि निर्वाचन संचालन करने के प्रयोजनार्थ तदर्थ समिति में बोर्ड के वहिर्गामी सदस्य अथवा पदधारी सम्मिलित नहीं किये जायेंगे,

परन्तु और भी कि इस प्रकार नियुक्त तदर्थ बार्ड की अवधि छः माह से अधिक की नहीं होगी, और, वह तदर्थ बोर्ड बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निर्वाचन के संचालन में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। यह व्यवस्था पूर्णतः अंतरिम व्यवस्था होगी और इस प्रकार नियुक्त तदर्थ बोर्ड, विहित अवधि के भीतर, निर्वाचन के उपरान्त नये बोर्ड को समिति का प्रबन्धन सौंप देगा।''

(11) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अपने निबन्धित पता पर हर समुचित समय निम्नांकित कागजात निःशुल्क निरीक्षण के लिए खुली रखेगी–

(क) इस अधिनियम की प्रति,

(ख) उस सोसाइटी को प्रशासित करनेवाली नियमावली की प्रति,

1. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपधारा (6) ''और उपधारा (8)'' निरसित तत्रैव ।
3. बिहार अधिनियम सं०–6, 2013 दिनांक–22–05–2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) उस सोसाइटी की उपविधियों की प्रति, तथा

(घ) अपने सदस्यों की पंजी

[1][XXXX]

टिप्पणी

[प्रार्थी, सहकारिता बैंक में सावधिक पदस्थापन पर चेयरमैन का प्रभारधारी, प्रार्थी इस आधार पर अपने पद से हटने में विलम्ब नहीं कर सकता कि शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन होने पर भी उन्हें संशोधन की शीघ्र जानकारी नहीं हुई क्योंकि अधिनियम में संशोधित प्रावधान केवल सरकार द्वारा मनोनीत पधारकों को ही प्रभावित करने को आशयित था और संशोधन तत्क्षण से प्रभावकारी होना आज्ञापित था। नवल किशोर यादव बनाम बिहार राज्य, 2002 (4) पी०एल० जे०आर० 426।]

[14क–कुछ रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के प्रबन्ध समिति का निर्वाचन ख'' (1) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा निबन्धित समिति की उप–विधि के किसी प्रावधानों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 तथा उसके अधीन बनी नियमावली सपठित बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिए विहित रीति से किया जायेगा,

परन्तु विद्यमान प्रावधानों के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा संचालित निबन्धित सहकारी सोसाईटी के सभी पूर्व निर्वाचन सुरक्षित रहेंगे,

परन्तु, और कि, सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन सम्पन्न कराने संबंधी कोई कार्रवाई, आदेश, निर्णय इस संशोधन के अधीन किया गया समझा जायेगा तथा वैसा सम्पन्न कोई निर्वाचन किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा डिक्री के होते हुए भी, विधिमान्य समझा जायेगा।''

3ख'' (2) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा निबंधित समिति की उप–विधि के किसी प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन, इस धारा के प्रावधान के अधीन सम्पन्न होगा यदि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो परन्तु निर्वाचन का परिणाम घोषित नहीं हुआ हो।''

[3][''(3) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा निबंधित समिति की उपविधि के किसी प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन निबन्धित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति का निर्वाचन इस अधिनियम की धारा 14 की उप–धारा (9) में यथा विहित प्रबंध समिति की कालावधि की समाप्ति के पूर्व अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पारित प्रबंध समिति के अधिक्रमण आदेश की तिथि से नौ माह के भीतर संपन्न होगा,

परन्तु इस संशोधन के अधिसूचना की तिथि को प्रबंध समिति के अधिक्रमण के मामले में, प्रबंध समिति का निर्वाचन नौ माह के भीतर होगा।''

[XXX]

4[XXX]

6. उप–धारा (1) के तहत अधिसूचित वर्गों अथवा किसी वर्ग की कोई भी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के निर्वाचन के परिणाम के 90 दिनों के अन्दर दाखिल एक निर्वाचन याचिका को छोड़ कर किसी भी रीति से प्रश्न नहीं उठाया जाएगा एवं उसे इस अधिनियम के धारा 48 के अधीन विवाद के रूप में विनिश्चय किया जाएगा। ऐसे निर्वाचन याचिका को रजिस्ट्रार अथवा इस अधिनियम की धारा–6 के अधीन रजिस्ट्रार के सहायतार्थ नियुक्त ऐसे अन्य पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जा सकेगा ।,

15. **ऋण लेने पर प्रतिबन्ध**– पंजीकृत सोसाइटी मात्र सदस्यों तथा गैर सदस्यों से उस सीमा तक एवं उन शर्त्तों के अधीन जमा और ऋण प्राप्त करेगी जो नियमावली अथवा उपविधियों में विहित होंगे ।

16. **ऋण देने पर प्रतिबन्ध**–(1) बिना निबंधक की सामान्य अथवा विशेष मंजूरी के तथा उसके द्वारा अधिसेपित प्रतिबन्धों के अधीन निबन्धित सोसाइटी–

1. उपधारा 11 का परन्तुक बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा निरसित ।
2. बिहार अधिनियम 18,2008 द्वारा अन्तः स्थापित ।
3. बिहार अधिनियम 3, 2012 दिनांक 10–02–2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपधारा (4) और (5) विलोपित तत्रैव ।

(क) सदस्यों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को ऋण नहीं देगी, अथवा

(ख) चल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर रुपये उधार नहीं देगी।

1 [परन्तु यदि कोई निर्देश प्राप्त होता है तो रजिस्ट्रार उसकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर उसका निपटारा करेगा]

(2) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी पंजीकृत सोसाइटी अथवा पंजीकृत सोसाइटियों के वर्ग को अचल सम्पति के बन्धक पर रूपये कर्ज देने से प्रतिषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकेगी।

(3) जहाँ निबन्धक ने उप–धारा (1) के प्रावधानों के अधीन वित्तदायी बैंक को मंजूरी दी हो, वहाँ निबंधित सोसाइटी, जो वैसे वित्तपोषक बैंक का सदस्य हो. मंजूरी के शत्तों जो निबन्धक द्वारा विहित किये जायें, वितपय बैंक के लिए अभिकर्ता के रूप में काम कर सकेगी और वैसे अभिकर्ता के रूप में वह कमीशन (शुल्क)। अथवा कमीशन के बिना वित्तदायी बैंक द्वारा दिये गए अथवा दिये जानेवाले ऋणों अथवा अग्रिमों से सम्बन्धित अथवा कोई सव्यवहार पूरा कर सकेगी।

17. गैर–सदस्य के साथ अन्य संव्यवहार प्रतिबन्ध– सदस्य के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के पंजीकृत सोसाइटी का संव्यवहार और भी वैसे रुकावट एवं प्रतिबन्धों के अध्यधीन होगा जो राज्य सरह नियमावली के द्वारा विहित करे।

18. आरक्षित निधि (1) निबन्धित सोसाइटी के शुद्ध लाभ का न्यूनतम पैंतीस प्रतिशत प्रतिवर्ष आर निधि में जमा कर दिया जायगा, परन्तु राज्य सरकार किसी सोसाइटी अथवा सोसाटियों के वर्ग के लिए इस अनुच में नियमानुसार कमी या वृद्धि कर सकेगी।

(2) उस सीमा तथा उस रीति, को छोड़कर जो नियमानुसार विहित किये जा सकेंगे, आरक्षित निधि ३ प्रयोग सोसाइटी के कारबार पर नहीं किया जायगा ।

2[(3) सभी निबन्धित सोसाइटियों द्वारा अपने शुद्ध लाभ का न्यूनतम दस प्रतिशत राशि 'सहकारी शिक्षा विकास निधि' में हस्तान्तरित किया जायेगा ।

(4) उन निबन्धित सोसाइटियों में जिनके हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान हो, शुद्ध लाभ के न्यूनतम दस प्रतिशत राशि 'हिस्सा मोचन निधि' में तब तक हस्तान्तरित किया जायेगा जब तक वह राशि सरका के हिस्सा पूँजी के बराबर न हो जाये ।,

3[(5) सोसाइटी के कारबार में अप्रयुक्त आरक्षित निधि का कोई अंश धारा 19 में विनिर्दिष्ट एक अथर अधिक तरीकों से उस नियमावली के अध्यधीन, जो राज्य सरकार एतदर्थ निर्मित कर सकेगी, निवेशित अधर निक्षिप्त किया जाएगा ।

19. निधियों का निवेशन– धारा 16 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के अध्यधीन पंजीकृत सोसाइवे अपनी निधियों को–

4 [(क) सरकारी बचत बैंक में, अथवा

(ख) अपने वित्तदाता बैंक में, अथवा

(ग) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम 2, 1882) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में, अथवा

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में, अथवा

(ङ) रजिस्ट्रार के सामान्य अथवा विशेष मंजूरी से और उन शत्तों पर जो वह अधिरोपित करे,

(i) किसी अन्य निबंधित सोसाइटी की प्रतिभूति पर अथवा शेयरों में, अथवा

(ii) किसी अनुसूची बैंक में अथवा रजिस्ट्रार के मंजूरी से बैंक का कारबार करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के पास

(च) नियमावली द्वारा अनुमत किसी अन्य रीति से, निवेशित अथवा जमा कर सकेगी।,

1. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2. उपधारा (3) और (4) बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. उपधारा (3) उपधारा (5) के रूप में पुर्नसंख्यांकित ।
4. प्रति स्थापित तत्रैव ।

20. दातव्य प्रयोजन में दान धारा 18 की उपधारा (1) अथवा किसी नियम के द्वारा अपेक्षित राशि

को आरक्षित निधि में डाल देने के बाद कोई निबन्धित सोसाइटी दातव्य विन्यास अधिनियम, 1890 (6 सन् 1890) की धारा 2 में परिभाषित की अनुसार किसी दातव्य प्रयोजन के लिए शुद्ध लाभ का दस प्रतिशत से अनाधिक रकम दे सकेगी:

निबन्धक अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश से किसी सोसाइटी अथवा सोसाइटियों के वर्ग को इस धारा के अधीन दान करने पर प्रतिषेध लगा सकेगा ।

21. निधियों के विभाजन पर प्रतिबन्ध — पंजीकृत सोसाइटी की निधियों का कोई अंश उसके सदस्यों में बोनस या लाभांश या अन्यथा विभाजित नहीं किया जायगा :

परन्तु, धारा 18 को उपधारा (1) अथवा किसी नियम द्वारा अपेक्षित रकम को आरक्षित निधि में डाल देने

के बाद, शुद्ध लाभ के किसी अवशेष को, विगत वर्षों के किसी उपलब्ध लाभ के साथ, सदस्यों में विभाजित अथवा सोसाइटी की विशेष सेवा करने के लिए किसी सदस्य को बोनस अथवा पारिश्रमिक के रूप में अदायगी करने अधवा सदस्यों के सामान्य लाभ के लिए प्रयुक्त करके, उस परिमाण तथा उन शत्तों के अधीन वितरित किया जा सकेगा जो नियमावली अथवा उपविधियों द्वारा विहित होंगे।

22. सदस्य के शेयर अथवा हित विषयक् प्रभार एवं समंजन— किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा

मृत सदस्य की सम्पत्ति से बाकी सोसाइटी का किसी सदस्य, उस सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के पूंजी का शेयर अथवा हित तथा निक्षेप अथवा अंशदान पर तथा लाभ में से किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की सम्पत्ति को संदेय किसी रकम पर निबन्धित सोसाइटी का प्रभार होगा और किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की सम्पत्ति को दी जानेवाली अथवा संदेय किसी रकम को वैसे ऋण की अदायगी में अथवा की ओर समजित कर सकेगी ।

23. सहयोग समिति का पूर्व दावा— भू—राजस्व या लोक माँग जैसा वसूलीय धन संबंधी किसी सरकारी दावा अथवा जमींदार का लगान या लगान जैसा वसूलीय धन संबंधी किसी दावा के अध्यधीन, किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की सम्पत्ति से निबंधित सोसाइटी बाकी कोई ऋण परादेय माँग पूर्विक प्रभार होंगे :

(क) यदि उक्त माँग बीज अथवा खाद की आपूर्ति अथवा क्रय हेतु अनुदत्त किसी ऋण के संबंध में बाकी हो तो, वैसी आपूर्ति अथवा ऋण की अन्तिम किस्त के प्रतिसंदेय होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर किसी समय वैसे सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य अथवा वैसे मृत सदस्य की सम्पत्ति की उपज अथवा अन्य कृषि उत्पादन पर,

(ख) यदि उक्त माँग पशु, पशु के लिए चारा, कृषि कार्य संबंधी अथवा औद्योगिक उपकरण अथवा यंत्र अथवा उत्पादनार्थ कच्चे माल की आपूर्ति अथवा ऐसे किसी ऋण के पूरे अथवा अंश से क्रीत किसी पशु अथवा वस्तु पर अथवा इस प्रकार से आपूरित अथवा क्रीत कच्चे माल से उत्पादित किसी सामग्री पर ।

टिप्पणी

ख परिसमापनाधीन समिति के ऋणों के लिए भूतपूर्व सदस्य के दायित्व का उल्लेख अधिनियम की धारा 23 में है और उसे सोसाइटी के किसी सदस्य का सोसाइटी के प्रति ऋण से कोई सम्बन्ध नहीं है। बरही टोला सहकारी समिति बनाम शम्भुनाथ सिंह, 23 पी०एल०टी० 104।,

23—क. गैर सदस्यों के प्रति धारा 23 का प्रवर्त्तन— किसी गैर—सदस्य अथवा मृत गैर—सदस्य की सम्पत्ति से धारा 16 की उपधारा (1) की कण्डिका (क) के अधीन प्राधिकृत, पंजीकृत सोसाइटी को वसूलीय कोई ऋण अथवा परादेय माँग वैसे परिमाण' तक तथा वैसे दावों, शत्तों एवं प्रतिबन्धों के अध्यधीन गैर—सदस्य की सम्पत्ति अथवा मृत गैर—सदस्य की सम्पत्ति पर पूर्विक प्रभार होंगे। जैसे किसी सदस्य अथवा मृत सदस्य की सम्पत्ति से निबंधित सोसाइटी का बाकी ऋण अथवा परादेय माँग धारा 23 के अधीन उस सदस्य की सम्पत्ति अथवा मृत सदस्य की सम्पत्ति पर पूर्विक प्रभार होती है।

24. सदस्य की मृत्यु होने पर हित का अन्तरण (1) निबंधित सोसाइटी, किसी सदस्य की मृत्यु होने

पर सोसाइटी की पूंजी में उसका शेयर अथवा हित नियमानुसार मनोनीत व्यक्ति को अथवा, यदि ऐसा मनोनीत व्यक्ति न हो तो, ऐसे व्यक्ति को, जो सोसाइटी अथवा प्रबन्ध समिति को उस मृत सदस्य का उत्तराधिकारी

अथवा वैध प्रतिनिधि प्रतीत हो, अंतरित कर सकेगी, अथवा वैसा मनोनीत व्यक्ति, उतराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि को, यथास्थिति नियम उपविधियों के अनुसार विनिश्चित उस सदस्य के शेयर अथवा हित अथवा वैध प्रतिनिधि प्रतीत हो, अन्तरित कर सकेगी, अथवा वैसा मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी अथवा धारा मूल्यानुसार राशि दे सकेगीः

परन्तु—

(i) असीमित दायित्व वाली सोसाइटी के मामले में वैसा मनोनीत व्यक्ति उत्तराधिकारी अथवा धारा 22 के अधीन शुल्क की राशि की कटौती करने के बाद सोसाइटी से लेने की अ₂ (5 प्रतिनिधि यथास्थिति, मृत सदस्य के शेयर अथवा हित का उपर्युक्त अनुसार विनिश्चित कर सकेगा,

(ii) सीमित दायित्व वाली सोसाइटी के मामले में सोसाइटी मृत सदस्य के शेयर अथवा हित को घार के अधीन विद्यमान शुल्क के अध्यधीन वैसे मनोनीत व्यक्ति उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनि को यथास्थिति, जो नियमावली एवं उपविधियों के अनुसार सोसाइटी के सदस्य होने योग्य हो मृत सदस्य की मृत्यु के तीन महीने के भीतर आवेदन देने पर उस आवेदन पत्र में वर्णित व्य को, जिसमें वैसी योग्यता हो, अन्तरित कर देगी :

परन्तु और भी यह कि सदस्य की मृत्यु की तिथि से छः माह की समाप्ति तक अथवा उस अवधि भीतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया किसी दावा का धारा 48 के अधीन निबटारा एक सौ रुपये से अधिक बुलाने की राशि का भुगतान उस उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि को नहीं किया जायगा जो नियमावली के अनुम् अथवा मनोनीत न हो ।

(2) ऊपर लिखे अनुसार, निबन्धित सोसाइटी वैसे मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधिक यथास्थिति सोसाइटी के मृत सदस्य का सारा अन्य धन आदाय कर सकेगी ।

(3) पंजीकृत सोसाइटी द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार किये गये सारे अन्तरण एवं भुगतान कियों अन्य व्यक्ति द्वारा सोसाइटी पर की गई किसी माँग के प्रति मान्य और प्रभावी होंगे ।

24—क. पंजीकृत सोसाइटी और उसके लेनदारों के बीच सुलह मंजूर करने की निबन्धक को शक्ति (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी पंजीकृत सोसाइटी और उसके लेनदा अथवा उनके किसी वर्ग में सुलह या व्यवस्था प्रस्तावित होगी, वहाँ निबन्धक सोसाइटी अथवा किसी उत्तमां अथवा वैसी सोसाटी की दशा में जिसके विषय में परिसमापन का आदेश पारित हो चुका हो, परिसमापक आवेदन पर, लेनदार अथवा लेनदारों के वर्ग की यथास्थिति, बैठक वैसी रति से बुलाकर संक्षिप्ततः संचालन का सकेगा जो नियमों द्वारा विहित होगी ।

(2) यदि मूल्य में तीन—चौथाई का प्रतिनिधित्व करनेवाले अधिसंरक्षक लेनदार अथवा लेनदारों के वर्ग स्वा अथवा परोक्षी के द्वारा बैठक में उपस्थित होकर किसी सुलह या व्यवस्था के लिए सम्मत हों तो वह सुलह सो व्यवस्था निबन्धक के आदेश से मंजूर हो जाने पर यथास्थिति सारे उत्तमणों अथवा उत्तमर्णों के वर्ग पर तथ सं सोसाइटी पर भी अथवा वैसी सोसाइटी की दशा में जिसके विषय में समापनादेश पारित हो चुका हो, परिसमाफ पर तथा उन सारे व्यक्तियों पर जिन्हें धारा 44 की उपधारा (3) की कंडिका (ग) के अधीन कार्य करते हैं। परिसमापक ने सोसाइटी की आस्तियों में अंशदान करने की अपेक्षा की हो, आबद्धकर होगी।

(3) यदि किसी समय निबन्धक का ऐसा समाधान हो कि निबन्धित सोसाइटी और उसके लेनदारों अथव उनके किसी वर्ग के मध्य किसी सुलह अथवा व्यवसाय में, जो बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनिय 1942 (विहार अधिनियम 7, सन् 1942) की आरम्भ तिथि को प्रवृत्त विधि के अनुसार अन्तिम हो चुकी थी अथवा जिसे इस धारा की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार ने तिथि के बाद मंजूर कर लिया था, सोसाइटी अभय उसके लेनदार अथवा लेनदारों के कथित वर्ग के हितार्थ नवीन सुलह या व्यवस्था करके पुनरीक्षित अथव प्रतिस्थापित करना अत्यावश्यक है तो वह स्वेच्छा से अथवा सोसाइटी अथवा किसी लेनदारों के आवेदन ए यथास्थिति लेनदार अथवा लेनदारों के वर्ग की वैसी रीति से बैठक बुलाकर संचालित करने का आदेश दे सकेगा नियमों के अनुसार विहित होगी, और यदि मूल्यानुसार तीन—चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिसंख्यक लेनदार अथवा लेनदारों का वर्ग यथास्थिति स्वयं अथवा परोक्षी के द्वारा बैठक में उपस्थित होकर पूर्ववर्त्ती सुलह व्यवस्था में पुनरीक्षण अथवा किसी नवीन सुलह अथवा व्यवस्था के लिए सहमत होवें तो निबंधक वैसी पुनरीक्षित सुलह अथवा व्यवस्था अथवा वैसी नई सुलह अथवा व्यवस्था की मंजूरी दे सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन मंजूरी कोई भी पुनरीक्षित सुलह अथवा व्यवस्था अथवा नवीन सुलह बा व्यवस्था उस समान रीति से तथा उन समान शतों के अध्यधीन नई सुलह या व्यवस्था के द्वारा पुनरीक्षित अथवा प्रतिस्थापित की जा सकेगी जिस रीति से तथा जिन शर्तों के अध्यधीन कोई सुलह या व्यवस्था नई सुलह अश्वा व्यवस्था के द्वारा उपधारा (3) के अधीन पुनरीक्षित अथवा प्रतिस्थापित की जा सकती है।

(5) उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन निबन्धक द्वारा स्वीकृत कोई भी पुनरीक्षित सुलह या आबद्धकर होगी ।

(6) उपधारा (2) के अधीन सुलह या व्यवस्था अथवा उपधारा (3) या उपचारा (4) के अधीन पुनरीक्षित अन्य आधार पर गुण–दोष के कारण अपास्त, संशोधित, पुनरीक्षित अथवा निरस्त घोषित नहीं की जा सकेंगी और न उसे चुनौती दी जा सकेगी।

(7) उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति लेनदार अथवा लेनदारों के वर्ग की बैठक बलाने के लिये निबन्धक का आदेश तथा उपधारा (2) के अधीन सुलह अथवा व्यवस्था अथवा उपधारा (3) निबंधक का आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे । अथवा उपधारा (4) के अधीन पुनरीक्षित सुलह अथवा व्यवस्था नई सुलह या व्यवस्था को मंजूर करते हुए निबंधक का आदेष शासकीय राजपत्र में प्रकाषित किये जायेंगे।

टिप्पणी

इस अधिनियम के अनुसार की गई सुलहनामा और निजि एकरारनामा में अन्तर है। सहयोग समिति के विरुद्ध लेनदार द्वारा लाया गया वाद के दौरान सुलह की योजना रहती है जिसे निबन्धक का अनुमोदन प्राप्त होता है।

स्पष्ट बहुमत द्वारा स्वीकृत सुलहनामा निबन्धक की स्वीकृति के पश्चात् सभी लेनदारों के लिए आबद्धकर होगी ।,

25. पंजीकृत सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन— जब तक कोई संशोधन इस अधिनियम के अधीन निबन्धित न हो जाए तबतक निबंधित सोसाइटी की उपविधियों में कोई भी संशोधन विधिमान्य नहीं होगी।

1 ख(2) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाय कि उपविधि का संशोधन इस अधिनियम अथवा नियमावली के प्रतिकूल नहीं हैं तो वह संशोधन हेतु प्रस्ताव के उपस्थापन की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर संशोधन को रजिस्ट्रीकृत करेगा ।,

(3) जब निबन्धक किसी निवन्धित सोसाइटी की उपविधियों के संशोधन को निबंधित करेगा तो वह सोसाइटी को अपने द्वारा प्रमाणित उस संशोधन की प्रति निर्गत करेगा जो इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि संशोधन सम्यक् रूप से निबन्धित हो चुका है।

2 (4) यदि उपधारा (2) में अधिकथित शर्तें पूरी नहीं की गयी हों तो रजिस्ट्रार प्रस्ताव उपस्थापन की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर अस्वीकृति आदेश के साथ–साथ उसके कारणों को निबन्धित डाक द्वारा भेजेगा ।

(5) नब्बे दिनों के भीतर अस्वीकृति आदेश नहीं भेजने की दशा में संशोधन रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा। ऐसे मामलों में अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से निबन्धन प्रमाण–पत्र निर्गत करना रजिस्ट्रार के लिए अनिवार्य होगा जो निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि संशोधन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है।

(6) उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा अस्वीकृति आदेश प्राप्त होने अथवा उपधारा (5) के अधीन संशोधन से सम्बन्धित निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं प्राप्त होने पर, यदि ऐसा आदेश अथवा निश्चयात्मक साक्ष्य की अप्राप्ति ऐसे रजिस्ट्रार से संबन्धित हो जिसमें सहकारी समिति के रजिस्ट्रार की शक्ति प्रत्यायोजित हो तो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास अपील हो सकेगी और यदि ऐसा आदेश सहकारी समिति के रजिस्ट्रार का हो तो राज्य सरकार के पास अपील हो सकेगी :

परन्तु ऐसी अपील आदेश–प्राप्तिध्साक्ष्य अप्राप्ति के दो महीने के भीतर दायर की जायेगी।,

1. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित।

26. **पंजीकत सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन निदेशित करने की रजिस्टार की शक्ति–** (1) यदि निबन्धक को ऐसा प्रतीत हो कि पंजीकृत सोसाइटी उपविधियों में संशोधन उसके हित में आव निबन्धित डाक से लिखित आदेश जारी करके उस आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सोसाइटी से एसपी अथवा समीचीन है तो सोसाइटी के सम्बद्धक सोसाइटी/संघ की राय लेने के बाद, वह उस सोसाइटी को निबंधित डाक से लिखित आदेश जारी करके उस आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सोसाइटी से ऐसे संशोधन की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) यदि कोई सोसाइटी विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा संशोधन करने में विफल हो जाए तो निबन् सोसाइटी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ऐसे संशोधन को निबंधित करके उस संशोधन की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि सोसाइटी को निबन्धित डाक से भेज सकेगा जो इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा संशोधन सम्यकरूपेण निबंधित हो गया है एवं वह संशोधन उस सोसाइटी के सदस्यों के लिए आबद्धकर होगा। संशोधन सम्यक्रूपेण निबंधित हो गया है एवं वह संशोधन उस सासाइटी के सदस्यों के लिए आबद्धकर होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश के जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर उस आक के विरुद्ध राज्य सरकार के पास अपील होगी। अपील पर राज्य सरकार के आदेश तथा उस अपील के परिणाम के अध्यधीन निबन्धक का आदेश अन्तिम होगा ।

टिप्पणी

[सहयोग समिति की आम सभा ही केवल निर्वाचन और अपनी उपविधियों में संशोधन करने के विषय निबंधक के निदेश को नहीं मानने के लिए सक्षम है। विजय कुमार मिश्र बनाम बिहार सरकार, 198 पी०एल० जे०आर० 846 : 1989 बी०एल०जे०आर० 636: 1989 (1) बी०एल०जे०आर० 420।]

30 में सदस्य किसी डि 1909) प्राप्त ि(

अध्याय 4

पंजीकृत सोसाइटी के सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व

2[''27. सदस्य का अधिकार– (1) सहकारी समिति का कोई भी सदस्य नियमों या समिति के उपविधि में विहित सदस्यता विषयक अदायगी कर देने के बाद समिति के सदस्य के अधिकारों का प्रयो कर सकेंगे,

परन्तु इस अधिनियम के किसी प्रावधान में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी सहकारी समिति का सदस्य, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा उपविधियों द्वारा विहित यथास्थिति, समिति के प्रबंधन में सहभागिता और न्यूनत्तम अपेक्षित सेवाएँ प्राप्त करने हेतु बुलाई गई बैठकों में यथोपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही समिति के बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग का सकता है।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति, प्रत्येक सदस्य की पहुँच की व्यवस्था, ऐसे सदस्यों अपने कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गये सहकारी समिति की बही, सूचना और लेखा तक, करेगी ।

(3) सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को सहकारी समिति में संधारित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसार से संबंधित नियमित संव्यवहारों के लेखाओं के संबंध में सभी जानकारीध्कागजात प्राप्त करने का अधिकार होगा। सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारीध्प्रबंधक सभी वांछित जानकारीध्कागजातों तक सदस्यों को पहुँच सुनिश्चित करेगा।

(4) सहकारी समिति के सदस्यों को इस अधिनियम, किसी प्रावधान के अधीन बनायी गयी नियमावली तथ उपविधियों के अनुसार सहकारी शिक्षा तथा सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।''

28. सदस्य का मत–3 ख(1) इस धारा की उप–धारा (2) एवं धारा 14 की उप–धारा (4) के अध्यधीन पंजीकृत सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सदस्य के रूप में पंजीकृत सोसाइटी के कार्य–कलापों में एक ही मत देर का अधिकार होगा, परन्तु बराबर मत प्राप्त होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।।

(2) किसी पंजीकृत सोसाइटी को, जो किसी दूसरी पंजीकृत सोसाइटी का सदस्य हो, उतने मत होंगे जितन उस अन्य सोसाइटी की उपविधियों में विहित होंगे एवं वह ऐसी उप–विधियों के अनुसार मताधिकार के प्रयोग करने के लिए, वैसे मतों की संख्या से अनधिक संख्या में सदस्यों को नियुक्त कर सकेगी, परन्तु कोई भी सदस्य, जो किस नियम के अधीन वैसी नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा, नियुक्त नहीं किया जायगा ।

1. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2. बिहार अधिनियम सं० 6, 2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. बिहार अधिनियम 10,2002 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) उपधारा (2) में उपबन्धित रीति को छोड़कर, निबन्धक को सामान्य अथवा विशेष स्वीकृति के बिना किसी सोसाइटी अथवा सोसाइटियों के वर्ग के लिए परोक्षी द्वारा मतदान अभिस्वीकृत नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

[मताधिकार प्राप्त सदस्य को सभा की नोटिस नहीं देने से वहां सभा गलत होगी खासकर जब उसमें सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो। गजानन नारायण पाटिल बनाम दत्तात्रेय विमन पाटिल, ए०आई०आर० 1990 एस०सी० 1023 (1990)) 3 एस०सी०सी० 634 (1990) आई० जे०टी० 5171]

29. सदस्य की धृति पर प्रतिबंध– राज्य सरकार अथवा अन्य पंजीकृत सोसाइटी को छोड़कर किसी भी पंजीकृत सोसाइटी के सदस्य को पंजीकृत सोसाइटी की पूँजी में कुल पूँजी का पंचमांश अथवा नियम के अधीन विहित वैसा न्यूनतम अनुपात से अनाधिक हित अथवा दावा नहीं होगा ।

30. शेयर अथवा हित जप्त नहीं होगा– धारा 22 के प्रावधानों के अध्यधीन पंजीकृत सोसाइटी की पूँजी में सदस्य का शेयर अथवा हित या अंशदान उस सदस्य द्वारा उपगत किसी ऋण अथवा दायित्व संबंधी न्यायालय की किसी डिक्री में जप्त या विक्रय नहीं किया जा सकेगा, न तो प्रेसिडेन्सी नगर शोधाक्षम्य अधिनियम, 1909 (3 सन् 1909) के अधीन शासकीय समनुदेशिती और न प्रान्तीय शोधाक्षम्य अधिनियम, 1920 (5 सन 1920) के अधीन प्राप्त (रिसीवर) वैसा शेयर, हित अथवा अंशदान का हकदार होगा अथवा दावा कर सकेगा।

31. शेयर अथवा हित के अन्तरण पर रोक (1) निबन्धित सोसाइटी की पूँजी में किसी सदस्य का

शेयर अथवा हित का अन्तरण या प्रभारण अधिकतम धृति के उन शत्तों के अध्यधीन होगा जो इस अधिनियम अथवा नियमावली में विहित किये जायेंगे ।

(2) असीमित दायित्व की पंजीकृत सोसाइटी की दशा में, सदस्य तबतक सोसाइटी की पूँजी अथवा सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग में अपने शेयर या हित का अन्तरण नहीं करेगा जबतक –

(क) वह वैसा शेयर अथवा हित कम–से–कम एक वर्ष तक नहीं धारित कर चुका हो, एवं

(ख) अन्तरण अथवा प्रभारण सोसाइटी को, अथवा सोसाइटी के सदस्य को, अथवा उस व्यक्ति को, जिसके सदस्यतार्थ आवेदन सोसाइटी ने स्वीकृत किया हो, नहीं किया जाए।

टिप्पणी

[सहयोग समिति के प्रति दायित्व पूरे संयुक्त परिवार का होता है। ए०आई०आर० 1953 उड़ीसा 300 ।,

32. भूतपूर्व सदस्य का तथा मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व – भूतपर्वं सदस्य अथवा मृत सदस्य की सम्पदा से पंजीकृत सोसाइटी के बाकी ऋण जो उसकी सदस्यता त्यागने अथवा मृत्यु की तिथि पर यथास्थिति, विद्यमान थे, का दायित्व वैसी तिथि से दो वर्षों की अवधि तक जारी रहेगा ।

टिप्पणी

[''पंजीकृत सहयोग समिति के कर्ज'' से अभिप्रेत हैं समिति को संदेय कर्ज। सदस्य की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष तक ही समिति को संदेय कर्ज का दायित्व रहेगा। चन्दर सिंह बनाम कमलपुर को–ऑपरेटिव सोसाइटी, आई०एल०आर० 24 पटना 681 225 आई०सी० 120–12–बी०आर० 553 1]

अध्याय–4 क

सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा तथा वार्षिक विवरणी

1[32क. वार्षिक आम सभा (1) प्रत्येक सहकारी समिति का बोर्ड, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, छह माह के भीतर वार्षिक आम सभा बुलायेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर, निम्नलिखित सूचीबद्ध विषयों में से सभी अथवा किसी पर चर्चा करेगी :–

(क) निबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गयी वार्षिक लेखा विवरणी पर विचारणय

(ख) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पर विचारणय

(ग) सांविधिक अंकेक्षकों एवं आन्तरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं हटाया जानाय

1. बिहार अधिनियम सं० 6, 2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा अन्तःस्थापित ।

(घ) अंकेक्षण के रिपोर्ट और निबन्धक को दाखिल की जाने वाली अंकेक्षत लेखा विवरणी विचारणः

(ङ) अंकेक्षणधविशेष अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन का विचारणय

(च) जाँच प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर की गई कार्रवाई पर विचारणय

(छ) शुद्ध अधिशेष का निपटानय

(ज) संबालन घाटा, यदि कोई हो, का पुनर्विलोकनय

(झ) दीर्घकालीन भावी योजना और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदनय

(ञ) बार्षिक बजट का अनुमोदनय

(ट) विनिर्दिष्ट आरक्षित एवं अन्य निधियों का सृजनय

(ठ) आरक्षित एवं अन्य निधियों की वास्तविक उपयोगिता का पुनर्विलोकनय

(ड) अन्य सहकारी समितियों में सहकारी समिति की सदस्यता पर प्रतिवेदनय

(ढ) जिस व्यक्ति की सदस्यता के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो अथवा जिसकी सदस्यत बोर्ड द्वारा समाप्त कर दी गई हो, व्यक्ति की अपीलय,

(ण) किसी निदेशक, अंकेक्षक या आन्तरिक अंकेक्षण को उस हैसियत से उसके कर्त्तव्य अथव संबंधित बैठकों में उसकी उपस्थिति के संबंध में भुगतेय पारिश्रमिक,

(त) संघध्परिसंघ में सहकारी समिति की सदस्यता,

(थ) अन्य संगठनों के साथ सहयोग,

(द) उपविधियों का संशोधन,

(घ) निदेशकों एवं पदधारियों के लिए आचार संहिता बनाना,

(न) सदस्यों के नामांकन एवं सदस्यता समाप्ति पर टिप्पणी,

(प) सहकारी समिति का विघटन,

(फ) ऐसे अन्य कृत्य, जो उपविधियाँ में विनिर्दिष्ट हों।

(2) उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए प्रावधानों के अनुसार सहकारी समिति के वार्षिक आम सभा, उपविधियों के अनुसार अधिसूचित समय, तिथि तथा स्थान पर होगी और यदि गणपूरि (कोरम) उपस्थित हो तो सहकारी समिति के अध्यक्ष सभा का सभापतित्व करेंगे,

परन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित कोई व्यक्ति सभा का सभापतित्व करेंगे,

परन्तु और कि ऐसी किसी समिति की दशा में जहाँ इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रबंध समिी अधिक्रमित हो गयी हो, वहाँ प्रशासक आम सभा का सभापतित्व करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में, उन द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति सभा का सभापति होगा ।

(3) सभा का सभापतित्व करने वाला व्यक्ति सभा की कार्यवाही का संचालन उस रीति से करेगा वे कारबार के तीव्रता तथा संतोषजनक निपटारे के लिए हो और सभा में आदेश के सभी बिन्दुओं पर निर्णय लेगा।

(4) आम सभा की सूचना निर्गत होने की तिथि को समिति की कुल सदस्य संख्या जो होगी उसका पंचमांश आम सभा की गणपूर्ति (कोरम) होगी।

(5) यदि आम सभा के लिए निर्धारित समय से एक घंटा के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो तो सभऐसी तिथि के लिए स्थगित कर दी जायेगी जो सात दिनों से पूर्व और इक्कीस दिनों के बाद न हो।

(6) स्थगित आम सभा के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी ।

(7) आम सभा में सभी प्रश्नों पर निर्णय बहुमत से किया जायेगा और मतों की समता की स्थिति है. सभा के सभापति निर्णायक मत देंगे।

(8) परोक्षी मत स्वीकृत नहीं किया जायेगा, किन्तु किसी विशिष्ट निबंधित सहकारी समिति अथवा किसे विशिष्ट निबंधित सहकारी समिति के वर्ग के मामले में, निबन्धक ऐसा करने की अनुमति दे सकेंगे।

(9) आम सभा में हाथ उठाकर मतदान किया जायेगा और केवल आपवादिक मामले में, यदि निबन्धक स्वप्रेरणा से अथवा संबंधित समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर इस प्रकार का निदेश दे तो, मतपत्र द्वारा मतदान अपनाया जा सकेगा ।

(10) आम सभा की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस प्रयोजनार्थ रखी गई एक बही में अभिलिखित किया जायेगा और सभा का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्यवृत हस्ताक्षरित किया जायगा ।

(11) किसी आम सभा में अपनायी गई प्रक्रिया संबंधी सभी मामलों में अपील निबन्धक के समक्ष संस्थित होगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

'ख32ख. वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाना प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर निबन्धक के समक्ष वार्षिक विवरणी दाखिल करेगी जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल रहेंगे :–

(क) कार्यकलापों का वार्षिक रिपोर्ट,

(ख) लेखाओं का अंकेक्षित विवरण,

(ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिशेष के निपटारे की योजना,

(घ) सहकारी समिति की उपविधियों में किये गये संशोधनों की सूची, यदि कोई हो,

(ङ) सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख तथा निर्वाचन का संचालन, यदि देय हो, से संबंधित घोषणा,

(च) कोई अन्य जानकारी, जो निबन्धक द्वारा अधिसूचित अधिनियम के किसी प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक, हो ।''

अध्याय 5
अंकेक्षण एवं निरीक्षण

2[''33. अंकेक्षण (1) सहकारी समिति अपनी लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार, इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षण द्वारा कराएगी। ऐसा अंकेक्षक चार्टड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत या तो चार्टड एकाउन्टेन्ट होगा या निबन्धक के कार्यालय का अंकेक्षक होगा।

(2) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक (गणित के साथ) अथवा वाणिज्य स्नातक होगी। ऐसे अंकेक्षकों अथवा चार्टड एकाउन्टेन्ट फर्म से अंकेक्षण का कम से कम तीन वर्ष के अनुभव की अपेक्षा की जायेगी। ऐसे अंकेक्षक अथवा चार्टड एकाउन्टेन्ड फर्म ही सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु पात्र होंगे।

(3) प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त, उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट अंकेक्षक अथवा चार्टड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा किया जायेगा ।

(4) प्रत्येक सहकारी समिति की लेखाओं का अंकेक्षण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिस वित्तीय वर्ष से ऐसा लेखा संबंधित हो।

(5) शीर्ष सहकारी समिति, अपनी लेखा–विवरणी के अंकेक्षण के उपरान्त, अंकेक्षक का प्रतिवेदन, सामान्य निकाय के अनुमोदनोपरान्त, तीस दिनों के भीतर निबन्धक को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, विधान मण्डल के पटल पर इस प्रयोजनार्थ अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार रखा जायेगा ।

(6) सहकारी समिति की लेखाओं पर प्रतिवेदन के अतिरिक्त अंकेक्षक का प्रतिवेदन में बोर्ड की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों द्वारा सहकारी समिति को मंजूर किए गए ऋण एवं अग्रिम या सहकारी समिति के साथ किए गए कारबार, बोर्ड की बैठकों पर हुये व्यय, निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक, निदेशकों को प्रतिपूर्ति किए गए व्यय, सदस्य, स्टाफ, निदेशक तथा अन्य की शिक्षा और प्रशिक्षण पर हुये व्यय भी अन्तर्विष्ट होंगे।

1. बिहार अधिनियम सं० 6, 2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2. बिहार अधिनियम सं० 6,2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(7) यह सुनिश्चित करना बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस दिन वार्षिक वित्तीय विवरणी को तैयार की आय और अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत कर दी जाय।

(8) अंधक के पारिश्रमिक सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियत किया जायेयाप परन्तु यदि अंकेक्षण, निबन्धक के कार्यालय के अंकेक्षक द्वारा किया जाता है तो निबन्धक अंकेक्षण फोस का भुगतान सहकारी समिति करेगी।

(9) सामान्य निकाय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी अंकेक्षण को पद से हटा सकेगा।

(10) किसी सहकारी समिति के अंकेक्षक की माँग पर सहकारी समिति के वर्तमान यापूर्व बोर्ड के सदस्य, सदस्य या कर्मचारी निम्नलिखित को उपलब्ध करायेंगे :–

(क) ऐसी जानकारी और ऐसा स्पष्टीकरण जिसे आवश्यक समझा जाय, तथा

(ख) सहकारी समिति के प्रत्येक ऐसे अभिलेखों दस्तावेजों बहियों लेखाओं और भाउचरीको अंकेक्षक की राय में जाँच करने और प्रतिवेदित करने में उसे समर्थ करने हेतु आवश्यक हो।

(11) जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में अस हो वा नियत तारीख से नब्बे दिनों के भीतर निबन्धक, सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण कारायेंगे।

(12) ऐसे अंकेक्षण संचालन करने का खर्च सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।''

टिप्पणी

[अधिनियम के अधीन बनी नियमावली के अनुसार ही पंजीकृत समिति का औडिट होगा। युगल क्रिया सिंह बनाम रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसाइटी, बिहार, 1960 बी०एल० जे०आर० 49।

यदि बैंक निदेशक मंडल द्वारा पूर्णतः निजी तौर पर प्रबंधित और नियंत्रित हो, स्थिति भिन्न हो सकेंगी समिति अवक्रमित हो गई हो और निबंधक द्वारा विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई हो तो सहकारी बैंक उसके कर्मचारियों का विवाद में रीट याचिका की अधिकारिता नहीं हो सकती है। एस० इतरत हुसैन बना निबंधक सहकारी समितियाँ, 2001 (2) पी०एल० जे०आर० 253 ।

बिस्कोमान की विद्यमान वस्तुस्थिति शोचनीय। बिस्कोमान के भवन में आवासित किरायेदार, अधिकर निगमित निकायों या सरकारी विभाग निःशुल्क आवास का उपयोग कर रहे हैं और बिस्कोमान को नुकसान पहुंच रहे हैं। बिस्कोमान एक निगमित निकाय, बढ़े दायित्वों तले चल रहा है। यह निगमित निकाय तदर्थवाद की स्कि में है जिसका लेखा अनंकेक्षित है, प्रबन्धन अवक्रमित है और छोटे पदाधिकारी तदर्थ प्रशासक बना दिये गये हैं बिस्कोमान अनेक मुकदमों का सामना कर रहा है। प्रशासक को निदेश दिया जाता है कि वह महालेखाका बिहार या अधिकार प्राप्त लेखाकार से लेखा को अंकेक्षित कराकर आस्तियों और दायित्वों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। प्रशासक, बिस्कोमान बनाम रामाधार शर्मा, 2002 (3) पी०एल० जे०आर० 46।,

ख ''33.क. विशेष अंकेक्षण (1) राज्य सरकार या अन्य सहकारी समिति या अन्य वाह्य व्यकि

या संस्था से निधियों का संव्यवहार करने वाली किसी सहकारी समिति का विशेष अंकेक्षण, ऋणदाताओं के अनुरोध पर या निबन्धक द्वारा स्वप्रेरणा से ऐसे लिखित विनिर्दिष्ट आदेशधनिदेश से आरंभ किये गए विशो अंकेक्षण के अधीन रहते हुए, होगा ।

(2) उप–धारा (1) के अधीन विशेष अंकेक्षण निबंधक के नियंत्रणाधीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारीध्वरीय स्तर के अंकेक्षण पदाधिकारी या ऐसे पदाधिकारियों की किसी कमिटी द्वारा किया जायेगा ।

(3) जहाँ विशेष अंकेक्षण में गम्भीर कुप्रबन्धन का पता चले, वहाँ ऐसे विशेष अंकेक्षण का खर्च सहकारी समिति से या कुप्रवन्धन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूल किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक विशेष अंकेक्षण आदेश निर्गमन की तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर पूरा किया जायस और निबंधक को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) ऐसे विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित का विवरण अन्तर्विष्ट होगा :–

(क) प्रत्येक भुगतान, जो अंकेक्षक को अधिनियम, अथवा अधिनियम के अधीन बनी नियमावली अथवा सहकारी समिति के उपविधियों के प्रतिकूल प्रतीत हो,

1. बिहार अधिनियम सं० 6,2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा अन्तःस्थापित

(ख) किसी घाटे बर्बादी अथवा हानि की, जो किसी व्यक्ति को गंभीर उपेक्षा अथवा कदाचार के कारण हुई हो, की राशिः

(ग) प्राप्त कोई रकम, जो लेखा–जोखा में लानी चाहिये थी किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा लेखा में नहीं लाई गई हो, एवं

(घ) कोई आस्तियों अथवा धन, जिससे कोई व्यक्ति सहकारी समिति के संगठन अथवा प्रबंधन के साथ संबंधित हो अथवा सहकारी समिति का कोई भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्य समिति की किसी संपत्ति का दुर्विनियोग किया हो अथवा कपटपूर्वक रख लिया हो।

(6) विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, निबंधक उसकी प्रतियों निम्नलिखित को प्रेषित कर देगा–

(क) आवेदक ऋणदाता,

(ख) सम्बन्धित सहकारी समिति, और

(ग) जहाँ धारा 40 के अधीन आवश्यक हो, अधिभार की कार्यवाही दाखिल करने हेतु अधिकृत अंकेक्षण पदाधिकारी।

[33.ख. लेखाओं तथा अभिलेखों का संधारण (1) प्रत्येक सहकारी समिति अपने निबंधित कार्यालय में निम्नलिखित लेखाओं और अभिलेखों को रखेगीः–

(क) समय–समय पर किए गए संशोधन सहित इस अधिनियम की एक प्रति,

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक,

(ग) निबंधन प्रमाण–पत्र तथा निबंधित उपविधियों की एक प्रति और संशोधन की तारीख के साथ समय–समय पर निबंधित संशोधनों की एक प्रति,

(घ) ऐसे संघध्परिसंघ की, जिसका वह सदस्य हो, तथा अपने प्रत्येक सदस्य सहकारी समिति के लिए अधिप्रमाणित उपविधियों की एक–एक प्रतिय

(ङ) सहकारी समिति द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशि की लेखा तथा उनका प्रयोजन,

(च) सहकारी समिति द्वारा सामानों की सभी खरीद–बिक्री का लेखा,

(छ) सहकारी समिति की आस्तियों तथा दायित्वों का लेखा,

(ज) कुल सदस्यता तथा विभिन्न सेवाओं का सदस्यवार उपयोग प्रदर्शित करने वाली पंजी,

(झ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर अद्यतन की गई चालू वित्तीय वर्ष के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों की सूची,

(ज) बोर्ड नीतियों की प्रतियाँ,

(ट) वार्षिक रिपोर्ट, अंकेक्षण प्रतिवेदन, विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन, जाँच प्रतिवेदन और उनका अनुपालनय

(ठ) अन्य विधियों तथा विनियमों की प्रतियाँ, जिनके अध्यधीन सहकारी समिति हो,

(ड) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो सहकारी समिति की क्रियाओं से सुसंगत हो,

परन्तु जहाँ सहकारी समिति का शाखा कार्यालय हो, वहाँ शाखा–कार्यालयों संबंधी लेखा एवं अभिलेख, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पचीस दिनों के भीतर किसी अवधि के लिए निबंधित कार्यालय में उपलब्ध रहेगाय

(ढ) नावार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक तथा निबंधक द्वारा समय–समय पर, निर्गत परिपत्रोंध्प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित सभी अन्य दस्तावेज, पंजी तथा परिपत्र आदि ।

(2) समर्थकारी अभिलेखों तथा भाउचरों सहित, प्रत्येक सहकारी समिति की लेखा पुस्तकें ऐसी अवधि के लिए जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यधीन, उपविधियों में उपबंधित की गयी हो।

1. बिहार अधिनियम सं० 6,2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा अन्तःस्थापित।

टिप्पणी

[अधिनियम के अधीन बनी नियमावली के अनुसार ही पंजीकृत समिति का औडिट होगा। युगल किशोर सिंह बनाम रजिस्ट्रार, को–ऑपरेटिव सोसाइटी, बिहार, 1960 बी०एल० जे०आर० 49।

यदि बैंक निदेशक मंडल द्वारा पूर्णतः निजी तौर पर प्रबंधित और नियंत्रित हो, स्थिति भिन्न हो सकेगी यदि समिति अवक्रमित हो गई हो और निबंधक द्वारा विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई हो तो सहकारी बैंक एवं उसके कर्मचारियों का विवाद में रीट याचिका की अधिकारिता नहीं हो सकती है। एस० इतरत हुसैन बनाम निबंधक सहकारी समितियाँ, 2001 (2) पी०एल० जे०आर० 253।

बिस्कोमान की विद्यमान वस्तुस्थिति शोचनीय। बिस्कोमान के भवन में आवासित किरायेदार, अधिकतर निगमित निकायों या सरकारी विभाग निःशुल्क आवास का उपयोग कर रहे हैं और बिस्कोमान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बिस्कोमान एक निगमित निकाय, बढ़े दायित्वों तले चल रहा है। यह निगमित निकाय तदर्थवाद की स्थिति में है जिसका लेखा अनंकेक्षित है, प्रबन्धन अवक्रमित है और छोटे पदाधिकारी तदर्थ प्रशासक बना दिये गये हैं। बिस्कोमान अनेक मुकदमों का सामना कर रहा है। प्रशासक को निदेश दिया जाता है कि वह महालेखाकार, बिहार या अधिकार प्राप्त लेखाकार से लेखा को अंकेक्षित कराकर आस्तियों और दायित्वों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। प्रशासक, बिस्कोमान बनाम रामाधार शर्मा, 2002 (3) पी०एल० जे०आर० 46।,

34. निबन्धक द्वारा निरीक्षण–समय–समय पर निबंधक स्वयं अथवा अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश से एतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निबंधित सोसाइटी का निरीक्षण कर सकेगा।

35. निबन्धक द्वारा जाँच– स्वेच्छा से तथा समाहर्ता के अनुरोध पर अथवा प्रबन्ध समिति के अधिसंख्यक अथवा सदस्यों की एक तिहाई से अन्यून के आवेदन पर किसी पंजीकृत सोसाइटी की संरचना, कामकाज एवं वित्तीय स्थिति के बारे में निबन्धक जाँच कर सकेगा अथवा अपने लिखित आदेश से एतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जाँच करने को निर्देशित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निबंधक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति–

(क) सोसाइटी के किसी अधिकारी से सोसाइटी के मुख्यालय के स्थान पर वैसे समय में वैसी बातों पर विचारार्थ सामान्य बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह निदेश करेगा, एवं

(ख) यदि सोसाइटी का अधिकारी वैसी बैठक बुलाने से इन्कार करे अथवा चूक जाए अथवा यदि वैसी संयोजित बैठक में कोरम न हो तो सोसाइटी की सामान्य बैठक बुलाने के लिए सूचना की अवधि को विहित करनेवाली किसी नियम अथवा उपविधि के होते हुए भी सदस्यों को स्वयं सूचना देकर वैसी बैठक उस रीति से बुला सकेगा जो वह उचित समझेगा। उपधारा (1) के अधीन निबन्धक अथवा उसका प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संयोजित उस बैंक को सोसाइटी की उपविधियों के अधीन संयोजित सामान्य बैठक की सभी शक्तियाँ होंगी ।

(3) जब इस धारा के अधीन जाँच होगी तो निबन्धक उस सोसाइटी को, वित्तदायी बैंक को, यदि हो, जिससे सोसाइटी सम्बद्ध होगी तथा उन व्यक्तियों को अथवा प्राधिकार को, यदि हो जिसके अनुरोध पर जाँच की जाए जाँच के परिणामों को संसूचित कर देगा।

टिप्पणी

[जाँच प्रतिवेदन को संसूचित करना जरूरी होता है। रामाशंकर प्रसाद सिंह बनाम राज्य, ए०आई०आर० 1973 पटना 269।,

36. निबन्धक द्वारा पंजियों का निरीक्षण (1) पंजीकृत सोसाइटी के उत्तमर्ण के आवेदन पर निबन्धक स्वयं अथवा लिखित आदेश से एतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को निदेश देकर सोसाइटी की पंजियों का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन तबतक कोई निरीक्षण नहीं होगा अथवा निरीक्षणार्थ निदेश नहीं दिया जायगा जबतक आवेदक–

(क) निबन्धक को संतुष्ट न कर दे कि ऋण की राशि बाकी है और उसने संदाय की माँग की है और समुचित समय के भीतर उसे संदत्त नहीं किया गया है, एवं

(ख) प्रस्ताविक निरीक्षण पर व्यय के लिए प्रतिभूति के रूप में उतनी राशि निबन्धक के पास जमा न करे निबंधक जितनी अध्यापेक्षा करे।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण के पश्चात निबन्धक सोसाइटी के लेनदार को तथा उस किसी वित्तदायी बैंक को, जिससे सोसाइटी को संबन्धन प्राप्त है, उस निरीक्षण का परिणाम संसूचित कर देगा।

37. वित्तदाता बैंक द्वारा बहियों का निरीक्षण–वित्तदाता बैंक किसी पंजीकृत सोसाइटी की, जो उससे संबद्ध प्राप्त है, बहियों का निरीक्षण करवा सकेगा तथा उस सोसाइटी को अपेक्षित जानकारी, विवरण एवं विवरणियाँ देने का निदेश दे सकेगा।

(2) सामान्य अथवा विशेष आदेश से निबन्धक द्वारा अनुमोदित वित्तपोषक बैंक का कोई अधिकारी अथवा उसका वेतनभोगी कर्मचारी वर्ग का कोई सदस्य उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण कर सकेगा।

(3) वित्तपोषक बैंक उस निरीक्षण का परिणाम निबन्धक को तथा संबन्धित सोसाइटी को संसूचित कर देगा।

38. लेख्यों को माँगाने तथा सम्मन जारी करने की शक्ति–धारा 33 के अधीन सोसाइटी की लेखा का औडिट अथवा धारा 34, 35, 36 अथवा 37 के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच करने के लिए–

(क) निबन्धक अथवा किसी प्राधिकृत व्यक्ति को हर समुचित समय पर सोसाइटी की अथवा उसकी अभिरक्षा में रहनेवाली बहियों, लेखा, लेख्यों, प्रतिभूतियों, नकद या अन्य सम्पत्तियों तक निर्वाध पहुँच रहेगी एवं वह उन बहियों, लेखाओं, लेख्यों, प्रतिभूतियों, नकद या अन्य सम्पत्तियों को अधिकार में रखनेवाला अथवा उसके लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति को उन्हें सोसाइटी के कार्यालय में अथवा उसके किसी शाखा में अथवा वित्तदायी बैंक की स्थिति को छोड़कर, उसके मुख्यालय के किसी स्थान पर, प्रस्तुत करने के लिए सम्मन कर सकेगा,

(ख) निबन्धक अथवा कोई प्राधिकृत व्यक्ति किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि उसे सोसाइटी की बातों की जानकारी है, सोसाइटी के कार्यालय में अथवा उसकी किसी शाखा अथवा, वित्तपोषक बैंक की स्थिति को छोड़कर, मुख्यालय के किसी स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन कर सकेगा एवं उस व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा तथा

(ग) यदि निबन्धक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी आशंका हो कि सोसाइटी की अथवा उसकी अभिरक्षा में रहनेवाली बहियों, लेखाओं, लेख्यों, प्रतिभूतियों, नकद तथा अन्य सम्पत्तियों में से किसी के संबंध में धोखाधड़ी, नुकसान या विकृति की जा सकती है तो वह दो व्यक्तियों की उपस्थिति में उपर्युक्त सामग्रियों को जप्त कर सकेगा और जप्त करनेवाला अधिकारी उसके लिए समुचित रसीद देगा और यदि वह अधिकारी निबन्धक के अलावा कोई अन्य होगा तो वह तुरन्त उस जप्ती का प्रतिवेदन अपने व्यवहित वरीय अधिकारी तथा निबन्धक के पास भेजेगा :

परन्तु इस कोंडका के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल नियमावली द्वारा इसके लिए प्राधिकृत व्यक्ति होंगे ।

39. जाँच तथा निरीक्षण का व्यय– जब धारा 35 के अधीन जाँच की जाए अथवा धारा 36 के अधीन

निरीक्षण किया जाय तो निबन्धक, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद तथा कारणों को अभिलिखित करने के बाद, ऐसी जाँच अथवा निरीक्षण का व्यय अथवा व्यय का वह अंश, जो वह उचित समझे जाँच अथवा निरीक्षण की माँग करनेवाले लेनदार अथवा सोसाइटी एवं सदस्यगण और सोसाइटी के अधिकारियों अथवा पूर्ववर्ती अधिकारियों के बीच विभक्त कर देगा।

टिप्पणी

खनिबन्धक, उप–निबन्धक अथवा सहायक निबन्धक के अनुरोध पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जायगी।,

40. अधिशुल्क (1) अतः धारा 33 के अधीन अंकेक्षण ख्तथा धारा 33क. के अधीन विशेष अंकेक्षण, अथवा धारा 35 के अधीन जाँच, अथवा धारा 34, धारा 36 अथवा धारा 37 के अधीन निरीक्षण के परिणामस्वरूप निबन्धक को ऐसा प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने, जिसने सोसाइटी के संगठन अथवा प्रबन्ध में भाग लिया है, अथवा सोसाइटी के किसी भूतपूर्व अथवा वर्त्तमान अधिकारी ने–

1. बिहार अधिनियम सं० 6, 2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा अन्तःस्थापित ।

(क) कोई ऐसी अदायगी की है जो सोसाइटी की विधि, नियमावली अथवा उपविधियों के प्रतिकूल है अथवा जो उस वित्तपोषक बैंक के निदेशों अथवा अनुदेशों के विरुद्ध है जिसके लिए सोसाइटी धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, अथवा

(ख) अपने आपराधिक अपेक्षा अधवा कदाचार के कारण सोसाइटी के अथवा उस वित्तप्रेषक बैंक को जिसके लिए वह धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, किसी क्षति अथवा ऊणता में अर्न्तग्रस्त कर दिया है, अथवा

(ग) किसी ऐसी राशि को लेखा में लाने की चूक की है जिसे लेखा में लाना चाहिए या, अथवा

(घ) सोसाइटी की अथवा उस वित्तपोषक बैंक की जिसके लिए यह धारा 16 की उपचारा (3) के अधीन अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है अथवा उसे छलपूर्वक अपने पास रख लिया है, निबन्धक वैसे व्यक्ति अथवा अधिकारी के आचरण की जाँच कर सकेगा और वैसे व्यक्ति अथवा अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, वैसी अदायगी अथवा क्षति अथवा राशि के संबंध में क्षतिपूर्ति के रूप में यथास्थिति सोसाइटी अथवा वित्तपोषक बैंक की आस्तियों में ऐसी राशि का अंशदान करने अथवा ऐसी सम्पत्ति का प्रत्यावर्त्तन करने की अपेक्षा करते हुए आदेश दे सकेगा जैसा निबन्धक इस धारा के अधीन कार्यवाही के व्यय पूरा करने के लिए ऐसी राशि देने का आदेश दे सकेगा जैसा वह निर्धारित करेगाः

परन्तु, किसी व्यक्ति अथवा अधिकारी को कोंडका (क) में निदेशित अदायगी के संबंध में अंशदान करने की अपेक्षा करते हुए किसी आदेश पारित करने के पहले उस व्यक्ति अथवा अधिकारी को प्रापक से वैसी अदायगी की राशि वसूलने के लिए तथा यथास्थिति सोसाइटी अथवा वित्तपोषक बैंक की निधियों में जमा करने के लिए युक्तियुक्त समय दिया जायगा :

' ख्परन्तु कि जिस तिथि को ऐसा काम हुआ अथवा चूक हुई उस तिथि से छह वर्षों के भीतर या प्रस्ताव दाखिल करने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, कण्डिका (क), (ख), (ग) अथवा (घ) में उल्लिखित किसी काम या चूक के सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित किया जायेगा ।,

(2) ऐसे व्यक्ति अथवा अधिकारी पर इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी अन्य विधि के अधीन उपगत आपराधिक दायित्व होते हुए भी यह धारा लागू होगा ।

(3) निबन्धक के आदेश की संसूचना की तिथि से तीन मास के भीतर उस व्यक्ति अथवा अधिकारी के आवेदन पर, जिसके विरुद्ध वह आदेश पारित हुआ हो, राज्य सरकार के पास उस आदेश के विरुद्ध अपील होगी। अपील पर राज्य सरकार का आदेश, तथा उस अपील के परिणाम के अध्यधीन निबन्धक का आदेश अन्तिम होंगे ।

अध्याय 6

प्रबन्ध समिति का विघटन

[1][41. **प्रबंध समिति का विघटन**–[2]["(1) यदि निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति का बोर्ड, जिसमें राज्य सरकार ने हिस्सा पूँजी का अंशदान किया हो अथवा राज्य सरकार द्वारा ऋण अथवा वित्तीय सहायता

दी गई हो अथवा सहकारी गारंटी पर ऋण दिया गया हो।

(i) लगातार ऋण अदायगी में चूक की हो, अथवा

(ii) इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों द्वारा उसपर अधिरोपित कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की हो, या

(iii) सहकारी समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के विरूद्ध कार्य किया हो, या

(iv) बोर्ड के गठन अथवा कार्यकलाप में गतिरोध हो, तो वह समिति के बोर्ड को अपनी आपत्ति अधिकथित करने का, यदि कोई हो, अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों सहित लिखित आदेश द्वारा सहकारी समिति के बोर्ड को अधिकतम छह माह के लिए अधिक्रमित कर सकेंगे और आदेश दे सकेंगे कि उसके सभी अथवा कोई सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट होने वाली पाँच वर्ष से अनधिक कालावधि तक के लिए सहकारी समिति के बोर्ड में निर्वाचन के लिए निरर्हित होंगे। निबन्धक इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश को लिखित रूप में अभिलिखित करेंगे और निबंधित डाक से संबंधित सहकारी समिति को सूचित कर देंगे। तब बोर्ड कार्य करना रोक देगा,

1. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. बिहार अधिनियम, सं० 6, 2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु ऐसी सहकारी समिति के मामलेमें जो बैंकिंग का कारोबार कर रही हों, बैंकिंग रेगूलेशन ऐक्ट, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे,

परन्तु और कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली ऐसी सहकारी समिति के मामले में, बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि अधिकतम एक वर्ष की होगी:

परन्तु और भी कि बैंकिंग प्रचालन वाली सहकारी समिति के बोर्ड का अधिक्रमण भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन कार्यवाही करते समय निबन्धक की राय में निबंधित समिति के हित में बोर्ड का निलंबन आवश्यक हो, तो वे बोर्ड को निलम्बित कर सकेंगे, जो उसके बाद कार्य नहीं करेगा और उप–धारा (1) की कार्यवाही की समाप्ति तक निबंधित समिति के कार्यकलाप के प्रबंधन के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे, जो वे उचित समझें:

परन्तु यदि इस प्रकार निलम्बित बोर्ड अधिक्रमित नहीं होता है, तो छह माह के उपरान्त कार्य करने लगेगा और निलंबन में रहने की अवधि की गणना उसकी अवधि में की जायेगी।

(3) जब कोई सहकारी समिति उप–धारा (1) के अधीन निलंबन के अधीन हो तो निवन्धक सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करेंगे। नियुक्त प्रशासक उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सहकारी समिति के बोर्ड के नव निर्वाचन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा नव निर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन का कार्यभार सौंप देंगे:–

परन्तु निबंधक को अधिक्रमण की अवधि के दौरान प्रशासक को बदलने की शक्ति होगी।

(4) उप–धारा (3) के अधीन नियुक्त प्रशासक सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो निबंधक द्वारा यथोचित नियत किया जाय। इस प्रकार नियत पारिश्रमिक सहकारी समिति के खाते से भुगतेय होगा:

परन्तु उप–धारा (3) के अधीन नियुक्त प्रशासक, निबन्धक द्वारा निर्मित सेवा शर्त्तों के अधीन कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम, नियमावली एवं समिति की उपविधियों में बोर्ड को प्रदत्त सभी कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करेंगे।''

(5) रजिस्ट्रार किसी निबंधित सोसाइटी की प्रबंध समिति को विघटित कर देगा यदि–

(क) निबंधित सोसाइटी के बहुसंख्यक सदस्य और प्रबन्ध समिति के निर्वाचित पदधारी अपनी सदस्यता या पद से त्याग कर देय या

(ख) किसी निबन्धित सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के स्थानों की कुल संख्या का आधा किसी कारणवश रिक्त हो जाय :

और निबन्धित सोसाइटी के बेहतर प्रबन्धन के लिए प्रशासक नियुक्त करेगा,

परन्तु यह कि यदि प्रवन्ध समिति के विघटन की अवधि के दौरान रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि निर्बोधत सोसाइटी के कार्यकलाप में पर्याप्त सुधार हो गया है और किसी नवगठित प्रबन्ध समिति को प्रबन्ध समिति को प्रबन्धन प्रत्यावर्तित करना वांछनीय है तो वह आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि प्रशासक नई

प्रबन्ध समिति के गठन की आवश्यक कार्रवाई करे और ऐसी समिति का गठन हो जाने पर प्रशासक ऐसे नवगठित प्रबन्ध समिति को तुरन्त प्रबन्ध सौंप देगा ।

(6) उप–धारा (1)[1] [एवं [उप–धारा (2) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये आदेश सम्बन्धित निबन्धित सोसाइटी को संसूचना के' ख्एक महीने, के भीतर प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के आवेदन पर राज्य सरकार के यहाँ अपील होगी, अपील पर राज्य सरकार का आदेश और ऐसी अपील के प्रतिफल के अध्यधीन यदि कोई हो, रजिस्ट्रार के आदेश अन्तिम होगा।

(7) रजिस्ट्रार, प्रशासक कां उसकी शक्तियों और कृत्यों तथा निबंधित सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह वांछनीय समझे और प्रशासक रजिस्ट्रार के पास किसी समय अनुदेश हेतु अनुरोध करेगा कि प्रशासक किस रीति से निर्बाधत सोसाइटी के प्रबन्ध का संचालन करे।

(8) धारा 42 के अन्तर्गत समिति के परिसमापन अथवा धारा 44 की उपधारा (8) के अन्तर्गत समिति के निबन्धन को रद्द करने सम्बन्धी रजिस्ट्रार की शक्तियाँ इस धारा से प्रभावित नहीं हुई समझी जायगी ।]

1. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा अन्तः स्थापित ।
2. प्रतिस्थापित तत्रैव ।

टिप्पणी

[समिति के प्रबन्ध को निर्धारित अवधि के लिए वापस लेने का कदापि अर्थ नहीं कि उसके संरचना में कोर परिवर्तन हो सके। कामता पाठक बनाम निबन्धक, को–आपरेटिव सोसाइटी लि०, 1971 बी०आर०एल०० (रेभन्यु) 117।

पूर्व सूचना दिए प्रबन्ध समिति को भंग कर देने का अधिकार राज्य सरकार को उस विशेष परिस्थिति में उपलब्ध है जहाँ सूचना देने से वह प्रयोजन हो विफल हो जायगा जिस प्रयोजन के लिए समिति को भंग करना, अपेक्षित हो। नई समिति के गठन संबंधी सरकारी अधिसूचना होने पर पुरानी समिति के सदस्यों को सुनवाई गर अवसर देना आवश्यक नहीं है।

सदस्यों के तीन वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात् और धारा 14(9) की दृष्टि से 9 माह की विस्तारित अवधि के भीतर किसी कारण से निर्वाचन नहीं है तो इस अधिनियम की इस धारा के अधीन उस सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति उक्त तिथि के प्रभाव से अधिक्रांत समझी जायेगी। नवल किशोर बनाम बिहार राज्य, 1991 (1) पी०एल० जे०आर० 572।

धारा 4 के अधीन आरंभ की गई कार्यवाही में निबन्धक इस धारा के अधीन कार्रवाई अग्रसर करते हुए निलम्बन का अंतरिम आदेश कर सकता है। अन्तरिम निलम्बन का आदेश समकालीन होने पर भी पृथक और स्वतंत्र आदेश समझा जायेगा और उसे सामासिक आदेश नहीं कहा जायेगा। साठी जोयान्ट फार्मिंग को–ऑपरेटिव सोसाइटी बनाम निबन्धक, 1991 (1) पी०एल० जे०आर० 625 1991 (1) बी०एल०आर० 265 1

बिस्कोमान की विद्यमान वस्तुस्थिति शोचनीय। बिस्कोमान के भवन में आवासित किरायेदार, अधिकतर निगमित निकायों या सरकारी विभाग निःशुल्क आवास का उपयोग कर रहे हैं और बिस्कोमान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। विस्कोमान एक निगमित निकाय, बढ़े दायित्वों तले चल रहा है। यह निगमित निकाय तदर्शवाद की स्थिति में है जिसका लेखा अनंकेक्षित है, प्रबन्धन अवक्रमित है और छोटे पदाधिकारी तदर्थ प्रशासक बना दिये गये हैं। बिस्कोमान अनेक मुकदमों का सामना कर रहा है। प्रशासक को निदेश दिया जाता है कि वह महालेखाकार, बिहार या अधिकार प्राप्त लेखाकार से लेखा को अंकेक्षित कराकर आस्तियों और दायित्वों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। प्रशासक, बिस्कोमान बनाम रामाधार शर्मा, 2002 (3) पी०एल० जे०आर० 46।

किसी समिति का विघटन धारा 41 के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है और समिति के विघटन के बाद निवन्धक द्वारा धारा 41 की उपधारा (1) या (5) के तहत् प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। बीरेन्द्र कुमार राय बनाम बिहार सरकार, 2005 (1) पी०एल० जे०आर० 423 ।

जिस क्षण समिति अपना अस्तित्व खो देती है, प्रबन्ध समिति का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्योंकि इसका अस्तित्व समिति के अस्तित्व या वैधानिक अवधि तक सहयोजित (ब्व–जमतउपदने) होता है। दो समितियों के विलयन के पश्चात् एक नयी समिति अस्तित्व में आती है तथा इसके निबन्धन के पश्चात् नयी समिति को अपनी प्रबन्ध समिति का चुनाव करना होगा। बीरेन्द्र प्रसाद राय बनाम बिहार सरकार, 2005 (1) पो०एल० जे०आर० 423।

निबन्धित समिति की असम्बद्धता एवं निदेशक पर्षद् के निलम्बन हेतु प्रथमतः एवं अनिवार्यतः कारण पृच्छा निर्गत करना सन्तुष्टि मात्र है जिसे निबन्धक द्वारा अभिलिखित किया जाना है एवं तद्नुसार विचार किया जाना है। अनुशंसाएँ जो विवादित थीं के आधार पर कारण पृच्छा सूचना मूलतः बिल्कुल अविधिक है। राजकिशोर प्रसाद बनाम बिहार सरकार, 2005 (3) बी०बी०सी० जे० (ट) 22।

सहयोग समिति का निलम्बन तथ्यों की अधिकम्य को सूचना निर्गत करते समय उपेक्षा नहीं की जा सकती है। विहार राज्य सहकारिता बैंक बनाम बिहार सरकार, 2005 (3) बी०वी०सी० जे० (ट) 107ः 2005 (2) पी०एल० जे०आर० 6851

आपत्ति दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत करने के पहले निबन्धक को यह अवधारित करना है कि इसके आधार क्या हैं। ऐसी अवधारण तथ्यों पर आधारित तथा तथ्यपरक (Subjective) होनी चाहिए। अगर प्राधिकारी के समक्ष अवधारण हेतु कुछ तथ्य हो तो इसकी अधिकारिता सूचना निर्गत करने के प्रारम्भिक प्रक्रम पर नकारा नहीं जा सकता है। बिहार राज्य सहकारी बैंक बनाम राज्य सरकार, 2005 (2) पी०एल० जे०आर० 6651]

[1]["42. **समापनादेश.**– निबन्धक अधिसूचना द्वारा किसी निर्वाधत सहकारी समिति का परिसमापन आदेश दे सकेंगे, यदि–

(क) कोई समिति के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा समिति के परिसमापन हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ हो,

(ख) धारा–35 के अधीन जाँच अथवा धारा–34, धारा–36 अथवा धारा–37 के अधीन निरीक्षण के बाद यदि निबन्धक की राय हो कि सदस्यों के हित में उस सहकारी समिति का परिसमापन आवश्यक हो,

(ग) निबंधन के उपरांत सहकारी समिति द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया है अथवा कार्य करना बन्द कर दिया गया हो,

(घ) निबंधन की शर्तों के प्रतिकूल सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या कम होकर दस से कम हो गई हो,

परन्तु ऐसा आदेश, सहकारी समिति के हिस्साधारक सदस्यों तथा हितबद्ध व्यक्तियोंध्संस्थाओं को कम से कम एक माह का नोटिस देकर उन्हें सुनने के पश्चात् ही पारित किया जायेगा।''

टिप्पणी

[समिति के विरुद्ध अतिक्रमण का आदेश पूर्व सूचना कारण बताने हेतु देने के पश्चात् ही पारित किया जा सकता है। यदि निबन्धक धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करते हैं तो समिति के कार्य व्यवस्था का प्रबन्ध भी करना होगा क्योंकि निबन्धक का ऐसा आदेश मात्र अन्तरिम होता है। साठी जोयान्ट फार्मिंग को–ऑपरेटिव सोसाइटी बनाम निबन्धक, 1991 (1) पी०एल० जे०आर० 625 (1991) 1 बी०एल० जे० आर० 6251]

43. **परिसमापनादेश के विरूद्ध अपील**– [1]["(1) उस सहकारी समिति का कोई सदस्य अथवा हितबद्ध व्यक्तिध्संस्था, राजपत्र में धारा 42 के अधीन पारित आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से दो माह के भीतर, उस आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा।''

(2) धारा 2 के अधीन आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से दो माह व्यतीत हो जाने तक प्रभावी नहीं होगा अथवा यदि अपील की गई हो तो तबतक प्रभावी नहीं होगा जबतक अपील के बाद अधिसूचना से उसे संपुष्ट न कर दिया जाए।

(3) अपील पर राज्य सरकार का आदेश और उस अपील के परिणाम यदि कुछ निकले, के अध्यधीन रजिस्ट्रार आदेश अन्तिम होंगे।

44. **परिसमापक एवं विघटन**–(1) जहाँ निबन्धक किसी पंजीकृत सोसाइटी के परिसमापन के लिए आदेश पारित करेगा वहाँ वह एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उस सोसाइटी का परिसमापक नियुक्त करेगा ।

(2) धारा 43 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति के पश्चात परिसमापक को सोसाइटी की सभी आस्तियों तथा उसके संव्यवहार से सम्बन्धित एवं सांसाइटी के संव्यवहार को चलाने के लिए अपेक्षित सभी वहियों, अभिलेखों तथा अन्य लेख्यों को अपने कब्जा में अविलम्ब लेने की शक्ति होगी, एवं इस तरह से सोसाइटी के सारे अधिकार, कर्त्तव्य, आस्तियाँ एवं दायित्व परिसमापक में निहित और उस पर न्यायगत हो जाएँगे ।

(3) निबन्धक के नियन्त्रण तथा पुनरीक्षण की शक्ति के अध्यधीन वैसे परिसमापक को यह शक्ति भी होगी कि वह–

(क) सोसाइटी की ओर से अपने पदनाम पर वाद तथा अन्य कानूनी कार्यवाहियों को संस्थित तथा प्रतिरक्षित करे,

(ख) किसी व्यक्ति से सोसाइटी की बाकी सारी राशियाँ अवधारित तथा वसूल करे,

(ग) समय–समय पर, धारा 32 के प्रावधानों के अध्यधीन सोसाइटी की आस्तियों में सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं, अथवा मनोनीत व्यक्तियों, उत्तराधिकारियों अथवा विधिसम्मत प्रतिनिधियों के द्वारा अथवा किसी अधिकारी अथवा पूर्ववर्ती अधिकारी के द्वारा किया जानेवाला अंशदान को अवधारित करें तथा समापन के पूर्ण होने तक अंशदान के किसी आदेश को पुनरीक्षित करे एवं वैसे अंशदानों को वसूल करे,

1. बिहार अधिनियम सं० 6, 2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) सोसाइटी के प्रति सारे दावों की छानबीन करे तथा इसअधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन सभी लेनदारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद दावाकर्त्ताओं में उत्पन्न प्राथमिकता के प्रश्नों का निबटारा करें।

(ङ) सोसाइटी के परिसमापन सम्बन्धी आदेश देनेवाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक सूद सहित सोसाइटी के प्रति दावों को प्राथमिकता के क्रमानुसार, यदि हों पूर्णतः या अनुपाततः सोसाइटी की आस्तियों की दृष्टि से, जैसा उचित हो, संदाय करें, एवं दावों की पूरी अदायगी के बाद शेष रहे आधिक्य को अपने द्वारा निश्चित दर, किन्तु हर हालत में सोसाइटी द्वास निर्धारित देय दर से अनधिक, पर उक्त तिथि से ब्याज की अदायगी में प्रयोग करें,

(च) जिन व्यक्तियों और सोसाइटी के बीच कोई विवाद हो उन व्यक्तियों से सुलह की व्यवस्था को अथवा ऐसा किसी विवाद को मध्यस्थता में निर्देशित करे,

(छ) अवधारित करे कि परिसमापन के व्यय को किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में वहन किया जायगा, एवं

(ज) सोसाइटी की आस्तियों के समाहरण और वितरण के सम्बन्ध में वैसा निदेश दे जो सोसाइटी के कामकाज के परिसमापन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना परिसमापक उससे वसूले जाने वाले अंशदान, ऋण या आस्तियों का अवधारण नहीं करेगा।

(4) यदि धारा 43 के अधीन परिसमापन के आदेश के विरुद्ध की गई अपील राज्य सरकार मंजूर कर लें तो परिसमापक सोसाइटी की आस्तियों, बहियों, अभिलेखों तथा अन्य लेख्यों पर से अपना कब्जा त्यागकर उन सब को प्रबन्ध समिति को सूपूर्द कर देगा तथा सोसाइटी के संव्यवहार को चलाना बन्द कर देगा, परन्तु परिसमापक की हैसियत से उसके द्वारा किये गये सारे कार्यों की वैधिक मान्यता बनी रहेगी मानो वे सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये हों।

(5) निबन्धक की विशेष स्वीकृति से, सम्बद्ध व्यक्ति उपधारा (3) की कंडिका (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) अथवा (छ) के अधीन परिसमापक के आदेश की निबन्धित डाक से संसूचना प्राप्त करने की तिथि से तीन माह के भीतर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील कर सकेगा।

(6) पुनरीक्षण के दौरान निबन्धक द्वारा दिया गया किसी आदेश अथवा अपील के दौरान जिला न्यायाधीश के द्वारा दिया गया किसी आदेश के अध्यधीन परिसमापक का आदेश, पुनरीक्षण में निबन्धक का आदेश तथा अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अन्तिम होंगे।

(7) जब सोसाइटी का कामकाज परिसमाप्त कर दिया जायगा तो परिसमापक सोसाइटी के अभिलेखों को उस स्थान पर जमा कर देगा जो स्थान निबन्धक निदेशित करेगा ।

(8) उपधारा (7) के अधीन सोसाइटी के अभिलेख्य जमा कर दिये जाने के वाद, निवन्धक सोसाइटी के निबन्धन को रद्द कर देगा और सोसाइटी का निगम निकाय का स्वरूप समाप्त हो जायगा।

[1][अध्याय 6–क

भूमि विकास बैंक

44–क. परिभाषाएँ– इस अध्याय में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'बोर्ड' से राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की प्रबन्धक समिति अभिप्रेत है,

(ख) 'भूमि विकास बैंक' के अन्तर्गत राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक भी है,

(ग) 'विहित' से इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(घ) 'प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक' से उस नाम की कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है,

(ङ) 'राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक' से धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उस रकम की कोई सोसाइटी अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत धारा ।। के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत बिहार राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड भी है और

(च) 'न्यासी' से धारा 44 के निर्दिष्ट न्यासी अभिप्रेत है।

1. बिहार अधिनियम 39, 1982 द्वारा अन्तः स्थापित ।

44–ख. इस अध्याय का उपबन्ध भूमि विकास बैंकों को लागू होगा– इस अध्याय का उपबन्ध इसमें यहाँ दिये गये सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उधार देनेवाले भूमि विकास बैंक को लागू होंगे, अर्थात् –

(1) भूमि की उन्नति और उत्पादनकारी प्रयोजन।

(ii) भूमि के बन्धकों का मोचन।

(ii) अन्य मूल्यवान स्थावर सम्पत्ति के बन्धकों का, ऐसी शर्त्तों के अध्यधीन जो विहित की जाए, मोचन ।

(iv) कृषकों के ऋणों का ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन जो विहित किये जाय समापन ।

(v) काश्तकारों द्वारा कृषि भूमि के हक का क्रय या अर्जन ।

(vi) कृषि–प्रयोजनों के लिए मकान उठाना, उन्हें फिर से बनाना या मरम्मत करना ।

स्पष्टीकरण' भूमि की उन्नति और उत्पादनकारी प्रयोजन' से कोई ऐसा संकर्म, निर्माण या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो भूमि की उत्पादन शक्ति को बढ़ाए और विशिष्टतः इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात् –

(क) कृषि प्रयोजन के लिए या खेती में लगे व्यक्तियों और मवेशियों के उपयोग के लिए जल के संचय, प्रदाय या वितरण के लिए कुंओं (जिसके अन्तर्गत नलकूप भी है), तालाबों या अन्य संकर्मो का संनिर्माण और उनकी मरम्मत ।

(ख) पूर्वगामी किसी भी संकर्म का नवीकरण का पुनर्निमाण ।

(ग) सिंचाई के लिए भूमि की तैयारी।

(घ) कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जानेवाली भूमि या कृषि योग्य बन्जर भूमि का जल निकास, नदी या अन्य जल प्रांगण से कर्षण का बाढ़ से अथवा जल से होने वाले कटाव या अन्य क्षति से बचाव ।

(ङ) बाँध निर्माण और इसी प्रकार की उन्नति ।

(च) कृषि के प्रयोजनार्थ–भूमि का कर्षण, उसकी सफाई और उन पर घेरा डालना या उसकी स्थायी उन्नति ।

(छ) बागवानी

(ज) इसमें उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए तेलचलित इंजनों, पम्पिंग सेटों और विद्युतचालित मोटरों का क्रय ।

(झ) ट्रैक्टरों या अन्य कृषि मशीनरी का क्रय ।

(ज) भूमि में विशेष किस्म की मिट्टी डालकर भूमि की उत्पादन शक्ति बढ़ाना ।

(ट) स्थायी खलिहान घर, मवेशी शेड और किसी भी प्रक्रम पर कृषि उपज को प्रसंस्कृत करने के लिए शेड बनानाय

(ठ) ऊख पेरने, गुड़ या खांडसारी चीनी या चीनी तैयार करने के लिए मशीनरी का क्रय ।

(ड) चकबन्दी के लिए भूमि का क्रय।

(ढ) नहरों की खुदाईय और

(ण) कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन, डेयरी, सूअरपालन, भेड़पालन आदि उद्योगों की स्थापनाय तथा

(त) अन्य प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार, समय–समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनार्थ भूमि–सुधार या उत्पादनकारी प्रयोजन घोषित करें।

44–ग. न्यासी की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य (1) निबन्धक या उस कक्षा में जब राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति को इस निमित्त नियुक्त करे तब वह व्यक्ति बोर्ड द्वारा जारी किये गये डिवेंचरों को धारण करनेवाले व्यक्तियों के प्रति राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ न्यासी होगा।

(2) न्यासी की शक्तियाँ और कृत्य इस अध्याय के उपबन्धों से, और राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक तथा न्यासी के बीच निष्पादित और बोर्ड तथा न्यासी की पारस्परिक सहमति से समय–समय पर उपान्तरित न्यास लिखत से, शासित होंगे ।

44–घ. न्यासी का एकमात्र निगम होना– न्यासी, डिबेंचरों के लिए न्यासी नाम का एकमात्र निगम होगा और ''स रूप में उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुहर होगी और वह अपने निगम नाम से वाद ला सकेगा और उसी नाम से उसपर वाद लाया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि वहव्यक्ति जिसको ऐसा ऋण देय हो, विवाद में विनिश्चय के लम्बित रहने तक इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह उस ऋण के मद्धे भूमि विकास बैंक द्वारा प्रख्यापित रकम का संदाय प्राप्त करे किन्न ऐसी प्राप्तियों से उस व्यक्ति के उस अधिकार पर, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा दावाकृत अतिशेष को वसूल करते का उसका है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) जहाँ किसी व्यक्ति पर उप–धारा (1) के अधीन कोई सूचना उसे देयों का संदाय प्राप्त करने के लिए तामील कर दी गई हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व देय ऋणों के लिए भोगवन्धक के रूप में धारित कोई सम्पत्ति ऐसे बन्धककर्ता को परिदत्त कर दे :

परन्तु वह किसी कृषि भूमि का कब्जा, खड़ी फसल यदि कोई हो, काटने के पश्चात् परिदत्त कर सकेगा और ऐसी दशा में उसे बन्धककर्ता को कब्जे के परिदान की तारीख को उसे देय रकम भूमि विकास बैंक से प्राप्त करने का हक होगा।

(4) जहाँ भोगबन्धक के रूप में किसी सम्पत्ति को धारण करनेवाला व्यक्ति उप–धारा (3) में उपदर्शित रीति से कब्जे का परिदान करने से इन्कार करे वहाँ कलक्टर, भूमि विकास बैंक द्वारा उसे इस निर्मित किये गये आवेदन पर, संक्षिप्त जाँच करने के पश्चात् बन्धकदार को बेदखल कर देगा और बन्धकित भूमि बन्धककत्तां को लौटा देगा और तदुपरि बन्धक पर्यवसित समझा जाएगा।

(5) इस धारा के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किन्हीं काश्तकारी विधियों के अध्यधीन होंगे।

44–ढ. उधार देने और भूमि को धारण करने की भूमि विकास बैंकों की शक्ति– इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए और तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार कोई भूमि विकास बैंक इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह धारा 44–ख में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उधार दे और उस भूमि को धारण करे जिसका कब्जा उसे अध्याय के उपबन्धों के अधीन अन्तरित किया गया हो।

44–णं. आक्षेपों को ग्रहण करने के लिए लोक–सूचना (1) जब धारा 44–ख में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए उधार के लिए कोई आवेदन किया जाय तब उस आवेदन की लोक सूचना जो हितबद्ध सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा करे कि वे उधार के बारे में अपने आक्षेप, यदि कोई हो, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व करें, ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जो विहित की जाएँ दी जायगी। वह व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसी लोक–सूचना दी जायगी और वह रीति जिसमें आक्षेप का निस्तारण उसके द्वारा किया जायगा ऐसी होगी जो विहित की जाए। ऐसी लोक–सूचना की प्रतियाँ पृथक–पृथक ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय, भेजी जाएँगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन सूचना देने के लिये सशक्त व्यक्ति उस धारा के अधीन किये गये हर आक्षेप पर विचार करेगा और या तो उसे पुष्ट करनेवाला या मंजूर करनेवाला आदेश लिखित रूप में पथरत करेगा। जब आक्षेप नामंजूर कर लिया जाता है तो वह भूमि विकास बैंक से सिफारिश करेगा कि आवेदन पर विचार करेः

परन्तु जब आक्षेप द्वारा उठाए गए प्रश्न का स्वरूप, ऐसे व्यक्ति की राय में ऐसा हो कि वह संतोषजनक रूप से सिविल न्यायालय द्वारा ही विनिश्चय किया जा सकता हो अन्यथा नहीं तब वह उस आवेदन पर विचार करना तबतक के लिए स्थगित कर देगा जबतक कि वह प्रश्न इस प्रकार विनिश्चित न हो जाय ।

(3) विहित रीति से प्रकाशित उप–धारा (1) के अधीन की अधिसूचना के बारे में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जायगा कि वह उन्नत की जानेवाले या उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित, भूमि या हित रखनेवाले या हित का दावा करनेवाले सभी व्यक्ति को उचित सूचना है।

(4) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन किसी आवेदन की सिफारिश की जाती है वहाँ भूमि विकास बैंक अपने द्वारा इस निमित बनाये गये नियमों के अनुसार, उधार देने के प्रयोजन के लिए, ऐसे आवेदन पर विचार करेगा।

(5) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन कोई आक्षेप न किया गया हो वहाँ विवाद प्रश्न आक्षेपों पर विचार करते के लिए सशक्त व्यक्तियों द्वारा ऐसी रीति से विनिश्चित किया जायगा जो वह ठीक समझे और किसी व्यक्ति की किसी भी दावे का, जिसके अन्तर्गत उद्‌गृहीता की उस सम्मत्ति के विरुद्ध जिसके लिए आवेदित उधार इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन मंजूर किया गया हो किसी भी प्रकार के बन्धक से उत्पन्न होनेवाला कोई दावा भी है। अधिकार उस समय तक नहीं होगा जबतक कि उधार उस पर व्यय सहित या उधार से उत्पन्न होने वाले कोई अन्य

रूप से संदत्त न कर दिये जाएँ।

44–त. संयुक्त हिन्दू कुटुम्बों अथवा अप्वयों या निःशक्त व्यक्तियों के नैसर्गिक वा विधिक संरक्षकों द्वारा निष्पादित बन्यक–(1) भूमि विकास बैंक द्वारा, चाहे बिहार सहकारी सोनाइटी (संशोधन) आअध्यादेश, 1975 के पूर्व या उसके पन्चत् दिये गये उसों की बावर बन्धक जो किसी हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के प्रवन्धक अथवा किसी अप्राप्तव्य या निःशक्त व्यक्ति के नेसनका विधिक संधक द्वारा घाग 44–ख में शिनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए किए गए हों, प्रतिकूल किसी विधि के होते हुए भी ऐसे संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के हर सदस्य एनआयएने प्राव्य या निःशक्त व्यक्ति पर वाध्य होंगे।

(2) उपधारा (1) उपबन्धों के अध्यन रहते हुए यह है कि वहाँ चाहे बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के पूर्व उसके पश्चात् भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक को इस आधार पर प्रसनगत किया जाय कि वह हिन्दू संयुक्त के अथवा अप्राप्तवय या निःशक्त व्यक्ति के नैसर्गिक या अधिक संरक्षक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया था जो ऐसे हिन्दू संयुक्त दुम्ब के सदस्यों अथवा अव्ययानिःशक्त व्यक्ति पर बाध्य नहीं हैं तो उसे सूचित करने का भार, तत्प्रतिकूल किसी विधि के होते मी उसे अधिक करनेवाले पक्षकार पर होना।

44–थ. उधार अनुदत्त करनेवाले आदेश का कतिपय विषयों के बारे में निश्चायक होना–भूमि विकास बैंक या आग 44–ख में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से सभी था किन्द्रों के लिए इस अध्याय द्वारा या बैंक की उपविधियों के आधीन प्राधिकृत व्यक्ति वा प्रबन्धक समितियों का ऐसा आदेश जिससे चाहें बिहार सहकारी सोसटी (पंचम सॉंगचन) अध्यादेश 1975 के पूर्व उसके पश्चात् मुनि के फायदे के लिए या उसमें विनिर्दिष्ट उत्पादनकारी प्रयोजनों के लिए उसमें वर्णित व्याक्ति की या उसकी सहमति से कोई उधार अनुदत्त किया जाय. निम्नलिखित विषयों के बारे में निश्चय होगा अर्थात्–

(क) अर्पित कर्म या उन्नति जिसके लिए उन किया गया है, घरा 44–ख के अर्थ में, यथास्थिति

(ख) उस व्यक्ति का आदेश कोको व्यान्यति ऐसी उन्नति करने का या ऐसे उत्पादनकारी

प्रयोजनके लिए व्ययरत करने का अधिकार था, और

(ग) उन्नति विनिर्दिष्ट भूमि को फायदा करनेवाली है और उत्पादनकानी प्रयोजन उस भूमि के जो प्रतिभूति की रूप में प्रतिस्थापित की गई हो या उसके भाग के जैसा भी सुस्त हों, सम्बन्ध में है।

44–द. भूमि विकास बैंक द्वारा उधारों की वसूली भूमि विकास बैंक द्वारा अनुदत्त कोई उधार जिसके अन्तर्गत उस पर प्रभार्य कोई व्याज तथा उस सम्बन्ध में उपगत ऐसा कोई खर्च यदि कोई हो, जो विहित किया जाय, भी देय होने पर सम्बद्ध बैंकद्वारा वसनीय होलाः

परन्तु ऐसा कोई उघार, व्याज या खर्च राज्य सरकारों मूनि विकास बैंक द्वारा भी वसूलनीय होगा चाहे वह उधार उससे सम्बद्ध किसी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ही अनुदत्त किया गया हो।

44–घ. कतिपय कालावधि के दौरान कलक्टर का वसूली करना – (1) ऐसी कालावधि के दौरान जो राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित करे कलक्टर के लिए यह सक्षम होगा कि वह उसे उस निमिन, भूमि विकास बैंक द्वारा किये गये आवेदन पर बैंक को देव सभी राशियाँ जिसके अन्तर्गत ऐसी वसूली का खर्च भी है, वसूल करें।

(2) कलक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से अधिकृत कोई व्यक्ति भूमि विकास बैंक को देय सभी राशियाँ निम्नलिखित क्रम और रीति से वसूली करेगा–

(क) उधार लेनेवाले से एस मानों वह उससे देय भू–राजस्व का बकाया हो।

(ख) उस भूमि से जिसके फायदे के लिए उधार अनुदत्त किया गया है ऐसे मानों वह उसे भूमि की बावत

(भू–राजस्व का बकाया हो। (ग) प्रतिमूति से, यदि कोई हो, ऐसे मानों वह उससे देय भू–राजस्व का बकाया हो।

(घ) समपारिंवक प्रतिभूति में समाविष्ट सम्पत्ति के विक्रय द्वारा भू–राजस्व की वसूली के लिए हो

(3) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी भी काश्तकारी विधि के अध्यधीन होगा।

44–**न. करस्थम और विक्रय**–(1) यदि भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी अन्य संदिय कोई किस्त या ऐसी किस्त का कोई भाग उस तारीख से जिसको वह देय हुआ एक मास ....

अंददत्त रह जाता है तो ऐसे बैंक को प्रबन्धक समिति या बोर्ड बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त बन्धकित भूमि के उत्पाद के जिसके अन्तर्गत उस पर खड़ी हुई फसल भी है और व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति फरस्थ या विक्रय द्वारा ऐसा किस्त या उसके किसी भाग को बसलो के लिए रजिस्टार से विहित रीति से आवेदन कर सकेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार पर सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (4,1882) में किसी बात के होते हुए भी बन्धकर्ता को रजिस्ट्रीकृत सूचना देने के पश्चात् ऐसे उत्पादन की और यदि आवश्यक होतो व्यक्तिक्रमों की ऐसे अन्य जंगम सम्पत्ति के करस्थम और विक्रय का निदेश दे सकेगाः

परन्तु भूमि विकास बैंक को बन्धीकृत उपकरणों से भिन्न खेती के ऐस उपकरण व्यक्तियों के ऐसे मवेशी जो रजिस्ट्रार की राय में, व्यतिक्रमी की काश्तकार के रूप में अपनी–अपनी जीविका को उपार्जन के लिए समय बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, ऐसे करस्थम और विक्रय के भागी न होंगे :

परन्तु यह और कि ऐसा कोर्ड करस्थम उस तारीख से जिसकी किस्त देय हई बारह माह को अवसान के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(2) करस्थम की गई सम्पत्ति का मुल्य यावतशक्त देय रकम की करस्थम व्यय और विक्रय के खर्च के बराबर होगा।

44– प. विक्रय की शक्ति का उपयोग कब किया जाए (1) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (4,

1882) में किसी बात के होते हुए भी यह है कि जहाँ बन्धक विलेख द्वारा भूमि विकास बैंक को यह शक्ति अभिव्यक्ति रूप से प्रदत्त की जाए कि यह न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय कर सकेगा. वहाँ ऐसे बैंक को प्रबन्धक समिति या बोर्ड या ऐसी प्रवन्धक समिति या बोर्ड द्वारा प्राधिकत किसी व्यक्ति को बन्धक धन या उसके किसी भाग के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में, बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त यह शक्ति होगों कि वह न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बंधीकृत सम्पत्ति का विक्रय करा लें।

(2) ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग तबतक नहीं किया जायगा जबतक कि–

(क) बोर्ड ने बन्धककर्त्ता के अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग पहले से ही प्राधिकृत न कर दिया हो।

(ख) ऐसे बन्धक धन या उसके किसी भाग के संदाय की अपेक्षा करने वाली रजिस्ट्रीकृत सूचना निम्नलिखित को न दी गई हो–

(1) बन्धककर्ता,

(ii) कोई व्यक्ति जिसकी बन्धकित सम्पत्ति अथवा उसे मोचित करने के अधिकार में कोई हित अथवा उसपर कोई प्रभार है,

(iii) बन्धक ऋण या उसके किसी भाग के संदाय के लिए कोई प्रतिभूतिय अथवा

(iv) वन्धककर्ता का कोई लेनदार जिसने उसकी सम्पत्ति के प्रशासन के लिए किसी–किसी बन्धकित सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त कर ली है, और

(x) ऐसे बन्धक धन या उसके भाग के संदाय में व्यतिक्रम, इस निमित दी गई सूचना के पश्चात् तीन माह तक न किया गया हो।

44—फ. जहाँ बन्यकित सम्पत्ति नष्ट हो जाए या प्रतिभूति अपर्याप्त हो वहाँ भूमि विकास बैंक की शक्तियाँ—जहाँ भूमि विकास बैंक को वन्धकित कोई सम्पत्ति पूर्णतः या अंशतः नष्ट हो जाए अथवा किसी अन्य कारण से, प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाए और बन्धककर्त्ता उतनी अतिरिक्त प्रतिभूति उपबन्ध करने के लिए जो पूर्ण प्रतिभूति को अपर्याप्त कहने के लिए अचेष्ट हो या ऋण के उतने भाग को पुनः संदाय करने के लिए जो उक्त बैंक को बन्धक समिति या बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, प्रबन्ध समिति या बोर्ड द्वारा युक्तिप्रद अवसर दिये जाने पर भी ऐसी प्रतिभूति का उपबन्ध या उधार के ऐसे भाग का पुनः संदाय न करे वहाँ पूर्ण उधार, उसके निबन्धन और शत्तों के होते हुए भी, तत्काल देय हुआ समझा जायगा और प्रबन्धक समिति या बोर्ड को उसकी वसूली के लिए बन्धककर्ता के विरुद्ध धारा 44—घ, धारा 44—न या धारा 44—प के अधीन कार्रवाई करते का हक होगा ।

स्पष्टीकरण—इस भाग के प्रयोजन के लिए, प्रतिभूत्ति तबतक अपर्याप्ती समझी जायगी जबतक कि बन्धकित सम्पत्ति का, जिसके अन्तर्गत उस पर की गई अभिवृद्धियाँ भी है, मूल्य बन्धक पर तत्समय देय रकम से उतने अनुपात में अधिक न हो जो नियमों या भूमि विकास बैंक की उप—विधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

44–ब. व्यतिक्रमी के विरुद्ध कार्रवाई करने की बोर्ड या न्यासी की शक्ति–(1) बोर्ड या न्यासी, किसी प्राथमिकी सहकारी भूमि विकास बैंक की प्रबन्धक समिति को किसी व्यतिक्रमी के विरुद्ध धारा 44–प. 44–न, 44–प या 44–फ के अधीन कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा और यदि प्रबन्धक, समिति ऐसा करने में उपेक्षा करे या असफल रहे तो, बोर्ड या न्यासी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा। न्यासी बोर्ड को निदेश दे सकेगा कि यह किसी व्यतिक्रमी के विरुद्ध वैसी ही कार्रवाई करे और बोर्ड के ऐसा करने में उपेक्षा करने पर या असफल रहने पर, स्वयं ऐसी कार्रवाई कर सकेगा।

(2) जहाँ बोर्ड द्वारा धारा (1) के उपबन्धों के अधीन कोई कार्रवाई की जाय वहाँ इस अध्याय या उसके अनुसरण में बनाए गए किन्हों नियमों के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानो उसमें प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक और उसकी प्रबन्धक समिति के प्रति सभी निर्देश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और बोर्ड के प्रति निदेश हो ।

(3) जहाँ न्यासी द्वारा उप–धारा (1) के उपबन्धों के अधीन कोई कार्रवाई की जाय वहाँ इस अध्याय या उसके अनुसरण में बताए गए नियमों के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानों उसें प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक और उसको प्रबन्धक समिति या राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक या बोर्ड के प्रत्ति सभी निर्देश न्यासी के प्रति निर्देश हों।

44–भ. विक्रय की पुष्टि–जहाँ कोई बन्धकित सम्पत्ति किसी प्राथमिकी भूमि विकास बैंक के द्वारा धारा 44–प के उपबन्धों के अधीन बेची जाती है वहाँ बैंक, विहित रूप से राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजेगा जिसमें वह रीति जिससे विक्रय किया गया है और विक्रय में परिणाम, उपवर्णित होंगे। जहाँ विक्रय राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक या न्यासी द्वारा किया जाए और न्यासी रजिस्ट्रार से भिन्न व्यक्ति हो, वहाँ वैसी ही रिपोर्ट यथास्थिति, बोर्ड या न्यासी द्वारा रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को उपर्युक्त रिपोर्ट के भेजे जाने के पश्चात् यथास्थिति, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की प्रबन्धक समिति या बोर्ड या न्यासी रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, विक्रय को, विक्रय की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर नष्ट या रद्द कर सकेगा।

(3) जहाँ रजिस्ट्रार न्यासी हो और उसने धारा 44–ब की उप–धारा (1) के अनुसरण में कोई कार्रवाई की हो, वहाँ वह स्वप्रेरणा से या भूमि विकास बैंक के आवेदन पर, बन्धकित सम्पत्ति के विक्रय को, विक्रय की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर नष्ट या रद्द कर सकेगा ।

(4) सम्बद्ध भूमि विकास बैंक के कार्यालय पर, पश्चात्वर्ती ब्याज और विक्रय की प्रक्रिया के दौरान उपगत खर्च, यदि कोई हो, और उसके द्वारा निक्षिप्त क्रय धन से पाँच प्रतिशत के बराबर क्रेता के संदाय के लिए कमीशन की राशि सहितय धन की उतनी राशियाँ जो धारा 44–प की उप–धारा (2) के खंड (ख) के अधीन तामील की गई सूचना में विनिर्दिष्ट हों, निक्षिप्त करने के पश्चात् बन्धककर्त्ता या बन्धकित सम्पत्ति में कोई अधिकार या हक या हित रखनेवाले किसी व्यक्ति के, विक्रय को अपास्त करने के लिए यथास्थिति भूमि विकास बैंक की प्रबन्धक समिति या बोर्ड या न्यासी या रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर, बन्धकित सम्पत्ति का विक्रय इस धारा की उप–धारा (2) या (3) के उपबन्धों के अधीन रद्द किया जायगा ।

(5) जहाँ इस धारा के उपबन्धों के अधीन विक्रय पुष्ट कर दिया जाए वहाँ वह आत्यकित हो जाएंगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5, 1908) के प्रयोजन के लिए आत्यंकित समझा जायगा ।

44–म. विक्रय आगम का व्यय– (1) इस अध्याय के अधीन किए गए विक्रय के आगम प्रथमतः विक्रय या क्रयातित विक्रय के सम्बन्ध में उपगत सभी खर्च, प्रभारों और व्ययों के संदाय के लिए, द्वितीयतः

उस बन्धक के कारण जिसके परिणामस्वरूप बन्धकित सम्पत्ति बेची गई थी, देय किसी या सभी ब्याज के संदाय के लिए, और तृतीयतः बन्धक के कारण देय मूल के जिसके अन्तर्गत वसूली से आनुषंगिक खर्च और प्रभार भी संदाय के लिए उपयोजित किए जायेंगे ।

(2) यदि उप–धारा (1) के अधीन निदिष्ट विक्रय के आगमों का कोई अवशिष्ट रह जाता है तो वह उस व्यक्ति को संदत्त किया जायगा जो सम्पत्ति में अपना हितवद्ध होना साबित कर दे और उस दशा में जब ऐसे व्यक्ति एक से अधिक हों तब उनकी संयुक्त प्राप्ति पर अथवा उसमें उनके हितों के अनुसार संदत्त किया जाएगा :

परन्तु इसके पूर्व कि ऐसे संदाय किए जाए वे प्रतिभूत राशियाँ जो भूमि विकास बैंक को बन्धककर्त्ता से बाकी हों, समायोजित की जाएगी।

44–य. क्रय का प्रमाण–पत्र सम्पत्ति का परिदान और क्रेता का हक– (1) जहाँ बन्थकित सम्पति का विक्रय आत्यकित हो गया हो, वहाँ बैंक, बेची गई सम्पत्ति, विक्रय आगम, उसके विक्रय की तारीख, उम्र व्यक्ति का नाम जिसे विक्रय के समय क्रेता घोषित किया जाए और वह तारीख जिसको विक्रय आत्यकित हुआ हो, विनिर्दिष्ट करनेवाली, विहित प्रारूप में प्रमाण–पत्र, क्रेता को अनुदत्त करेगा और ऐसे प्रमाण–पत्र के पेश किए जाने पर, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (16, 1908) के अधीन नियुक्त वह अवर–रजिस्ट्रार जिनकी अधिकारिता की परिसीमाओं के भीतर, प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो, ऐसे प्रमाण–पत्र की प्रति अपनी ऐसी सुसंगत पुस्तिका में प्रविष्ट करेगा जो इस प्रयोजन से रखी गई हो।

(2) जहाँ बन्धकित सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन बेची जाय और क्रेता को उप–धारा (1) के उपबन्धों के अधीन प्रमाण–पत्र अनुदत किया जाए वहाँ कलक्टर क्रेता उसके चारिस या हित में उत्तराधिकारी के आवेदन पर कब्जे का परिदान ऐसे व्यक्ति को किए जाने के लिये आदेश देगा और ऐसे व्यक्ति और उसके उप–निर्देशिती को कब्जा दिला देगा।

44–क–क. क्रेता के हक का अनियमितताओं के आधार पर प्रश्नगत न किया जाना–जहाँ कोई सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन विक्रय की शक्ति के प्रयोग में बेची जाय या क्रेता का हक इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायगा कि–

(क) विक्रय को प्राधिकृत करने के लिए अपेक्षित परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई थीं,

(ख) विक्रय की सम्यक् सूचना नहीं दी गई थी, और

(ग) विक्रय की शक्ति का प्रयोग अन्यथा अनुचित या नियमित रूप से किया गया थाय

किन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे ऐसी व्यक्ति के अप्राधिकृत, अनुचित या अनियमित प्रयोग से कोई नुकसान हुआ हो, भूमि विकास बैंक के विरुद्ध नुकसान के लिए उपचार का हक होगा।

44–क–ख. बन्धककर्ताओं के दिवालिएपन के आधार पर बन्धक को प्रश्नगत न किया जाना–दिवालिएपन से सम्बद्ध किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित कोई बन्धक इस आधार पर कि वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक निष्पादित नहीं किया गया था या इस आधार पर कि वह बन्धककर्ता के अन्य लेनदारों के ऊपर भूमि विकास बैंक को अधिमान देने की दृष्टि से निष्पादित किया गया था, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

44–क–ग. रिसीवर की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ–(1) बोर्ड, स्वप्रेरणा से या प्राथमिक भूमि विकास बैंक के आवेदन पर और उन परिस्थितियों में जिनमें धारा 44–प द्वारा प्रदत्त विक्रय की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, सम्बद्ध भूमि विकास बैंक की प्रबन्धक समिति के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति की लिखित रूप से बन्धकित सम्पत्ति या उसके किसी भाग की उपज या आय का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और ऐसा रिसीवर इस बात का हकदार होगा कि वह सम्पत्ति का कब्जा ले ले या, यथास्थिति, उसके उत्पाद या आय का या दोनों का संग्रहण करे, अपने द्वारा वसूल किए गए धन में से प्रबन्धक के सम्बन्ध में अपना व्यय जिनके अन्तर्गत उसका ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, भी है जो बोर्ड द्वारा नियत किया जाए, रख ले, और अतिशेष को सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (4,1882) की धारा 69–क की उप–धारा (8) के अनुसार उपयोजित करे ।

(2) बोर्ड, पर्याप्त हेतुक से, ऐसे रिसीवर को बन्धककर्त्ता द्वारा किए गए आवेदन पर हटा सकेगा और रिसीवर के पद की रिक्ति भर सकेगा।

(3) इस धारा की कोई बात बोर्ड को उस दशा में रिसीवर नियुक्त करने के लिए अशक्त नहीं करेगी जब वन्धकित सम्पत्ति सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर के अधिकार में पहले ही से हो।

44—क—घ. पट्टों पर निबन्धन—(1) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (4, 1882) की या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि विकास बैंक को बन्धक की गई सम्पत्ति का कोई बन्धककर्त्‌ता ऐसी किसी सम्पत्ति का पट्टा या उसके किन्हीं काश्तकारी के अधिकार या किसी अन्य अधिकार, हक या हित का सृजन, लिखित रूप में दल की पूर्व सहमति से ही और ऐसे निबन्धन और शत्रों के अध्यधीन हो जो बैंक अधिक घोषित करे, कर सकेगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु भूमि विकास बैंक के अधिकार, यथास्थिति, पट्टाधारी या काश्तकार या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे प्रवर्तनीय होंगे मानो वह स्वयं बन्धककर्त्ता हो ।

(2) जहाँ भूमि विकास बैंक को कब्जे सहित बन्धक की गई भूमि किसी काश्तकार के वास्तविक कब्जे में हों वहाँ बन्धककर्त्ता या भूमि विकास बैंक काश्तकार को इस बात की सूचना देगा कि वह पट्टा और बन्धक के चालू रहने के दौरान भूमि विकास बैंक की लगान संदत्त करे और ऐसी सूचना दिए जाने पर यह समझा जायगा कि काश्तकारी भूमि विकास बैंक का काश्तकार हो गया है।

44–क–ङ. भूमि विकास बैंक की ओर से निष्पादित दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण–(1) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (16, 1908) में किसी बात के होते हुए भी किसी भूमि विकास बैंक के किसी अधिकारी के लिए यह आवश्यक न होगी कि वह अपनी शासकीय हैसियत से अपने द्वारा निष्पादित किसी लिखित के रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय पर स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा उपसजात हो या उस अधिनियम की धारा 58 में यथा उपबन्धित से हस्ताक्षर करे।

(2) जहाँ कोई लिखित ऐसे निष्पादित की जाए वहाँ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिसे ऐसी लिखत रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की जाए यदि वह ठीक समझे, तो उसके सम्बन्ध में किसी जानकारी के लिए भूमि विकास बैंक के पूर्वोक्त अधिकारी को निदेश कर सकेगा और उसके निप्पादन के बारे में अपनी समाधान होने पर लिखत का रजिस्ट्रीकरण कर देगा।

44–क–च. वोर्ड द्वारा कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन–बोर्ड यदि यह ठीक समझे तो धारा 44–प, 44–व, 44–म, 44–क–ग के अधीन की अपनी शक्तियाँ या उनमें से कोई, अपने द्वारा गठित ऐसी कार्यपालिका समिति को प्रत्यायोजित कर सकेंगा जो उसके तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हो ।

44–क–छ. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के उपबन्धों का इस अध्याय के अधीन सूचनाओं का लागू होना–सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (4, 1882) की धारा 102 और 103 के और उक्त धाराओं के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए उस अधिनियम की धारा 104 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के उपवन्ध यथाशक्य इस अध्याय के अधीन तामील की गई सूचनाओं की बावत लागू होंगे।

44–क–ज. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के पर्यवेक्षण की बोर्ड की शक्ति–इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पर्यवेक्षण की ऐसी शक्तियाँ जिनके अन्तर्गत ऐसे बैंकों का लेखा–बहियों और कार्यवाहियों के निरीक्षण की शक्तियाँ भी हैं, होंगी जो नियमों द्वारा विहित जाए।

44–क–झ. नियम बनाने की शक्ति–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोग को प्रभावी करने के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी।

(2) ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् –

(क) इस अध्याय के अधीन करस्थम को प्रभावी करने की रीति, करस्थम की गई सम्पत्ति की अभिरक्षा, संरक्षण और विक्रय, विनश्वर वस्तुओं का उस दशा में तुरंत विक्रय जहाँ ऐसी वस्तुएँ करस्थम की गई हों,

(ख) भूमि विकास बैंक को बन्धकित सम्पत्ति के विक्रय का संचालन, विक्रय अधिकारियों की नियुक्ति, ऐसे विक्रय के व्ययों की वसूली, उनसे सम्बद्ध क्रय–धन, क्रय–निक्षेप और बन्धकित सम्पत्ति का उस दशा में पुनर्विक्रय जब विक्रय धन विक्रय की कार्यवाहियों में निक्षिप्त न किया जाए,

(ग) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा उनके संव्यवहारों की बावत राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की विवरणियाँ और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों और राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक के बीच लेखाओं का कालिक विवरण, उन रकमों का संदाय जो राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को अन्तरिक, बन्धकों पर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वसूल की गई हों, वह प्रारूप जिसमें उधारों के लिए भूमि विकास बैंकों को आवेदन किए जा सकेंगेय ऐसे उधारों के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित सम्पत्तियाँ, बन्धककर्ताओं से भूमि विकास बैंकों के कारवार के संचालन में साधारणतः सम्बद्ध हों, और

(घ) ऐसे सभी विषय जो नियमों द्वारा विहित किए जाने के लिए इस अध्याय में अपेक्षित या अनुज्ञात हैं।

[अध्याय 6–ख सहकारी बैंक

44–क–ज] अध्याय का सहकारी बैंकों पर लागू होना–(1) इस अध्याय के उपबन्धों निक्षेप निगम अधिनियम (डिपोजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऐक्ट) 1961 (47, 1961) में यथापरिभाषित सहकारी बैंक पर. इस अधिनियम के अन्य भागों में अन्तर्वि उपबन्धों के अतिरिक्त लागू होंगे। जहाँ प्रकट अथवा विभि असंगति का कोई प्रश्न उत्पन्न हो वहाँ इस अध्याय के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्य भागों के उपक प्रभावी होंगे।

(2) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, निक्षेप बीमा निगम से तात्पर्य है। है निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (47) 1961) की धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा निगम और रिजर्व बैंक से तात्पर्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिय ऐक्ट, 1934 (2, 1934) के अधीन, स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।

44–क–ट-विभाजन, समामेलन, समझौता आदि–(1) किसी सहकारी बैंक के बारे में समझौता क व्यवस्था या उसके समामेलन या पुनर्निर्माण अथवा उसको आस्तियों और दायित्वों के विभाजन या अंतरण को कोई स्कीम मंजूर करने के आदेश, रिजर्व बैंक की पूर्वलिखित मंजूरी के बिना न दिया जाएगा।

(2) जहाँ केन्द्रीय सरकार ने किसी सहकारिता बैंक के सम्बन्ध में, बैंककारी विनियमन अधिनिय (बैंकिंग रेगुलेशन्स ऐक्ट), 1949 (10, 1949) की धारा 45 की उप–धारा (2) के अधीन अधिस्थगन आदेश दिया हो, वहाँ रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के पूर्वलिखित अनुमोदन से अधिस्थगन की अवधि में निम्नलिखित स्कोर तैयार करा सकेगा

(i) सहकारिता के पुननिर्माण के लिये, या

(ii) किसी अन्य सहकारिता बैंक (इसमें आगे ''अंतरिती बैंक'' के रूप में निर्दिष्ट) के साथ उसके समामेलन के लिये ।

(3) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, यदि कोई सहकारिता बैंक जो निक्षेप–बोमा निगम अधिनियम (डिपोजिट इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ऐक्ट), 1961 (47, 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, समामेलित किया जाय या जिसके सम्बन्ध में समझौता या व्यवस्था अथवा पुननिर्माण की कोई स्कोप मंजूर की गई हो और निक्षेप–बीमा निगम, उस अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (2) के अधीन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को भुगतान करने का भागी हो गया हो, तो ऐसा बीमाकृत बैंक जिस बैंक के साथ समामेकित किया गया हो वह बैंक अथवा ऐसे समामेलन के बाद गठित नया सहकारिता बैंक अधवा, यथास्थिति, बीमाकृत या अंतरिती बैंक, उस अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सीमा तक और रीति से, निक्षेप बीमा निगम को प्रतिसंदत्त करने की मध्यता के अधीन होगा।

44–क–ठ- सहकारी बैंकों की प्रबन्धक समिति का अतिष्ठित किया जाना–इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल वात के होने पर भी, यदि इसकी अपेक्षा रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में लोकहित में अथवा किसो सहकारी बैंक के काम–काज की निक्षेपकर्ताओं के हित में अहितकर होने देने से रोकने के लिये या सहकारी बैंक का उचित प्रवन्ध सुनिश्चित करने के लिये की जाय तो रजिस्ट्रार, ऐसी शत्तों पर और कुल मिलाकर पाँच वर्षों से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, उस सहकारी बैंक की प्रवन्धक समिति या अन्य प्रबन्ध निकाय को (चाहे वह जिस किसी नाम से भी कहा जाय) अतिष्ठित करने तथा उसके लिए प्रशासक नियुक्त करने का आदेश पारित करेगा।

44–क–ड- परिसमापन आदेश के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी या अध्यपेक्षा–(1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना परिसमाए नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निक्षेप बीमा निगम अधिनियम (डिपोजिट इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ऐक्ट), 1961 (47, 1961) की धारा 13–घ में वर्णित परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा यरि रजिस्ट्रार से वैसी अपेक्षा की जाय तो वह किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश देगा।

1. बिहार अधिनियम 39, 1982 द्वारा अन्तःस्थापित ।

44–क–क-विशेष बीमा निगम की प्रतिभूति–जहाँ कोई सहकारी बैंक विशेष बीमा निगम अधिनियम, 1981 (47, 100)) के अर्थ के तौधकृत बैंक होने के पाते परिसमाप्त हो आय का समापनाधीत्र कर लिया जाय और निक्षेप बीधा विग उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारी (1) के अधीन श्रीधाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को भुगतान करने कान्दा हो जाए तो विशेष श्रीधा विग को उस अधिनियम की धारा है। में उपबंधित सीधा लक और रीति से प्रतिपूर्ति की आथगी।

44–क–ण-रिजर्व बैंक की मंजूरी का अभ्मपेक्षा–की अंतिभता इस अधिनिषध में अंतर्निश किसी प्रतिकूल बात को होने पर भी कह रिजर्व बैंक की पूर्व लिखित मंजूरी से या उसके द्वारा अपेक्षा करने पर

(1) किसी सहकारिता बैंक के परिसमापन का आदेश दिया जाय, या

(ii) उसके सम्बन्ध में समझौता या व्यवस्था या पुनर्निर्माण या सामेलन की स्कीम बनाई जाय, या

(उ) उसके सम्बन्ध में उसकी प्रबन्धक समिति किसी अन्य प्रवन्ध निकाय (चाहे जिस किसी गाय से भी कहा आय) के अधिक्षान और उसके लिये प्रशासक की नियुक्ति का आदेश दिया जाए,

वहाँ इसके विरुद्ध न हो कोई अपील पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन किया जायगा और प नह अनुज्ञेय ही होगा तथा रिजर्व बैंक की ऐसी मंजूरी था अध्यक्षा पर किसी भी रोति से प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

[1][अध्याय 6–ग

प्राथमिक कृषि सोसाइटी, कृषक सेवा सोसाइटी और बहुदेशीय सहकारी सोसाइटी के लिये विशेष उपबन्ध

44–क–त. इस अध्याय के उपबन्ध केवल कृषि साख सोसाइटी पर लागू होंगे– इस अध्याय के अन्तर्विष्ट उपबन्ध केवल प्राथमिक कृषि सोसाइटी, कृषक केन्द्र सोसाइटी और बहुद्देशीय सहकारी सोसाइटी पर लागू होंगे ।

44–क–थ. सोसाइटियों के समापन और अनेक सोसाइटियों के समामेलन (एक में मिलाने) का आदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति–(1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी जहाँ रजिस्ट्रार का समाधान हो कि सहकारी आन्दोलन के हित में, या सहकारी सोसाइटियों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ अथवा इस कारण से कि सोसाइटी जीवनक्षम (चल सकने वाली) इकाई के रूप में काम नहीं कर पा रही है, या उसने अशोध्या ऋण (डूबी रकम) उपगत कर लिया है अथवा वह निष्क्रिय हो चुकी है, यह आवश्यक है कि उस सोसाइटी को समाप्त कर दिया जाय, वहाँ वह (रजिस्ट्रार) राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा सोसाइटी के समापन का निदेश दे सकेगा और धारा–44 में समापक के जो कृत्य बताए गये हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिये व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा।

[2][''(2) (क) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में, इस अध्याय के अध्यधीन सोसाइटियों के प्रचालन में एकरूपता लाने हेतु उनके मजबूती एवं उपयोगिता को बढ़ाने एवं कृषि विकास के उद्देश्य के लिए उन्हें सक्षम (भायबुल) बनाने हेतु प्राथमिक सहकारी साख सोसाइटी का क्षेत्र पंचायत के सह–अंतक होगा एवं प्रत्येक पंचायत में केवल एक जैसा से सोसाइटी होगा।

(ख) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी यदि एक प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का क्षेत्र इस उप–धारा की उप–कडिका (क) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया जायेगा, तो रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार की ओर से काम करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो कि सहायक निबंधक की पंक्ति से नीचे का न हो। यह आदेश द्वारा एक या एक से अधिक सोसाइटियों जैसा कि मामला हो, के विखण्डन अथवा सविलियन जिसमें कि पुनर्गठन शामिल हों के लिए आदेश कर सकेगा एवं वैसे पुनर्गठन के पश्चात् नई सोसाइटीध्सोसाइटियों का निबंधन कर सकेगा।'',

[2][''(3) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी इस उप–धारा (2) के अधीन पुनर्गठित सोसाइटी या सोसाइटियाँ अपने प्रबंध समिति के साथ विघटित समझे जायेंगे एवं इस धारा की उप–धारा (2) के अधीन नई सोसाइटीध्सोसाइटियों के निबंधन की तिथि से पदमुक्त समझे जायेंगे एवं वैसे रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की सदस्यता पंचायत के लिए सृजित अपने–अपने प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी में हस्तान्तरित समझे जायेंगे जो कि उप–धारा

1. बिहार अधिनियम 21, 1976 द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. बिहार अधिनियम 18, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) के अधीन पुनर्गठन के पश्चात् वैसे सदस्य जो उस पंचायत से सम्बन्ध रखता हो एवं उनके सभी आस्तियाँ व दायित्व नये सोसाइटीध्सोसाइटियों में बाँट लिया जायेगा जैसा कि रजिस्ट्रार सरकार द्वारा रीति विहित हो :

परन्तु राज्य सरकार समय–समय पर इस धारा की उप–धारा (2) के अधीन सृजित नई सोसाइटीध्सोसाइटियों के दायित्वों के अधिस्थान की घोषणा कर सकेगा।.'',

1[''(4) (क) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी इस धारा की उप–धारा (2) के अधीन सोसाइटियों के पुनर्गठन एवं इस धारा की उप–धारा (3) के अधीन नई सोसाइटीध्सोसाइटियों के स्थापना हेतु रजिस्ट्रारध्सरकार वैसे समय जब तक नई प्रबंध समिति का गठन न हो जाये तदर्थ प्रबंध समिति गठित करेगा अथवा तदर्थ प्रबंध समिति के गठन हेतु प्रावधान विहित करेगा एवं तदर्थ प्रबंध समिति जो गठित होगी प्रावधानों के अनुसार कृत्यों का पालन एवं वैसे शक्तियों का प्रयोग करेगी जैसा कि विहित हो।

(ख) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी इस उप–धारा की कंडिका (क) के अधीन निर्वाचन के पश्चात् नई प्रबंध समिति के गठन के बावत सभी वैसे सम्बद्ध सोसाइटियों के प्रबंध समिति जिसके प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी सदस्य हो या वैसे सम्बद्ध सोसाइटियों या परिसंघ का इस अधिनियम में विहित प्रावधानों के अधीन गठन किया जाएगा, ताकि वैसे सोसाइटियों के प्रबंध समिति को गठित किया जा सके।'',

(5)[2] [XXXX]

(6) [3][''उप–धारा (2)''] के अधीन स्थापित नई सोसाइटी में स्थानीय क्षेत्रों के भीतर पड़नेवाले परिवारों का कम–से–कम एक वयस्क सदस्य होगा। वह सोसाइटी का नामीय (नामिनल) या सह–सदस्य होगा। उसे मतदान का अधिकार प्राप्त होगा, बशर्ते कि वह ख''सदस्यता शुल्क'', चुकाए। वह सोसाइटी का पूर्ण सदस्य हो सकेगा बशर्ते कि वह सोसाइटी का कम–से–कम एक शेयर खरीदे। उसे सोसाइटी से कर्ज और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त करने का हक होगा। उसे सोसाइटी का कोई निर्वाचन (एलेक्टिव) पद धारण करने का भी हक होगा।

44–क–द. रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील– धारा 44–क–थ की उप–धारा (1) के अधीन, समापन से या समामेलन से या नयी समिति की स्थापना और उक्त धारा की उप–धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से व्यथित कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध, आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अभिवेदन दे सकता है और राज्य सरकार आपत्तियों की सुनवाई के बाद उन पर ऐसा आदेश दे सकेगी जो वह उचित समझे और राज्य सरकार का वह आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि–न्यायालय में अपील नहीं की जायगी।

44–क–ध. समामेलन (मिलाए जाने के बाद गठित नई सोसाइटी का निर्वाचन–धारा 44–क–थ की उप–धारा (2) के अधीन स्थापित नई सोसाइटी का निर्वाचन सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छः महीने के भीतर होगा किन्तु अभिलिखित किये जाने वाले विशेष कारणों से सरकार इस अवधि को और छः महीने तक बढ़ा सकेगी।]

[4][''अध्याय VI–घ

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों के प्रयोज्य विशेष उपबंध

44 'क न'. अध्यायटप्–घ का अधिप्रभावी होना– इस अधिनियम के किसी दूसरे अध्याय अथवा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 या निर्मित नियमावली या निर्गत आदेश में किसी प्रतिकूल या असंगत बात होने पर भी इस अध्याय के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा।

44 'क प'. प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के जमाकर्त्ताओं एवं उधारकर्त्ताओं के लिए सदस्यता सुनिश्चित करना–प्रत्येक व्यक्तिं जो प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के उधारकर्त्ता या जमाकर्त्ता हों या

ऐसी समिति के जमाकर्त्ता या उधारकर्त्ता बनना चाहते हों, तो उन्हें धारा 44 'क थ' (।फ) की उप–धारा (6) के शर्तों के अधीन उस समिति का सदस्य पूर्ण मताधिकार के साथ सदस्य अथवा सह–सदस्य बनाया जा सकेगा।

44 'क फ' सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले में स्वायत्तता – अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी को सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले में स्वायत्तता निम्न क्षेत्रों सहित प्राप्त होगा–

1. बिहार अधिनियम 18, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. बिहार अधिनियम 18, 2008 द्वारा विलोपित ।
3. प्रतिस्थापित तत्रैव ।
4. अन्तःस्थापित तत्रैव ।

(क) रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश के अनुरूप जमा एवं ऋणों पर सूद दरय

(ख) उधार एवं निवेशय

(ग) ऋण नीति एवं वैयक्तिक ऋण निर्णयः

(घ) कार्मिक नीति, कर्मचारी की भर्ती, पदस्थापन एवं मुआवजाय तथा

(ङ) अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं अंकेक्षण के लिए क्षतिपूर्ति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली।

44 'क ब' राज्य सरकार के अंशदान की सीमा–अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत किसी सहकारी सोसाइटी के हिस्सा पूँजी में राज्य सरकार का अंशदान उस सोसाइटी के कुल प्रदत्त हिस्सा पूँजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, परन्तु राज्य सरकार या ऐसी सोसाइटी राज्य सरकार के अपने अंशदान घटाने के लिए स्वतंत्र होगी और सोसाइटी को ऐसा करने से राज्य सरकार द्वारा नहीं रोका जाएगा।

44 'क भ' सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या एवं प्रतिबंध–(1) राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध समिति में सरकार का केवल एक नामित सदस्य (छवउपदमम) होगा।

(2) प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंध समिति में सरकार का कोई नामित सदस्य (छवउपदमम) नहीं होगा।

44 'क म'. सम्बद्धक सोसाइटी की सदस्यता–(1) (क) सरकार द्वारा अधिसूचित एवं यथाविहित प्रावधान किए जाने पर बिहार सरकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत् निबंधित अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी समिति बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित समिति सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा।

(ख) सरकार द्वारा अधिसूचित एवं यथाविहित प्रावधान किए जाने पर बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निबंधित सम्बद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा।

(2) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी समिति अपने पसन्द की संबद्धक समिति का सदस्य हो सकता है अथवा उस समिति की सदस्यता छोड़ सकता है।

44 'ख क' कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रतिबंध–अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत किसी सोसाइटी को व्यवसाय करने के लिए कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

44 'ख ख' जमा निवेश की स्वतंत्रता– अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत सोसायटी को अपने निधि को रिजर्व बैंक के द्वारा बनाये गये दिशा–निर्देश के अनुसार किसी भी वित्तीय संस्था में निवेश अथवा जमा करने की स्वतंत्रता रहेगी।

44 'ख ग'. उधार लेने की स्वतंत्रता– अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकता है एवं पुनर्वित्त राष्ट्रीय बैंक या किसी दूसरे पुनर्वित्त एजेन्सी से प्रत्यक्षतः अथवा रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अपने पसन्द की किसी भी वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर सकेगा। ये सहकारी सोसाइटी संबद्धक समिति से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

44 'ख घ', प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु दिशा–निर्देश–राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी द्वारा लाभांश भुगतान करने हेतु निबंधक सामान्य दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

44 'ख ङ' किसी मद में अंशदान–अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत कोई भी समिति अपना शुद्ध मूल्य एवं अपनी पूँजी बढ़ाने के अतिरिक्त किसी दूसरे मद में अंशदान नहीं करेगी।

44 'ख च'. राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति की सदस्यता हेतु अयोग्यतायें–(1) प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी को छोड़कर अन्य किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य जो राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति के सदस्य को जिसमें उस सोसाइटी के द्वारा 90 दिनों से अधिक की अवधि तक के लिए व्यतिक्रमी हो तो सम्बन्धित बैंक के मुख्य कार्यपालक की सूचना पर निबंधक, सहयोग समितियों द्वारा उन्हें प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति का सदस्य जो राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति के सदस्य को जिसमें उस सोसाइटी के द्वारा एक वर्ष से

अधिक की अवधि के लिए व्यतिक्रमी हों, तो सम्बन्धित बैंक के मुख्य कार्यपालक की सूचना पर निबंधक, सहयोग समितियों द्वारा उन्हें सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) कोई भी व्यक्ति अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, यदि–

(क) वह व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं हो, या

(ख) वह व्यक्ति नामांकन भरने की तिथि को, उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण या सोसाइटी के किसी बकाये के सम्बन्ध में सोसाइटी अथवा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा

(ग) उसे सोसाइटी में किए गये किसी निवेश अथवा उससे लिए गए किसी ऋण को छोड़कर सोसाइटी के साथ किए गए किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसाइटी द्वारा बेची या खरीदी गई किसी सम्पत्ति में अथवा सोसाइटी में किसी संव्यवहार में किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा

(घ) उसके विरुद्ध किसी निबंधित सोसाइटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा

(ङ) उसके विरुद्ध किसी निबंधित सोसाइटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लोंबत हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो।

(4) किसी निर्वाचित व्यक्ति को सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत प्रबंध समिति का सदस्य या पदधारक के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वह एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सोसाइटी के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में व्यतिक्रमी हो, जब तक सोसाइटी का बकाया राशि सूद सहित उनके द्वारा जमा नहीं किया जाता है।

44 'ख छ', अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का अवक्रमण–(1) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति का अवक्रमण इस अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत निबंधक द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा।

(2) प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंध समिति का अवक्रमण इस अधिनियम की धारा 41 के तहत् निबंधक द्वारा सिर्फ निम्नलिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत ही किया जायेगा–

(क) अगर सोसाइटी तीन साल लगतार घाटे में रहा हो, अथवा

(ख) यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी प्रकाश में आया हो, या

(ग) यदि इस परिणाम का न्यायिक निदेश हो, या

(घ) यदि तीन लगातार बैठकों में गणपूर्ति का अभाव रहा हो।

44 'खज'. निर्वाचन–(1) अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान प्रबंध समिति के कार्यकाल समाप्ति के पूर्व कराया जाएगा तथा प्रबंध समिति के अवक्रमण की स्थिति में निबंधक उस सोसाइटी के अवक्रमण की तिथि से छह महीने के अंदर निर्वाचन कराया जाएगा।

(2) जिस सोसाइटी का अवक्रमण उपर्युक्त धारा 44 'ख छ' के उप–कंडिका 'क' एवं 'ख' में वर्णित परिस्थिति में हुआ है, उस प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंध समिति का सदस्य अवक्रमण से पाँच वर्षों के लिए दुबारा चुनाव लड़ने योग्य नहीं होगा।

44 'ख झ', विवेकपूर्ण मानक–निबंधक द्वारा सभी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के पूँजी का रिस्कवेटेड एसेट रेसियो सहित विवेकपूर्ण मानक का निर्धारण राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से विशिष्ट रूप से किया जाएगा।

44 'ख ञ' निदेशकों एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की बर्खास्तगी–(1) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति के सदस्य या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड को पूरा करना होगा।

(2) कोई व्यक्ति राज्य सहकारी बैंक अथवा एक केन्द्रीय सहकारी बैंक के समिति के सदस्य अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं करते हों, उक्त पद के लिए अयोग्य माने जायेंगे एवं यदि वह व्यक्ति पद पर पदासीन रहते हैं, तो , तो रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीय बैंक को इस परिणाम के परामर्श प्राप्त होने पर निबंधक द्वारा बर्खास्त किए जा सकेंगे।

44 'ख ट' राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति में विशेषज्ञों का सहयोजन–(1) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीधं सहकारी बैंक के प्रबंध के समिति में उतने ही विशेषज्ञों की संख्या रहेगी जितने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सदस्य व्यावसायिक योग्यता अथवा अनुभव रखते हों।

(2) यदि ऐसे विशेषज्ञ राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति में निर्वाचित नहीं होत हैं, तो ऐसे कमी की सीमा तक उनकी रिक्तियाँ ऐसे व्यक्तियों के प्रबंध समिति में सहयोजन के द्वारा भरी जाएगी तथा उन्हें पूर्ण मताधिकार होगा।

44 'ख ठ', लेखा का अंकेक्षण– राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने लेखा का अंकेक्षण राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित पैनल के सनदी लेखाकार (चार्टर्ड आकउण्टेंट) से करायेगा।

44 'खड'. राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक का विशेष अंकेक्षण–(1) निबंधक, रिजर्व बैंक के अनुरोध पर ऐसे विचारार्थ विषय जिस पर निबंधक की सहमति हो, राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के विशेष अंकेक्षण करने की व्यवस्था करायेगा एवं रिजर्व बैंक द्वारा नियत समय के अन्दर उसे रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायेगा।

(2) निबंधक स्वतः या राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति के अनुरोध पर ऐसे बैंक का विशेष अंकेक्षण कराने की व्यवस्था कराएगा।

44 'ख ढ'. प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी द्वारा बैंक 'शब्द' के प्रयोग पर प्रतिबंध– (1) कोई प्राथमिक कृ षि साख सोसाइटी 'बैंक', 'बैंकर' अथवा 'बैंकिंग' शब्द के किसी दूसरे व्युत्पन्न का प्रयोग नहीं करेगा।

(2) निबंधक उस प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी को अनिबंधित करेगा, जो इस धारा की उप–धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा।

44 'ख ण', कैडर प्रणाली को समाप्त करना–अल्पकालीन साख संरचना में कोई कैडर प्रणाली नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

44 'ख त'. राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक का परिसमापन – निबंधक रिजर्व बैंक के परामर्श पर राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक का परिसमापन करने का आदेश देगा तथा एक माह के अन्दर परिसमापक की नियुक्ति करेगा।

44 'ख थ'. रिजर्व बैंक के नियामक अधिकार का कार्यान्वयन–इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमावली में किसी बात के होते हुए भी राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में निबंधक, सहयोग समितियों द्वारा रिजर्व बैंक के नियामक अधिकारों को लागू कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

44 'ख द' राज्य सरकार द्वारा छूट–अल्पकालीन साख संरचनान्तर्गत कोई सोसाइटी रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक परामर्श के बिना इस अधिनियम की धारा 62 (2) से किसी भी तरह इस अध्याय के प्रावधान के प्रयोग से विमुक्त नहीं हो सकेगा।'',

अध्याय 7
दंड एवं प्रक्रिया

[1]**[''45. अपराध और शास्तियाँ**–(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि–

(क) कोई सहकारी समिति, अथवा उसका कोई पदाधिकारी, अथवा सदस्य, जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाये, या मिथ्या जानकारी दे, अथवा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित कोई जानकारी अथवा इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन कोई जानकारी निबंधक को जानबूझकर नहीं दें, अथवा,

(ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किसी सम्मन, अधियाचना अथवा इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन निर्गत, विधिसम्मत लिखित आदेश की अवज्ञा करे, अथवा,

(ग) कोई नियोक्ता जो बिना किसी पर्याप्त कारण के, अपने कार्मिकों से कटौती की गई राशि को कटौती की तिथि से चौदह दिनों के भीतर सहकारी समिति को भुगतान करने में असफल हो, अथवा

(घ) कोई पदाधिकारी, अथवा अभिरक्षक, जो सहकारी समिति की पंजियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकद, प्रतिभूति एवं अन्य परिसम्पत्तियों की अभिरक्षा, जिनका वह पदाधिकारी अथवा अभिरक्षक हो, जानबूझकर अधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल हो, और

1. बिहार अधिनियम सं० 6, 2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ङ) कोई व्यक्ति, जो सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों, अथवा पदधारियों के निर्वाचन के पूर्व निर्वाचन के दौरान, अथवा उसके पश्चात्, भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो।

(2) इस धारा की उप–धारा (1) के अधीन कोई अपराध एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से या 2000/– (दो हजार) रु० तक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगाः

परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति दुर्विनियोजन, कपट, न्यास–भंग, छल या ऐसे अन्य किसी कार्य, जिसवं नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, का दोषी हो, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी समिति को हानि हुई हो, तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन भी दण्डनीय होगा।''

[1][**45–क. नये सचिव को कार्यभार सौंपा जाना**–(1) नया सचिव निर्वाचित हो जाने या किससे सहकारी सोसाइटी का अवक्रमण होने अथवा सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारियों की पदावधि समाप्त हो जाने पर, पदाधिकारी सचिव या सहकारी सोसाइटी के कार्यालय का प्रभार धारण करनेवाले व्यक्ति अपने कार्यालय का प्रभार और उक्त सोसाइटी के सचिव या कार्यालय प्रभारी के रूप में अपने कब्जे के सभी कागज–पत्र और सम्पति नये सचिव को अथवा उक्त सोसाइटी के काम–काज का प्रभार लेने के लिये विहित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित व्यक्ति को सौंप देगा।

(2) यदि किसी सहकारी सोसाइटी का पदावरोही सचिव या सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति उपर्युक्त उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार अपने पद का प्रभार सौंपने में असफल हो या सौंपने से इन्कार करे, तो विहित प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त (इम्पावर्ड) कोई पदाधिकारी लिखित आदेश द्वारा पदावरोही सचिव या सचिव के पद का प्रभार धारण करनेवाले व्यक्ति को अपने पद का प्रभार और ऐसे सचिव के रूप में अपने कब्जे के सभी कागज पत्र और सम्पत्ति नये निर्वाचन की दशा में नये सचिव को और अवक्रमण या पदावधि समाप्त हो जाने की दशा में सोसाइटी के कामकाज का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त पदाधिकारी कां तुरन्त सौंप देने का निदेश दे सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे उप–धारा (1) के अधीन निदेश निर्गत किया गया हो उक्त निदेश का अनुपालन करने में असफल हो, तो वह छः महीने तक के कारावास से या 500 रु० तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) यदि ऐसा अपेक्षित हो, विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी पदाधिकारी की स्थानीय पुलिस और पदाधिकारी मजिस्ट्रेट की सहायता से पदावरोही सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाले व्यक्ति से पं कागज–पत्र और सम्पत्ति बलपूर्वक कब्जा कर लेने और उन्हें, नये निर्वाचन की दशा में नये सचिव की ओर उसके अवक्रमण या पदाधिकारियों की पदावधि समाप्त होने की दशा में जहाँ नया निर्वाचन होना बाकी हो, वहाँ सोसाइट का काम–काज चलाने के लिए नियुक्त राज्य सरकार के पदाधिकारी को सौंप देने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी।

45–ख. सचिव या सहकारी सोसाइटी के कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अभिलेखों का पेश किया जाना–(1) रजिस्ट्रार या सहकारी विभाग के किसी अन्य राजपत्रित पदाधिकारी के निदेश पर सहकार सोसाइटी का सचिव तुरन्त सोसाइटी के वैसे सभी कागज–पत्र और दस्तावेज सौंप देगा, जो रजिस्ट्रार या ऊपर वर्णित पदाधिकारी उक्त सहकारी सोसाइटी के कामकाज के संबंध में निरीक्षण या जाँच के लिए अपेक्षा करें।

(2) यदि सचिव या सहकारी सोसाइटी के कार्यालय का प्रभारी व्यक्ति पूर्ववर्ती उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दस्तावेज सौंपने में असफल हो या सौंपने से इन्कार करे या सौंपे जाने से अपने अपने को बचाए, तो वह छः महीने तक के कारावास या 500 रुपये तक जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। ऐसा अपराध संज्ञेय होगा।

(3) जब कोई व्यक्ति जिसे इस धारा की उप–धारा (1) के अधीन निदेश निर्गत किया गया हो, सभी अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल हो या प्रस्तुत करने से से इन्कार करे या को बचाये तब निदेश निर्गत करनेवाला पदाधिकारी पुलिस और दण्डाधिकारी या प्रस्तुत किए जाने से अपने बलपूर्वक उस सोसाइटी के सभी अभिलेख और दस्तावेज अभिग्रहण (सीज) कर सकेगी।,

46. सहकारी शब्द के प्रयोग पर रोक–(1) पंजीकृत सोसाइटी को छोड़कर अन्य व्यक्ति अर्थश सोसाइटी राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी व्यापार अथवा संव्यवहार वैसे नाम अथवा पदनाम से नहीं करेगी जिसमें ''सहकारी'' शब्द जुड़ा रहे :

1. बिहार अधिनियम 39, 1982 द्वारा अन्तःस्थापित ।

परन्तु, इस धारा की कोई भी बात उस तिथि को ''सहकारी'' शब्द जुड़ा नाम अथवा पदनाम से संव्यवहार करनेवाले किसी व्यक्ति अथवा हित उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगी जिस तिथि को सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 प्रवृत्त हुआ ।

(2) सोसाइटी का कोई अधिकारी अथवा सदस्य अथवा कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, को अर्थदण्ड का भागी होगा जो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा और यदि उसका अपराध जारी रहेगा तो सजा प्राप्ति के बाद अपराध को जारी रखने की स्थिति में पाँच रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड लगेगा ।

47. अपराध का संज्ञान–(1) द्वितीय श्रेणी दण्डाधिकारी के न्यायालय से अन्यून न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जाँच नहीं करेगा।

[1]["(2) इस अधिनियम की धारा 45 की उप–धारा (1) (ग) के अधीन अपराध को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2, 1974) के प्रयोजनार्थ संज्ञेय माना जाएगा।"

(3) निबन्धक की पूर्वानुमति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जायेंगी तथा निवन्धक किसी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की अनुमति नहीं देगा जब तक वह उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दे।

48. विवाद–(1) यदि किसी पंजीकृत सोसाइटी के संव्यवहार को स्पर्श करता हुआ (सोसाइटी के किसी वेतन भोगी सेवक के विरुद्ध सोसाइटी अथवा उसकी प्रबन्ध समिति द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई सम्बन्धी विवाद को छोड़कर दूसरा) कोई विवाद–

(क) सदस्यों, भूतपूर्वक सदस्यों अथवा मृत सदस्यों के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों और सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की प्रतिभूतियों में हों चाहे वे प्रतिभूतियाँ सदस्य अथवा गैर–सदस्य होंय

(ख) सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य के द्वारा दावा करने वाले व्यक्ति अथवा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की प्रतिभूतियाँ, चाहे वैसी प्रतिभूतियाँ सदस्य हों अथवा गैर–सदस्य, और सोसाइटी, उसकी प्रबन्ध समिति अथवा सोसाइटी के किसी अधिकारी, अभिकर्ता अथवा सेवक में, अथवा

(ग) सोसाइटी अथवा उसकी प्रबन्ध समिति और सोसाइटी के किसी भूतपूर्व अथवा वर्त्तमान अधिकारी, अभिकर्ता अथवा सेवक में, अथवा

(घ) सोसाइटी और किसी अन्य निबन्धित सोसाइटी में, अथवा

(ङ) धारा 16 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन प्राधिकृत वित्तदायी बैंक और वैसा व्यक्ति में जो निबन्धित सोसाइटी का सदस्य न हो, उत्पन्न हो जाए जाय तो वैसा विवाद निबन्धक के पास निर्देशित कर दिया जायगा :

परन्तु, यदि धारा 32 अथवा धारा 63 के फलस्वरूप भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व समाप्त है जाए तो भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की सम्पदा के विरुद्ध कोई दावा विवाद नहीं माना जायगा ।

स्पष्टीकरण–(1) सदस्य, गैर–सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य अथवा गैर–सदस्य के मनोनीत व्यक्ति उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि अथवा सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की प्रतिभूतियों, चाहे ऐसी प्रतिभूतियाँ सदस्य अथवा गैर–सदस्य हो, से बाकी किसी ऋण अथवा माँग के सम्बन्ध में निबन्धित सोसाइटी द्वारा कोई दावा इस उपधारा के अभिप्राय के अन्तर्गत सोसाइटी के संव्यवहार का स्पर्श करता हुआ विवाद होगा यद्यपि वैसा ऋण अथवा माँग मान ली गई हो एवं विवादास्पद बिन्दु केवल सोधन–क्षमता अथवा सोधन प्रवर्तन–रीति हो ।

स्पष्टीकरण–(2)– यह कि अमुक व्यक्ति पंजीकृत सोसाइटी का सदस्य था या है, अथवा नहीं, इस उपधारा के अभिप्राय के अन्तर्गत एक विवाद होगा ।

(2) ऐसे निर्देश की प्राप्ति पर निबंधक–

(क) स्वयं विवाद का निबटारा कर सकेगा, अथवा

1.बिहार अधिनियम सं० 6, 2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) एतदर्थ निबन्धक की शक्तियों का प्रयोग करनेवाले किसी व्यक्ति के पास निष्पादनार्थ अन्तरित का सकेगा, अथवा

(ग) किसी नियम के अध्यधीन मध्यस्थ या मध्यस्थों के पास निष्पादणार्थ निर्देशित कर सकेगा।

(3) किसी नियम के अध्यधीन, निबन्धक उपधारा (2) की कोंडका (ख) बके अधीन अन्तरित अथवा उक्त उपधारा की कोंडका (ग) के अधीन निर्देशित किसी निर्देश को वापस लेकर उक्त उपधारा में उपबन्धित रीति में कार्रवाई कर सकेगा।

(4) मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति तथा निबन्धक मध्यस्थ अथवा वैसे अथवा मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाही में अनुसरित प्रक्रिया नियमावली से विनियमित होगी।

(3) वैसे विवाद की दशा में, जिसमें सांपाश्विक प्रतिभूति अन्तर्गत हो, उस विवाद का निबटारा करने वाला व्यक्ति बन्धक अधिनिर्णय देने को सक्षम होगा और उसका वही प्रभाव होगा जो किसी सक्षम व्यवहार न्यायालय की बन्धक डिक्री का होता है।

(6) उपधारा (2) की कंडिका (ख) अथवा (ग) के अभीन अंतरित अथवा निर्देशित विवाद में हुए किसी

निर्णय से धुब्ध व्यक्ति उस निर्णय की तिथि से तीन माह के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकेगा।
(7) इस धारा के अधीन विवादों के मामले में, निबन्धक को व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 114

एवं आदेश XLVII, नियम । के अधीन सिविल न्यायालय में निहित पुनर्विचारण की शक्ति होगी और उक्त संहिता की धारा 151 में विनिर्दिष्ट अंर्तभूत अधिकारिता भी होगी।

(8) जहाँ निबन्धक को उचित प्रतीत हो, वहाँ वह, आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा से, मामले का अभिकथन करके उसे जिला न्यायाधीश के पास निर्णयार्थ निर्दिष्ट कर सकेगा और जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा।

(9) इस धारा में स्पष्टतया उपबन्धित बातों को छोड़कर, इस धारा के अधीन निबन्धक का निर्णय तथ अपोल अधवा पुनर्विचार पर निबन्धक के आदेशों के अध्यधीन, उपधारा (2) की कंडिका (ख) (ग) के अधीन अन्तरित अथवा निर्दिष्ट विवाद में दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

टिप्पणी

[प्रबन्ध समिति द्वारा संयुक्त निदेशक के आदेश से किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो वह कर्मचारी निदेशक के पास अपील कर सकता है।

बिहार राज्य को–ऑपरेटिव बाजार संघ लि० बनाम को–ऑपरेटिव पदाधिकारी, 1973 बी०एल० जे०आर० 353 ए०आई०आर० 1973 पटना 74।

कर्मचारी की सेवा–शों से सम्बन्धित विवाद का मामला निबन्धक के अधिकारिता के बाहर है। निबन्धक के निर्णय जो समिति के किसी विवाद से सम्बन्धित हो तो दूसरी अपील नहीं की जा सकती है।

मो० इस्लाम बनाम जिला सहयोग पदाधिकारी। 1979 बी०बी०सी० जे० 101: 1979 बी०एल० जे० 87। सहकारी समिति द्वारा पारित निर्णय डिक्री के ही समान है **रामचन्द्र सिंह बनाम सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक, नवादा 1941 पी०डब्लू०एन० 536.**

निबन्धक धारा 48 (2) के अधीन समिति से सम्बन्धित किसी विवाद के समाधान के लिए सक्षम है। ए०आई०आर० 1962 एस०सी० 1367: 1962 बी०एल० जे०आर० 687.

प्रस्तुत धारा के अन्तर्गत निबन्धक समिति के किसी विवाद को अन्तरित करने के सक्षम है तथैव !

निबन्धक अधिनियम की धारा 48(6) के अधीन पारित अपने आदेश का पुनरीक्षण की प्रदत्त शक्ति के अनुसार पुनरीक्षण नहीं कर सकते हैं। **तथैव** ।

इस धारा के अध्यधीन शक्ति की प्रकृति न्यायिक है और चुनाव–विवाद भी भली–भाँति इस धारा की परिधि में समाविष्ट हो जाता है। चन्देश्वर प्रसाद बनाम बिहार सरकार, 1987 पी०एल० जे०आर० 159 : 1987 बी०बी०सी० जे० 132 : ए०आई०आर० 1987 पटना 208: 1987 बी०एल० जे० 203 ।

इस धारा के अधीन कार्यवाहियाँ सिविल वाद की प्रकृति की हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अधन सिविल न्यायालय द्वारा अन्यथा संज्ञेय होती। कानून ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता को निकाल लिया है और उसे सोसाइटी के सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, पदधारकों, अभिकर्त्ताओं और सोसाइटी के पदाधिकारियों यासेवकों के बीच सोसाइटी के कारोबार या प्रवन्ध से संयुक्त विवादों के विनिश्चयार्थ निबन्धक या निबन्धक की शक्ति प्रयोग करने वाले व्यक्ति को प्रदत्त कर दी है। **योगेन्द्र प्रसाद बनाम अपर निबंधक,** 1992 (1) पी.एल.जे.आर. 9 (एस.सी.)।

यदि बैंक निदेशक मंडल द्वारा पूर्णतः निजी तौर परप्रबंधित और नियंत्रित हो, स्थिति भिन्न हो सकेगी यदि समिति अवक्रमित हो गई हो और निबंधक द्वारा विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई हो तो सहकारी बैंक एवं उसके कर्मचारियों का विवाद में रीट याचिका की अधिकारिता नहीं हो सकती है। एस० इतरत हुसैन बनाम **निबंधक सहकारी समितियाँ**, 2001 (2) पी०एल० जे०आर० 253 द्य

यदि निबंधक द्वारा पुनर्विचारण की सुनवाई की गई हो और अंतिम तौर से निर्णय कर दिया गया हो तो उस पर आगे कोई पुनर्विचार नहीं हो सकता। अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निबंधक का कर्त्तव्य होता है कि वह इस निष्कर्ष को अभिलिखित करे कि वह विषयवस्तु को जिला न्यायाधीश को निर्देशित करना उपयुक्त समझा हैय परन्तु वैसे मामले में, जिसमें निबंधक विषयवस्तु को जिला न्यायाधीश को निर्देश करना उपयुक्त नहीं समझता हो और अपने स्तर से निबटारा चाहता हो तो अंतिम निर्णय के बाद धारा 48 (8) के तहत् जिला न्यायाधीश के निर्णय के लिए निर्देशित करने की उसकी शक्ति नहीं होगी। **रामाधार शर्मा बनाम बिहार राज्य**, 2002 (1) पी०एल० जे०आर० 646 1

यदि बैंक निदेशक मंडल द्वारा पूर्णतः निजी तौर पर प्रबंधित और नियंत्रित हो, स्थिति भिन्न हो सकेगी यदि समिति अवक्रमित हो गई हो और निबंधक द्वारा विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई हो तो सहकारी बैंक एवं उसके कर्मचारियों का विवाद में रीट याचिका की अधिकारिता नहीं हो सकती है। **एस० इतरत हुसैन बनाम निबंधक सहकारी समितियाँ**, 2001 (2) पी०एल० जे०आर० 253 1

यदि निबंधक द्वारा पुनर्विचारण की सुनवाई की गई हो और अंतिम तौर से निर्णय कर दिया गया हो तो उस पर आगे कोई पुनर्विचार नहीं हो सकता। अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निबंधक का कर्त्तव्य होता है कि वह इस निष्कर्ष को अभिलिखित करे कि वह विषयवस्तु को जिला न्यायाधीश को निर्देशित करना उपयुक्त समझा हैय परन्तु वैसे मामले में, जिसमें निबंधक विषयवस्तु को जिला न्यायाधीश को निर्देश करना उपयुक्त नहीं समझता हो और अपने स्तर से निबटारा चाहता हो तो अंतिम निर्णय के बाद धारा 48 (8) के तहत् जिला न्यायाधीश के निर्णय के लिए निर्देशित करने की उसकी शक्ति नहीं होगी। **रामाधार शर्मा बनाम बिहार राज्य**, 2002 (1) पी०एल० जे०आर० 646 1

भूखंड से सम्बन्धित विवाद के न्यायनिर्णय के लिए वाद संस्थित। वाद की संघार्यता को अधिनियम की धारा 57 के तहत् चुनौती दी गई। अधिनियम की धारा 57 अधिनियम की धारा 48 के अधीन यथोपबन्धित निबंधित सोसाइटी के कारोबार से सम्बन्धित विवाद के सम्बन्ध में वाद की अधिकारिता वर्जित करती है। अधिनियम की धाराओं 48 और 57 को साथ–साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि यदि सदस्यों के बीच निबंधितसोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में कोई विवाद उठ खड़ा हो, तो उसे निबंधक द्वारा निबटायगा और उसके सम्बन्ध में किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी। निबंधित सोसाइटी के कारोबार से सम्बन्धित तथाकथित विवाद में केवल निबंधित सोसाइटी के कारोबार ही नहीं, बल्कि निबंधित सोसाइटी के कामकाज भी अंतर्विष्ट होंगे। प्रावधान का व्यापक अर्थ दिया गया है। भूखंड की पहचान और सदस्यों को उन्हें बेचे गए भूखण्ड पर कब्जा दिलाना निबंधित सोसाइटी के कारोबार का हिस्सा है और निबंधित सोसाइटी के कामकाज से सम्बन्ध रखता है। निबंधित सोसाइटी के कारोबार को इससे कोई लेना–देना नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। वाद अधिनियम की धारा 57 के तहत् वर्जित किया जाता है। **राधा कृष्ण जायसवाल बनाम शीला कंचन**, 2003 (1) पी०एल० जे०आर० 18।

प्रार्थी अपीलार्थी रिट याचिका के माध्यम से उत्तरवादियों को चुनाव में भाग लेने को चुनौती देता है। अतः धारा 48 के अनुसार रिट याचिका अपस्थापित और मिथ्याधारित है। प्रार्थी को निबंधक से ही अनुरोध करना है कि जिला न्यायाधीश से मामला के सम्बन्ध में मंतव्य दिलवा देते। प्रार्थी को 30 दिनों के भीतर धारा 48 (8) के तहत् उपचार के लिए कदम उठाने की छूट दी जाती है। विजय कुमार बनाम बिहार राज्य, 2003 (2) पी०एल० जे०आर० 647 द्य

शक्तिमत्ता–यदि प्रार्थी के विरुद्ध लोक ऋण की भरपाई के लिए कार्यवाही लम्बित हो और अपीली प्राधिकरण का आदेश हो जिसमें घोषणा की गई हो कि निदेशक मंडल को (संयुक्त या पृथक् पृथक् रूप में) राशि वसूल करना है। प्रार्थी इस कारण अपना मनोनयन पत्र स्वीकृत कराने में समर्थ नहीं हो सका। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है, मात्र यह वजह उच्च न्यायालय के लिए आधार नहीं हो सकती, जिसपर वह इस पहलू पर विचार करे कि क्या अधिनियम अधिकारातीत है। यदि प्रार्थी चुनाव में प्रवेश के लिए पासपोर्ट के तौर पर भी राशि

जमा कर दे तो वह अपने लिए स्थिति से बचाव कर सकता है। यह पूर्णतः प्रार्थी पर निर्भर करता है कि वह जमा करे या नहीं। उच्च न्यायालय के लए यह अच्छा आधार नहीं है जिस पर वह अधिनियम के अधिकारातीत होने पर विचार करे। **नरेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य**, 2003 (3) पी०एल० जे०आर० 410 ।

सेवा विवादों को धारा 48 के अन्तर्गत निर्णयार्थ निबन्धक के पास प्रासंगिक (तममिततमक) नहीं किया जा सकता है। ऐसे विवादों को धारा 48 (1) के अन्तर्गत प्रासंगिक सामान्य विवादों से अलग समझा जाना चाहिए। हल्के विवादों को धारा 48 के चतुर्दिक परिधि के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं समझा जाना चाहिए। **विद्या भूषण सिंह अभय बनाम बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ समिति**, 2005 (3) पी०एल० जे०आर० 386।

धारा 48 में निहित प्रावधानों के तहत् दिए गये उपायों (तमउमकल) के उपयोग किए बिना रीट याचिक दाखिल को गई। निर्वाचन कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद कोई सहायता नहीं दी जा सकती है। चूँकि निर्वाचन कार्यक्रम पहले ही निर्गत हो चुका है, कुछ हिस्सों में निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है, अपीलार्थी के लिए, इसे चुनौती मात्र अधिनियम की धारा 48 के तहत् देने का उपाया शेष था, जिसे उपयोग नहीं किया गया। अब कोई सहाय्य प्रदान नहीं किया जा सकता है। **उमेश राय बनाम बिहार राज्य**, 2004 (2) पी०एल० जे०आर० 818 ।

सहपठित निबंधन अधिनियम, 1908–आवंटन का रद्द किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को अनदेखी। यद्यपि निबंधन अधिनियम में इस बात का कोई विशिष्ट उपाय या तरीका नहीं है, जिसके द्वारा दस्तावेज का निबंधक के समक्ष पूर्व में निबंधित अन्तरण का दस्तावेज किसी अनुवर्ती निष्प्रभावित विलेख के द्वारा रद्द किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद यदि दस्तावेज के निबंधक को ऐसे निष्प्रभावी दस्तावेज को निबंधन के लिए स्वीकार करने का अधिकार था तो यह कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अपेक्षा के अनुसार किया जाना था तथा यह किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुँचा कर नहीं किया जा सकता, जिस व्यक्ति के पक्ष में पूर्व पूर्व अन्तरित दस्तावेज निबंधित किया गया था। जब एक बार किसी निबंधित दस्तावेज के द्वारा एक सम्पत्ति का अन्तरण किया जाता है, तो अन्तरण करने वाले व्यक्ति में निहित सिविल अधिकार उसे सुपुर्द किया जाता है तथा ऐसे निहित अधिकार को समाप्त करने का अधिकार एक सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल कोर्ट को ही है एवं निबंधक को सिविल कोर्ट का ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे कि वह अधिकार एवं पक्षकार के स्वामित्व का निर्णय कर सके। आक्षेपित आदेश खण्डित किया जाता है एवं मामले को निबंधक के पास पुनर्विचार हेतु भेजा जाता है। **स्वाति पाण्डे बनाम निबंधक**, सहकारी समिति, 2007 (2) पी०एल० जे०आर० 525 1,

49. निबंधक परिसमापक एवं मध्यस्थ को व्यवहार न्यायालय की कतिपय शक्तियाँ होगी–इस नियमावली के अध्यधीन निबन्धक धारा 35 के अधीन जाँच अथवा धारा 36 के अधीन निरीक्षणार्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति, किसी परिसमापक, निबंधक की शक्तियों का प्रयोजन करने वाला किसी व्यक्ति, अथवा धारा 48 के अधीन नियुक्त किसी मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों, जहाँ तक इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन के अनुपालन के लिए शक्तियों की आवश्यकता है, उन्हीं साधनों से एवं यथा सम्भव, उसी रीति से साक्षियों और संबन्धित पक्षों के सम्मन करने तथा उन्हें उपस्थित होने को विवश करने, शपथ पर उनका परीक्षण करने तथा उन्हें वहियों, लेखाओं, लेख्यों अथवा सम्पत्ति को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी जिन साधनों तथा जिस रीति का प्रावधान व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 सन् 1908) में व्यवहार न्यायालय के लिए किया गया है।

50. सम्पत्ति की जप्ती–(1) जहाँ परिसमापक अथवा सोसाइटी के आवेदन पर निबन्धक का समाधान हो जाने पर कोई भी व्यक्ति किसी वैसे आदेश के निष्पादन को विफल अथवा विलम्बित करने की नीयत से, जो धारा 44 या 48 के अधीन उसके विरुद्ध पारित किया जा सकेगा ।

(क) अपनी सम्पत्ति को पूर्णतः अथवा अंशतः व्ययन करने को है, अथवा

(ख) निबन्धक के क्षेत्रीय अधिकारिता से अपनी सम्पत्ति को पूर्णतः अथवा अंशतः हटाने को है,

वहाँ निबन्धक जबतक उसके समाधान पर्यन्त समुचित प्रतिभूति न दी जाए, उक्त सम्पत्ति को अथवा उसके वैसे भाग को, जिसे वह आवश्यक समझे, जप्त करने का निर्देश दे सकेगा और उस तरह की जप्ती का वही होगा जो सक्षम न्यायालय द्वारा जप्ती का होता है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन पारित जप्ती का आदेश निबन्धक के आवेदन पर, उप समाहर्त्ता द्वारा जिसकी अधिकारिता में वह सम्पत्ति स्थित हो उसी रीति से निष्पादित किया जायगा जिस रीति से राजस्व न्यायालय का आदेश निष्पादित किया जाता है।

51. आदेशों का लागू होना–धारा 44, 48 एवं 50 के अधीन पारित आदेश, इस अधिनियम के अधीर उपवन्धित लागू होने की किसी अन्य रीतिके अतिरिक्त, आवेदन पर से निम्नांकित तरह से प्रवृत्त कराए जायेंगे–

(क) जब निबन्धक परिसमापक अथवा मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के द्वारा पारित होंगे तो क्षेत्रीय अधिकारिता रखनेवाले किसी व्यवहार न्यायालय के द्वारा उसी रीति से जिस रीति से वैसे न्यायालय की डिक्री लागू कराई जाती है।

(ख) जब जिला न्यायाधीश द्वारा पारित होंगे तो उसी रीति से जिस रीति से जिला न्यायाधीश के समक्ष लम्बित किसी वाद में पारित की गई डिक्री लागू कराई जाती है।

52. बकाया राशि की वसूली— किसी व्यक्ति अथवा किसी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा संदेय राशि—

(क) जो धारा 33 के अधीन किया गया औडिट—शुल्क के रूप में हो,

(ख) जो निबन्धक के उस आदेश के अनुसार हो जिसे उसने धारा 39 के अधीन जाँच अथवा निरीक्षण व्यय को विभाजित करने के लिए दिया हो,

(ग) जो धारा 40 के अधीन पारित आदेश के अनुसार हो,

(घ) जो धारा 44 के अधीन निबन्धक अथवा परिसमापक द्वारा पारित आदेश के अनुसार हो, अथवा,

(ङ) जो धारा 48 के अधीन पारित अथवा दिया गया आदेश, निर्णय अथवा अधिनिर्णय के अनुसार हो, की वसूली उस क्षेत्र में, जिसमें बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम, 4 सन् 1914 प्रवृत्त हो, लोक—माँग के रूप में अथवा राज्य भर में भू—राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी जिसे वह लोक—माँग संदेय हो अथवा जिसे भू—राजस्व का बकाया संदेय हो ।

[1][(च) किसी प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी या मृत सदस्य के वैधिक प्रतिनिधि का देय रकम के रूप में।,

टिप्पणी

[सहयोग समिति के सहायक निबन्धक द्वारा धारा 6 में दिया गया अधिनिर्णय, जो अपील में पुष्ट हो चुका हो, प्रमाण—पत्र न्यायालय द्वारा उल्लंधित नहीं किया जा सकता ।,

53. सरकार के संदेय राशियों की वसूली—पंजीकृत सोसाइटी अथवा उसके वर्तमान या भूतपूर्व अधिकारी अथवा सदस्य से, अथवा उसकी प्रतिभूतियों से अथवा मृत सदस्य की सम्पदा से अथवा उसकी प्रतियों से सरकार को अधिनिर्णय व्यय सहित संदेय सभी राशियों की वसूली भू—राजस्व के बकाये के समान की जायेगी ।

54. सम्पदा जिससे सोसाइटी के जिम्मे बाकी राशियाँ वसूल की जायेंगी—सरकार को निबन्धित सोसाइटी के जिम्मे बाकी सभी राशियाँ तथा धारा 33, 39, 44, अथवा 48 के अधीन निबन्धित सोसाइटी से वसूलीय सभी राशियाँ प्रथमतः सोसाइटी के सम्पत्ति से द्वितीयतः उस सोसाइटी की दश में जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित है, उसके दायित्व की सीमा के अध्यधीन सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं अथवा उसकी प्रतिभूतियों से एवं तृतीयतः, अन्य सोसाइटियों की परिस्थिति में निबन्धक द्वारा निर्धारित परिमाण अथवा अनुपात की सीमा तक सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों अथवा मृत सदस्यों की सम्पदाओं अथवा उसकी प्रतिभूतियों से वसूल की जा सकेगी।

55. भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व—धारा 53 एवं 54 में किसी बात के होते हुए भी, हर हालत में भूतपूर्व सदस्यों तथा मृत सदस्यों की सम्पदाओं का दायित्व धारा 32 एवं 63 के प्रावधानों के अध्यधीन रहेगा।

[2][56. निबन्धक को पुनरीक्षण की शक्ति— रजिस्ट्रार आवेदन किये जाने पर अथवा स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रार अथवा धारा 44 के अधीन नियुक्त परिसमापक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा पारित किसी आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा परंतु ऐसा आदेश अधिकतम छह माह के भीतर पारित किया गया हो :

परन्तु रजिस्ट्रार को ऐसे किसी आदेश के पुनरीक्षण करने की शक्ति नहीं होगी जहाँ इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपील का प्रावधान हो ।

टिप्पणी

[निबन्धक द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग अथवा पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने की समय—सीमा निर्धारित नहीं है।]

1. बिहार अधिनियम 5, 1989 द्वारा अन्तः स्थापित ।
2. बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित ।

5.7 न्यायालय की अधिकारिता पर रोक–[1](1) इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबंधित बातों के सिवा, किसी व्यवहार अथवा राजस्व न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन निबंधित सोसाइटी के परिसमापन अथवा विघटन अथवा किसी निबन्धित सोसाइटी की प्रबंध समिति के निलम्बन अथवा रजिस्ट्रार को धारा 48 के अपेक्षा अनुसार निर्देशित किया जाने वाला किसी विवाद अथवा अध्याय (टप्प्क) के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में अधिकारिता नहीं रहेगी।]

(2) जब कोई सोसाइटी परिसमापनाधीन रहे, तो परिसमापना विधि में निवन्धक की अनुमति के बिना तथा उसके द्वारा लगाये गए शत्तों के अध्यधीन सोसाइटी के कामकाज को स्पर्श करने वाली किसी बात के सम्बन्ध में परिसमापक अथवा सोसाइटी अथवा उसके किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद अथवा अन्य वैधिक कार्यवाही नहीं होगी और न संस्थित की जायेगी।

(3) राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, निबन्धक, निबन्धक के सहायतार्थ नियुक्त व्यक्ति, परिसमापक, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के किसी भी वैसे आदेश को, जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन अन्तिम किसी भी न्यायालय में मान्य घोषित किया गया हो अधिकारिता भाव को छोड़कर गुणागुण अथवा किसी भी आधार पर चुनौती, आपास्त, शोधित, पुनरीक्षित अथवा निरस्त नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी

[धारा 57 के उद्देश्य यह है कि सोसाइटी के ब्योरे सम्बन्धी सभी बातों का निबटारा निबन्धक करेगा। परिसमापक को अपने निर्णय सम्बन्धी हेतु को समझाने के लिए न्यायालय में ले जाना अनुचित है।

भूखंड से सम्बन्धित विवाद के न्यायनिर्णय के लिए वाद संस्थित। वाद की संधार्यता को अधिनियम की धारा 57 के तहत् चुनौती दी गई। अधिनियम की धारा 57 अधिनियम की धारा 48 के अधीन यथोपवन्धित निबंधित सोसाइटी के कारोबार से सम्बन्धित विवाद के सम्बन्ध में वाद की अधिकारिता वर्जित करती है। अधिनियम की धाराओं 48 और 57 को साथ–साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि यदि सदस्यों के बीच निबंधितसोसाइटी के कामकाज के सम्बन्ध में कोई विवाद उठ खड़ा हो, तो उसे निबंधक द्वारा निबटायगा और उसके सम्बन्ध में किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी। निबंधित सोसाइटी के कारोबार से सम्बन्धित तथाकथित विवाद में केवल निबंधित सोसाइटी के कारोबार ही नहीं, बल्कि निबंधित सोसाइटी के कामकाज भी अंतर्विष्ट होंगे। प्रावधान का व्यापक अर्थ दिया गया है। भूखंड की पहचान और सदस्यों को उन्हें बेचे गए भूखण्ड पर कब्जा दिलाना निबंधित सोसाइटी के कारोबार का हिस्सा है और निबंधित सोसाइटी के कामकाज से सम्बन्ध रखता है। निबंधित सोसाइटी के कारोवार को इससे कोई लेना–देना नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। वाद अधिनियम की धारा 57 के तहत् वर्जित किया जाता है। **राधा कृष्ण जायसवाल बनाम शीला कंचन**, 2003 (1) पी०एल० जे०आर० 18।

सैरात बन्दोबस्ती के मामले में 1935 अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धित समितियों को, 1996 अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धित समितियों की अपेक्षा अधिमान्यता (चतपवतपजल) दी जानी चाहिए। अधिनियम, 1996 के तहत् निबन्धित समितियों सरकारी हस्तक्षेप से बिल्कुल स्वतन्त्र है। **बाकरगंज मछुआ स्वावलम्बी सहकारी समिति सीमित बनाम बिहार सरकार**, 2005 (2) पी०एल० जे०आर० 172।]

[2][अध्याय 7–क

करस्थम्

57–क. मामले जिनमें करस्थम् के लिए आवेदन किया जा सकेगा–जहाँ किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा मृत सदस्य की सम्पदा से निबन्धित सोसाइटी को अथवा वैसी निबन्धित सोसाइटी को जो इस अधिनियम की धारा 16 के उपधारा (1) के किसी भी प्रावधान के अधीन गैर–सदस्यों को ऋण स्वीकृत करने के लिए निबन्धक द्वारा सम्यकरूपेण प्राधिकृत हो, किसी व्यक्ति से जो निबन्धित सोसाइटी का सदस्य न हो अथवा यदि वैसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो उसकी सम्पदा से कोई ऋण अथवा परादेय माँग संदेय रहे, वहाँ सोसाइटी, किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त, जिसका वह विधानानुसार हकदार हो, निबन्धक के पास आवेदन पत्र दे सकेगी जिसमें वह व्यतिक्रमी के कब्जा में रहनेवाली निम्नांकित वस्तुओं को करस्थम् करके ऋण अथवा परादेय माँग की वसूली का अनुरोध करेगी–

1. बिहार अधिनियम 5, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. बिहार अधिनियम 16, 1948 द्वारा अन्तःस्थापित ।

(1) व्यतिक्रमी की धृति पर खड़ी अथवा असंगृहित खड़ी अथवा असंगृहित कोई फसल अथवा धरती की अन्य उपज ।

(2) कोई फसल अथवा धरती की अन्य उपज जो व्यतिक्रमी की धृति पर उगाई गई हो तथा काटी अथवा संग्रह की जा चुकी हो एवं खेत अथवा घर–आंगन में अन्न–दमाही के स्थान पर अथवा धृति अथवा खलिहान में जमा करके रखी हो।

57–ख. आवेदन का प्रपत्र–(1) पूर्वगामी धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन पत्र में निम्नांकित बातों का उल्लेख रहेगा–

(क) व्यतिक्रमी की घृति तथा उसकी सीमायें, वैसा अन्य विवरण जो उसको पहचान के लिए यथेष्ट हो,

(ख) व्यतिक्रमी का नाम,

(ग) बकायों का विस्तृत हिसाब,

(घ) करस्थम् की जानेवाली उपज का प्रकार और अनुमानित मूल्य,

(ङ) स्थान जहाँ वह मिलेगी अथवा वैसा अन्य विवरण जो उसकी पहचान के लिये यथेष्ट हो, एवं

(च) यदि फसल खड़ी हो अथवा जमा नहीं की गई हो तो जब उसे काटे अथवा जमा किये जाने की संभावना हो, उस समय का उल्लेख ।

(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 सन् 1908) में वाद–पत्र हस्ताक्षरित तथा सत्यापित करने के लिये जो रीति विहित है उसी नियमानुसार आवेदन–पत्र को हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जायेगा ।

57–ग. आवेदन–पत्र की प्राप्ति पर प्रक्रिया–(1) अग्रगामी धाराओं के अधीन आवेदन देने के समय आवेदक निबन्धक के पास वैसा लिखित साक्ष्य देगा जो वह आवेदन के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे ।

(2) निबन्धक, उस साक्ष्य को लेने के बाद यदि उचित समझेगा तो आवेदन को ग्रहण अथवा अस्वीकृत करेगा।

(3) जहाँ निबन्धक आवेदन को तत्क्षण ग्रहण अथवा अस्वीकृत नहीं कर सके वहाँ वह, यदि उचित समझे, आवेदन–पत्र में विनिर्दिष्ट उपज को करस्थम् हेतु आवेदन के कार्यान्वयन के लम्बित रहने तक अथवा आवेदन–पत्र की अस्वीकृति तक हटाये जाने से प्रतिषेधनार्थ आदेश दे सकेगा।

(4) जब उपज काटे जाने अथवा संग्रह किये जाने की संभावना के यथेष्ट समय से पहले किसी उपज को करस्थम् के लिए आदेश दिया जाये तो निबन्धक उतने समय तक के लिये आदेश के कार्यान्वयन को स्थापित कर सकेगा जितना समय तक वह उचित समझेगा, और यदि वह आवश्यक समझेगा तो करस्थम् के लिए आदेश के कार्यान्वयन के लम्बित रहने तक उपज को हटाये जाने से प्रतिषेधित करते हुए आदेश कर सकेगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन अथवा उपधारा (4) के अधीन आदेश का तामीला तथा प्रकाशन उस रीति से किया जायगा जो राज्य सरकार नियमावली द्वारा निर्धारित करेगी ।

57–घ. करस्थमादेश का कार्यान्वयन–(1) यदि अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन कोई आवेदन–पत्र ग्रहण किया जाये तथा किसी उपज के करस्थम् के लिए आदेश किया जाये तो निबंधक निर्धारित ब्योरे के साथ उस आदेश की एक प्रति समाहर्त्ता के पास कार्यान्वयन हेतु प्रेषित करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की प्राप्ति के पश्चात् समाहर्त्ता उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपज अथवा उस उपज के किसी वैसे अंश को जो वह उचित समझे, करस्थम् करने के लिए अधिकारी प्रतिनियुक्त करेगा और वह अधिकारी वहाँ जायगा जहाँ वह उपज है तथा वह उस उपज को स्वयं अपने प्रभार में लेकर अथवा अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को उसका प्रभारी बनाकर एवं राज्य सरकार द्वारा उस आश्रय की बनायी गई नियमावली के अनुसार करस्थम् की अधिसूचना प्रकाशित करके करस्थम् करेगा :

परन्तु, वैसी उपज जिसकी प्रकृति संग्रह के योग्य नहीं होगी, काटे अथवा संग्रह किये जाने के योग्य होने के समय से कम–से–कम बीस दिन से पूर्व किसी समय इस धारा के अधीन करस्थम् नहीं की जायेगी ।

57–ङ. माँग तथा हिसाब की तामीली–(1) करस्थम् करने के समय करस्थम् करने वाली अधिकारी व्यतिक्रमी पर करस्थम् करने के आधारों को प्रदर्शित करते हुए हिसाब के साथ बाकी राशि के लिए लिखित माँग तथा करस्थम् में उपगत व्यय तामील करेगा ।

.(2) जहाँ करस्थम् करनेवाले अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि करस्थम् की गई सम्पत्ति का स्वामी व्यतिक्रमी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है वहाँ वह उस व्यक्ति पर उसी तरह माँग तथा हिसाब की प्रतियाँ तामील करेगा।

(3) यथासाध्य माँग और हिसाब व्यक्तिगत रूप से तामील किये जायेंगे, किन्तु यदि वह व्यक्ति जिस पर वे तामील किये जाने है, पलायन कर रहा हो अथवा अन्यथा उपलब्ध न रहा हो तो अधिकारी मॉग और हिसाब की प्रतियाँ उस मकान के बाहर सहजदृश्य भाग में चिपका देगा जिसमें वह सामान्यतः निवास करता है।

57–च. उपज काटने आदि का अधिकार–(1) इस अध्याय के अधीन करस्थम् किसी व्यक्ति को कोई उपज काटने, संग्रह अथवा जमा करने अथवा उसे सम्यरूपेण संरक्षणार्थ अन्य आवश्यक काम करने से प्रतिषेधित नहीं करेगा।

(2) यदि हकदार व्यक्ति उचित समय पर वैसा करने से चूक जाए तो करस्थम् करनेवाला अधिकारी करस्थम्–गत खड़ी फसल अथवा असंगृहीत उपज को पक जाने पर कटवा लेगा अथवा संग्रह करवा लेगा तथा उस तरह की कोटियों में अथवा अन्य स्थानों, पर जिस तरह की कोटियाँ अथवा स्थान उस प्रयोजन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त किये जाते हैं, अथवा पड़ोस में किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर जमा करवा देगा अथवा उसके सम्यक् तरह से संरक्षण के लिए अन्य आवश्यक काम करेगा।

(3) हर हालत में करस्थमगत सम्पत्ति करस्थम् करनेवाले अधिकारी के अथवा उसके द्वारा एतर्थ नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के प्रभार में रहेगी।

57–छ. जब तक माँग का समाधान न हो, विक्रय की उद्घोषणा निर्गत होगी–(1) जब तक करस्थम् के पूरे व्यय के साथ माँग का तुरन्त समाधान हो जाए, करस्थम् करनेवाला अधिकार करस्थम्गत सम्पत्ति के ब्योरे को तथा जिस माँग के लिए करस्थम् किया गया हो उसको विनिर्दिष्ट करते हुए एक घोषणा जारी करके अधिसूचित करेगा कि वह अमुक स्थान पर तथा अमुक दिन को, जो करस्थम् किये जाने के समय से कम–से–कम तीन दिन अथवा अधिक–से–अधिक सात दिन बाद होगा, करस्थम् सम्पत्ति को लोक नीलाम द्वारा बेच देगा :

परन्तु, यदि फसल अथवा उपज इस प्रकार की हो कि उसका भंडारण किया जा सके किन्तु उसका भंडारण उस समय तक नहीं हुआ हो तो विक्रय का ऐसा दिन निश्चित किया जायगा जिस दिन के आने के पहले फसल या उपज भंडारण के लिए तैयार हो जाये ।

(2) जिस गाँव में व्यतिक्रमी की भूमि स्थित हो उस गाँव में किसी सहज दृश्य स्थान पर उद्घोषणा–पत्र चिपका दिया जायगा ।

57–ज. विक्रय–स्थान–विक्रय उस स्थान पर किया जायगा जहाँ करस्थम्गत सम्पत्ति स्थित हो, अथवा लोक निवास के निकटतम स्थान पर करस्थम् करनेवाले अधिकारी की राय में विक्रय करना अधिक लाभप्रद हो।

57–झ. खड़ी फसल कब बेची जायगी–(1) उस फसल अथवा उपज को काटने अथवा जमा करने तथा भंडारण हेतु तैयार होने से पहले नहीं बेचा जायेगा जो भंडारण किये जाने योग्य होगी।

(3) उस फसल अथवा उपज को काटने अथवा जमा करने से पहले बेचा जा सकता है जो भंडारण किये जाने योग्य न हो, एवं क्रेता स्वयं अथवा एतर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर प्रवेश तथा फसल या उपज को सहेजने, काटने अथवा जमा करने के प्रयोजनार्थ सभी आवश्यक कार्य करने का हकदार होगा।

57–ज. विक्रय की रीति–विक्रय करनेवाले अधिकारी के विचारानुसार सम्पत्ति की लोक–नीलाम से बिक्री, एक अथवा अधिक लौट में, की जायगी और यदि सम्पत्ति के अंश की बिक्री से करस्थम् विक्रय के परिव्यय सहित माँग का समाधान हो जाए तो शेष के सम्बन्ध में करस्थमादेश को कार्यान्वित नहीं किया जायगा।

57–ट. विक्रय का स्थगन–यदि, सम्पत्ति के विक्रयार्थ रखे जाने पर (विक्रय करनेवाले अधिकारी के अनुमान में) उचित कीमत न पेश आये, और यदि संपत्ति का स्वामी अथवा उसके द्वारा एतद्ध प्राधिकृत व्यक्ति सम्पत्ति की बिक्री को दूसरे दिन तक, अथवा (यदि विक्रय स्थान पर हाट लगता हो) दूसरे हाट के दिन तक स्थगित करने के लिए आवेदन करे तो उस दिन तक बिक्री स्थगित कर दी जायेगी, और उस दिन बिक्री पूरी कर ली जायेगी चाहे जो भी उस सम्पत्ति की कीमत मिले ।

57–ठ. विक्रय धन की अदायगी–प्रत्येक लौट की कीमत विक्री के समय, अथवा बिक्री करनेवाले अधिकारी के निदेशानुसार बिक्री के तुरन्त बाद, भुगतान कर दी जायगी, और वैसी आदायगी के व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायगी।

57–ड. क्रेता को प्रमाण–पत्र दिया जायगा–जब विक्रय धन की पूरी भुगतान हो जायगी तब विक्रय करनेवाला अधिकारी क्रेता को उसके द्वारा क्रीत सम्पत्ति तथा भुगतान की गई कीमत का वर्णनयुक्त प्रमाण–पत्र देगा।

57–ढ. विक्रय की आमदनी का उपयोग किस प्रकार होगा–(1) इस अध्याय के अधीन करस्थम्गत सम्पत्ति का प्रत्येक विक्रय की आय से विक्रय करनेवाला अधिकारी राज्य सरकार द्वारा करस्थम् तथा विक्रय के परिव्यय की गणना के लिए निर्धारित फीस की दर के सम्बन्ध में समय–समय पर बनाई जानेवाली नियमावली के अनुसार करस्थम् तथा विक्रय का परिव्यय भुगतान करेगा।

(2) शेप का उपयोग उस बाको रकम तथा विक्रय के दिन तक उस पर सूद के संधान पर किया जायगा जिसके लिए करस्थम् किया गया हो तथा बची रकम (यदि बचे) उस व्यक्ति को दे दिया जायगा जिसकी सम्पत्ति बेची गई हो।

57–ण. कुछ व्यक्ति क्रय नहीं कर सकते हैं–इस अध्याय के अधीन सम्पत्ति विक्री करनेवाले अधिकारी तथा उन अधिकारियों द्वारा नियुक्त अथवा उनके अधीनस्थ सभी व्यक्ति एवं निबन्धित सोसाइटियों के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के सदस्य अधिकारियों द्वारा विक्रीत किसी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खरीदने से प्रतिपेधित किये जाते हैं।

57–त. विक्रय के पहले माँग की अदायगी हो जाने पर प्रक्रिया–(1) यदि इस अध्याय के अधीन करस्थम् किये जाने के बाद और करस्थम्गत सम्पत्ति की बिक्री के पहले किसी समय व्यतिक्रमी अथवा करस्थम् सम्पत्ति के स्वामी के रूप में यथार्थ दावा करनेवाला कोई व्यक्ति, यदि वह व्यतिक्रमी न हो, करस्थमादेश कार्यान्वित करनेवाले समाहर्त्ता के पास, अथवा करस्थम् करनेवाले अधिकारी के हाथ में धारा 57–ड. के अधीन तामील की गई माँग में विनिर्दिष्ट रकमों को, माँग की तामीली के बाद उपगत सभी खर्च के साथ, जमा कर देगा, तो यथास्थिति समाहर्त्ता अथवा अधिकारी उसके लिए रसीद स्वीकृत कर देगा एवं करस्थमादेश कार्यान्वित नहीं किया जायगा।

(2) जब करस्थम् करनेवाला अधिकारी जमा रकम प्राप्त कर लेगा तब वह उस रकम को तत्क्षण समाहर्त्ता को दे देगा।

(3) इस धारा के अधीन जमा किये जाने की तिथि से एक मास की समाप्ति के बाद समाहर्त्ता उस जमा रकम में से करस्थमार्थ आवेदक को उसकी बाकी राशि अदाय, करेगा, किन्तु वह तब ऐसा नहीं कर सकेगा जब इस बीच करस्थम्गत सम्पत्ति के स्वामी के रूप में यथार्थ दावा करनेवाला व्यक्ति करस्थम् की वैधता को चुनौती देते हुए तथा उस सम्बन्ध में प्रतिकार का दावा करते हुए आवेदक के विरुद्ध वाद संस्थित कर देगा।

57–थ. जप्ती के अधीन सम्पत्ति का करस्थम्– जब इस अध्याय के अधीन निर्गत करस्थमादेश और करस्थम् के अध्यधीन सम्पत्ति के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय द्वारा निर्गत जप्ती अथवा विक्रय के आदेश में कोई विरोध उत्पन्न हो जाए तो करस्थमादेश अभिभावी होगाय किन्तु यदि उस आदेश के अधीन सम्पत्ति बेच दी जाती है तो बिक्री की अतिरिक्त आय धारा 57–ढ के अधीन सम्पत्ति के स्वामी को उस न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं दीं जायगी जिसने जप्ती अथवा बिक्री का आदेश निर्गत किया है।

57–द. गलत करस्थम् के प्रतिमार के लिए वाद एवं अपील–इस अध्याय के अधीन निवन्धक या समाहर्त्ता द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, किन्तु यदि कोई भी व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति धारा 57–क के अधीन किये गये आवेदन पर वैसे मामले में करस्थम् की गई है, जिस तरह के मामले में उस धारा ने वैसा आवेदन करने की अनुमति न दी हो, तो वह प्रतिकर की वसूली के लिए उस आवेदक के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकेगा :

परन्तु, यदि निबन्धक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक निबन्धक अथवा उपनिबन्धक वैसा आदेश पारित करे तो करे तो निबन्धक के पास अपील होगी और उस अपील पर दिया गया उसका निर्णय अन्तिम होगा।

57–ध, नियमावली बनाने की शक्ति–इस अध्याय के पूर्ववगामी प्रावधानों के अधीन सभी मामलों में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर नियमावली बना सकेगी।

57–न. निर्वाचन–इस अध्याय में, जबतक कोई बात विषय अथवा संदर्भ के विरुद्ध न हो–

(क) ''समाहर्त्ता'' में वह अधिकारी शामिल होगा जिसे राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन समाहर्त्ता के किसी भी कार्य सम्पादन के लिए नियुक्त करेगी।

(ख) '' अतिक्रमी'' से अभिप्रेत है (मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि रूपत) वह व्यक्ति जिसे कोई ऋण अथवा परादेय माँग वसूलनीय हो जैसा धारा 57–क में निर्दिष्ट है,

(ग) ''धृति'' से अभिप्रेत है कृषि अथवा उद्यान के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोई भूमि।]

अध्याय 8

प्रकीर्ण

58. निबन्धक एवं अन्य अधिकारी लोक सेवक हैं–निबन्धक, निबन्धक की शक्तियों का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति, धारा 34 अथवा 36 के अधीन निरीक्षण अथवा धारा 35 के अधीन जाँच के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, परिसमापक तथा मध्यस्थ अथवा मध्यस्थगण जिन्हें धारा 48 के अधीन कोई विवाद निर्दिष्ट किया जायगा, भारतीय दंड संहिता (45 सन् 1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक माने जायेंगे।

59. सोसाइटी की पंजियों से प्रविष्टियों का प्रमाण–(1) कामकाज के दौरान नियमित रूप से रखी गई निबन्धित सोसाइटी की बही, पंजी अथवा सूची में किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि नियमानुसार निर्धारित रीति से प्रमाणित रहे, तो वह उस प्रविष्टि की विद्यमानता के साक्ष्य में ग्राह्य होगी तथा प्रत्येक मामला में जहाँ और जिस परिमाण तक वह बातों, संव्यवहारों तथा लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए मौलिक प्रविष्टि प्रस्तुत किये जाने पर ग्राह्य हुई होती वहाँ और उस परिमाण तक वह बाते, संव्यवहारों तथा लेखाओं के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

(2) वैसी सोसाइटियों के मामले में, जिनके विषय में राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष निदेश करे, सोसाइटी के किसी अधिकारी को किसी वैसी वैधिक कार्यवाही में, जिसमें सोसाइटी पक्ष न हो, सोसाइटी की कोई भी वैसी बही प्रस्तुत करने, जिसकी विषयवस्तु को उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित किया जा सके, अथवा उसमें अभिलिखित, बातें, संव्यवहारों तथा लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने को विवश नहीं किया जा सकता जबतक न्यायालय अथवा न्यायाधीश विशेष हेतुक से ऐसा आदेश न दें।

60. अपील सुनने की शक्ति का प्रत्यायोजन– राज्य सरकार[1] [XXXX] इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपील की सुनवाई की अपनी शक्ति को सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

61. पंजीकृत सोसाइटियों का सहकारी परिसंघ में अनिवार्य सम्बंधन–2[(1) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार राज्य की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियाँ वैसी रीति से तथा उन शर्त्तों पर बिहार को–ऑपरेटिव फेडरेशन से सम्बद्ध होगी जो रीति तथा जो शर्त्त इस प्रयोजनार्थ नियमावली द्वारा निदेशित की गयी हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन बिहार को–आपरेटिव फेडरेशन के संगठन तथा कार्यों को विनियमित किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन अनिवार्य सम्बन्धन का प्रावधान है।

62. पंजीयन की अध्यापेक्षाओं से विमुक्ति–(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के प्रत्येक मामलों में विशेष आदेश के द्वारा तथा वैसे शर्त्तों के अध्यधीन, जैसे शर्त्त यह अधिरोपित करेगी, किसी सोसाइटी को इस अधिनियम की पंजीयन सम्बन्धी किसी अध्यापेक्षा से विमुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी निबन्धित सोसाइटी को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान से विमुक्त कर सकेगी, अथवा निदेश दे सकेगी कि अमुक प्रावधान अमुक सोसाइटी के प्रति वैसे उपांतरणों के साथ लागू होगा जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट रहेंगे।

63. परिसीमन– भारतीय परिसीमन अधिनियम, 1908 (9 सन् 1908) में किसी प्रावधान के होते हुए भी निबन्धित सोसाइटी के किसी सदस्य से बाकी ब्याज सहित ऋण के लिए परिसीमा की अवधि की गणना उस तिथि से की जायगी जिस तिथि को उस सदस्य की मृत्यु हुआ हो अथवा सोसाइटी की सदस्यता समाप्त हो गई हों।

64. आयकर, मुद्रांकन शुल्क तथा पंजीयन शुल्क से विमुक्त करने की शक्ति–(1) शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके केन्द्र सरकार किसी निबन्धित सोसाइटी एवं निबन्धित सोसाइटियों के वर्ग के मामले में सोसाइटी के मुनाफा अथवा मुनाफा के कारण सोसाइटी के सदस्यों द्वारा प्राप्त लाभांश अथवा अन्य अदायगियों के सम्बन्ध में संदेय आयकर को माफ कर सकती है।

1. शब्द ''धारा 26, 40 एवं 41 में अपील की सुनवाई की शक्ति को छोड़कर'' बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा विलोपित ।
2. प्रतिस्थापित तत्रैव ।

(2) अधिसूचना जारी करके संग्राहक सरकारकिसी निबन्धित सोसाइटी एवं निबन्धित सोसाइटियों के वर्ग के मामले में निम्नांकित को माफ कर सकती है–

(क) पंजीकृत सोसाइटी या उसके किसी अधिकार एवं सदस्य के द्वारा अथवा उसकी ओर से निष्पादित लिखत और ऐसी सोसाइटी के कारबार अथवा ऐसे लिखतों के किसी वर्ग, अथवा रजिस्ट्रार अथवा किसी परिसमापक अथवा परिसमापकगण के इस अधिनियम के अधीन निर्णयों, अधिनिर्णयों अथवा आदेशों से सम्बन्धित तत्समय प्रभार्य मुद्रांक शुल्कय तथा

(ख) तत्समय प्रवृत्त निबन्धन विधि के अधीन संदेय कोई शुल्क ।

इस उपधारा में '' संग्राहक सरकार'' से वही अभिप्रेत है जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (2 सन् 1899) में अभिप्रेत है।

टिप्पणी

[सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी किसी तरह के दस्तावेज के लिए मुद्रांक शुल्क देने से मुक्त है। पाटलीपुत्र को–ऑपरेटिव सोसाइटी हाउस कन्स्ट्रक्शन सोसाइटी लि० बनाम बिहार राज्य, 1977 बी०बी०सी० जे० 78]

65. पंजीकृत सोसाइटी के शेयर एवं डिबेन्चर से सम्बन्धित लिखतों की अनिवार्य निबंधन से विमुक्ति–भारतीय निबन्धन अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) की कंडिका (ख) और (ग) की कोई बात निम्नांकित पर लागू नहीं होगी–

(1) किसी पंजीकृत सोसाइटी की आस्तियाँ सम्पूर्णतः अथवा अंशतः अचल सम्पत्ति के रूप में होने पर भी इस सोसाइटी में शेयरों से सम्बन्धित किसी लिखत, या

(2) जहाँ तक किसी डिबेंचर के धारक के लाभ के लिए न्यास पर न्यासियों को सोसाइटी द्वारा उसकी पूरी या थोड़ी अचल सम्पत्ति के बंधकित, हस्तांतरित या अन्यथा अन्तरित करनेवाले किसी निबन्धित लिखित के जरिए प्रदत्त प्रतिभूति का धारक हकदार हो, वहाँ तक छोड़कर अचल सम्पत्ति पर अथवा में किसी अधिकार, हक या हित को परिसीमित अथवा समाप्त करते हुए असृजित, अघोषित करनेवाले सोसाइटी द्वारा निर्गत कोई डिबेंचर, अथवा

(3) किसी ऐसी सोसाइटी द्वारा निर्गत किसी डबेंचर का अन्तरण अथवा उस पर पृष्ठांकन ।

टिप्पणी

[निबंधक को जिस प्रकार निर्वाचन सम्बन्धी किसी मुकदमे को अन्तरित करने का अधिकार है ठीक उसी तरह राज्य सरकार को निर्वाचन सम्बन्धी मुकदमे निबंधक से ले लेने का अधिकार है। राज्य सरकार में सहकारी विभाग का मंत्री शामिल है।]

65–क.[1] [XXXX]

[2][**65–ख. कठिनाई दूर करना**–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार परिस्थिति के अनुसार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश के जरिये, कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो।]

66. नियम बनाने की शक्ति– राज्य सरकार इस अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रयोजन के सम्पादनार्थ सम्पूर्ण राज्य अथवा उसे किसी भाग के लिए एवं किसी पंजीकृत सोसाइटी अथवा पंजीकृत सोसाइटियों के वर्ग के लिए नियम बनाना।

(2) पूर्वगामी शक्ति की सर्वसाधारणतः पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम विशेषकर–

(i) सोसाइटी के पंजीयन के लिए आवेदन के प्रपत्र या पालनीय शर्त्त और वैसे आवेदन के विषय में प्रक्रिया विहित करनाय

(ii) प्रवेशार्थ आवेदन करनेवाले या सदस्य रुप में प्रविष्ट व्यक्तियों द्वारा पालनीय शर्त विहित कर सकेंगे एवं सदस्यों के प्रवेश तथा निर्वाचन, तथा सदस्यता के अधिकारों के प्रयोग के पहले की जानेवाली अदायगी तथा अर्जित किये जानेवाले हितों का प्रावधान करना,

1. ''धारा 65 क'' बिहार अधिनियम 10, 2002 द्वारा विलोपित ।
2. बिहार अधिनियम 31, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(iii) किसी सोसाइटी के सदस्यों की अधिकतम संख्या विहित करनातथा धारा 29 के प्रावधानों के अध्यधीन किसी सदस्य द्वारा सोसाइटी में धारित शेयरों की अधिकतम संख्या अथवा पूँजी का भाग विहित करना,

(iv) सदस्यों के पदत्याग की स्वीकृति के शर्त विहित कर सकेंगे, तथा सदस्यों के निष्कासन एवं सदस्यता त्यागने वाले अथवा निष्कासित किये जानेवाले सदस्यों की अदायगी विहित कर सकेंगे,

(v) सदस्यों की साधारण बैठक तथा वैसी बैठक में प्रक्रिया एवं वैसी बैठक में प्राप्त शक्तियों का प्रावधान करना,

(vi) सोसाइटी जिन विषयों के सम्बन्ध में उपविधियाँ बनायेगी अथवा बना सकेगी उन विषयों तथा उपविधियों के निर्माण, परिवर्तन तथा निराकरण में अनुसरित प्रक्रिया, एवं वैसा निर्माण, परिवर्तन अथवा निराकरण से पहले पूरे किये जानेवाले शत्तों को विहित करना,

(vii) उस रीति को विहित करेंगे जिस रीति से प्रबन्ध समितियाँ अथवा उनकी उपसमितियाँ ख'' धारा 14 'क' उप–धारा (1) के अधीन अथवा अन्यथा गठित प्राधिकार द्वारा निर्वाचन संचालित होगा'',, तथा प्रबन्ध समितियों के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, निलम्बन और निष्कासन के लिए, या प्रबन्ध समितियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जानेवाली शक्तियों तथा सम्पादित किये जानेवाले कार्यों के लिए प्रक्रिया का प्रावधान करना,

(viii) उन शत्तों को विहित कर सकेंगे जिनके अधीन किसी सोसाइटी के व्यतिक्रमी सदस्य को उसकी प्रबन्ध समिति में नियुक्त करने से किसी सोसाइटी को प्रतिषेधित किया जायगा एवं उस सोसाइटी में सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने की उसे स्वीकृति अथवा अन्य सोसाइटी में प्रतिनिधित्व करने के अधिकार विहित करना,

(ix) जब सोसाइटी अपना दायित्व का स्वरुप अथवा परिणाम बदले तो उसके लिए प्रक्रिया विहित कर सकेंगे, तथा सोसाइटियों के एकीकरण और विभाजन के लिए प्रावधान कर सकेंगे एवं वैसे एकीकरण और विभाजन के शत्तों को विहित करना,

(x) उन शर्तों एवं बन्धेजों को विहित कर सकेंगे जिन पर तथा उस रीति को विनियमित कर सकेंगे जिसके अधीन शेयर, जमा अथवा डिबेंचर से अथवा अन्यथा निधियाँ अर्जित करना,

(xi) ऋण हेतु आवेदन करनेवाले सदस्यों द्वारा पूरा किये जानेवाले शर्त, जिस अवधि के लिए ऋण दिया जा सकेगा वह अवधि, दी जा सकनेवाली ऋण राशि तथा ऋण लौटाने की रीति विहित करना।

(xii) सोसाइटी की नियंत्रणाधीन किसी निधि का निक्षेपण अथवा निवेशन के लिये प्रावधान करना,

(xiii) उन शत्तों, प्रतिषेधों एवं प्रतिबन्धों को विहित कर सकेंगे जिनके अध्यधीन सोसाइटी–

(क) गैर–सदस्यों से कारबार करना, अथवा

(ख) चल सम्पत्ति के प्रति अग्रिम देना,

(xiv) काम–काज पूँजी तथा शुद्ध लाभ की गणना का तरीका, उस लाभ के वितरणार्थ शर्तें, तथा किसी सोसाइटी अथवा सोसाइटियों के वर्ग द्वारा संदेय लाभांश को अधिकतम दर विहित करना,

(xv) आरक्षित निधियों का निर्माण एवं अनुरक्षण तथा उन निधियों को जिन वस्तुओं पर लगाया जाए उन वस्तुओं के लिए एवं डूबंत ऋणों के अपलेखन के लिए प्रावधान कर सकेंगे,

(xvi) शेयर–धन की वापसी एवं शेयरों के अन्तरण के लिए शर्त्त विहित करना,

(xvii) उस तरीका का प्रावधान कर सकेंगे जिसके अनुसार मृत सदस्य के हित का मूल्य निर्धारण तथा उस व्यक्ति का मनोनयन होगा जिसे वैसा हित दिया अथवा अन्तरित करना,

(xviii) सदस्यों की पंजी तथा, जहाँ सदस्यों का दायित्व शेयरों के जरिए सीमित हो वहाँ शेयर तथा शेयरधारकों की पूँजी के निर्माण एवं अनुकरण के लिए प्रावधान करना,

(ix) सोसाइटी द्वारा प्रयोग किये जानेवाले प्रपत्रों, रखी जाने वाली लेखाओं और पंजियों एवं समर्पित किये जाने वाले प्रतिवेदन और विवरण समर्पित किये जायेंगे उनका एवं वैसे किसी प्रतिवेदन अथवा विवरण को समर्पित करने से चूकने की दशा में उन सबकी तैयारी पर व्यय के उद्ग्रहण का प्रावधान करना,

(xx) धारा 33 के अधीन अंकेक्षण एवं सोसाइटी की आस्तियों और दायित्वों को प्रदर्शित करते हुए तुलन–पत्रों के आवधिक प्रकाशन से लिए नियम विहित कर सकेंगे,

1. बिहार अधिनियम 18, 2008 द्वारा अन्तः स्थापित ।

(xxi) जिन व्यक्तियों के द्वारा एवं जिन प्रपत्रों में सोसाइटी के अभिलेखों और पंजियों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियों को प्रमाणित किया जायगा उनका एवं वैसी प्रतिलिपियों की आपूर्ति के लिए उद्‌गृहीत किये जाने वाले शुल्कों का प्रावधान करना,

(xxii) अभिलेखों एवं पजियों को अभिरक्षित करने तथा नष्ट करने का प्रावधान करना,

(xxiii) परिसमापक की नियुक्ति अथवा निष्कासन, तथा उसके पारिश्रमिक के भुगतान में अपनाई जानेवाली प्रक्रिया का प्रावधान करना,

(xxiv) परिसमापक द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे तथा सोसाइटी के किसी अधिशेष के निस्तार की रीति का उपाय करना,

(xxv) इस अधिनियम के अधीन अपील करने तथा उसके निस्तार के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया विहित करना,

(xxvi) मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति में, रजिस्ट्रार (अथवा निबन्धक की शक्तियों का प्रयोग करता हुआ किसी व्यक्ति) तथा मध्यस्थ अथवा मध्यस्थगण के समक्ष कार्यवाही में, साथ–साथ मामलों के अन्तरण, निर्देशन एवं प्रत्याहरण में, अपनाई जानेवाली प्रक्रिया विहित करना,

(xxvii) धारा 49 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगार्थ प्रक्रिया एवं शत्त विहित कर सकेंगे,

(xxviii) घारा 24–क के अधीन उत्तमणों की बैठक बुलाने, करने तथा संचालन के लिए प्रक्रिया विहित करना, एवं

(xxix) इस अधिनियम में नियमावली से विहित किये जानेवाले स्पष्टतः अध्यापेक्षित अथवा अनुमत सभी विषयों का प्रावधान करना,

[1][“(xxx) सदस्यता शुल्क की रीति विहित कर सकेगी एवं सदस्यता शुल्क हेतु अंशदान के लिए वित्तीय सहायता के साथ–साथ महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग सदस्यों जो किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों के खास वर्ग अथवा वर्गों से सम्बन्ध रखता हो, के न्यूनतम हिस्सा–पूँजी का प्रावधान कर सकेंगे।”

(3) इस धारा में प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति प्रकाशन के पश्चात् बनायी गई नियमावली के शर्त्ते के अध्यधीन रहेगी।

(4) इस धारा के अधीन बनायी गई सभी नियमों का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन किया जायगा एवं इस प्रकाशन के बाद वे ऐसे प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित हुये हों।

[2][**66–क. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, लघु कृषक, सीमांत कृषक और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए सहकारी ऋण के अनुपात का निर्धारण**–ऐसे निदेशों के अधीन जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जायें, प्राथमिक कृषक सहकारी सोसाइटी सहकारिता वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियोंध्अनुसूचित जन जातियों, लघु और सीमांत कृषकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच कुल उधार का ऐसा अनुपात सवितरित करेगी, जो रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा, सोसाइटी के वर्ग और उपर्युक्त वर्गों के व्यक्तियों की सदस्य संख्या को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अधिकथित किया जाय ।

उक्त सोसाइटी उपर्युक्त वर्गों को उधार देने के सम्बन्ध में पृथक लेखा रजिस्ट्रार द्वारा विहित रीति से रखेगी।

[3][**66.ख. सहकारी समितियों की कार्मिक नीति**–(1) सहकारी समितियों को, अपनी उपविधियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, समिति के कार्मिकों के पदों के स्वरूप और संख्या तथा कार्मिकों की भर्ती की रीति अवधारित करने की स्वायत्तता होगी। इस प्रयोजनार्थ सहकारी समिति अपनी कार्मिक नीति बना सकेगी। सहकारी समितियाँ अपनी उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति के अधीन रहते हुए अन्य के बीच निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगीः–

(1) पात्रता, आयु और अनुभव,

(2) वेतनमान और अन्य उपलब्धियाँ,

(3) भर्ती की रीति,

(4) सेवा की शत्ते, और

(5) अपनाई जानेवाली अनुशासनिक प्रक्रिया।

1. बिहार अधिनियम 18, 2008 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2. विहार अधिनियम 39, 1982 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2. बिहार अधिनियम सं० 6, 2013 दिनांक 22–05–2013 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपविधियों के प्रावधानों एवं कार्मिक नीति का अतिलघन में की गई नियुक्ति शून्य समझी जायेगी माना ऐसी नियुक्ति कभी विद्यमान नहीं थी एवं वेतन तथा अन्य भत्तों के रूप में किये गये भुगतान की राशि यदि कोई हो, धारा 40 के अधीन वसूलनीय होगी।''

टिप्पणी

[संकल्प दिनांक 9—2—1989 द्वारा गठित समिति के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह राज्य भर में जाकर विभिन राज्य स्तरीय सहकारी समितियों में नियुक्तिध्प्रोन्नति करे। निगम नियुक्ति या एवं नियमितिकरण और प्रोन्नति के लिए की पहचान करे और फिर समिति के पदाधिकारियों के पास आवश्यक नियुक्ति नियमि भेजे। प्राथी के नियमितिकरण और प्रोन्नति साफ तौर से धारा 66 वी के प्रतिकूल था, अतः वापस लिए गए। प्रशासक को चाहिए कि वह संकल्प दिनांक 6—2—1989, जो सवैधानिक रूप से वैध है, के अलोक में निगम के आवश्यकता आधारित पदों की पहचान करे और उपयुक्त और विधिमान्य नियुक्तियाँ करे। **राम कुमार सिंह बनाम बी०एस०एस०सी०कॉप० डेव० कारपोरेशन कारपोरेशन लि०**, 2002 (2) पी०एल० जे० भार० 744।

धारा 66 बी और अधिसूचना दिनांक 9—2—1989 संविधान सम्मत हैं। बिहार राज्य सहकारिता बैंक में किसी पद पर नियुक्ति विभागीय अधिसूचना व अधिसूचना दिनांक 9—2—1989 के प्रावधानों के अनुसार ही की जा सकती है। प्रतिनियुक्तियों का बैंक की सेवा में अंतर्विलयनधनियमितिकरण अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। **प्रिय रंजन सिन्हा बनाम बिहार राज्य**, 2002 (3) पी०एल० जे०आर० 33।

राज्य सरकार ने नियुक्ति की पद्धति निर्धारित करते हुए दिनांक 9—2—1989 को अधिसूचना के माध्यम से एक नियुक्ति—समिति गठित की है। पूर्व में न्यायालय ने धारा 66 बी की शक्ति और अधिसूचना की वैधता की पुष्टि की। प्रार्थी के पूर्व में किये गये नियमितिकरण और प्रोन्नति को अधिसूचना का सर्वथा उल्लंघन माना गया और प्रार्थी की पूर्व रिट—याचिका भी खारिज कर दी गई। पुनः प्रार्थी की उसी पद पर तदनन्तर की प्रोन्नति और नियमितिकरण को वैध नहीं धारित किया जा सकता, क्योंकि समिति द्वारा वैसा नहीं किया गया था। नियुक्ति समिति के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा 9—2—1989 के बाद की गई कोई भी नियुक्तिध्प्रोन्नतिधनियमितिकरण अधिसूचना का उल्लंघन है। तथापि प्रशासक को निर्देशित किया जाता है कि वह आवश्यकता आधारित पदों को पहचान करें और अधिसूचना दिनांक 9—2—1989 के अनुसार सीधी भर्ती या पूर्व के पदधारकों के नियमितिकरण या प्रोन्नति के द्वारा उपयुक्त और विधिसम्मत नियुक्ति के लिए कार्रवाई करें। **राम कुमार सिंह बनाम बी०एस०सी०सी०डी० कारपोरेशन लि०**, 2002 (3) पी०एल० जे०आर० 202 ।

केन्द्रीय सहकारिता बैंक जिनमें लोक लेखा समितियाँ सम्बद्ध हैय विनिर्दिष्ट लेखा खोलकर लोक लेखा समियितों के प्रबन्धकों को वेतन अदायगी की पद्धति में परिवर्तन लोक लेखा समितियों के कामकाज में सुधार की कड़ी है और इससे सेवा—शर्त्तें में कोई फेरबदल नहीं होता है। **बिहार राज्य सहकारिता प्रबंधक संघ बनाम बिहार राज्य**, 2003 (3) पी०एल० जे०आर० 322 ।

सहकारी समितियों पर विस्तृत नियंत्रण रखता है और इस तरह से सहकारी समितियाँ वास्तव में राज्य की प्रशासनिक अंग का काम करती हैं। अतः राज्य सरकार वास्तव में लोक लेखा समितियों के प्रबन्धकों की सेवा—शर्त्तों को नियंत्रित करती है और उनके वेतनमान भी निर्धारित करती है। अतः उनका वेतन राज्य सरकार निर्धारित करती है जो जीवन—यापन स्तर पर होता है। अतः महँगाई भत्ता देकर मूल्यवृद्धि के विरुद्ध सुरक्षा देने से इन्कार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। **बिहार राज्य सहकारिता प्रबन्धक संघ बनाम बिहार राज्य**, 1999 (3) पी०एल० जे०आर० 110 ।

यद्यपि लोक लेखा समितियों के प्रबंधक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, फिर भी भारत के नागरिक होने के नाते न्यायोचित और उपयुक्त वेतन दिया जाना लाजिमी है। अतः उनका वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है न कि वेतन आयोग जैसा विशेषज्ञ निकाय द्वारा। अतः उन्हें महँगाई भत्ता आदि के लिए राज्य सरकार के सेवकों के समान सुविधा मिलनी चाहिए। इससे इनकार करना उचित नहीं है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत से जुड़े कल्याणकारी राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करना अनुचित, गलत और असंवैधानिक है। लोक लेखा समितियों के प्रबन्धक राज्य सरकार के कर्मियों के समान महंगाई भत्ता के हकदार हैं। **तत्रैव** ।

सहकारी समिति के उपाध्यक्ष द्वारा वर्ग 3 और 4 पदों पर कर्मियों की नियुक्ति। राज्य सरकार के परिपत्र द्वारा निबंधित समितियों के लिए विनिश्चित प्रक्रिया का उल्लंघन करके की गई प्रतयेक नियुक्ति अवैध होगी। **अंजनी कुमार सिंह बनाम प्रबंधक, जमुई केन्द्रीय सहकारिता बैंक लि०**, 1994 (2) पी०एल० जे०आर० 761।

बिना विभागीय कार्यवाही शुरू किए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के शाखा प्रबंधकों के वित्तीय वर्ष के लिए ऋणों की वसूली के लिए निरूपित मानकों को प्राप्त करने में विफलता के कारण सेवा की समाप्ति। मात्र कारण पृच्छा नोटिस का तामीला नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का सम्पूर्णतः अनुपालन नहीं है। **कपिलेश्वर शर्मा बनाम बिहार राज्य**, 1993 (2) पी०एल० जे०आर० 552 ।

बिहार सरकार राज्य भर में सभी सहकारी समितियों पर अधिकारिता लागू करने को सक्षम है। अतः इसे निश्चय ही नियुक्ति के लिए मापदंड और भर्ती की पद्धति निरूपित करने का कानूनी अधिकार है और ऐसे मामले धारा 66 के परिक्षेत्र के अन्तर्गत हैं। **राँची जिलाध्कैडर सहकारी समिति लि० बनाम पी०ओ०**, 1998 पी०एल० जे०आर० 591

राज्य सरकार को सहकारिता बैंक द्वारा दी गई नियुक्तियों को रद्द करने में सक्षम नहीं है। धारा 66 बी राज्य सरकार को भर्त्ती आदि के सम्बन्ध में आम नीति निर्धारित करने का अधिकार है। सहकारिता बैंक के विशेष पदाधिकारी (राज्य सरकार के कार्यकारी) द्वारा राज्य सरकार के निदेश के अनुपालन करते हुए बैंक के अस्थायी कर्मचारियों की सेवा–समाप्ति के आदेश को विशेष पदाधिकारी का आदेश नहीं कहा जा सकता। **शिवशंकर प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य**, 1987 पी०एल० जे०आर० 270 ।

चयन प्राधिकरण की संरचना और चयन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई तालिका से भिन्न किसी सूत्र से की गई नियुक्ति के विरुद्ध रोक लगाने सम्बन्धी अधिसूचना की वैधता निःसन्देह वैध है। **तेजा प्रसाद बनाम बिहार राज्य**, 1992 (2) पी०एल० जे०आर० 568 ।

प्रार्थी उस नियुक्ति आदेश के तहत् अपने अधिकारों का दावा करते हैं जो अधिनियम की शर्त्तों के तहत् पहले से शिथिल है। ऐसी नियुक्ति का कोई अस्तित्व आरंभ से ही नहीं है। तत्रैव ।

प्रार्थीगण पहले दैनिक वेतनभोगी के और बाद में उनकी नियुक्ति नियमित आधार पर, आपेक्षित आदेश से इस आधार पर रद्द कर दी गई कि ये नियुक्तियाँ पूर्व में अधिसूचित शासकीय आदेश के विपरीत थीं। अधिनियम में उपबन्धित स्पष्ट वर्जना के होते हुए यह धारित करना कठिन है कि चयन की निर्धारित पद्धति और प्रक्रिया या मापदण्डों के अनुपालन किये बिना और किसी अन्य सूत्र से नियमित नियुक्तियाँ की जा सकती हैं। मात्र इस वजह से कि चयन प्राधिकरण का पूर्णतः गठन नहीं हुआ था । **तत्रैव**।

इस धारा की शक्तिमत्ता को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि विधायिका द्वारा बिना किसी संकेत के कि अधिनियम का उल्लंघन किन–किन बातों से होगा, अथवा इसका विस्तार क्या हैय यह धारा राज्य सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है और नैसर्गिक न्याय के नियम को दरकिनार करती है। जब किसी न्याय–निर्णयन की आवश्यकता हो और प्राधिकरण के पास विवेकाधिकार के लिए कोई अवयव हो। यदि स्वयं विधायिका कतिपय कोटियों की नियुक्तियाँ रद्द और घोषित करती हो, तो न्याय निर्णय सर्वथा अनावश्यक हो जाता है। नैसर्गिक न्याय के नियम कानूनी नियम नहीं है, जिसका प्रयोग वर्जित नहीं हो सकता यदि इसकी वर्जना आवश्यक निहितार्थ से भी अनुमतेय हो । प्रावधान को मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। **तत्रैव** ।

कर्मचारी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, बाद में धारा 66 बी की अवहेलना के आधार पर बरखास्तगी। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई कानूनी प्रावधान यह अधिकार सरकारी परिपत्रों से निष्पादित होती हैं। सरकारी परिपत्र कानूनी आदेश को अभिभूत नहीं कर सकता। धारा की कसौटी पर ऐसी नियुक्ति को सामान्य नियुक्ति से अन्तर करना कठिन है। वह सिर्फ इस बात का हकदार है कि उसके मामले पर एक भिन्न वर्ग के रूप में विचार किया जाए, क्योंकि इस जैसी नियुक्ति अनुच्छेद 14 और 16 में अंतर्विष्ट सामान्य नियमों का अपवाद–स्वरूप है। **तत्रैव** ।

कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई (वेतन या भत्तों के रूप में प्राप्त) धन को वापस नहीं लिया जा सकता । नियोजक प्रत्येक विधिक, गैर–निःशुल्क काम या सेवा के लिए प्रतिकर देने को बाध्य है। यदि किसी व्यक्ति ने वस्तुतः कार्य किया हो, तो उसे उसके द्वारा वास्तविक रूप में प्राप्त या प्राप्य परिलब्धियों से वंचित नहीं किया जा सकता । **तत्रैव** ।

वेतन भुगतान स्थगित किया गया। धारा 66 बी के अन्तर्गत विधिवत् नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को वेतन नकारा नहीं जा सकता है। राज्य सरकार केवल पदों की प्रकृति एवं सृजित संख्या का निर्धारण करने के लिए तथा पैक्स के के मैनेजर के वेतन भुगतान का तरीका जो केन्द्रीय सहकारी अधिकोष शाखा में विशेष खाता खोलकर किया जा सकता है, देखने के लिए अधिकृत है। यह बिलकुल ही नहीं अवधारित करता है कि विधितः नियुक्त एवं उचित तरीका से कार्यरत् कर्मचारी को बिना वेतन भुगतान के इतनी लम्बी अवधि तक रहना पड़े। **योगेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य**, 2004 (4) पी०एल० जे०आर० 448 (पटना)।

निबंधक अथवा सचिव, सहकारिता विभाग के द्वारा कार्य करने वाली सरकार को निर्देश निर्गत करने का वैध एवं मान्य अधिकार है। ऐसे निर्देशों की वैधानिक स्थिति है तथा इस हद तक यह राज्य में निबंधित अनेक प्रकार को समितियों पर बाध्यकारी है। **श्याम किशोर सिन्हा बनाम बिहार सरकार**, 2007 (3) पी०एल० जे०आर० 830।

धारा 66–बी–सहकारी समिति के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 की जाती है, इस शर्त के अध्यधीन कि वैसे कर्मचारी जिन्हें गबन, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता अथवा धोखाधड़ी के आरोप में सजा हो चुकी हो, उन्हें इस बड़ी हुई आयु सीमा के लाभ से बाहर रखा जाएगा। यह सुस्थापित है कि एक ही आरोप में एक व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी सकती। आवेदनकर्ताओं को 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किया जा रहा है, क्योंकि उनकी सेवा पुस्तिका में यह उल्लिखित है कि उन्हें पूर्व में दण्डित किया जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के अधीन विहित गारण्टी एवं संरक्षण का उल्लंघन किया गया है। पुनः ऐसी सजा से युक्त सेवा नियमावली में संशोधन के अभाव में इस क्षेत्र में आदेश को व्यापक नहीं बनाया जा सकता है। और यह भी कि, जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान है, तो सजा के एक–दूसरे भाग का सृजन करते हुए कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने का कोई अवसर नहीं है। वह भी केवल इस आधार पर कि बहुत पहले उसे कोई सजा दी गई थी। आगे यह भी कि, कर्मचारियों की वार्धक्य सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति की दो आयु सीमा नहीं हो सकती। आक्षेपित खण्ड को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 20 (2) का उल्लंघन माना गया तथा इसे अधिकार का अतिशय (अतिक्रमण के हद तक) प्रयोग माना गया। अतः इसे खारिज किया जाता है। आवेदकों को सभी लाभों के साथ सेवा में पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है तथा वे सेवा में 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक बने रहेंगे। **श्याम किशोर सिन्हा बनाम बिहार सरकार**, 2007 (3) पी०एल० जे०आर० 8301

धारा 66–बी–दुग्ध सहकारी समिति (कोमफेड) के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि। राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने से इंकार करना। धारा 66–बी को एक वैध विधायन माना गया है। नियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति के मामले में विभिन्न सहकारी समितियों को निर्देश निर्गत करने का अधिकार राज्य सरकार को है तथा समिति के अधीन काम करने वाले कर्मचारी इन निर्देशों से प्रशासित होंगे। ये निर्देश ''कोमफेड'' सहित सभी सहकारी समितियों पर लागू होंगे। ''कोमफेड'' के निदेशक पर्षद् द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष तक नहीं बढ़ाने का निर्णय मनमाना एवं अवैध है तथा इसे खंडित किया जाता है। निर्देश दिया जाता है कि उनकी सेवा में फिर से बहाली की जाए तथा वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उसमें बने रहेंगे। कोमफेड को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की स्वतन्त्रता दी जाती है, यदि बाद में वे यह पाएँ कि आवेदकों ने सचिव द्वारा विहित शर्त्तों को पूरा नहीं किया हो। **राम नारायण सिंह बनाम बिहार सरकार**, 2007 (3) पी०एल० जे०आर० 214 ।

धारा 66–बी–पी०ए०सी०एस० के पेड मैनेजर (संदत्त प्रबंधक) को वेतन। ऐसी समितियों का पी०ए०सी०एस० के रूप में काम करने के संबंध में राज्य सरकार पर कोई जवाबदेही नहीं लादी जा सकती। ऐसी समितियों को अपना कोष सृजित करना है तथा प्रबंधकों को वसूली एवं जमा प्राप्त करना है। **शैल देवी बनाम बिहार सरकार**, 2007 (1) पी०एल० जे०आर० 533।]

67. **निरसन**–इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम एतद् द्वारा, जहाँ तक वे राज्य पर लागू हैं, उक्त अनुसूची के चौथे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट परिमाण तक निरसित किया जाता हैं।

अनुसूची

निरसित अधिनियम

(धारा 67 देखें)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षक	निरसन का परिणाम
1	2	3	4
1912	II	सरकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912	
1920	XXXVIII	नयागमत्ता अधिनियम 1920	जहाँ तक उसका संबंध 1912 के अधिनियम ।। से है ।

The Bihar
Co-operative Societies Act, 1935

[Act VI of 1935]

[29th May, 1935]

An Acts to consolidate and amend the law relating to Co-operative Societies in the State of Bihar[2]*[(x* xx)

Preamble.--Whereas it is expedient to facilitate the formation, working and consolidation of co-operative societies for the promotion of thrift, self help and mutual aid among agriculturists and other persons with common needs and for that purpose to consolidate and amend the law relating to co-operative societies in the State of Bihar [2][(xxx)

And whereas previous sanction of the Governor-General under sub-section (3) of section 80-A of the Government of India Act has been obtained to the passing of this Act;

It is hereby enacted as follows :

CHAPTER! *Preliminary*

1. Short title and extent.--(1) This Act may be called the Bihar Co-operative Societies Act, 1935.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

Comments & case-law

{The whole gamut of this Act and the Rules framed thereunder as also the model Byelaws for the co-operative societies would show in the ultimate analysis, that they rested on the larger principles of co-operation which are sought to be codified and given a legalistic form by the statutory provisions. The golden web that runs through the fabric of the co-operation movements is that of self-help and mutual help through democratic management and a conscious eschewing of the profit motive. Every member, regardless of number of shares he owns, has only one vote to further this concept. *Harender Narain Banker vs. State of Bihar,* 1985 PLJR 1078.

The preamble, the scheme and other available material must be examined to see if there are any discernible guidelines. Power granted to State Government to exempt a Co-operative society from application of provisions of the Act or application **of** its provisions with modification will not make that provision void on the ground of excessive delegation. *Registrar of Co-operative Societies v. K. Kunjabmu,* AIR 1980 **SC** 350: (1980) 1 SCC 340.

The Act virtually provides a complete Code for both election to the Board of Directors of the Co-operative movement; and the resolving of election disputes in appellate forum. The object is to promote self help, non-profit motive and democratic

legislative papers-For Statement of Objects and Reasons, See the B & 0. Gazette **1934,** Pt. V. p. 106; for report of the Select Committee, see ibid, 1935 Pt. V, p. 65; and for proceeding in Council, see B & 0, Legislative Council Debates, Vol. XXXI, p. 225 and Vol. **XXXII,** pp 603 and 665.

local Extent-See sl. (2).

2. Omitted by Act 5 of 1989.

working thereof evidenced by electoral process. *Chandeshwar Prasad vs. State of Bihar,* 1987 PLJR 159 (FB.) :1987 BRLJ 55 :AIR 1987 Pat 208.

Co-operative Societies Act cannot be challenged on the ground that the protection afforded by Article 31 A (1)(c) was not available to co-operative societies. Protection of Article 31 (1) (c) cannot be said to be not available on the ground that interest of co-operative,society may not necessarily be in public interest. *Daman .Singh vs. State of Punjab,* AIR 1985 SC 973.

Power to order amalgamation of a co-operative society of which an individual is a member, with another society cannot Be remotely held to offend the dignity of a human being so as to offend the basic structure of the Constitution within the meaning of Article *20ibid.*'.. "

An exemption granted in favour of all buildings belonging to Co-operative societies from the provisions of Rent Control Laws cannot be said to be discriminatory and violative of Article 140 of Constitution of India. *S.M. Mahendra vs. State ofTamil Nadu,* AIR 1985 SC 270 : (1985) 1 SCC 395.

In a field where both Central and State legislation is envisaged under the constitution, the fact of legislation by Parliament does not necessarily mean that the field has become occupied, thereby ousting the State Legislature's competence to pass any law in respect of the matter. Both Central and State Acts can operate in the same field if they are. not found to be repugnant or inconsistent with each other. *Mohan Mishra vs. State of Bihar,* 1996 (2) PLJR 171. ,

There can be no fixed connotation in regard to co-operative societies. The concept of co-operation as enshrined in the parent Act is a concept derived from the statute and not from the constitution. The picture that has emerged by the Statute can always be altered by statute by the law making body. It cannot be contended that the frame work of the co-operative ·societies is a. basic structure of the. Constitution and are, therefore, unalterable by the State legislature. If the fundamental of co-operative laws are derived from State legislation, it cannot be doubted for a· moment that the State legislature has the jurisdiction to alter the nomenclature of the co-operative societies. The. history of co-operative legislation itself shows that there is no fixed connotation of co-operative societies. It is well known that initially a cooperative society was formed on the basis of co-operation of individuals. The next . step was the concept of incorporation of co-operative societies, that brought in the State. With the State having come in the picture, the concept relating to charge of liability was introduced. With the power of the legislature to make laws, care the provision of liability of the members. Initially, the liability of members was unlimited. Then came the concept of liability limited by shares. Co-operative Societies Act now recognises limited liability of co-operative societies as well as unlimited liability of· co-operative societies. Promotion of co-operative societies has now been included in the directive principles of the Constitution. The State have been enjoined to act in a manner so as to promote the concept of co-operation. It would thus be seen that there is no fixed, concept in regard to the co-operative societies. The concept has been changing from time to time. In that view of the matter, one cannot jusifiably contend that there was fixed notions guiding co-operative societies. But, by this, it should not be misunderstood that the democratic principles' may be completely waived or done away within the matter of functions of co-operative societies. It is, therefore, unsound at the threshold to contend that the amendments are annihilative

of the concept of co-operative societies. The right of voluntary and autonomous asscciation or the right to democratic control and self management or the right to equality is managing the affairs of society has not been annihilated by the Ordinances. They have only been placed within chartered channels consistent with public interest. The conclusion therefore, is that the Ordinances do not lack legislative competency. They are clearly enactments falling within item 32 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution. They do not fall within item 43 of List I. Competencewise they are valid pieces of legislation. *Sheetal Prasad Gupta vs. State of Bihar,* (1990) 1 BLJ 493 (FB).

Legal fictions are only for a definite purpose and they are limited to the purpose for which they are created and should not be extended beyond the legitimate field. *3engal Immunity Co. Ltd. vs. State of Bihar,* AIR 1955 SC 661.

Where the Statute enacts that something is to be deemed to exist or some status be deemed to have been acquired which would not otherwise have been so, full effect must be given to the fiction but not so as to extend it beyond the purpose for which it was created. *Bindesh Kumar Singh vs. State of Bihar,* 1995 (1) PLJR 86; *State of Travancore-cochin vs. S. V.C.F.,* AIR 1953 sc333..

Where the language is plain and unambiguous and admits of only one meaning no question of construction or interpretation of the provision arises, for the State speaks for itself. *State of U.P. vs. Vijay Anand Maharaj,* AIR 1963 SC 946; *Ramsakha Singh vs. State of Bihar,* 1992 (2) PLJR 598.

The removal from Membership of Managing Committee of Co-operative society on ground of default in repayment of loan within the prescribed period is contemplated under the Rules. *Jai Karan Singh vs. State of Haryana,* AIR 1996 P & H 67.

The prescribed procedure under the.Act must be strictly followed in case of expulsion of a Member, and notice to show cause must also be given. *Smt. Sarla Devi vs. Shailesh,* AIR 1996 Bom 98.

Restrictions imposed by Registrar, Co-operative, on Co-operative Societies, requiring purchases of machinery to be made through Regional Agro Industries Development Co-operative Ltd. are justifiable, when in public interest *George Kokkattummdayil vs. Joint Registrar,* AIR 1996 Ker 26.

Review.--Power of review has been given only to Registrar, Co-operative Societies, and is vested in State Government under the Assam Act. *C.B.K. Fishery Co-operative Society Ltd.: vs. State of Assam,* AIR 1996 Gau 23.

Reservation of seats for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and others cannot be in addition to total strength of Board of Directors provided Linder law. *H.L. Roche vs. Citizen Co-operative Bank, Ltd.* AIR 1996 Bom. 126.

Scope.--Societies registered under this Act cannot claim priorities over those societies registered under 1996 Act in the matter of settlement of Jalkars. *Simri Bakhtiarpur Prakhand Matsyajivi Swablambi Sahkari Samiti Ltd. vs. State of Bihar,* 2005(3)PLJR68.]

2. Definitions.---In this Act, unless there is anything repugnant in the subject orcontext

(a) 'bye-laws' means the registered bye-laws for the time being inforce and includes a registered amendment of the bye-laws;

(b) · 'Co-operative Federation' means a registered society the main object of which is to co-ordinate and facilitate the activities of other registered societies and to foster the growth of the co-operative *movement;*

1 [(bb) 'Co-operative Year' means a year beginning with the [1st April] and ending on the [31st March;]

3·{(c)Sec. 2] 'financing bank' means the State Bank of India, a nationalised Commercial Bank, a State Co-operative Bank, a Co-operative Bank, a Development Bank, a Regional Rural Bank or any other bank to be notified by the State Government the objects of which include the crea tion of funds out of which money is to be lent to the co-operative societies or other institutions or both;]

5[(ccc) "Government" means State Government of Bihar."

(d) 'liquidator' means a person or persons appointed by the Registrar un der sub-section (1) of Section 44 to wind up the affairs of a registered society;

4["(e) "Board" means Board of Directors or Governing Body or Managing Committee by whatever name it is called to whom the management of the affairs of a Co-operative Society is entrusted;"

(f) 'member' includes a person joining in the application for the registra tion of a society and a person admitted to membership after registra tion in accordance with the rules and the bye-laws of such society;

4(ff) 'Multi-purpose Co-operative Society' is a primary society formed for providing more than one type of service to its members and includes a society registered as a Cane-growers' Co-operative

1[(fff) 'nominal or associate member' means a member who possesses such privileges or rights of a member of a society, and who is subject only to such liabilities of a member as may be specified by the bye-laws;]

(g) "Officer" includes a chairman, secretary treasurer, member of a manag ing committee or any other person empowered by or under this Act, or the rules or the bye-laws of registered society to give direction in regard to the business of the Society;

6["(go) "Office-bearer" means a President, Vice-president, Chairperson, Vice-chairperson, Secretary or Treasurer of a Co-operative Society and in-eludes any other person to be elected by the Board of any Co-operative Society."

1(ggg) 'primary society' is a society of which no member is a registered soci ety;]

'[(gggg) 'Primary agricultural credit society' means a co-operative society, the primary object of which is to render assistance, financial or otherwise, to farmers, rural artisans and agricultural labourers and includes farmers service society and multipurpose co-operative society;]

(h) 'registered society' means a society registered or deemed to be regis tered under this Act;

(i) 'Registrar' means a person appointed to perform the duties of Registrar of Co-operative Societies under this Act;

---

1. Ins. by Act 39 of 1982.
2. Subs. by Act 5 of 1989
3. Subs. by by Act. 39 of 1982
4. Ins. by Act 21 of 1976
5. Ins. by Act 18 of 2008.
6. Subs by Act 6 of 2013

6 Subs by Act 6 of 2013

(j) 'rules' means rules under this Act.

'[(k) Family" means husband, wife and their dependent sons and unmarried daugners as unit."

2[(k) "Short Term Co-operative Credit Structure" includes the State Co-operative Bank, Central Co-operative Banks and the Primary Agricultural Credit Societies.

(m) "National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural DevelopTent established under Section 3 of National Bank for Agriculture and Rural DevelopTent Act, 1981 (Act 61 of 81).

(n) "Reserve Bank" means Reserve Bank of India established under Section-3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act No. 2 of 34).

(o) "Affiliating Society" means a registered society of which another registered society is a member; and "affiliated society" means a registered society, which is a member of an "affiliating society".

(p) "Panchayat" means the Gram Panchayat notified as per Section-11 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 and amendments made thereto from time to time."

[3]["(q) "General Body" means all the members or delegates of all the members of that Co-operative Society collectively;

"(r) "Functional Directors" means functional executive directors of the Society specified in Rules or Bye-laws of that Co-operative Society;"

"(s) "Backward Classes" means and includes the fist of Backward Classes of citizens specified in Annexure-2 of the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 (Bihar Act No. 3, 1992), as amended from time to time;"

"(t) "Extremely Backward Classes" means and includes the list' of Backward Classes of citizens specified in Annexure-t of the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 (Bihar Act No. 3, 1992), as amended from time to time;"]

Comments & case-law

[Member of Joint family joining society whether represents entire joint family? From the bye-law that if a certain member of a joint family becomes a member of the soceity no other member of the family can afterwards become a member of the *society,* it does not follow that if a member of the family joins the society he must necessarily join the society as representing the entire joint family and not in his individual capacity. It simply means that more ttian one member of a Join family cannot join the society, the intention being to prevent separate debts being contracted by different members of the joint family which have meant a great drain upon funds of the society. *Lalji Bhagat vs. Hansdin Co-operative Society,* LPA No. 14 of 1942, dated 28.10.1942 Pat.

Where neither the Act nor the rules framed thereunder confer power on the Cooperative society to amend its bye-laws with retrospective effect, any amendment made in the bye-laws of a Co-operative society will have prospective effect only. *C.I. T. vs. Bizpur Co-operative Sugar Factory Ltd.,* (1988) 3 sec 533.

The Supreme Court left open the question as to member of primary society is competent to raise dispute touching business of a Central Society of which the primary society is the member. *Tara Chand vs. Zamindar Co-operative Marketing-cum-Processing Society Ltd.,* AIR 1980 SC 1663.

"Person aggrieved"-Meaning of---Defamation---Manager of Co-operative Bank--Section 500 oflndian Penal Code--AIR 1950 Pat. 545.

A Co-operative society is not a statutory body because it is not created by a statute. ft is a body created by a group of individuals in accordance with the provisions of a statute. A cooperative society is, therefore, not a Corporation, established by or under an Act of Central or State Legislature. *S. S. Dhanoa vs. Municipal Corporation,* AIR 1981 SC 1395: 1981 BBCJ (SC) 206 : (1981) 3 sec 431.

A Co-operative society is not a 'State' within the meaning of Article 12 of the Constitution. Hence, a writ petition by non-employee of a co-operative society challenging his termination of service is not maintainable. *Harendra Narain Banker vs. State of Bihar,* 1985 PLJR 1078. see also *Chakradhar Patel vs. Samasingha Service Co-op. Society,* AIR 1982 Orissa 38.

1: Ins. by (Arndt.) Act 10 of 2002.
2. Ins. by Act 18 of 2008
3. Ins by Act 6 of 2013

CHAPTER II *Registration of Societies*

6. The Registrar.---(1) The State Government may appoint a person to be Registrar **of** Co-operative Societies for the State or any portion of it, and may appoint persons to assist such Registrar.

2 The State Government may, by general or special order published in the ocia Gazette, confer--

(a) on any person appointed under sub-section (1), to assist the Registrar, all or any of the powers of the Registrar under the Act except the powers under Section 26, 2[xxx] [and]

4[(b) on any Co-operative Federation or Financing Bank all or any of the powers of the Registrar under Section 20, sub-section (3) of Section 28, Section 33, Section 34, Section 35 and Section 36.

'[(3) Where the State Government is of opinion thatthe Registrarneeds the assistance of Additional Registrar for speedy disposal of business, it may by order published in the official gazette, appoint such number of Additional Registrars as it may deem fit].

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of the Act, the Registrar may delegate, transfer or assign to the Additional Registrar· such of his powers and functions and duties as he may consider necessary including the power under sections 26 and 50 and the Additional Registrar shall, thereupon have powers of Registrar in matters so delegated, transferred or assigned to him]

Comments & case-law

[Powers of Joint Registrar to review judgments. *Jahanabad Consumers Co-op. Stores vs. State of Bihar,* 1959 BLJR 298 : ILR 38 Pat. 877.

An order conferring Registrar's power on Assistant Registrar by Gazette notification could not have a retrospective effect. *Achyuta Nand Singh vs. State of Bihar,* 1972 BRLJ (Rev.) 15: AIR 1971 SC 2001 : 1972 PLJR 146.

Assistant Registrar if conferred with powers of Registrar for deciding dispute under section 48(1). The Assistant Registrar would be deemed to be persons assisting the Registrar within the meaning of section 6(1) and exercising powers of the Registrar within the meaning of section 6(2)(a). *Raghav Jha vs. Registrar, Co-op. Societies,* AIR 1983 Pat. 137 : 1983 BRLJ 7s.

A person appointed to assist the Registrar is entitled to exercise all or any of the powers of the Registrar under the Act except under Section 26, such Assistant Registrars are entitled by statutory operation to exercise the power under the Act conferred by the State Government except to the extent expressly excluded by the statute. *Yogendra Prasad vs. Additional Registrar,* 1992 (1) PLJR 6 (S.C.)]

Section 6 makes a clear distinction between the exercise of powers of the Registrar by the Additional Registrar as a delegate of the Registrar and or the Assistant Registrars or Deputy Registrars appointed to provide assistance to the Registrar and empowered as such in the discharge of their functions under the Act. Such subordinate Officers are empowered by Statutory operation to exercise the powers under the Act conferred by the State Government except to the extent expressly excluded by Statute. *Yogendra Prasad vs. Additional Registrar,* 1992 (1) BLJ 1 (SC).]

1. Ins. by Act 39 of 1982.
2. Omitted by Act 29 of 1956.
3. Subs. by ibid.

7.Societies which may be registered.--'(1) Subject to the provisions of the Act, a Co-operative Society constituted in accordance with the provisions of the said Act as amended from time to time, which has as its object, the promotion of the common interest of its members in conformity with the co-operative principles and securing the fulfilment of any or all directives contained in Part IV of the Constitution of India, may be registered under this Act with or without limited liability."

Provided that, unless the State Government by general or special order otherwise directs-

(a) the liability of a society of which a member is a registered society shall be limited; and

(b) the liability of a society of which the primary object is the creation of funds to be lent to its members, and of which the majority of the members are agriculturists, and of which no member is a registered society, shall be unlimited.

(2) Where the liability of a society is limited, the liability of each member, past member, or the estate of a deceased member shall on liquidation, be limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by such member, or where the liability is limited by guarantee, to the amount of such guarantee, or where it is limited in any other manner, then as may be determiend by the rules or bye laws subject, however, to the provisions of section 32.

(3) Where the liability of a society is unlimited, all members, past members, and the estates of deceased members shall on liquidation, be jointly and severally liable for and in respect of all its obligations, subject, however, to the provisions of section 32.

8. Conditions of registration.--(1) No society, other than a society of which a member is registered society, shall be registered under this Act which does not consist of at least ten persons above the age of eighteen years and, where the primary object of the society is the creation of tunas to be lent to its

. members, unless such persons (a) reside in the same town or village or in the same group of villages; or (b) save where the Registrar otherwise directs, are members of the same tribe, class or occupation.

2**[(1A)** The State Government may by notification in the official Gazette reduce the minimum number of membership of 10 persons for particular class of Co-operative Socieites.]

3[(1b) Notwithstanding anything contrary contained in Bihar Co-operative Societies Act, 1935 or any other Bihar Act or' Rules framed thereunder or ye laws of a Co-operative Society or class of Co-operative Societies or any order issued by the State Government or Registrar of Co-operative Societies, there shall be only one registered Fishermen Co-operative Society in a Block with its area of operation extending over the whole Geographical limit of the Block.]

(2) The word "limited" shall be the last word in the name of every society with limited liability registered under this Act.

Comments & case Law

[Sections 8 and 41 (b) read with Rules 8 to 10 and bye-laws-reduction of the area of *thana* resulting in taking out the residence of some members of the society-termination of membership of such members and subsequent supersession of the Managing Committee which comprised of some membefS from above-since the registration of the society was thanawise the result of reduction of the area of the *thana* in question would be that its area of operation) S also reduced-consequently those persons whose residence falls out of the revised area of *thana* would automatically cease to be members-question of amendment of bye-laws before termination of their membership not necessary in view of language employed in the bye-law. *Bhawanipur Fishermen's Co-operative Society vs. State of Bihar,* 1995(1) PLJR 366.]

1. Subs. by (Arndt.) Act 10 of 2002.
2. Ins. by Act 39 of 1982.
3. Ins. by Act 22 of 2010.

9. Application for registration.-(1) An application for the registration of a socsty sale made to the Registrar, and shall be accompanied by a copy of the proposeed *bye*-laws of the society and the persons by whom or on whose behalf such application is made shall furnish such information in regard to the society as the Registrar may require.

(2) The application shall be signed-

'[a) if none of the applicants is a registered society by at least ten persons or less number of persons qualified in accordance with the requirements of sub-section (1) or sub-section (1-A) of section 8']

2[Provided that applicants, either male or female, shall be from different families :

(b) if any of the applicants is a registered society, by a duly authorised person on behalf of every such registered societies, and where all the members of the society are not registered societies by ten other members or, where there are less than ten other members, by all of them.

3[(3) The following shall be attached to such applications :

(a) Four copies of the proposed bye-laws of the Cooperative Society as adopted by the founder members

(b) A list containing names of members with their address, occupation and share participation.

(c) A list containing names of the persons of first Board as elected by the founder members.

(d) True copy of the resolution of the meeting duly signed by the Chairman in which the Bye Laws have been adopted.

10. Power of Registrar to decide questions.-When any question arises whether for the purposes of this Act a person is an agriculturist, or non agriculturist, or whether any person is resident in a particular town or village or group of villages, or whether two or more villages shall be considered to form a group or whether any person belongs to any particular tribe, class or occupation, the question shall be decided by the Registrar, whose decision shall be final.

Comments & case-law

[Registrar is vested with powers to pass order of appointment of special officers for interim period where holding of annual general meeting for election of office-bearers of society has been stayed by High Court. Such order is not illegal or without jurisdiction. *Nawal Kishore Prasad Sinha vs. State of Bihar,* 1982 PLJR 376 : AIR 1983 Pat. 8]

11. Registration.---4[(1) If the Registrar is satisfied that a society has complied with the provisions of this Act and Rules and that its proposed bye-laws are not contrary to this Act or to the Rules, he may register the Society and its bye-laws. And_he will send by registered post to the organiser/promoter of the Society, within

1. Subs. by Act 39 of 1982.
2. "Proviso" ins. by Arndt. Act 10 of 2002.
3. Sub-section (3) ins. by ibid.
4. Subs. by ibid.

90 days from the date of submission of. application, a registration certificate and original copy of the registered bye-laws duty sealed and signed by him.

(2) If in the opinion of the Registrar, the conditions stipulated under sub-section (1) above appear not to have been complied with, within 90 days of the presentation 'of the application before him, he shall record. reasons for refusal and refuse to register the society and send this decision by registered post to the organiser/ promoter. In the event of the refusal not being sent within the stipulated period, the Society shall be deemed registered and in such a situation the Registrar within one month thereafter shall ·send by registered post, the registration certificate for deemed registration alongwith original copy of the registered bye-laws duly sealed and signed.

.(3) In the event where the organiser/promoter has received the refusal order in accordance with the provisions of sub-section (2) or has not received registration certificate of deemed registration an appeal shall lie to the Registrar if the refusal order has been passed by an officer appointed to assist the Registrar under subsection 2{a) of section 6 of this Act and to the State Government if such order has been passed by the Registrar himself :

Provided that such appeal shall lie within sixty days from the receipt of the refusal order or within sixty days from the expiry of th~ prescribed period of communication in case of deemed registration. (4) If in the opinion of the Registrar, the organiser/promoter has got a society registered by fraud or mistake, then the Registrar shall appeal to the State Government· for cancellation of the said registration.

Provided that such appeal may be filed within sixty days from the registration order.

Comments & case-law

[Removal of servant on ground of shrinkage of work-previous approval of Registrar is not necessary.

Wher the petitioner who was holding a post of Credit. Agricole Inspector under Bihar State Co-operative Bank, was removed from his service on the ground of shrinkage in business, it was held that the order of removal was not illegal as the Board of Directors of the Bank had power under the bye laws and regulations of the Bank to terminate the services of any officer when no longer, required on giving three months notice or pay in lieu thereof. Previous approval of the Registrar of Co operative Societies is not necessary for the removal. *Chaturbhuj Sahai vs. Chairman,* AIR 1955 Pat. 223.

Sections 11 (1), 14(2) · and 25 of the Act show that the constitution of the Managing Committee must be made in accordance with the rules, and the bye-laws made by any society must conform to the Act and the Rules. Bye-laws made in contravention of the Act and the Rules will be invalid and cannot prevail over the rules. 1959 Pat. LR 175 : 1959 BLJR 38.

An act beyond the object mentioned in the memorandum is ultra vires. But if the act done is fairly incidental, reasonably ancillary to its main business, conducive

to the statement of the objects, unless such an act is expressly prohibited, it cannot be held to be ultra vires. The acquiring of land for cultivating and procuring good quality seeds by a Society carrying on business of distribution of seeds to agriculturists is not prohibited by bye-laws. *Gajadhar Prasad Choudhary vs. State of Bihar,1983 PLJR* 662: AiR1984 Pat. 105.]

1[“1**1A. Registration of societies not registered under this Act.--**Where a society registered under section 5 of the Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act, 1996 intends to convert itself into a co-operative society under this Act, it nay apply for registration under provisions of this Act in accordance with procedure o be, prescribed and notified by the Government.

2[11B. Notwithstanding anything contrary contained in any provision of Bihar Act VI of 1935 or any other Act, Rules made thereunder and Bye-laws of a regis tered Co-·operative Society or class of Co-operative Societies, any order issued by the State Government or Registrar, Co-operative Societies, all existing Fishermen Co-operative Societies at block level, area of operation being confined to the Geographical limit of, the Block shall stand merged in one Co-operative society and shall be deemed to be registered as a new Co-operative Society under Bihar Act VI of 1935, and the. Registrar, Co-operative Societies shall issue registration certificate:

Provided that on such reorganisation, all members of the existing Co-operative Society or Societies registered under Bihar Act VI of 1935 or Bihar Self Supporting Co-operative -Societies Act, 1996 shall be deemed to have become members of such reorganized Society and shall have all rights and liabilities as members of the said Society:

Provided further that on such reorganisation, for managing the affairs of the_©Y Society and all such affiliating Societies of which the Fishermen Co-operative Society is a member, the Registrar/Government shall constitute an ad hoc Managing 5mimittee for a period not exceeding one year, within which the new Managing Committee shall be constituted after elections."]

12. Evidence of registration.-A Certificate of registration signed by the Registrar shall be conclusive evidence that the 'society therein mentioned is duly TQ96 tered unless it is proved that the registration of the society has been cancelled .

. CHAPTER III .-

Incorporation, Duties and Privileges of Registered Societies

13. Societies to be bodies corporate.--The registration of a society shall render it a body corporate by the name under which it is registered, with perpetual succession and a common seal and with power to acquire and hold property, to enter into contract, to institute and defend suits and other legal proceedings and to do all thing necessary for the purposes for which it is constituted.

3**[13-A, Promotion of Co-operative movement by Government.--"(1)** It shall be the duty of the State Government to encourage and promote the voluntary forma tion, autonomous functioning, democratic control and professional management of Co-operative Societies in the State and to take such steps in this direction as. may be necessary. .

(2) To encourage and promote the Co-operative Society, the State Government, if it deems necessary, may-

(a) With a view to aid the growth of a Co-operative Society in general or of any class of registered societies subscribe directly to the share capital of a Co-operative Society;

(b) assist in the formation and augmentation of the share capital of a Co-operative Society;

(c) give roans or make advances to a Co-operative Society or guarantee repayment of principal amount and payment of interest on debentures issued' by a Cooperative society or guarantee repayment of principal amount and payment of interest on loans or advances to a Co-operative Society."

1. Ins. by Act 18 of 2008.
2. Ins. by Act 22 of 2010.
3. Subs. by Act 6 of 2013.

[1][13B. Display of Name.--Every Co-operative Society shall display name and address of its registered office as registered under the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 in legible letters and at such conspicuous places of every such office where it carries its business and in the following also:

(a) Every information and authorised publication;

(b) All contracts, business, letters, indents, Invoice, Statements of accounts, Money receipts, Vouchers etc : ,

(c) All Bills of Exchange, Promissory Notes, Endorsements, Cheques and pay orders which are signed by it or on its behalf.

(2) Every registered Society must have the word/words "Co-operative" and "Limited/unlimited" in its name in State language or synonymous words of other languages recognised in the State list.

Comments & case Law

[Sections 13-A, 66B read with Rule 33 of Bihar Co-operative Societies Rules, 1959---amendment in the Act in 1989 by which certain class of societies qualify as 'State' within the meaning of Article 12 of the Constitution---but such societies were not so before 1989 Amendment--- therefore, appointments made in 1987 cannot be challenged for the alleged violation of Articles 14 and 16 of the Constitution because at that time the society was not a 'State'-accordingly no writ can lie in the matter. *Ajay Kumar Mishra* vs. *Registrar, Co-operative Societies,* 1995(2) PLJR 397 .]

14. Registered societies to have a managing committee etc.--(1) Every registered society shall have an address, registered in accordance with rules, to which all notices and communications may be sent, and shall send notice, in writing to the Registrar and to the financing bank, if any, of which it is a share holder and to the Co-operative Federation, if any, of which it is member, of any change in the said address within fifteeri days of such change,

2[(2) The management of registered Society shall be vested in managing committee constituted in accordance with the provisions of this Act and rules/byelaws of the society made under this AGL.

Notwithstanding any thing contained in any provision of this Act or Rules Byelaws of the Society the maximum number of members including office bearer or office bearers in a managing committee of Society shall be seventeen in Apex and State level Society, fifteen in Central Co-operative Society and thirteen in Primary Society:

4["Provided that there shall be reservation of two seats for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, two seats for the Backward Classes and two seats for the Extremely Backward Classes on the Board of every Co-operative Society:

Provided further that for the purpose of reservation of seats as in the above proviso, the State Government may, by general or special order, exclude the Board of societies or class of societies not consisting of individuals as members or not having members from above categories of reservation:

Provided further that the total number of seats so reserved shall not exceed fifty per cent of the total number of seats:

Provided further also that as nearly as but not exceeding fifty per cent of the total number of seats so reserved shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the Extremely Backward Classes, as the case may be:

Provided further also that as nearly as but not exceeding fifty per cent of the total number of seats not reserved above for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the Extremely Backward Classes shall be reserved for women:

Provided further also that the total number of seats so reserved for women shall not be less than two.

The seats so reserved shall be filled up from amongst the members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, Backward and Extremely Backward Classes and women either by election or/ and by co-option. This provision shall apply to all societies from the Primary Society and up to the Apex societies:

pProvided further also that such reservation in Primary Society and up to the Apex Society shall be governed by the Rules made under this Act for this purpose."

[3][(3) An Officer of the State Government if deputed to a registered society either as a Managing Director, Executive officer or in similar position shall be the Chief Executive thereof and subject to general direction and control of the Managing Committee, shall have the following powers and functions;

(i) to have general control over the administration of the registered society;

(ii) to convene meetings of the Managing Committee;

(iii) to receive all moneys and securities on behalf of the registered society and to make arrangement for the proper maintenance and custody of cash balances and other properties of the registered society;

1. "Sec. 13B" Ins. by (Arndt.) Act 10 of 2002.
2. Subs. by ibid.
3. Ins. by Act 5 of 1989.
4. Subs by Act 6 of 2013

(iv) to endorse and transfer promissory notes, Government and other Securies and to endorse, sign and negotiate cheques and other negotiable instrument on behalf of the registered society.

(v) **to** be responsible for the general conduct, supervision and management to the day-to-day business and affairs of the registered society;

(vi) to sign all deposits, receipts and operate the accounts of the registered society with Bank .

(vii) to sign all bonds and agreements on behalf of the registered society;

(viii) to determine the powers, duties and responsibilities of the employees of the registered society;

(ix) to appoint, promote, transfer, punish, suspend, remove or dismiss any paid employee of the registered society except to the extent of the powers vested in the Managing Committee under the bye-laws of the registered society;

(x) to institute, conduct, defend, compound or to withdraw any suit or other legal proceedings for or against the registered society and also to compound and allow time for payment to satisfaction of any claims; .

(xi) to delegate all or any of the powers to an employee or employee of the registered society subject to his control and supervision;

[1][(4) [3][(a) Notwithstanding any thing contained in any provision of this Act, or of rules framed there under or the bye laws of any registered Society where the State Government has subscribed directly to the Share Capital of a registered Society an amount exceeding Rupees Thirty Lakh, in that case the State Government shall have the right to nominate three persons as members on the Managing Committee of that Society :

Provided that among the members so nominated two will be from the Government service and the third one will be an officer of Cooperative/ Financing Institution connected with the affairs of the Society.

Provided further. that those *ex-officio* members as provided in the bye-laws of the society shall be counted in the quota/numbers fixed/provided for nomination.

Provided further also that such nominated members shall participate in any meeting of the managing committee or ordinary general meeting of the share holders of the registered Society, convened in accordance with the provisions of the Act and Rules framed thereunder and its bye laws. They shall have right to vote in the meeting of the managing committee but shall have no right to vote in the ordinary general meeting of the share holders."

[3]["(4)(b) Notwithstanding anything contained in any provision of this Act, or Rules framed thereunder or the Bye-laws of any Co-operative Society, persons having experience in the field of banking, management, finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the Co-operative Society may be coopted to the Board of the Society:

Provided that the number of such co-opted members shall not exceed two and that number shall be in addition to the specified maximum number prescribed in the subsection (2.):

Provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the Co-operative Society in their capacity as such members or to be eligible to be elected as Office-bearers of the Board:

Provided further also that the Functional Directors of a Co-operative Society shall also be the members of the Board and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of Directors specified in the sub-section (2.)"

[2][(5) Notwithstanding any thing contained in any provision of this Act, Rules made there under and bye laws of the Society the existing members and office bearers nominated by the Government shall cease to be a member of the managing committee within ninety days of the publication of this Amendment Act in the official gazette; and such registered society shall have elections to the vacant posts for the remaining period of its term;

1. Sub-Section (4) "Subs. by (Admt) Act 10 of 2002.
2. Sub-section (5) subs. by ibid.
3. Sub-Sec. 4 renumbered as 4(a) and 4(b) Ins by Act 6 of 2013.

Bihar Co-operative Societies Act, 1935

Provided further that in superseded societies the Administrator of the Society shall constitute new managing committee by election within twelve months from the date of publication in the official gazette of this Amendment Act 2002; otherwise the Registrar shall appoint a new Administrator for a further period of three months and get the managing committee constituted by election.

[1][xxx]

[2][(7) Notwithstanding the provisions of re-numbered sub-section (9) the nominated members of the Managing Committee including the Chairman shall hold office durinc the pleasure of the State Government.] ,

3[xxx]

[4]["(9) Notwithstanding anything contained in any provision of Rules or the Bye-laws of any Co-operative Society the term of office of elected members of the Board and its_ Office-bearers shall be five years from the date of election and the term of Office-bearers shall be co-terminus with the term of the Board:

Provided that the Board may fill a casual vacancy on the Board by nomination out of the same class of members in respect of. which the casual vacancy has arisen, if the jerm of the Board is less than half of its original term:· '

Provided further that if the term of the Board remains for more than half of its. original term and if any vacancy arises for elected members or Office-bearers for any reason whatsoever, the Bihar State Election Authority shall fill the vacancy for remaining period by holding by-election." ,

[4]["(1 0) If for any reason Bihar State Election Authority has failed to conduct the election of the Board in any Co-operative Society where Government has provided share capital or loan or financial assistance or any Government guarantee, the Board shall be deemed automatically superseded from the date of expiry of its term and the Registrar, Co-operative Societies shall appoint any person· as Administrator for a period of not more than six months for getting the new Board constituted by election. The Administrator so appointed shall provide every possible help to the Bihar State Election Authority to, conduct the election. This arrangement shall be' an interim arrangement arid the Adrlf istrator shall hand over the management of the Society to the new Board after election within the prescribed period: · · ·

Provided that where the Government has not provided share capital or loan or, financial assistance or any Government guarantee and where the Bihar State Election Authority fails to conduct elections before the expiry of the term of the Board, the Registrar of the Co-operative Societies may order to convene a special Gene!@} Meeting of the members, for appointing an ad-hoc Board for the purpose of conducting elections:

pProvided further that the outgoing members and Office-bearers of Board shall TO! be included in ad-hoc Board for the purpose of conducting elections:

Provided further also that the term of ad-hoc Board so appointed shall not exceed six months and the ad-hoc Board so appointed shall provide every possible help to the Bihar State Election Authority to conduct the election.

This arrangement shall be an interim arrangement and such appointed ad-hoc Board shall hand over the management of the Society to the new Board after election within the prescribed period."

(11) Every registered society shall keep open to inspeition free of charge at all resonable times at its registered address-

(a) a copy of this Act.

(b) a copy of the rules governing such society

(c) a copy. of the bye-laws of such society, and (d)a register of its members;

3[xxx]

1. "Sub-Section (6)" "repealed by (Admt) Act of 2002.
2. "Sub-section (7), (9) & (10) subs. by ibid.
3. Sub-Section (8) and proviso to sub-section(11) omitted by ibid.

4, Subs by Act 6 ot2013.

The restraints contained in Section 14(1) are in public interest and are not vulnerable to any serious challenge. *Sheetal Prasad Gupta vs. State of Bihar,* (1990)1 BLJ 493 (FB).

It cannot be accepted that the amendments by the ordinance have no nexus with the Preamble to the Ordinances. The amendment are in relation to co-operative societies and for putting them financially on sound footing. It cannot therefore, be contended that the provisions of Section 14(4) of the Ordinance are not in accordance with the Preamble to the Ordinances or that they are not law for the purpose of placing co-operative societies financially on sound footing. Further, whether the amendment is in consonance with the preamble or not has to be judged from the provisions of the Statute itself. It cannot be judged with reference to political public statements. **A** politician may have various reasons of their own for making particular statement in public. They have to cater to public whims. **A** court of law, therefore, is not concerned with public statement which are for consumption of politicians and people at large, rather the Court concerned with the statute itself to find out whether the amendments have any nexus with the objective of the Ordinance. Judged by those standards, it is manifest that there is no clash between the avowed and the real objectives. The amendments, therefore, cannot be said to be pieces of colourable legislation. *Sheetal Prasad Gupta vs. State of Bihar,* (1990)1 BLJ 493 (FB).

The third proviso to Section 14(4) lays down that the State Government shall nominate members of the Managing Committee including the Chairman as far as possible from amongst the persons (i) having interest in co-operative movements, (ii) having knowledge and experience of organizing or managing Co-operative societies or (iii) having experience of general administration, or (iv) is the member of such registered society, or (v) is or was associated with the administration and implementation of the Bihar and Orissa Act VI, 1935. From this, it cannot be contended that these categories are foreign to the objectives of sound management of co-operative societies. The categories mentioned nomination are based on sound footing. It is well known that there is not in the present situation in Bihar in regard to the co-operative societies. Persons who have been at the helm of affairs have been more concerned about enriching themselves rather than attending to the well being of the share holders and farmers. The State Government lacks the power of taking effective measures to stem that rot. That has called for amendments clothing the State Government with the power to control the management. It is obvious that Sections 13(A) and 14 of the Act are provisions in the interest of society for their better management. They are, therefore, in public interest. *Sheetal Prasad Gupta vs. State of Bihar,* (1990)1 BLJ 493 (FB).

The appointment of an Administrator is a kind of interim arrangement in cases where either the Managing Committee ceases to exist by lapse of time without holding elections within the stipulated period, or is superseded under sub-section (1) or sub-section (5) of section 41. *Ramsakha Singh vs. State of Bihar,* 1992 (2) PLJR **598.**

Sub-section (8) of section 14 provides that no person shall be eligible for election or nomination as an "Office-bearer" of the Managing Committee if he has been an "Office-bearer" of the Managing Committee for two consecutive terms of office. Section 14 (9) provides that not withstanding anything contained in the Rules or Bye-Laws, the term of the Members and Office-bearers of Managing Committee of a registered Co-operative Society shall be three Co-operative years. A person who

was nominated or co-opted in place of an elected member who died during the currency of his terms of office cannot have a term of office for full three co-operative years from the date of his nomination or co-option. His term will come to an end when. The managging Committee's term is completed. *Shambhu Prasad Roy vs. State of Bihar, 995(1).* **PLJR**319. 6.

The language of sub-section (10) of section 14 is quite clear and is quite clear and is quit unambiguous. It provides that concequence envisaged therein will set in only if the elections for electing the office-bearers of Co-operative Society are not at all held. Where election are duly held within prescribed time, but are set aside by the Registrar in deciding an election dispute under section 41, the provisions of section 14(10) of the Act *per se* will not be applicable. *Ramsakha Singh vs. State of Bihar, 1992(2)*PLJR 598.

Sections 14 and 41 read with Rule 211 of Bihar Co-operative Societies Rules, 1959- election commences from the initial notification calling upon the constituency or the representatives who have to participate at such election by filing nomination paper and it culminates only with the declaration of the result-therefore the direction· of the Registrar to ignore the election held on 20.4.1990 on the basis of notice of programme issued on 29.3.90 and voter list prepared upto 30.6.89 is not valid-such election held valid. *Nawal Kishore Singh vs. State of Bihar,* 1991(1) PLJR 572.

Sections 41 and 66B read with rule 33 of Rules, 1959---temporary appointments made by Managing Committee, Central Co-operative Bank without properly giving advertisements calling for applications for filling vacancies and ignoring directions of Registrar, Co-op. Societies-Administrator appointed after the State Government had dissolved the erstwhile managing committee cancelling appointment of petitioners on ground that appointments had been made in contravention of procedure prescribed by Registrar-order of termination simpliciter--appointment of a paid employee in any registered co-operative society is subject to any general or special order issued by the Registrar in exercise of power under rule 33---order of termination simpliciter is not bad as principles of natural justice are not attracted. *Satish Kumar vs. State of Bihar* 1990(1) PLJR 219; 1989 PLJR 566.

Sections 14(2), 41, 48 & 65-Stay order passed by the High Court directing no meetings to be held till disposal of the case on 23.12.1980--meeting held on 30.12.1980 by the members of the Co-operative Bank electing office bearers-some business also transacted by the new office bearers on the next day and a copy of proceedings sent to Registrar---election held void by Registrar and special officers appointed to look after the work of the Co-operative Bank-elected members disputing the decision of the Registrar holding the election void on the ground that there was no notice and knowledge of the stay order to the members who participated in the election meeting-plea challenged on the ground that notice of stay order was communicated to the executive officer and that amounts to sufficient noticevalidity of action of Registrar who acted on the directions of Minister, Co-operation in holding the election void because of the stay order is not merely the wish of the court but a command-the plea that if any violation of stay was there it should be dealt only under Contempt of Courts Act, 1971 and the action should not be held void cannot be accepted. *Nawal Kishore Prasad Sinha vs. State of Bihar,* 1982 PLJR 377.

Sections 14(4), 14(9) and 14(10) read with Rule 22(2) of Bihar Co-operative Societies Rules, 1959--date of commencement of term of Managing Committee-provisions of section 14 and rule 22 prescribe for constitution of a Managing Committee of a Registered Co-operative Society-term of Members and Office-bearers of the Managing Committee is three co-operative years from date of their election and not from the date on which the constitution of the Managing Committee was completed on nomination by the State Government-from a bare perusal of sub-section (9) of section 14 it is clear that the term of Members and office-bearers is "three co-operative years" and these persons can continue to hold office even on expiry of their terms till election is held or for nine months from the close of the co-operative year, whichever is earlier-under proviso to sub-section (10) of section 14, irrespective of the date when the election is held, the term of the Members and office bearers is deemed to have commenced from the beginning of the co-operative year in which election was held-decisions of Registrar are correct. *Bihar State Handloom Weavers Union vs. State of Bihar,* 1994(1) PLJR 584.

Sections 14(5) and (6) as inserted by Amending Ordinance of 1988-power of Registrar--sub-section (9) of section 14 being part of section 41, will not override the provisions of sub-sections (5) and (6)-similar is the position in case of rules 20 and 21Registrar, cannot, therefor give election programme or directions in this regard to Administrators and it is the latter who have to do it themselves-similarly, Registrar cannot appoint Returning Officer for elections. *Vidya Singh vs. State of Bihar,* 1989 PLJR 377.]

1[14A. Election to the managing committee of certain registered societies.--"(1) Notwithstanding, any thing contained in any provision of this Act, rules made thereunder and byelaws of a registered society, the election to the managing committee of cooperative societies registered under this Act shall be conducted by Bihar State Election Authority constituted under Bihar State Election Authority Act, 2008 in the manner prescribed for the conduct of election under Bihar State Election Authority Act, 2008 and rules made thereunder read with Bihar Co-operative Societies Act, 1935 and rules made thereunder:

Provided that all the previous elections of registered co-operative societies conducted by the Competent Authority under the existing provisions would be saved.

Provided, further that any action, order, decision to hold the election of managing committee of cooperative societies shall be deemed to have been made under this Amendment and any election so held shall be valid, notwithstanding any judgment, order or decree of any court."

[1] ["(2) Notwithstanding, any thing contained in any provisions of this Act, rules made thereunder and bye-laws of a registered society, the election to the managing committee of co-operative societies registered under this Act shall be held in terms of the provision of this Section, even if the process of election has commenced but the result of such election has not been declared."

[2]["(3) Notwithstanding, any thing contained in any provision of this Act, rules made thereunder and bye-laws of a registered society, the election to the managing committee of co-operative societies registered under this Act shall be held before the expiry of the term of managing committee as prescribed in Sub-section (9) of Section-14 of this Act or within period of nine months from the order of supersession of managing committee passed under the provisions of this Act:

Provided that in the case of supersession of managing committee of any society as on the date of notification of this Amendment, the election to the managing committee shall be held within nine months."

2[(4)[**xxx**]

2[(5)[**x x x**]

1. Subs. by Act 3 of 2012.
2. Deleted by ibid.

(d) in securities specified by Reserve Bank of India, or

(e) with the general or special sanction of the Registrar and on such conditions as he may impose.

(i) In shares or securities of any other registered societies.

(ii) In any scheduled Bank or with the sanction or Registrar in other registered societies carrying Banking business.

(f) may invest or deposit in any other mode permitted by the rules.

Comments & Case Law

[Section 19- -Accused, Secretary of a Co-operative Society--held, accused, is not a public servant-accused's conviction under Section 408, Penal Code not justified.' *Basudeo Mandal vs. State,* 1974 PLJR (NOC) 1.]

20. Contribution to charitable purpose.-Any registered society may after the amount required by sub-section (1) of section 18 or by any rule has been carried to the reserve fund, contribute an amount not exceeding ten percent of the net profits to any charitable purpose, as defined in section 2 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890):

Provided that the Registrar may, by general or special order, prohibit any society or class of societies from making any condition under this section.

21. Restrictions on division of funds.--No part of the funds of a registered society shall be divided by law of bonus or dividend or otherwise among its members;

provided that after the amount required by sub-section (6) of section 18 or Dy any rule has been carried to reserve fund, the balance of the net profits, if any, together with any available profits of past years, may be distributed as dividend among members or paid as bonus or remuneration to a member for any specific service rendered to the society or used for the common benefit of members to such extent and under such conditions as may be prescribed by the rules or bye-law.

22. Charge and set off in respect of shares or interest of members.- A registered society shall have a charge upon the share or interest in the capital and on the deposits or contribution of a member, past member or deceased member and upon any amount payable out of profits to a member or past member or to the estate of a deceased or the estate of such deceased member to the society, and may setoff any sum credited or payable to a member, past member or the estate of a deceased member in or towards payment of any such debt.

23. Prior claim of society.--Subject to claim of the Government in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue or as a public demand or any claim of landlord in respect of rent or any money recoverable as rent, any debt or outstanding demand due to a registered society from any member, past member, or the estate of deceased member, shall be a first charge.

(a) if the demand as due in respect of the supply of or any loan granted for the purchase of seed or manure upon the crops or other agricultural produce of such member or past member or belonging to the estate of such deceased member, at any time within two years from the date on which the last instalment of such supply or loan shall become re-payable.

(b) if the demand is due in respect of the supply of or any loan granted for the purchase of cattle, fodder for cattle, agriculture or industrial implements or machinery or raw materials for manufacture any upon cattle or thing so supplied, or purchased, the whole or any part from any such loan or upon any articles manufactured from raw materials so supplied or purchased.

Comments & case-law

[Section 23 merely deals with the liability of a past member for the debts of a society in winding up, and has no reference whatever to a debt of a member of a society to the society. *Barhitola Co-po. Society vs. Sambhunath Singh,* 23 PLT 104.]

1**[23A. Application of section 23 to non-members.**-Any debt to outstanding

1. Ins. by Act. 16 of 1948

demand due to a registered society, authorised under clause (a) of sub-section (1) of section 16, from any non-member or estate of a deceased non-member, shall be a first charge on the property of the non-member or belonging to the deceased nonmember to the same extent and subject to the same claims, conditions and restrictions as debt or outstanding demand due to a registered society from any member or the estate of a deceased member is under section 23, a first charge on the property of the member or belonging to the estate of the deceased member.]

24. Transfer of interest on death of member.-(1) A registered society, may on the death of a member, transfer his share or interest in the capital of the society to the person nominated in accordance with the rules or, if there is no person so nominated, to such person as may appear to the society or, managing committee to be the heir or legal representative, as the case may be, a sum representing the value of such member's share or interest, as ascertained in accordance with the rules or bye-law;

Provided that-

(i) In the case of society with unlimited liability, such nominee, heir or legal representative as the case may be, may require payment by the society of the value of the share or interest of the deceased member ascertained, after, deducting the amount of any charge existing under section 22;

(ii) in the case of society with limited liability, the society shall transfer, subject + to any charge existing under section 22, the share or interest of the deceased, member to such nominee, heir or legal representative, as the case may be, being qualified in accordance with the rules and bye-laws for membership of the society or in his application within three months of the death of the deceased member, to any person specified in the application who is so qualified:

Provided further that no payment of sum in excess of rupees one hundred shall be made to any such heir or legal representative who has not been nominated in accordance with the rule, until after the decision under section 48 of any claim which may, within that period, be made by any other person.

(2) Subject as aforesaid, a registered society may pay all other money due to deceased member from the society to such nominee, heir or legal representative, as the case may be. :

(3) All transfers and payments, made by a registered society in accordance with the provisions of the section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by other person.

'[**24A. Power of Registrar to sanction compromise between a registered society and its creditors.-(1)** Notwithstanding anything contained in this Act, where a compromise or arrangement is proposed between a registered society and its creditors or any class of them, the Registrar may on the application in a summary way of the society or of any creditor, or in the case of society in respect of which an order of winding up has been passed, if the liquidator, order a meeting of the creditors or class of creditors as the case may be, to be called, held and conducted in such manner as may be prescribed by rules.

(2) If a majority in number representing three-fourths in value of the creditors, or class of creditors, as the case may be present either in person or by proxy at the meeting, agree to any compromise or arrangement, the compromise or arrangement shall, if sanctioned by an order of the Registrar, be binding on all the creditors or the class of creditors as the case may be and also on the society, in the case of a society in respect of which an order of winding up has been passed, on the luquidator and on all persons who have been or may be required by the liquidator acting under clause (c) of sub-section (3) of section 44 to contribute to the assets of the society.)

(3) If at any time it appears to the Registrar that it is expedient that any compromise or arrangement between a registered society and its creditors or any

1. Ins. by Act 8 of 1935.
2. Sub-sections (3) to (7) ins. by Act 16 of 1948.

class of them, which has become final in accordance with the law in force on the date of the commencement of the Bihar Co-operative Societies (Amendment) Act, 1942 (Bihar Act 7 of 1942), or which was, after the date sanctioned by the Registrar under sub-section (2) of this section, should, in the interest of society or of its creditors or of the said class of creditors, be revised or replaced by a fresh compromise or arrangement, he may either of his own motion or on the application of the society, order a meeting of the creditors or class of creditors as the case may be, present either in person or by proxy at the meeting, agree to the revision of the previous compromise or arrangement, or to any fresh compromise or arrangement, the Registrar may sanction such revised compromise or arrangement or such fresh compromise or arrangement.

(4) Any revised compromise or arrangement or fresh compromise or arrangement sanctioned under sub-section (3) may be revised or replaced by a fresh compromise or arrangement in the like manner and subject, to the like conditions as a compromise or arrangement may be revised or replaced by a fresh compromise or arrangement under sub-section (3).

(5) Any revised compromise or arrangement or fresh compromise or arrangement sanctioned by the Registrar under sub-section (3) or sub-section (4) shall be binding on all-the creditors or the class of creditors, as the case may be, and also on the society.

(6) A compromise or arrangement under sub-section (2) or a revised compromise or arrangement or a fresh compromise or arrangement under sub-section (3) or sub-section (4) shall not be liable to be challenged, set aside, modified, revised or declared void in any Court, upon merits or upon any ground whatsoever except want of jurisdiction.

(7) The order of the Registrar calling a meeting of creditors or class of creditors, as the case may be, under sub-section (1) or sub-section (3), and the order of the Registrar sanctioning a compromise or arrangement under sub-section (2) or a revised compromise or arrangement or a fresh compromise or arrangement under sub-section (3), or sub-section (4) shall be published in the official Gazette.]

Comments & case-law

[Composition arrived at in pursuance of the provisions of this Act does not stand on the same footing as a private agreement where pending a suit by a creditor against a Co-operative Society, a scheme of composition is adopted and approved by the Registrar, that binds the plaintiff in the suit who is a party to the scheme. If he continues the suit and obtains a decree, the decree cannot be executed and the scheme can be pleaded as a bar of execution. The creditor's remedy is to obtain satisfaction of the decree in the manner provided for in the scheme. *Mahamaya Ojhain vs. Laheriasarai Central Co-operative Bank,* 1941 IC 468 : 7 BR 780 : 1941 PWN 531 : AIR 1941 Pat. 497.

Section 24-A (2) of this Act makes a scheme of compromise agreed to by the specified majority, if sanctioned by an order of Registrar binding on all the creditors or the class of creditors, as the case may be and also on the Co-operative Society. It may be that a particular creditor was no party to the scheme of compromise, but section 24-A (2) makes his individual participation absolutely immaterial. Where therefore pending a suit by a depositor against a Co-operative Bank for recovery of his deposit a scheme of compromise under section 24-A of the Act is agreed to by the required majority of creditors and sanctioned by the Registrar of Co-operative Societies; and a decree is subsequently passed in favour of the depositor in his suit the decree cannot be executed, against the Bank. The depositor-plaintiff is bound by the compromise though not a party to it. It was further held that the compromise, while not a bar to the passing of decree, is a clear bar to execution. *Buxar Central Co-op. Bank Ltd. vs. Akhauri Bindhyachal Prasad,* 185 IC 606: AIR 1940 Pat. 361.]

25. Amendment of the bye-laws of a registered society.-(1) No amendment of the bye-laws of a registered society shall be valid until the amendment has been register<d under this Act.

[1]["(2) If the Registrar is satisfied that an amendment of the byelaws is not contrary to this Act or to the rules, he shall register the amendment within ninety **days** from the date of submission of the proposal for amendment.

(3) When the Registrar registers an amendment of the bye-laws of a registered society, he shall issue to the society a copy of the amendment certified by him, which shall be conclusive evidence that the amendment has been duly registered. [2]["(4) If the conditions specified in sub-section (2) have not been fulfilled the Registrar shall dispatch refusal order with reasons by registered post within ninety **days** from the submission of the proposal.

(5) In case of non-dispatch of the refusal order within ninety days, the amendment shall be deemed registered. In such cases it will be essential for the fegistrar to issue the certificate of registration under his seal and signature, which **will** be conclusive evidence that the amendment has been duly registered.

(6) On receipt of the refusal order under sub-section (4) and on non-receipt of *the* conclusive evdience relating to the amendment as specified under sub-section (S) an appeal shall lie before the Registrar if the conclusive evidence or refusal order relates to the Registrar having been delguated with the power of Registrar and if such order has been passed by the Registrar Co-operative Society himself then appeal shall lie before the State Government :

Provided that such appeal shall be filed within two months from the receipt of order or non receipt of conclusive evidence.]

Comments & case-law

[The bye-laws of a co-operative society framed in pursuance of the provisions of the relevant Act cannot be held to be law or have the force of law. They are neither statutory in character nor they have statutory flavour so as to be raised to the status Of law. Statutory provisions have precedence and must be complied with bye-laws if not in conformity with the statute, have to be ignored, in order to give effect to the statutory provisions. *Central Co-operative Bank Ltd. vs. Addl. Industrial Tribunal,* AIR 1970 SC 245. See also *B.K. Garad vs. Nasik Merchants Co-op. Bank,* AIR 1984 SC 192.

Rules have the status of subsidiary legislation or delegated legislation. Byelaws of a co-operative society, on the other hand, can at best have the status of an Article of a Company governed by the Companies Act, 1956. *ibid.*

It is function of the Court to construe legislative measures and enriching the correct meaning of a statutory provision, opinion of executive branch is hardly relevant. Nor can the court abdicate in favour of such opinion. *ibid.*

Sections 25, 26 read with Rules 16 to 20 amendment in bye-laws-amendments suggested by Registrar to be discussed by General-body for which Board of Directors were directed to call a special general meeting-Registrar also directing for stay of election on the date fixed already for the purpose till amendments are approved by the general body-no such power to Registrar to stay election-amendments having been approved through a sub-committee by the outgoing Board of Directors not valid not having been approved by the general body---elections held ignoring the direction 5j Registrar valid. *Vijay Kumar Mishra vs. State of Bihar,* 1989 PLJR 846.]

26. Power of Registrar to direct amendment of the bye-laws of a registered society.-(1) If it appears to the Registrar that an amendment of the byelaws of a registered society is necessary or desirable in the interest of such society [3][after taking the opinion of affiliating society/federation of that society], he may, by order in writing to be issued to the society, by registered post, require the society to make the amendment within such time as he may specify in such order.

(2) If any society fails to make any such amendment within the time specified, the

1.Subs. by (Amdt.) Act 10 of 2002
2.Sub-section (4), (5) & (6) added by ibid.
3.Ins. by (Amdt.) Act 10 of 2002.

Registrar may, after giving the society an opportunity of being heard, register such amendment, and issue to the society by registered post a copy of the amendment, certified by him, which shall be conclusive evidence that the amendment has been duly registered, and such amendment shall be binding on the members of such society.

(3) An appeal shall lie to the State Government from any order of the Registrar passed under sub-section (2) within two months from the date of the issue of such order. The order of the State Government on appeal and, subject to the result of such appeal, if any, the decision of the Registrar shall be final.

Comments & case-law

[Power of the Registrar to impose amendment of bye-law cannot be exercised without hearing the concerned society. Order registering amendments without giving opportunity of hearing to the society is liable to be quashed. *Kinigam Service Co-op. Society vs. Dy. Registrar,* AIR 1981 Orissa 112.

The General Body of a Co-operative Society is alone competent to consider amendments to be made in its bye-laws. The General Body is fully competent to ignore the direction of the Registrar of Co-operative Societies to stay the holding of election at its Annual General Meeting and proceed to hold election of office-bearers. The Registrar enjoys plenary powers under section 26 (2), but should always be extremely circumspect in forcing a society to accept a clause in its bye-laWS, which the members of the Co-operative Society sitting together do not approve, unless of course, the society's bye-laws are completely contrary to the provisions of this Act. *Vijoy Kumar Mishra vs. State of Bihar,* 1988 PLJR 478.

Section 26(2)---the Registrar while enjoying the plenary powers under this section should always be extremely circumspect in forcing a society to accept a clause in the bye-laws which the members of the society sitting together do not approve and which affect their right detrimentally unless the society's bye-laws are completely contrary to the provisions of the Act and the Rules and are detrimental to the co-operative movement. *Vijay Kumar Mishra vs. State of Bihar,* 1989 PLJR 846.

Sections 26 and 28--Section 28 (1) does not prohibit the concept of indirec elections, even though the whole Act is silent on indirect elections-the concept of one member one vote' also does not rule out indirect elections-the right to one vote does not imply that the voter has a right to vote at every stage-indirect elections must be permitted where the electorate is too large. *Pancharian Sharma vs. Stale of Bihar,* '1989 PLJR 437.

Power of Registrar to amend Bye-Laws-The Registrar is empowered to amend Bye-laws of a Co-operative Body and provide for prohibiting members of affiliated Co-operative Societies to participate ir election where such' affiliated GO operatives are defaulters. The Registrar is competent to lay down not only criteria for admission to membership of apex bodies but also the consequences of default. The Registrar in exercise of power under section 25 can direct amendments to be made ir Bye-laws of Affiliating Society for _regulating admission and eligibility to participate in election by Primary affiliated Co-operative Societies. Representative of affiliated Co-operative found to be a defaulter in respect of sum due by Primary Affiliated Society to Affiliating Society" becomes ineligible to participate in election of officer-bearers of Affiliating Society. *Mohan Mishra vs. State of Bihar,* 1996, (2) PLJR 171.

Prescription of eligibility to participate in election being limited to only those Primary Affiliated Societies who have repaid atleast 40% of the loans amount is not unreasonable and is in the interest of Co-operative, movement. being an attempt to bring about financial discipline. *ibid.*]

CHAPTER IV

Rights and Liabilities of Members of Registered Societies

[1]["**27. Right of a Member.--(1)** Member of a Co-operative Society shall exercise the rights of a member after he has made such payment to the Society in respect of membership as may be prescribed in the rules or Bye-laws of the Society:

Provided that notwithstanding anything contained in any provisions of this Act,

1. Subs. by Act 6 of 2013.

the member of a Co-operative Society can exercise the right to vote at the election of members of the Board of Society only after ensuring minimum attendance, as required in the meetings convened for participation in management of the Society and availing of minimum requisite services of the Society as may be prescribed by the Rules or the Bye-laws of the Society made under this Act.

(2) Every Co-operative Society shall provide access to every member to the **books,** information and accounts of the Co-operative Society kept in regular transaction of its business with such member.

(3) Every member of a Co-operative Society shall have the right to get all information/documents regarding books, information and accounts of the Co-operative Society kept in regular transaction of its business. The Chief Executive Officer/ Manager of the Co-operative Society shall ensure access to the member to all required information/documents.

(4) The members of any Co-operative Society shall have the right to get cooperative education and co-operative related training as per the Rules or Bye-laws made under any provisions of this Act."

28. Votes of members.--'[(1) Subject to the provisions of sub-section (2) of this section and of sub-section (4) of section 14 each member of a registered society shall have one vote only as a member in the affairs of the society, provided that in the case of an equality of votes, the Chairman shall have a casting vote.]

(2) A registered society which is a member of any other registered society shall have as many voters as may be prescribed by the bye-laws of such other society and may, subject to such bye-laws, appoint any number of its members, not exceeding the number of such votes, to exercise its voting power, provided that no member who is disqualified for such appointment under any rule shall be so appointed.

(3) Save as provided in sub-section (2), voting by proxy shall not be allowed except with the general or special sanction of the Registrar for any society or class of societies.

Comments & case-law

[The voting right in proportion to the financial share holding of each member (as in Companies) has been excluded. A member, regardless of number of shares he owns, has only one vote. *Harender Narain Banker vs. State of Bihar,* 1985 PLJR 1078.

The provisions of this section do not negative the system of indirect election. To permit every member to take part in election of Director may be colossal task. Therefore provisions can certainly be made for indirect election. *Panchanan Sharma vs. The State of Bihar,* 1989 PLJR 437.

A member having a voting right, if he is not given a notice of a meeting such meeting will be illegal especially when there is a no confidence motion against the chairman of the co-operative society. *Gazanan Narain Patil vs. Dhattatraya Waman Patil,* AIR 1990 SC 1023 : (1990) 3 SCC 634: (1990) IJT 517.]

29. Restriction on holding of members.-No member of a registered society [2][other than the State Government or another registered society]. shall have or claim any interest in the capital of a registered society exceeding one-fifth of the total capital or such smaller proportion as may be prescribed by the rules.

30. Share or interest not liable to attachment.-Subject to the provisions of section 22, the share or interest of a member in the capital of, or contribution to, a registered society shall not be liable to attachment or sale under any degree or order of a Court of justice in respect of any debt or liability incurred by such member and neither the Official Assignee under the Presidency-towns lnsolvencey Act, 1909 (3 of 1909) nor a Receiver under the Provincial Insolvency Act, 1920 (5 of 1920) shall be entitled to, or have any claim on, such share, interest or contribution.

31. Restrictions on transfer of share or interest.-(1) The transfer of charge of the share or interest of member in the capital of registered society shall be subject to such conditions as the maximum holding as may be prescribed by this Act Or by the rules.

1. Ins by Act 6 of 2013
2. Subs. by ibid.

1. Subs. by Act 14 of 1955, for "other than another registered society".
2. Subs. by (Arndt) Act 5 of 1989.

(a) Conservation of the Annual Statement of Accounts presented by the Board **for** being filed before the Registrar,

(b) consideration of Annual Report presented by the Board,

(c) appointment and removal of Statutory Auditors and Internal Audi

(d) consideration of the auditor's report and audited Statement of Accounts for being filed with the Registrar,

(e) consideration of audit/special audit compliance report,

(f) report on action taken on inquiry report, if any,

(g) disposal of net surplus,

(h) review of operational deficit, if any,

(i) approval of the long term perspective plan and the annual operational plan,

(j) approval of the annual budget,

(k) creation of specific reserves and other funds,

(l) review of actual utilization of reserve and other funds,

(m) report on membership of the Co-operative Society in other Co-operative Societies,

(n) appeal of a person whose application for membership has been rejected or whose membership has been terminated by the Board,

(o) remuneration payable to any Director, Auditor or Internal Auditor in connection with his duties in that capacity or his attendance at related meeting,

(p) membership of the Co-operative Society in Union/Federation,

(q) collaboration with other organisation,

(r) amendment of Bye-laws,

(s) formulation of code of conduct for the Directors and Office-bearers,

(t) note on admission and termination of membership of the members,

(u) dissolution of the Co-operative Society,

(v) such other functions specified in the Bye-laws.

(2) In accordance with the provisions for the works specified, under sub-section (1), the Annual General Meeting of the Co-operative Society shall be held at a time, date and place notified in accordance with the Bye-laws and if a quorum is present, the Chairman of the Co-operative Society shall preside the meeting:

Provided that in the absence of Chairman, Vice-Chairman, or in the absence of both Chairman and Vice-Chairman, a person elected by the members from among themselves shall preside the meeting:

Provided further that in case of a Society where the Managing Committee has either been superseded under the provision of the Act, the Administrator shall be the Chairman of the General Meeting and in his absence a person nominated by him shall be the Chairman of the meeting.

(3) The person presiding at the meeting shall conduct the proceedings in such manner as may be conducive to expeditious and satisfactory disposal of business and shall decide all points of order at the meeting.

(4) The quorum for a General Meeting shall be one fifth of the total membership of the Society on the date of issue of the notice of the meeting.

(5) If within an hour of the time scheduled appointed for the meeting the quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to a date not earlier than seven days and not later than twenty-one days.

(6) No quorum shall be necessary for an adjourned meeting.

(7) All questions before a General Meeting shall be decided by a majority of votes and in the event of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

(8) Voting by proxy shall not be allowed, but the Registrar may permit this to be done in the case of any particular Registered Society or class of Registered Societies. (9) Voting at a General Meeting shall be done by show of hands and only in exceptional case voting by ballot may be resorted to if the Registrar so directs, on his own motion, or on the application filed by the Society concerned.

(10) The minutes of proceeding of General Meeting shall be recorded in a book to be kept for the purpose and the minutes shall be signed by the person presiding at the meeting.

(11) An appeal shall lie to the Registrar on all matters relating to procedure followed at any General Meeting and his decision thereon shall be final.

[1][**328.** ***Filing Annual Returns. Every*** Co-operative Society shall file Annual Returns before the Registrar within six months of the end of each financial year which shall include following subjects:-

(a) Annual Report of the activity;

(b) Audited Statement of the Accounts;

(c) Plan to deal with the surplus as approved by General Body;

(d) List of the amendments done, if any, in the Bye-laws of the Cooperative Society;

(e) Declaration relating to the conduct of election, if due, and date for the arrangement of General Body Meeting;

(f) Any other information, if required to carry out any of the provisions of the Act notified by Registrar.

CHAPTER V

Audit and Inspection

2[33 ***Audit.-(1)*** A Co-operative Society shall get its accounts audited by Auditor from a panel approved by State Government or the authority authorized by the State Government, at least once in every financial year. Such Auditor shall either be Chartered Accountants within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 or Auditors from the office of the Registrar.

(2) The minimum educational qualification of the Auditors from a panel approved by State Government or an authority authorized by the State Government shall be Graduate (with Mathematics) or Commerce Graduate from any recognised University. Such Auditor or Chartered Accountants firm shall be required to have at least three years of audit experience. Only such Auditor or Chartered Accountants firm shall be eligible for the audit of the accounts of Co-operative Society.

1. Ins by Act 6 of 2013
2. Subs. by ibid.

(3) The audit of the accounts of every Co-operative Society shall be done by the Auditor or Chartered Accountant firm, specified under sub-section (2), appointed by the General Body of Co-operative Society.

(4) It shall be mandatory to audit the accounts of every Co-operative Society eithin six months of the end of the financial year to which accounts is related to.

(5) Apex Co-operative Society, with the approval of General Body, shall compulsonly submit the Audit Report, after the audit of its statement of accounts, to the *Fe*gistrar within thirty days which shall be placed before the State Legislature in accordance with the procedure laid down for this purpose by the State Government.

(6) The Auditor's Report in addition to the report on the accounts of the Cooperative Society shall also contain report on the attendance at Board meeting, by Directors, the loans and advances sanctioned to or the business done with the Cooperative Society by the Directors, expenditure on Board Meetings, remuneration paid to Directors, expenditure reimbursed to Directors, expenditure on education and training for members, staff, Directors and others.

(7) It shall be the duty of the Board to ensure that annual financial statements are prepared and presented for audit within forty-five days of closure of the financial year.

(8) The remuneration of an Auditor shall be fixed by the General Body:

Provided that if audit is done by the Auditor of the office of Registrar, the Cooperative Society shall pay the audit fee fixed by the Registrar.

(9) The General Body may, at a special meeting, remove an Auditor from office by a resolution passed by a majority of the members present and voting.

(10) Upon the demand of the Auditor of a Co-operative Society the present or former Office-bearers, Board members or employees of the Co-operative Society shall furnish-

(a) such information and explanation, as may be considered necessary, and

(b) each of the record, documents, books, accounts and vouchers of the Co-operative Society as are, in the opinion of the Auditor, necessary to enable him to make the examination and report.

(11) Where a Co-operative Society fails to get its Annual Accounts audited when due, Registrar shall get the accounts of the Co-operative Society audited within a period of ninety days from the date when the audit was due.

(12) The cost of conducting such audit shall be borne by the Co-operative Society."

Comments & Case-law

[Section 33 requires the audit of registered society to be conducted in accordance with rules framed under the Act. Where no rules had been framed under the Act and there was procedure prescribed for the manner in which the audit had to be conducted, the general rule will apply that the person who has to conduct the audit shall lay out his own machinery and procedure for conducting the same. Apart from that even in absence of the rules, the auditor has jurisdiction to audit and the audit report cannot be challenged as being void because of absence of the rules. *Juga! Kishore Singh vs. Registrar,* 1960 BLJR 49.]

1. Ins by Act 6 of 2013

[1]["**33A. Special Audit.--(1)** A Co-operative Society dealing with funds from the Government or other external individual or institution may be subject to a special audit initiated by the Registrar at the request of such creditor or of his own motion with written specific order/direction.

(2) Special Audit under sub-section (1) shall be done by District Audit Officer/ Senior level Audit Officers or any Committee of such Officers under the control of Registrar.

(3) Where the Special Audit reveals serious mismanagement in the Co-operative Society, costs of such Special Audit may be recovered from the Co-operative Society or the persons responsible for the mismanagement.

(4) Every Special Audit shall be completed and the report submitted to the Registrar within one hundred and twenty days from the date of issuance of the order.

(5) The Special Audit Report shall contain a statement of:

(a) every payment which appears to the Auditor to be contrary to Act, Rules or Bye-laws of the Society,

(b) the amount of any deficiency, waste or loss which appears to have been caused by the gross negligence or misconduct of any person in the performance of duties,

(c) the amount of any sum received which ought to have been accounted for, but it is not brought into account by any person, and

(d) any asset or money to which any person related with the organization or management of the Co-operative Society or any former or present member of the Co-operative Society has misappropriated or fraudulently retained any property of the Society.

(6) The Registrar shall, within a period of thirty days train the date of the receipt of the Special Audit Report transmit copies of the same to

(a) the applicant creditor,

(b) the Co-operative Society concerned, and

(c) the authorized Audit Officer to file proceedings of surcharge, where necessary, under Section 40.

1[**33B.** ***Maintenance of accounts and records.--(1)*** Every Co-operative Society shall keep at its registered office the following accounts and records:

(a) a copy of this Act with amendments made from time to time,

(b) the minutes book,

(c) registration certificate and a copy of the registered Bye-laws and the amendments registered from time to time with date of amendment,

(d) a copy of the authenticated Bye-laws of the Federation/Union of which it is a member and for each of its member Co-operative Societies,

(e) account of all sums of money received and expended by the Co operative Society and their respective purposes,

(f) account of all purchases and sales of goods by the Co-operative Society,

(g) account of the assets and liabilities of the Co-operative Society,

{h) a register showing total membership and the member wise use of various services,

(i) a list of members with voting rights for the current year updated within thirty days of closure of the financial year,

(j) copies of the Board policies,

(k) Annual Report, Audit Report, Special Audit Report, Inquiry Report and their compliances,

(1) copies of other laws and regulations to which the Co-operative Society is subject,

(m) such other documents as are relevant to the functioning of the Society:

Provided that where a Co-operative Society has branch offices, accounts and records related to the branch, shall be available at the registered office for any period within twenty five days of the end of the financial year,

(n) all other documents, register, circulars, etc. required in accordance with the provisions and circulars issued by NABARD, Reserve Bank of India and Registrar from time to time.

(2) The books of accounts of every Co-operative Society together with supportng records and vouchers shall be preserved for such period as may be provided in *the* Bye-laws subject to any other laws for the time being in force."

34. Inspection by Registrar.--The Registrar may from time to time inspect a registered society himself or cause it to be inspected by some person authorised by him in this behalf by general or special order.

35. Inquiry **by Registrar.--(1)** The Registrar may, of his own motion and shall, on the request of the Collector, or on application of a majority of the managing committee, or of not less than one-third of the members, hold an inquiry, or direct some person authorised by him by order in writing in this behalf to hold an inquiry, into the constitution, working and financial condition of a registered society.

(2) The Registrar or the person authorised by him under sub-section (1) may:

(a) require an officer of the society to call a general meeting at such time and place at the headquarters of the society, and require the society to take into consideration such matters, as he may direct, and

(b) if the officer of society refuses or fails to call such a meeting or if there be no quorum at a meeting so convened, call such meeting himself by giving notice to the members in such a **way as** he may consider reasonable, notwithstanding any rules or byelaws prescribing the period of notice for calling a general meeting of the society. Any meeting so convened by the Registrar or the person authorised by him under sub-section (1) shall have all the powers of a general meeting convened under the bye-laws of the society.

(3) When an enquiry is made under this section, the Registrar shall communicate the results of the inquiry to the society, the financing bank, if any, to which the society is affiliated and to the persons or authority, if any at whose instance the inquiry is made.

1. Ins by Act 6 of 2013

Comments & caca-law

[The communication of result of the enquiry is essential. *Ramashankar Prasad **Singh vs. State,*** AIR 1973 Pat. 269.]

36. Inspection of books by Registrar.-(1) Registrar may, on the application of a creditor of a registered society, inspect or direct some person authorised by him in this behalf by order in writing to inspect, the books of the society.

(2) No inspection shall be made or directed under section (1) unless the applicant-

(a) satisfies the Registrar that the debt is a sum then due, and that he has demanded payment thereof and has not received satisfaction within a reasonable time; and

(b) deposits with the Registrar such sum as security for the costs of the proposed inspection as the Registrar may require.

(3) Where an inspectior. is made under sub-section (1), the Registrar shall communicate the results of such inspection to the creditor, to the society and to the financing bank, if any to which the society is affiliated.

37. Inspection of books by financing bank.--(1) A financing bank may cause an inspection to be made of the rooks of any registered society which is affiliated to it and mav direct such society to furnish such information, statements and returns as may be required.

(2) An inspection under sub-section **(1)** may be made by any of the officers of the financing bank or by any member of its paid staff approved by the Registrar by general er special order.

(3) The financing bank shall communicate the rc,sult of such inspection to the Registrar and to the society concerned.

38, Power to call for documents and to issue summons.-- The Registrar or any person authorised to audit the accounts of a society under section 33 or to mak3 an inspection or to held an inquiry under sections 34, 35, 36, or 37.

(a) shall,at a!! reasonable time have free access to the books: accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of the society and may summon any person in possession of or respons:ble for the custody of any such books, accounts, documents, securities, cash or other properties, to produce the same at the office of the society or at any branch thereof or except in the case of a financing bank, at any place at its headquarters;]' [**]

(b) may summon any person who, has reason to believe has knowledge of any of the affairs of the society to appear before him at the office of the society or, at any branch thereof or except in tits case of a financing *bark,* et any place at its headquarters, and may examine such person on oath; [and]

[2][(c) may seize in presence of two persons the bocks, account, document; securities, cash and other properties belonging to or in the custody of the society, if he apprehends any fraud,or damage or mutilation of any of the articles above referred to, and the officer so doing shall grant proper receipt therefor and, ner he is an officer other than the

1. The word "and " omitted by Act of 1956.
2. Ins. by ibid.

such order. The order of the State Government on appeal, and subject to the result of such appeal, if any, the order of the Registrar, snall be final.

Comments & case-law

[In a case coming under section 40 (1) (b), opportunity to recover the amount from the person to whom it is paid referred to in the proviso to section 40 (1), is not available to the ·hairman against whom the order of surcharge is passed. Moreover, absence of oppe tunitv is a mere irregularity and does not render the surcharge proceading void.

Under the proviso to section 40 (1); the petitioner is not entitled, in law, to have a notice giving him an opportunity to recover the amount from the payee. *Jugal Kishore Singh vs. Registrar,* 1960 BLJR 49.

The prosecution under section 49 of Indian Penal Code be initiated not only at the instance of appropriate authority of the society, but also at the instance of the Registrar, Deputy Registrar or the Assistant Registrar of the Co-operative Societies as provided under section 40 of this Act. *State of Bihar vs. Amulya Ratan Pathak,* 1968BLJR474.

When a matter falls under any specific provision, then it must be governed by that provision and not by other general provisions. Therefore, where the Society held its employee 'iable for shortage of assets put under his custody and charge by reas011 of his negligence or misconduct, the matter being fully covered by section 40 **(1)** (b), must mean that section 48 is not applicable. *Uma Shanker Sharan Shrivas~ava vs. Biscomaun,* 1985 PLJR 19: 1984 BBCJ 905: AIR 1985 Pat. 46.

. The roviso to section 40 (1) providing the period of limitation speaks of passing the order within-the period of six years, unlike the periods fixed under Limitation Act for initiating an action or starting a proceeding within the prescribed pericd of limitation. The period of limitation referred to in this provision is not for initiat:ng c\ proceeding but only for passing of order under the section.

Sction 40 perts.ins to the administrative power of the Registrar, flowing only as a pre-condition from the results of an audit, inquiry, inspection or winding up. This section is not attracted or applicable to a reference of a dispute under section 48 by a Society against it officer, agent or servant for defalcation of its funds. *Kinjer Vyapar Manda/ Sahyog Samiti !td.* vs. *Deputy Registrar.* 1986 PLJR 264 (FB): AIR 1986 Pat 206 *(Uma Shankar Sharan Shrivastava vs. Biscomaun,* 1985 PLJR 19: 1984 BBCJ 904:AIR 1985 Pat. 46 Overruled)

Sections 40 and 48 are mutually exclusive and operate in altogether different fields Action under section 40 must be preceded by r proceeding under sections 33 to 37. No such pre-requisite 0r ve-condition is necesse·,, for action under section 48. *ibid.*

Mere acquittal in criminal case does rot automatically absolve the liability of a cashier of a co-operative society under surcharge proceeding initiated against him for misai:propriation. *P. Narayan Rao vs. State of Orissa,* AIR 1984 Orissa 32.

A proceeding under this section is not in substitution of section 48 therefore mere initiation or an order passed under this Section does not divest its jurisdiction or power of the Registrar u/s 48 when it was referred for a decision to the dispute. Mo reover exercise of the jurisdiction to pass an award under this section or revision u/s 56 does not amunt to double jeopard,y. *Yogendra Prasad vs. Additional Registrar,* 1992 (1) PLJR 9 (SC).

Sec. 40 pertains to 'S:. rcharge' whilst Sec. 48 pertains to wide-ranging disputes.

Under Sec. 40 only the Registrar is empowered to take ction and if conditions in clauses (a), *(bj,* (c) ana (d) of sub-section (1) herect are satisfied, he may enquire

into the matter and fix the quantum of the surcharge by way of compensation. On the other hand, under Sec. 48 it is only the parties to the dispute who can move and initiate action for the reference of such a dispute to the Registrar. Section 40 pertains to the administrative power of the Registrar stemming from the result of an audit or *an enquiry* or an inspection, etc. It is a vested power to penalise for misconduct and negligence on the one hand, in order to compensate the society by way of surcharge *therefor* on the other. It has nothing to do with *inter se* disputes which may rise under the five sub-clauses of sub-section (1) of Sec. 48. In a limited way the two sections can be said to be mutually in altogether different fields,

The pre-requisite for any action under Sec. 40 is that it must be preceded by a proceeding under Secs. 33 to 37 of the Act. It is only after the result of an audit, an *inquiry,* an inspection or a winding up of the society that the Registrar gets vested with the power to inquire into the conduct of a person and to levy a surcharge in order *to* compensate the society, On the other hand, Sec. 48 envisages no such prerequisite or pre-conditions for its coming into *operation.* No audit, inquiry or inspection etc., need precede a dispute with regard to which a reference may be made under Sec. 48. *Kinjer Vyapar Mandal Sahyog Samiti Ltd. vs. Deputy Registrar, Co-operative Societies Patna,* 1986 BLJR 237: 1986 BBCJ 209: 1986 BLJ 569 (FB).

Section 40 pertaining to surcharge, provides that if as a result of an audit or enquiry, it appears to the Registrar that any person who has taken part in the organisation or management of the Co-operative Society or any past or present Officer of the Society has either made a paymetn contrary to law or has been guilty of misappropriation etc., the Registrar may enquire into the matter and make an order requiring that person to contribute sum by way of compensation to the assets of the Society. Such an order can be passed only within six years of the act of omission or commission. *Bihar State Co-operative Marketing Union vs. Uma Shankar Sharan,* 1992 (2) PLJR (SC) 42.

In the instant case, a Board of Directors was very much in existence be it the Board which came into power in 1983 or the one that claims to have come into power on 15.11.1986. Therefore, the grounds stated in Annexure 14 are not covered by the situations under which Section 41 (6) of the Act' empowers the State Government to dissolve the Board of Directors of the Society. *Vijaya Kumar Mishra vs. State of Bihar,* (1989) 1 BLJ 636.

The disciplinary authority was within his right not to accept the report of the enquiry committee and for differing with the report and before recording his own *finding* in law the special officer was not required to give any notice to the respondent. But the special officer when he differed with the findings of the enquiry committee was required to record the reasons on the basis of the evidence for holding the respondent guilty of the charge. *Special Officer, Hazaribagh Central Co-operative Bank Ltd. vs. Madanmohan Prasad,* 1987 BLJR 439: 1987 PLJR (NOC) 74.

Section 41 of the Act, as it appears, empowers the Registrar and on the recommendation of the Registrar, the State Government, to dissolve a Managing Committee and follow up steps are thereafter provided. In these applications, the procedure provided under sub-sections (1) to (5) of Section 41 does riot apply since Annexure 14 has been issued by the State Government on the basis of the report amde by the Registrar as contained in Annexure 13 under sub-section (6) of Section 41 of the Act. *Vijaya Kumar Mishra vs. State of Bihar,* (1989) 1 BLJ 636.

Article 19 (1) (c) of the Constitution provides a citizen with a right to form associations of unions. By the impugned provision of Section 41 (6) of the Act, the union or association which has been formed is not being dissolved. Secondly, the

right to form an association by its members does not confer a right on them to claim under Article 19 (1) (c) that the activities of the association must also be permitted to be carried on in the manner desired by the members. In the instant case, it is obvious that by Section 41 (6) there will be no alteration in the composition of the association. All that is provided therein is that in the circumstances enumerated, the management for a specified period will be taken over by the Government from the Managing Committee. *Brijesh Rai vs. State of Bihar,* 1982 BLJ 133.

The removal from membership of Managing Committee of Co-operative on ground of default in repayment of loan within the prescribed period is contemplated under the Rules. *Jai Karan Singh vs. State of Haryana,* Al R 1996 P & H 67.

Two situations are envisaged in which the State Government becomes endowed with the powers to effect the dissolution of a Managing Commitee of a Co-opearative Society (i) when the State Government feels that the dissolution of the managing committee of a Co-operative Society is essential in the interest of the co-operative movement as a whole and the society in particular, and (ii) when the State Government apprehends any mismanagement of the society. *Vijaya Kumar Mishra vs. State of Bihar,* (1989) 1 BL.J 636.

Sub-section (6) of section 41 provides for an appeal from the order of the Registrar under sub-section (1) of section 41. In other words, if the Registrar passes an order of dissolution of the Managing Committee of a Co-operative Soecity, an Ag° grieved person has a right to appeal to the State Government. However, "deemed supersession" of Managing Committee under section 14 (10) is not subject to appeal under section 41 (6) . *Ramsakha Singh vs. State of Bihar,* 1992 (2) PLJR 598.

Sections 40 and 48--period of six years limitation is limited for the purpose of section 40 and cannot govern the reference u/s 48 where all actions were taken within 2 years, the aid of section 32 or 63 cannot be taken. *Bihar State Co-op. Marketing Union Ltd. vs. Uma Shankar Sharan,* 1992(2) PLJR (SC) 42.

Sections 40 and 48-remedies under---both remedies continue to be available until one is chosen---therefore, amount can be recovered by taking recourse to section 48 even though remedy for this was available u/s 60 specially since no step to recover the amount u/s 40 was taken. *ibid.*

Section 40-Secretary of a Co-operative Society can be prosecuted by Registrar, Deputy Registrar or Assistant Registrar. *State of Bihar vs. Amutya Ratan Pathak,* 1968 PLJR 474.

Sections 40 & 48--Both the sections are mutually exclusive and operate in altogether different fields-while action u/s 40 must be preceded by a proceeding u/ ss. 33 to 37 no such pre-requisite or pre-condition is necessary for action u/s 48. *Kinjer Vyapar Mandal Sahyog Samiti vs. Dy. Registrar,* 1986 PLJR 264 (FB).]

CHAPTER VI

Dissolution of Managing Committee

1[41. Dissolution of Managing Committee.-"(1) In the opinion of the Registrar, the Board of any Registered Society, the State Government has contributed to the share capital therein, or loan or financial aid has been provided by the State Government or loan has been provided on Government guarantee,

(i) is persistently making defaults or

(ii) is negligent in the performance of its duties imposed on-it by this Act, the Rules or the Bye-laws, or

1. Subs. by Act 6 of 2013

(iii) has conducted against the interest of the Co-operative Society or its members or

(iv) there is stalemate in the constitution or functioning of the Board, he may, after giving opportunity to the Board/Managing Committee to state its objection, if any, by order with reasons in writing, supersede the Board of the Co-operative Society for a period not exceeding six months and order that all or any of its members may be disqualified from being elected to the Board of the Co-operative Society for a period to be specified in the order not exceeding five years. Registrar shall record every order passed under this Section in writing and inform the concerned Co-operative Society through registered post. The Board shall thereupon cease to function:

Provided that in case of Co-operative Society carrying on the business of banking, provisions of Banking Regulation Act, 1949 shall also apply:

Provided further that in case of Co-operative Society carrying the business of banking the maximum period of supersession shall be of one year:

Provided further also that the dissolution of the Board of the Co-operative Society having banking operation shall be done in consultation with the Reserve Bank of India.

[1] [(2) Where the Registrar while proceeding to take action under sub-section (1) is of opinion that suspension of the Board is necessary in the interest of the Registered Society, he may suspend the Board which shall thereupon cease to function and make such arrangement as he thinks proper for the management of the affairs of the Registered Society till the proceedings under sub-section (1) are completed:

Provided that if the Board so suspended is not superseded it shall be reinstated after six months and the period during which it has remained suspended shall count towards its term.

[1] [(3) When any Co-operative Society is under supersession under sub-section (1), the Registrar shall appoint an Administrator to conduct the affairs of the Society The Administrator appointed under sub-section (1), shall take necessary action fo the holding of fresh election of the Board of the Co-operative Society within the specified period as under sub-section (1) and shall hand over the management to the newly elected Board:

Provided that the Registrar shall have the power to change the administrator during the period of supersession.

[1][(4) The Administrator appointed under sub-section (3) shall get remuneration, as may be fixed by the Registrar, as he deems fit to carry on the business of the Cooperative Society. The remuneration so fixed shall be payable from the accounts of Co-operative Society:

Provided that the Administrator appointed under sub-section (3) shall work under the service condition laid down by the Registrar and shall perform all the duties and carry on responsibilities assigned to the Board under this Act, Rules and the Bye-laws.]

(5) The Registrar may dissolve the Managing Committee of a registered society in case where-

(a) majority of the members and elected office-bearers of the Managing Committee of a registered society resign from their respective membership or office; or

(b) half the total number of seats of the Managing Coinmittee of a registered society, becomes vacant for any reason whatsoever;

and shall appoint Administrator for the better management of the registered society;

1. Subs. by Act 6 of 2013

Provided that if during the period of dissolution of the Managing Committee, the Registrar is satisfied that the affairs of a registered society have sufficiently improved and it is desirable to restore the management to a newly elected Managing Committee, he may by order direct that the Administrator shall take steps for the constitution of a new Managing Committee and on such Committee having been constituted in accordance with the provision of this Act and the Rules, the Administrator shall hand over the management to such newly constituted Managing Committee forthwith.

(6) An appeal shall lie from an order of the Registrar under sub-section (1) '[& sub section (2) to the State Government on application made by any member of the Managing Committee within '[one] month from the date of communication of the order to the registered society concerned. The order of the State Government on appeal, and subject to the result of such appeal, if any, the order of the Registrar shall be final.

(7) The Registrar may issue such direction to the Administrator as to his powers and duties and the affairs of registered society as the Registrar deems desirable and the Administrator may apply to the Registrar at any time for instruction as to the manner in which the Administrator shall conduct the management of the registered society.

(8) Nothing in this section shall be deemed to effect the powers of Registrar to order the windings up of a registered society under section 42 or to cancel the registration of the registered society under sub-section (8) of Section 44.] **Comments & case law**

[The word "dissolve" convey the meaning of putting an end to the very existence of the managing committee and cannot be revived. Sub-section (3) also indicates that the word "dissolve" has not been used in narrow sense. *Kamta Pathak vs. Registrar,* 1971 BRLJ (Rev.) 117.

,.. Where a meeting to elect office bearers was held when the High Court had issued a stay order, the Registrar was justified in holding such meeting void and appointing a special officer to look after the management of the society till fresh election according to law. *Nawal Kishore Pd. Sinha vs. State of Bihar,* 1982 PLJR 376: **AIR 1983** Pat. 8.

The provision of Sec. 41 (6) does not provide for alteration of the composition of the association rather it provides for taking over of the management for a specified period.

The provisions of Sections 41 (1) and 41 (6) take into consideration different circumstances and therefore the provision of Sec. 41 (6) is not discriminatory.

The power given to the State Government u/s 41 (6) to dissolve the managing committee without notice is for a specific purpose i.e. to act quickly under the particular circumstances where giving of notice may frustrate the purpose of taking such an action. However, since such a power will cloth the State Government with an arbitrary power which would be violative of the principles of natural justice and fair play, it is necessary for the Government to afford an opportunity to show cause against the decision soon after dissolution of the committee. *Brijesh Rai vs. State of Bihar,* 1982 PLJR 136: 1982 BBCJ 190.

The provisions of section 41 (6) only empower the State Government to pass a tentative order subject to the final decision in the matter. Therefore, the provisions of section 41 (6) cannot be said to be unconstitutional on the ground of being violative of principles of natural justice. *Md. Maqsood Alam vs. State of Bihar,* 1987 PLJR 958.

The real purpose of enacting sub-sections (6) to (10) of section 41 is to prevent a serious apprehended mismanagement of a Co-operative society, which cannot be averted except by action without delay. There must be some material to justify such an apprehension, to validate an order under section 41 (6). *ibid.*

Where the Board of Directors is superseded by the Registrar of Co-operative Societies, the authority appointed by the Registrar to exercise the powers of the

1. Subs. for words "three" and sub-section (2) added by (Amdt.) Act 10 of 2002.

erstwhile Board of Directors has no power to divest itself of the power conferred by the Registrar and to invest another person with that power. *Gwalior District* C*ooperative Central Bank Ltd. vs. Ramesh Chandra Mangi,* AIR 1987 SC 337: 1984 (Supp) SCC 528.

The two grounds for dissolution stated in section 41 (6) clearly visualise a situation in which the Board of Directors is in existence and its continuance is detrimental to the Co-operative Society itself. This provision does not envisage a situation in which the Board of Directors has disappeared completely or lost its existence. Where the order of dissolution is based on report assailing the conduct of the General Body of the society and not that of the Board of Directors, the order of dissolution will be unjustified and without substance. *Vijay Kumar Mishra vs. State of Bihar,* 1988 PLJR 478.

Where it is specifically mentioned in the notification that it is to remain in force until further orders, the Government is empowered to issue a fresh notification making a fresh committee. Therefore, setting up of a new committee replacing the committee earlier set up for the purpose even during the currency of it cannot be termed as supersession or removal of that committee.

The notification which is to remain in force till further orders does not confer any legal right on the members of the committee- mentioned in the notification and. therefore where a new notification is issued by the Government with a new committee it cannot be said that it was necessary on the part of the Government to have provided to the members of the old committee a hearing, otherwise it amounts to infringement of the rule of natural justice. *Radheshyam Singh vs. State of Bihar,* 1981 BRLJ 233: 1981 BLJR 497: AIR 182 Pat. 35.

Where managing committee of a society has been superseded, and a committee of Administrators appointed, no tenure for members of committee or Administrator is fixed. This Committee can be reconstituted by dropping some of the members without the dropped members being entitled to a hearing before order of removal by the Registrar. *Padma Charan Samant Singhar vs. Registrar,* AIR 1981 Orissa 150. *See also Parmeshwara Bagh vs. State ofOrissa,* AIR 1981 Orissa 154.

Where written consent of financing Bank has been obtained prior to the passing of order of supersession of managing committee of a co-operative society, the order of supersession is not vitiated on account of any defect in notice to the Bank, since no further notice was required under law. *Durga Shankar Kar vs. State of Orissa,* AIR 1982 Orissa 20.

Order of supersession passed by Assistant Registrar by virtue of powers of Deputy Registrar delegated to him, cannot be said to be without jurisdiction. *ibid.*

Where the Managing Committee of a Co-operative Bank has been superseded by an order of the Registrar, the Special Officer appointed under section 41 has jurisdiction to discharge the functions of the erstwhile Managing Commitee. The Special Officer, acting as the Disciplinary Authority is competent to reject the findings of an Enquiry Committee. However, in such cases, the Special officer must record his reasons for coming to a contrary conclusion, and the contrary finding by him must be based on the materials on record. *Special Officer vs. Madan Prasad,* 1986 PLJR **(NOC)** 74.

The power of State to act under sub-section (9) of section 41 is not available where the initial order had been passed by the Registrar under section 41 (1). The power conferred on the State Government by section 41 (9) can be exercised only in cases where the order of supersession was passed by the State Government itself in exercise of power under section 41 (6). *Prabhu Dayal Singh vs. State of Bihar,* 1987 PLJR 645.

Removal of office bearers of a society without opportunity of hearing is violative of principles of natural justice. *Narsingha Charan Acharya vs. State of Orissa,* AIR 1985 Orissa 62.

Under this section it is only the Registrar who has power to direct to special

officer to terminate services of an employee. *Nandkishore Roy vs. The State of Bihar,* 1989 (1) BL.J 472.

Sub-section (9) of this Section is applicable only in cases of supersession of the managing committee of the co-operative society but shall not override the special provisions under Sub-sections (5) and (6) of this Section which are applicable in cases where the old managing committee ceases to exist. As a result of corning into force of sub-section (5) of this Section a fresh election is to be held. *Vidya Singh vs. The State of Bihar,* 1989 (1) BLJR 513.

If for any reason election is not held after expiry of 3 years term of the members and within the extended period of 9 months in view of section 14 (9). the managing committee of such co-operative society shall be deemed to have been superseded with effect from the said date under this section of the Act. *Nawal Kishore vs. The State of Bihar,* 1991 (1) PLJR 572.

In a proceeding initiated under this Section, it is open to the Registrar to make an interim order of suspension while proceeding to take action under this Section the order of interim suspension shall be deemed as separate and independent order, although contemporaneous and cannot be said to be a composite order. *Saathi Joint Farming Co-operative Society Ltd. vs. The Registrar,* 1991.(1) PLJR 625: 1991 (1) BLJR 265. .

Section 41(6)-supersession of Co-operative Society and taking over of its management by State Government-nature of power. *Brij Bihari Singh vs. State of Bihar,* 1990(2) PLJR 217.

Sections 41 and 48---no election of a Board of Directors can be set aside except by filing an election petition-no election can be said to be void *ab initio* merely on the *suo motu* assessment of a party or the Government-the Government or the appellate authority cannot abrogate to itself the authority to declare an election void even if according to it correct procedure was not followed and it cannot proceed to effectively destroy the result of the election by resorting to dissolution of the Board of Directors. *Vijay Kumar Mishra vs. State of Bihar,* 1989 PLJR 846. •

Section 41--Limitation on power of the Registrar for supersession of managing committee. *Chandeshwar Prasad vs. State of Bihar,* 1987 PLJR 159 (FB).]

Dissolution of a society can be done in accordance with provisions of section 41 and Administrator can be appointed by Registrar after dissolution of society under sub-section (1) or (5) of section *41. Virendra Kumar Roy vs. State of Bihar, 2005(1)* PLJR423.

Order of Managing Director deaffiltating the petitioner Bank from the Apex Bank challenged before Registrar. Registrar, on the recommendation of Managing Director of the Apex Bank issuing show cause as to why the Board of Directors of the petitioner Bank be not suspended. First and foremost requirement u/s 41 (1) even for issuing show cause notice being satisfaction to be recorded by Registrar and opinion to be formed. Registrar neither recording satisfaction nor forming opinion and simply referring to recommendations of the Managing Director of Apex Bank. Show cause notice patently illegal. *Raj Kishore Prasad vs. State of Bihar,* 2005(4) PL ·'R 571.

Registrar has to form an opinion about the existence of the grounds before issuing a notice inviting objection. Such opinion should be subjective one based on materials. Recording of pnma facie satisfaction about the existence of the grounds before issuing trie notice and the materials for forming the opinon being before the Registrar then it cannot be said that the Registrar issued the notice without forming an opinion. It there are some materials before the authority to form an opinion then its sufficiency cannot be gone at the initial stage of issuance of notice. *Bihar State Cooperative Bank vs. State of Bihar,* 2005(2) PLJR 665.]

1. Subs. by Act 6 of 2013
1. Subs. by Act 6 of 2013

"[1][42. ***Winding-up order.-The*** Registrar may, by notification, order a registered Co-operative Society to be wound up if-

(a) on receipt of a request for the winding-up of the Society by, special resolution passed by three-fourth of the members of the Society,

(b) after an inquiry has been held under Section 35 or an inspection made under Section 34, Section 36 or Section 37, the Registrar is of the opinion that winding-up of the Society is necessary in the interest of members, or

(c) if a Society has not commenced working after registration or has ceased working.

(d) if the number of the members of the Society has been reduced to less than ten contrary to the condition of registration:

Provided that such order can only be passed after giving a notice of one month and providing opportunity of hearing to the shareholder members and persons/institutions having interest in the Society."

Comments & case-law

[The order of supersession can only be passed after giving a showcause notice. The contemplates interim suspension it is necessary in the interest of the society. The Registrar has to make necessary arrangements for the management of the airs of the society till the proceeding under sub-section 1 of the Section is com<te. Thus the suspension is only interim in nature. *Saathi Joint Farming Co-operative Society vs. The Registrar,* 1991 (1) PLJR 625: (1991) 1 BLJR 265.

Section 42--if the Registrar proposes to pass an order of winding up of a Societ• · the Society or the concerned office bearers must be informed about the reasons or he grounds on which he proposes to make such an order-the absence of such opportunity will make the order bad in law and cannot be sustained. *Bihar Co-op. Fruits & Veg. Mktg. Fed. Ltd. vs. State of Bihar,* 1996(2) PLJR 796.

Section 42---even though the section from a plain reading does not contemplate any prior notice and opportunity of hearirg, the need for such notice or opportunity of hearing has to be read impliedly because otherwise such order would violate the principles of natural justice in view of the nature of the order which would definitely visit the Society and the concerned persons with civil consequences. *ibid.]*

43. Appeal against the order of winding up.-'["(1) Any member of a Society or person/institution having interest in it, may appeal against an order passed under Section 42 to the State Government, within two months from the date of the publication of such order in the Official Gazette."

(2) An order under section 42 shall not take effect until the expiry of two months from the date of the publication of such order in the official Gazette or, if an appeal be preferred, unless and until it is confirmed by notification on appeal.

(3) The order of the State Government on appeal and, subject to the result of such appeal, if any, the order of the Registrar shall be final.

Comments & case-law

[The Registrar of Co-operative Societies has clearly no jurisdiction over a person who neither is not has been member of a Co-operative Society. but has jurisdic'tion over a past member under section 43 of this Act. It cannot be said that this award is without jurisdiction merely on the ground under the claim was barred by limitation or because the award was a second award in respect of the same debt which was the subject matter of prior award. These points are clearly within the Registrar's jurisdiction and the fact that the falls into an error of law in deciding them does not make his award any way less valid. *Burhitola D. Co-op. Society vs. Shambhunath Singh,* 23 PLT 104.)

1. Subs. by Act 6 of 2013

44, Liquidation and dissolution.--(1) Where the Registrar has passed an order for the winding up of a registered society, he shall appoint a person or persons to be liquidator of the society.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 43, a liquidator on appointment shall have power to take immediate possession of all assets belonging to the society and all books, records and other documents pertaining to the business thereof and to carry on the business of the society so far as may be necessary, and all the rights, duties, assets and liabilities of the society shall be vested and shall devolve upon the liquidator as such.

(3) Subject to the Registrar's power of control and revision, **such** liquidator shall also have power-

(a) to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the society by his name of office;

(b) to determine and realise all sums due to the society from any person;

(c) to determine from time to time, subject to the provisions of section 32, the contribution to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by any officers or former officers, to the assets of the society and from time to time, to revise any order of contribution until the winding up is completed, and to realise such contribution;

(d) to investigate all claims against the society and subject to the provisions of this Act, to decide questions of priority arising between claimants after giving an opportunity of being heard to all the creditors;

(e) to pay claims against society the (including interest) up to the date of the publication in the official Gazette of the notification ordering the winding up of the society according to their respective priorities, if any, in full or rateably as the assets of the society permit; and to apply the surplus, if any, remaining after payment of the claims in full, in payment of interest from the said date of a rate fixed by him but not exceeding in any case the rate agreed to be paid by the society;

(f) to make any compromise or arrangement with persons between whom and the society there exists any dispute or to refer any such dispute to arbitration;

(g) to determine by what persons and in what proportions the cost of the liquidation are to be borne; and

(h) to give such directions in regard to the collection and distribution of the assets of the society as may appear to him to be necessary for winding up the affairs of the society;

Provided that the liquidator shall not determine the contribution, debt or assets to be recovered from any person unless an opportunity of being heard has been given to such person.

(4) If an appeal from the order of winding up is allowed by State Government under section 43, the liquidator shall give up possession of the assets, books; records and other documents of the society or the managing committee; and shall cease to carry on the business of the society, provided that all his acts done in his

capacity as liquidator shall continue to have legal validity as if they had been done by the managing committee or the society.

(5) With the special sanction of the Registrar, an appeal shall lie to the Court of the District Judge within three months from the date of communication by registered post of an order of a liquidator under clauses (b), (c), (d), (e), (g) or {h) of sub-section (3) to the person concerned.

(6) The order of the liquidator, subject to any order of the Registrar in revision or to any order of the District Judge on appeal, if any shall be final.

(7) When the affairs of the society have been wound up, the liquidator shall deposit the records of the society in such place as the Registrar may direct.

(8) After the records of a society have been deposited under sub-section (7), the Registrar shall cancel the registration of the society and the society shall then cease to exist as a corporate body,

Comments & case-law

[Determination of contribution-Opportunity of being heard should be given to members-- Effect of non-compliance-Order by liquidator, to be without jurisdiction. AIR 1955 Orissa 158.

Principles governing exclusion of jurisdiction of civil court See AIR 1935 Orissa 300.]

'[CHAPTERVI-A

Land Development Banks

44/4, Definitions.---In this Chapter, unless context otherwise requires.

(a) 'Board' means the managing committee of the State Co-operative Land Development Bank;

(b) 'Land Development Bank' includes the State Co-operative Land Development Bank and the Primary Co-operative Land Development Bank;

(c) 'Prescribed' means prescribed by rules made under this Chapter;

(d) 'Primary Co-operative Land Development Bank' means a registered society of that name;

(e) 'State Co-operative Land Development Bank' means registered society of that name, registered under section 11, and includes the Bihar State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd. registered as such under section 11; and

(f) 'Trustee' means the Trustee referred to in section 44-C.

448. Applications of Chapter to Land Development Banks.---The provisions of this Chapter shall apply to Land Development Banks advancing loans for all or any of the purposes herein enumerated, that is to say-

(i) land improvement and productive purposes;

(ii) the redemption of mortgages on lands;

(iii) the redemption of mortgages an other valuable immovable property subject to such conditions as may be prescribed;

(iv) the liquidation of debts of agriculturists subject to such restrictions as may be prescribed;

1. Chapter VI-A with sections 44-A to 44-0 ins. by Act 39 of 1982 and shall be deemed to *have* been ins. from 25th June, 1968.

(v) the purchase or acquisition of title to agricultural lands by tenants; or (vi) the erection, re-building or repairing of houses for agricultural purposes.

Explanation.--"Land improvement and productive purposes' means any work, construction or activity which adds to the productivity of the land, and, in particular, includes the following, that is to say.

(a) construction and repair of wells (including tube-well, tanks and other works) for the storage, supply or distribution of water for the purpose of agriculture or for the use of men and cattle employed in agriculture;

(b) renewal or reconstruction of any of the foregoing **work;**

(c) preparation of land for irrigation;

(d) drainage, reclamation from river or other waters or protection from floods or from erosion or other damage by water, of land used tor agricultural purposes or waste land which is cultivable;

(e) bunding and similar improvements;

(f) reclamation, clearance and enclosure of permanent Improvement of land for agricultural purposes; (g) horticulture:

(h) purchase of oil-engines, pumping sets and electrical motors for any 0f the purposes mentioned herein;

(i) purchase of tractors or other agricultural machinery;

(j) increase of the productive capacity of land by addition to it of special variety of soil;

(k) construction of permanent farm-house, cattle sheds and sheds for processing of agricultural produce at any stage;

(I) purchase of machinery for crushing sugarcane, manufacturing gur or Khandsari sugar or sugar;

(m) purchase of land for consolidation of holdings;

(n) digging canals;

(nn) the establishment of poultry, fishery, dairy, piggery and sheep repairing, etc. and

(o) such other purposes as the State Government may, from time to time, by notification in the official Gazette declare to be improvement or productive purpose for the purposes of this Chapter.

44C. Appointment of Trustee and his powers and functions.--(1) The Registrar, or where the State Government appoint any other person in this behalf, such person shall be the Trustee for the purpose of securing the fulfilment of the obligations of the State Co-operative Land Development Bank to the holders of debenture issued by the Board.

(2) The powers and functions of the Trustee shall be governed by the provisions of this Chapter and by the instrument of trust executed between the State Cooperative Land Development Bank and the Trustee, as modified from time to time by mutual agreement between the Board and the Trustee.

44D. Trustee to be a corporation sole.--The Trustee shall be a corporation sole by the name of the Trustee for the debenture and as such shall have perpetual succession and a common seal and in his corporate name may sue and be sued.

44E, Issue of debenture by the Board.--(1) With the previous sanction of the Trustee, and subject to such terms and conditions as he may impose, the Board may from time to time, issue debentures of such denominations for such period as ꝑ'Tay deem expedient on the security of the mortgages held or mortgages partly helg and partly to be held and either transferred or deemed to have been transferred, *under the* provisions of section 44-J, to the Co-operative Land Development Bark and other properties of such Banke

Provided that notwithstanding anything contained in this sub-section regarding issue of debentures on security of mortgages, it shall be competent for the Board **with** the previous sanction of the trustee, and subject to such terms and conditions as it may impose to issue debentures in the security *of* the Government guarantee regarding re-payment of principal and payment of interest thereon in respect of *loans* issued to the corporate bodies implementing special schemes of agricultural development, irrigation etc, on the basis of Government Guarantee.

(2) Such debentures may contain a term fixing a period not exceeding thirty years, from the date of issue, during which they shall be redeemable, or reserving to the Board *the* right, to *call* in at any time any of the debentures in advance of the date fixed for redemption, after giving to the debenture holders concerned not less than three month's notice in writting.

(3) The total amount due on the debentures issued by the Board including those issued before the commencement of the Bihar Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1975 and outstanding at any time shall not exceed the aggregate of-

(a) the amounts due on the mortgages:

(b) The value of the properties and other assets transferred or deemed to have been transferred under section 44-J to the State Co-operative Land Development Bank and subsisting at such time;

(c) the amounts paid under the mortgages aforesaid and remaining in the hands of the Board *or* of the Trustee at that time;

(d) the amount due on the Government guarantee on the basis of which loans have been issued to corporate bodies.

(4) Debentures in excess of the limit specified in sub-section (3) may be issued with permission *of* the Trustee.

44F, *Vesting* of mortgaged property in the Trustee and floating charge of debenture holders.--Upon the issue of debentures under the provisions *of* section 44E, the mortgages, properties and other assets, referred to in sub-section (3) of that section, held by the State Co-operative Land Development Bank shall vest in the Trustee and the holders of debentures shall have floating charge on all such mortgages, properties and assets and on the amount paid under such mortgages and remaining in the hands of the State Co-operative Land Development Bank or of the Trustee.

44G. Guarantee by the State Government of principal and interest on debentures.-(1) The State Government may, if in their opinion it is necessary in the public interest so to do, and subject to such terms and conditions as the State Government may think fit to impose, guarantee the principal of and interest on the debentures issued by the Board, including debentures, if any, issued prior to the commencement of Bihar Co-operative Societies (Amendmbnt) Ordinance, 1975 subject to such maximum amount as may be fixed by the State Government.

(2) The State Government may, subject to the provisions of any Act in that regard, increase the maximum amount of any guarantee given under sub-section.(1).

44H. Priority of mortgage, over claims.--(1) Mortgage executed in favour of a Land Development Bank shall have priority over **any** claim of the State Government arising from a loan, under the Land Improvement Loans Act, 1883 (19 of 1883), of the Agriculturists' Loans Act, 1884 (12 of 1884) or any other law for the time time being in force, granted subsequent to the execution of the mortgage.

(2) A mortgage executed in favour of a Land Development Bank shall have priority also over the claim of any other person arising out of a mortgage of any description executed or any other charge created, after the issue of a public notice under section 44. C in respect of the property of the loanee specified in the said public notice.

441. Right of Land Development Bank to purchase mortgaged property.- Notwithstanding the provisions contained in the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land} Act, 1961 (Bihar Act XII of 1962) but subject to any tenancy law for the time being in force, it shall be lawful for Land Development Bank to purchase any mortgaged property sold under this Chapter, and the property so purchased shall be disposed of by such bank by sale in such manner and within such period as may be fixed by the Trustee:

Provided that a purchaser of such mortgaged property from a Land Development Bank shall purchase it subject to the provisions of the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 (Bihar Act XII of 1962).

44J. Mortgages executed in favour of Land Development Bank to stand vested in Trustee.--The mortgages executed in favour of and all other assets transferred to the State Co-operative Land Development Bank by its members, either before or after the commencemnt of the Bihar Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1975 shall vest in the Trustee with effect from the date of such execution or transfer and likewise mortgages or transfer of assets in favour of Primary Co-operative Land Development Bank by its members shall be deemed to have been transferred to the State Co-operative Land Development Bank and shall vest in the Trustee.

Comments and case-law

[The Registrar of Co-operative Societies is empowered under section 44AJ to rescind or cancel the Resolution of the Board of Directors within four weeks from the date of receipt of the copy of Resolution. However, any order passed by the Registrar after expiry of period of four week in pursuance to directions of the High Court cannot be held to be illegal or without jurisdiction. *Ajay Kumar Mishra vs. Registrar,* 1995 (2) PLJR 397.

Reservation of seats for Scheduled Castes / Scheduled Tribes and others cannot be in addition to total strength of Board of Directors provided under law .H.L. *Roche vs. Citizen Co-operative Bank Ltd.* AIR 1996 Born 126.]

44K. Power of Primary Land Development Bank to receive money and grant discharge.--Notwithstanding that a mortgage executed in favour of a Primary Land Development Bank has been transferred or is deemed, under provisions of section 44-J, to have been transferred to the State Co-operative Land Development Bank--

(a) *all* moneys due under the mortgage shall, in the absence *of* any specific direction to the contrary issued by the Board of Trustee and communicated to the mortgagor, be payable to the Primary Land Development Bank and such payment shall be as valid as if the mortgage had not been so transferred; and

(b) the Primary Land Development Bank shall, in the absence of any specific direction to the contrary, issued by the Board of Trustee and communicated to the Primary Land Development Bank, be entitled to sue on the mortgage or take any other proceeding, including a proceeding under this Act, for the recovery of the moneys due under the mortgage.

44L. Registration of mortgage in favour of Land Development Bank.- Notwithstanding anything contained in the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), it shall not be necessary to register mortgages executed in favour of Land Development Bank provided that the Land Development Bank concerned sends within such time and in such manner as may be prescribed a copy of the instrument; whereby movable or immovable property is mortgaged for the purpose of securing repayment of the loan to the Registering Officer within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property mortgaged is situate, and such Registering Officer shall file a copy or copies, as the case may be, in his Book no. 1 prescribed under section 51 of the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908).

44M. Power of Land Development Bank to pay prior debts of mortgagors and secure consequential reliefs.--(1) Where a mortgage is executed in favour of a Land Development Bank for payment of prior debts of the mortgagor, such Bank may, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 '(4 of 1882) by such notice in writing may be prescribed, require any person to whom any such debts is due to receive payment of such debt or part thereof from the Bank at its registered office or any of its branch offices within.such period as may be specified in the notice.

(2) Where any such person fails to receive such notice or such payment, such debt or part there of, as the case may be, shall cease to carry interest from the expiration of the period specified in the notice;

Provided that were there is a dispute as regards the amount of any such debt, the person to whom such debt is due may refer the dispute to Registrar for decision in accordance with provisions of section 48:

Provided further that the person to whom such debt is due shall, pending the decision in the dispute, be bound to receive payment, of the amount offered by the Land Development Bank towards the debt but such receipts shall not prejudice the right, if any, of person to recover the balance claimed by him.

(3) Where a notice has been served under sub-section (1) on any person for receiving payment of his dues, such person shall be bound to deliver possession, to the mortgagor, or any property held in usufructuary mortgage for the debts due on or before the date specified in the aforesaid notice: •

Provided that the may deliver possession of any agricultural land after harvesting of the standing crop, if any, and in such an event he shall be entitled to receive the amount due to him from the Land Development Bank on the date of delivery of possession given to the mortgagor.

(4) Where a person holding any property in usufructuary mortgage refuses

delivery of possession in the manner indicated in sub-section (3), the Collector shall, on an application of the Land Development Bank made in this behalf. after making a summary enquiry reject the mortgagee and restore the mortgaged land to the mortgagor and the mortgage shall thereupon be deemed to have terminated.

(5) The provisions of this section shall be subject to any tenancy laws for the time being in force:

44N. Powers bf Land Development Bank to advance loans and to hold lands.- Subject to the provisions of this Act and in accordance with the rules made thereunder, it shall be competent for a Land Development Bank to advance loans for the purposes referred to in section 44-B and to hold lands the possession of which is transferred to it under the provisions of this Chapter.

440. Public notice for entertaining objection.---(1) When an application for a loan is made for any of the purposes mentioned in section 44-B, a public notice shall be given of the application in such manner and form as may be prescribed, calling upon all persons interested to make their objections to the toan, if any, before the date specified therein. The person by whom such public notice shall be given and the manner in which the objection shall be disposed of by him shall be such as may be prescribed. Copies of such public notice shall also be sent separately to such persons and within such time as may be prescribed.

(2) The person empowered to give notice under sub-section (1) shall consider every objection made under that sub-section and pass an order in writing either upholding or overruling it. When the objections is overruled, he shall recommend the application to the Land Development Bank for its consideration:

Provided that when the question raised by an objection is, in the opinion of such person, one of such a nature that it cannot be satisfactorily decided except by a Civil Court, he shall postpone the consideration of the application until the question has been so decided.

(3) A notice under sub-section (1) published in the manner prescribed, shall for the purpose of this Act, be deemed to be proper notice to all persons having or claiming interest in the land to be improved, or offered as security for the loan.

(4) Where an application is recommended under sub-section (2) the Land Development Bank shall, in accordance with the rule made by it in this behalf, consider such application for the purpose of making the loan.

5. Where no objection under sub-section (1) has been made the question at issue shall be decided by the person empowered to consider objections in such manner as he may deem proper and no person shall have any claim what-soever including any claim arising out of a mortgage of any description against the property of the loanee for which the loan applied for is sanctioned, under the provisions of this Chapter, until such time as the loan together with interest thereon or any other dues arising out of the loan are paid in full.

44P. Mortgage executed by managers of Hindu joint families or natural or legal guardians of minors or disabled persons.-(1) Mortgages, in respect of loans by a Land Development Bank either before or after the commencement of the Bihar Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1975 by the manager of a Hindu joint family or the natural or legal guardian *of* a minor or disabled person for any of the purposes specified in section 44-B, shall be binding on every member of such Hindu joint family, or such minor or disabled person, notwithstanding any law to the contrary.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), where a mortgage executed in favour of a Land Development Bank, either before or after the commencement of the Bihar Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1975, is called in question on the ground that it was executed by the Manager of a Hindu joint family or a natural er legal guardian of a minor or disabled person for a purpose not binding on the members of such Hindu joint family or such minor or disabled person, the burden of proving the same shall, notwithstanding any law to the contrary, lie on the party. alleging it.

44Q. Order granting loan conclusive of certain matters.-Written order by the Land Development Bank, or person or managing committees authorised by this Chapter or undr the bye-laws of the bank to make loans for all or any of the purposes specified in section 44-B granting either before or after the commencement of the Bihar Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1975, a loan to or with the consent of a person mentioned therein for the benefit of the land or for the productive purpose specified therein, shall be conclusive of the following matters namely:-

(a) that the work described or the purpose for which the loan is granted, is an improvement or productive purpose; as the case may be, within the meaning of section 44-B;

(b) that the person had on the date of the order a right" to make such improvement or incur expenditue for such productive purpose, as the case may be; and

(c) that the improvement is one benefitting the land specified and the productive purpose concerns the land offered as security or any part thereof as may be relevant.

44R. Recovery of loan by Land Development Bank.--Any loan granted by a Land Development Bank, including any interest chargeable thereori and, such cost, if any as may be prescribed incurred in connection therewith shall, when they become due, be recoverable by the bank concerned:

Provided that such loan, interest or cost may be recoverable also by the State Co-operative Land Development Bank even if the loan has been granted by a Primary Co-operative Land Development Bank affiliated to it.

44S. Collector to make recoveries during certain period.--(1) During such period as the State Government may, by general or special order, notifying in the official Gazette, it shall be competent for the Collector, on application being made to him in this behalf by a Land Development Bank, to recover all sums due to the Bank, including the cost of such recovery.

(2)The Collector or any person specially authorised by him in this behalf, shall recover all sums due to a Land Development Bank in the following order and manner, namely:

(a) from the borrower as if they were in arrears of land revenue due by him.

(b) out of the land for the benefit of which the loan has been granted as if they were arrears of land revenue in respect of that land.

(c) from a surety, if any, as if they were arrears of land revenue due by him;,

(d) out of the property comprised in the collateral security, if any according to the procedure for the realisation of land revenue **by** the sale of immovable property other than the land on which the/revenue is due.

(3) the provisions of this section shall be subject to any tenancy law for the time being in force.

A4T, Distraint and sale.--(1) lf any instalment payable under mortgage executed in favour of a Land Development Bank or any part of such instalment has remained unpaid for more than one month from the date on which it fell due, the managing committee of such a bank or the Board may, in addition to any other remedy available to the bank, apply to the Registrar for the recovery of such instalment of part there of by distraint and sale the produce of the mortgaged land, including the standing crops thereon, and any other movable property of the default in the manner prescribed. On receipt of such application the Registrar may, after giving registered notice to the mortgagor notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882), direct distraint and sale of such produce and, if necessary, also of such other movable property of the defaulter:

Provided that such implements of husbandry other than the implements mortgaged to the Land Development Bank, and such cattle of the defaulter as may, in the opinion of the Registrar, be necessary to enable the defaulter to earn his livelihood as an agriculturist shall not be liable for such distraint and sale:

Provided further that no such distraint shall be made after the expiry of twelve months from the date on which the instalment fell due.

(2) The value of the property distrained shall be, as far as may be, equal to the amount due, and the expenses of the distraint and the cost of the sale.

44U. Powers of sale when to be exercised.-(1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882). where a power of sale without the intervention of the court is expressly conferred on a Land Development Bank by the mortgage deed, the managing committee of such bank or the Board or any person authorised by such managing committee or the Board in this behalf shall, in case of default of payment of mortgage money or any part thereof, have power, in addition to any other remedy available to the bank, to bring the mortgaged property to sale without the intervention of court.

(2) No such power shall be exercised unless and until-

(a) the Bo rad has previously authorised the exercise of the power conferred by sub-section (1) after considering the representation, if any, of the mortgagor;

(b) the registered notice requiring payment of such mortgage money or part thereof has been served upon-

(i) the mortgagor;

(ii) any person who has any interest in, or charge upon the property mortgaged or in or upon the right to redeem the same;

(iii) any surety for the payment of the mortgage debt or any part there of; and

(iv) any creditor of the mortgagor who has in a suit for the administration of his estate obtained a decree for sale of the mortgaged property; and.

(c) default has been made in payment of such mortgage money or part thereof, for three months after service of notice in this behalf,

44V, Powers of Land Development Bank where mortgaged property is destroyed or security becomes insufficient-Where any property mortgaged to a

Land Development Bank is wholly or partially destroyed or for any reason the security is rendered insufficient and the mortgagor, having been giyen a reasonable opportunity, by the managing committee of the said bank or the Board of providing further security enough to make the whole security sufficient or of re-paying such portion of the loan as may be determined by the managing committee or the Board has fail*ed* to provide such security or to repay such portion of the loan the whole of the loan shall, notwithstanding its terms and conditions, be deemed to fall due at once and the managing committee or the Board shall be entitled to take action against the mortgagor, under section 44-S or section 44-T or section 44-U, for the recovery thereof.

Explanation.--For the purpose of this section, security shall be deemed to be insufficient unless the value of the mortgaged property, including improvement thereon, exceeds the amount for the time being, due on the mortgage by such proportion as may be specified in the rules or the bye-laws of the Land Development Bank.

44W. Power of the Board orTrustee to take action against defaulters.--(1) The Board or the Trustee may direct the managing committee of a Primary Cooperative Land Development Bank to take action against a defaulter under sections 44-S, 44-T, 44U or 44-V and if the managing committee neglects or fails to do so, the Board or the Trustee may take such action. The Trustee may direct the Board to take similar action against a defaulter and on the Board's neglect or failure to do so, may take such action himself.

(2) Where an action is taken under the provisions of sub-section (1) by the Board, the provisions of this Chapter or any rules made in pursuance there of shall apply as if all references therein to a Primary Co-operative Land Development Bank and its managing committee were references to the State Co-operative Land Development Bank and the Board.

(3) When an action is taken under the provisions of sub-section (1) by the Trustee, the provisions of this Chapter or any rules made in pursuance thereof shall apply as if all references therein to Primary Co-operative Land Development Bank and its managing committee or the State Co-operative Land Development Bank or the Board were references to the Trustee.

44X. Confirmation of sale.-Where any mortgaged property is sold under the provisions of section 44-U by a Primary Land Development Bank, the Bank shall, in the manner prescribed, submit to the State Co-operative Land Development Bank and the Registrar a report setting forth the manner in which the sale has been effected and the result of the sale. Where the sale is made by the State Co-operative and Development Bank or the Trustee is a person other than the Registrar. Similar Report shall be submitted by the Board or the Trustee as the case may be, to the Registrar,

(2) After the report aforesaid has been submitted to the Registrar the managing committee of a Primary Co-operative Land Development Bank or the Board of the Trustee, as the case may be, may with the approval of Registrar, confirm or cancel the sale within one hundred and twenty days of the date of sale.

(3) Where the Registrar is the Trustee and has taken action pursuant to subsection (1) of section 44-W, he may confirm or cancel the sale of the mortgaged property of his own motion or on the application of a Land Development Bank within

one hundred and twenty days from the date.

(4) Upon the mortgagor or any person having a right, title or interest in the mortgaged property applying to the managing committee of a Land Development Bank or the Board or the Trustee or the Registrar as the case may be, tor setting aside the sale after having deposited at the Office of the Land Development Bank concerned such sums of money as may be sufficient tor payment of the amount specified in the notice served under clause (b) of sub-section (2) of section 44-\U together with subsequent interest and costs, if any, incurred during the process of sale and a commisson, tor payment to the purchaser, or a surn equal to five percent of the purchase money deposited by him, the sale of the mortgaged property shall be cancelled under the provisions of sub-section (9) or (3) of this section.

(5) When sale is confirmed under the provisions of this section it shall become absolute and shall be deemed to be absolute tor the purpose of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

44V. Disposal of sale proceeds.-(1) The proceeds of the sale, effected under this Chapter shall be applied first to the payment of all costs, charges and expenses incurred in connection with the sale or attempted sales, secondly to the payment of any or all interest due on account of the mortgage in consequence whereof the mortgaged property was sold and thirdly to the payment of the principal due on account of the mortgage including cost and charges incidental to the recovery.

(2) If there remains any residue from the proceeds of sale referred to under subsection (1), the same shall be paid to the person proving himself interested in the property sold, or if there are more such persons than one, to such persons upon their joint receipt or according to their respective interest therein:

Provided that, before such payments are made, the unsecured dues owing from the mortgagor to the Land Development Bank may be adjusted.

44Z. Certificates of purchase, delivery of property and title to purchaser. Where a sale of mortgaged property has become absolute the Bank shall grant a certificate to the purchaser, in the prescribed form, specifying the property sold, the sale-proceeds, the date of its sale, the name of the person who at the time of the sale is declared to be the purchaser, and the date on which the sale become absolute and upon the production of such certificate, the Sub-Registrar appointed under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) within the limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property specified in the certificate is situated shall enter a copy of such certificate in the relevant book maintained for such purpose.

(2) Where a mortgaged property is sold under the provisions of this Chapter and a certificate is granted to the purchaser under the provisions of sub-section (1), Collector shall, on the application of the purchaser, his, their or successor-ininterest, order delivery of .possession to be made to such a person and shall put in possesston such a person or his nominee.

44AA.Title of purchaser not to be questioned on ground of irregularities, etc.-- Where any property is sold in exercise of power of sale under this Chapter, the title of the purchaser shall not be questioned on the ground that-

(a) the circumstances required for authorising the sale had not arisen,

(b) due notice of the sale was not given, or

(c) the power of sale was otherwise improperly or irregularly exercised; but any person who has suffered any damage by an unauthorised, improper or irregular exercise 'bf such power is entitled to have a remedy in damage against the Land Development Bank.

44AB. Mortgage not to be questioned on insolvency of mortgagor.--Notwithstanding anything in any law relating to insolvency, a mortgage executed in favour of a Land Development Bank shall not be called in question on the ground that it was not executed in good faith for valuable consideration or on the ground that it was executed in order to give the Land Development Bank a preference over the other creditors of the mortgagor.

44AC. Appointment of receiver and his powers.--(1)The Board may, of its own motion or on the application of a Primary Land Development Bank and under circumstances in which the power of sale conferred by section 44U may be exercised, appoint in writing a person other than member of the managing committee of the Land Development Bank concerned to be the receiver of the produce of and income of the mortgaged property or any part thereof and such receiver· shall be entitled either to take possess on of the property or collect its produce and income, or both, as the case may be, to retain out of any money realised by him in expenses or management including his remuneration, if any, as fixed by the Board and to apply to balance in accordance with the provisions of sub-section (8) of section 69A of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882).

(2)The Board may, for sufficient cause; removes such receiver on an application made by the mortgagor and fill the vacancy in the office of the receiver.

(3) Nothing in this section shall empower the Board to appoint a receiver where the mortgaged property is already in the possession of a receiver appointed by a competent court.

44AD. Restrictions on leases.--(1) Notwithstanding anything contained in the transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882), or any other law for the time being in force, no mortgagor of property mortgaged to a Land Development Bank shall, except with the prior consent in writing of the bank and subject to such terms and conditions as the bank may impose lease or create to any tenancy rights or any other right, title, or interest in any such property:

Provided that the rights of the Larid Development Bank shall be enforceable against the lessee or the tenant, or any other person, as the case may be, as if he himself were a mortgagor.

(P) Where the land, mortgaged with possession to a Land Development Bank, is in actual possession of a tenant, the mortgagor or the Land Development Bank shall give notice to the tenant to pay rent to the Land Development Bank during the currency of the lease and the mortgage and on such notice being given, the tenant shall be deemed to have attorned to the Land Development Bank.

44E, Registration of documents executed on behalf of a Land Development Bank.-(1)Notwithstanding anything in the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), it shall not be necessary for any officer of a Land Development Bank to appear in person or by any agent at any registration office in any proceedings connected with the registration of any instrument executed by him in his official capacity or to sign as provided in section 58 of that Act.

(2) Where any instrument is so executed, the Registering Officer to whom such

instrument is presented for registration may, if he thinks fit, refer to the aforesaid officer of the Land Development Bank for any information in respect thereof and on being satisfied of the execution thereof, shall register the instrument.

44AF. Delegation of certain powers by Board.--The Board if it thinks fit, may delegate all or any of its powers under sections 44lJ, 44W, 44X or 44AC to an Executive Committee consisting of three or more of its members constituted by it.

44AG. Provisions of the Transfer of Property Act, 1882 to apply to notice under this Chapter.-The provisions of Sections 102 and 103 of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) and of any rule made by the High Court under section 104 of that Act for carrying out the purposes of the said sections shall apply so far as may be, in respect of all notices to be served under this Chapter.

44AH. Board's power of supervision over Primary Co-operative Land Development Banks.-Subject to the provisions of this Act, the Board shall have such powers of supervision over the Primary Co-operative Land Development Banks, including powers of inspection of account books and proceedings of such bank, as may be prescribed by rules.

44AI. Power to make rules.-The State Government may, after previous publication, make rules for carrying into effect the purposes of this Chapter.

(2) Such rule may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the manner of effecting distraint under this Chapter, the custody, preservation and sale of di strained property, immediate sale of perishable articles where such articies are distrained;

(b) conduct of the sale of the property mortgaged to Land Development Banks, appointment of sales officers, recovery of expenses of such sale, deposit of the purchase money in connection therewith and resale of the mortgaged property where purchase money is not deposited in sale proceedings:

(c) submission of returns and reports by Primary Co-operative Land Development Bank to the State Co-operative Land Development Bank in respect of their transactions periodical statement of accounts between the Primary Co-operative Land Development Banks and the State Cooperative Land Development Bank, payment of amount recovered by the Primary Co-operative Land Development Bank on mortgages transferred to the State Co-operative Land Development Banks the form in which application to Land Development Banks for loans may be made, the properties offered as security for such loans the investment of money realised by Land Development Banks from the mortgagors and matters generally relating to the conduct of business of Land Development Banks: and

(d) all matters expressly required or allowed in this Chapter to be prescribed by rules.]

'[CHAPTER VI-B *Co-operative Banks,*

44AJ. Application of the Chapter to Co-operative Banks.-(1) The provisions of this Chapter shall apply to a Co-operative Bank as defined in the Deposit

1. Chan, VI-B and Secs, 44 AJ to 44 AO Ins. by Act 39 of 1982,

Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961) in addition to the provisions contained in other parts of this Act, where any question of apparent or implied inconsistency arises, the provisions of this Chatper shall prevail over the provisions of the other parts of this Act.

(2) For the purposes of this Chapter, 'Deposit Insurance Corporaton means the Deposit Insurance Corporation established under the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961) and 'Reserve Bank'means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

Comments & case law

[Section 44AJ read with Clause 48 of the bye-laws of Central Co-operative Bank, Arrah-although the Registrar is empowered to rescind or cancel the resolution of the Board of Directors within four weeks from the date on which the Board's proceeding was received by him, the order passed by the Registrar after the said period under the orders of the High Court certainly cannot be held bad for want of any authority or jurisdiction. *Ajay Kumar Mishra vs. Registrar, Co-operative Societies,* 1995(2) PLJR 397.]

44AK. Division, amalgamation, compromise, etc.-(1) No order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or reconstruction or of division or transfer of assets and liabilities of a Co-operative Bank shall be made without the previous sanction in writing of the Reserve Bank. 4

(2) Where an order of moratorium has been made by the Central Government under sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) in respect of a Co-operative Bank, the Registrar, with the previous approval of the Reserve Bank in writing may during the period of moratorium, prepare a scheme,

(i) for the re-construction of the Co-operative Bank; or

(ii) for its amalgamation with any other Co-operative Bank (herein referred to as the transferee Bank).

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act where a Cooperative Bank being an insured bank within the meaning of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961) is amalgamated or in respect of which a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned and the Deposit Insurance Corporation has become liable to pay to the depositors of the insured bank, under sub-section (2) of section 16 of the Act, the bank with which such insured bank is amalgamated or, the new Co-operative Bank formed after such amalgamation or, as the case may be, the insured bank or the transferee bank shall be under an obligation to repay the Deposit Insurance Corporation in the circumstances, to the extent and in the manner referred to in section 21 of that Act.

44AL. Supersession of Managing Committee of Co-operative Bank.- Notwithstanding anything contrary contained in this Act Registrar shall if so required in writing by the Reserve Bank in public interest or for preventing the affairs of the Co-operative Bank being conducted in a manner detrimental to the interests of the depositors or for securing the proper management of the Co-operative Bank; pass an order for the supersession of the managing committee or other managing body (by whatever name called) of that Co-operative Bank and appointment of an administrator therefore, upon such terms and for such periods not exceeding five years in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank.

there will be only one such society in each panchayat.

(b) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, if the area of a Primary Agriculture Credit Society is found not to be that of a panchayat as provided under sub-clause (a) of this subsection, the Registrar or an officer authorized by Registrar to act on his behalf, who shall not be below the rank of Assistant Registrar, may order for reorganization including amalgamation or division of one or more such societies as the case may be and register the new society/ societies after such reorganisation."

["(3) Notwithstanding anything contrary in this Act, the society or societfes which are reorganised under sub-section (2) along with its managing committee shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist from the date of registration of the new society/ societies under sub-section (2) and the membership of such registered society shall stand transferred to the respective primary agriculture credit society created for the panchayat to which such members belong after reorganization under sub-section (2) and all the assets and liabilities thereof shall get divided/distributed amongst the new society/ societies in the manner prescribed by the Registrar/Government:

Provided that the State Govt. may from time to time, declare a moratorium on the liabilities of the new society/societies created under sub-section (2) of this Section."

["(4)(a) Notwithstanding anything contrary in this Act, upon the reorganisation of societies under sub-section (2) of this section and establishment of new society/ societies under sub-section (3) of this section, the Registrar/Government shall constitute or provide for constitution of an ad hoc managing committee for the purposes of managing the affairs of the new society/societies till such time as a new managing committee is constituted after elections under the provisions of this Act and the ad hoc managing committee so constituted shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(b) Notwithstanding anything contrary in the Act, upon the constitution of the new managing committee after elections under clause (a) the managing committee of all such affiliating societies o which a primary agriculture credit society is a member or federation of such affiliating societies, shall be reconstituted, as per provisions contained in this Act for constitution of the managing committee of such societies."

'[x x x x]

(6) Every family residing within the local limits of the new society determined under 2[sub-section (2) shall be represented by at least one adult member of the family who shall be a normal or associate member of the society and shall be entitled to a right of voting if he pays a [membership fee] and may become a full-fledged member of the society if he purchases at least one share of the society and he shall be entitled to receive loan therefrom and shall also be eligible to hold any elective post of the society.

44AR. Appeal from the order of the Registrar.--Any person aggrieved by the liquidation under sub-section (1) of section 44A0 or by amalgamation or establishment of new societies and the registration there of under sub-section (2) of the said section may file a representation before the State Government against the

1. Deleted by Act. 18 of 2008
2. Subs by idid.

order of the Registrar within thirty days of the date of order and the State Government may, after hearing the objections, pass such orders as may be deemed fit and the order of the State Government thereon shall be final and shall not be called in question in any Court of law.

44AS. Election of new society formed after amalgamation.- The election of the new society established under sub-section (2) of section 44AQ shall be held within a period of six months from the date of registration of the society unless, for special reasons to be recorded in writing, the State Government may extend the period by another six months.]

[1][Chapter VI-D

Special Provision's Applicable to societies in Short Term Co-operative Credit Structure.

44AT. Over-riding effect of Chapter VI-D.--Notwithstanding anything contrary or inconsistent contained in any other chapter of this Act or the Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act 1996 or rules framed thereunder or bye-laws of any registered society or orders issued thereunder, the provisions of this chapter shall have overriding effect.

44AU. Ensuring membership of Primary Agriucltural credit society to depositors and borrowers.-Every person who is a borrower or depositor of a Primary Agriculture Credit Society or wants to become a borrower or depositor of such society shall be compulsorily made a member or an associate member of such society in terms of sub-section (6) of section-44AQ with full voting rights.

44AV. Autonomy in all financial and internal administrative matters.-A co-operative society under Short Term Co-operative Credit Structure shall, have automony in all financial and internal administrative matters including the following areas:

(a) Interest rates on deposits and loans in conformity with Reserve Bank guidelines.

(b) Borrowing and investments.

(c) Loan policies and individual loan decisions.

(d) Personnel policy, staffing, recruitment, posting and compensation to staff, and

(e) Appointment of auditors and compensation for the audit and internal control system.

44AW. Limit on State Government's subscription.-The State Government's subscription in the share capital of any Co-operative Society under the Short Term Co-operative Credit Structure shall not exceed 25% of the total paid up share capital of such society:

Provided that the State Government or such society shall have option to further reduce the subscription of the State Government and that the society shall not be prevented from doing so by the State Government.

44AX. Restriction on number of Government Nominees.--(1) There shall be only one Government nominee in the Managing Committee of the State Cooperative Bank and Central Co-operative Banks.

(2) There shall be no Government nominee in the Managing Committee of a Primary Agricultural Credit Society.

44AY. Membership of an affiliating society.--(a) A co-operative society under the Short Term Co-operative Credit Structure registered under the Bihar Co-

1. Inserted by Act. 18 of 2008

made with the society or in any property sold or purchased by the society or in any other transaction of the society, except in any investment made in, or any loan taken from the society;

(d) he has any proceeding for surcharge relating to any registered society pending against him.

(e) he has a criminal proceeding relating to any transaction of a registered society pending against him in which cognizance has been taken.

(4) No person elected as member or other office bearer in the management committee of a co-operative credit structure shall be allowed to act as such if he is in default for a period exceeding twelve months in payment of dues to the society unless the amount in default with due interest is paid to the society.

44BF. Supersession of Short Term Co-operative Credit Structure.-(1) The supersession of the Managing Committee of Stats Co-operative Bank or Central Co-operative Bank under section-41 of this Act shall be done by Registrar, Cooperative Societies in consultation with Reserve Bank.

(2) The supersession of the managing committee under section-41 of this Act of a Primary Agricultural Credit Society shall be done by Registrar, only under the following conditions:-

(a) if a socierty incurs losses for three consecutive years, or

(b) if serious financial irregularities or frauds have been identified, or

(c) if there are judicial directives to this effect, or

(d) if there is lack of quorum for three consecutive meetings.

44BG. Elections.--(1) The election to the managing committee of a cooperative society under the Short Term Co-operative Credit Structure shall be conducted before the expiry of the term of the.existing Managing Committee and in case of supersession of the Managing Committee of such co-operative society; the election may invariably be conducted within six months from the date of supersession.

(2) A member of the Managing Committee of a Primary Agriculture Credit Society which has been superseded under the conditions mentioned in sub-clause (a) and (b) of section-44BG(2) shall not be entitled to contest again for a period of five years after such supersession.

44BH. The Prudential norms.-The prudential norms including Capital to Risk Weighted Assets Ratio shall be specified by the Registrar for all the Primary Agricultural Credit Society in consultation with National Bank.

44Bl, Removal of Directors and Chief Executive Officers.---(1) The members of the Managing Committee or chief executive officer of the State co-operative Bank or central co-operative Bank shall fulfill such criteria as may be stipulated by RBI.

(2) A Person who does not fulfill the. criteria for the post of Chief Executive officer or a member in the committee of the State co-operative Bank or a Central cooperative bank as stipulated by the Reserve Bank shall be treated as ineligible for such post and if such person is holding the post, he shall be removed by the Registrar on receipt of advice to this effect from the Reserve Bank or the National Bank.

44BJ. Co-option of professionals in Managing Committee of State Cooperative Bank and Central Co-operative Bank.---(1) The managing committee of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall have such number of professionals as members having the professional qualifications or

experience as may be stipulated by Reserve Bank of India.

(2) If members with professional qualifications or experience as stipulated by the Reserve Bank are not elected in number specified by the Reserve Bank of India in the Committee of the State Co-operative Bank or Central Cooperative Bank, to the extent of shortfall, such vacancies shall be tilled by co-option of such persons in the committee and such co-opted members shall have full voting rights.

448K. Audit of accounts.--The State Co-operative Bank or Central Cooperative Banks shall cause audit of its accounts by a Chartered Accountant selected from a panel approved by National Bank.

44BL. Special audit of State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank.-(1) The Registrar shall arrange to conduct the special audit of State Cooperative Bank or Central Co-operative Banks, on the request of Reserve Bank on such specific terms of references as agreed to by the Registrar and also arrange to furnish the report to Reserve Bank within the time stipulated by the Reserve Bank of India.

(2) The Registrar may also on its own motion or or? the request of the

Managing Committee of State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank arrange to conduct the special audit of suck bank.

44BM. Restriction of using word "Bank" by the Primary Agricultural Credit Society.--(1) No Primary Agricultural Credit Society will use the word "Bank", "Banker" or "Banking" or any other derivative of the word "Bank".

(2) The Registrar shall deregister such Primary Agricultural Credit Society, which violates the provision of sub-section (1) of this section.

44BN. Abolition of Cadre system.-There shall not be any Cadre system in Cooperative Credit Structure with effect from such date as notified by the State Government.

44BO. Winding up of State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank.--The Registrar shall make an order for the winding up of State Cooperative Bank or Central Co-operative Bank and appointment of a liquidator within one month If so advised by the Reserve Bank.

44BP. Implementation of regulatory prescriptions of Reserve Bank.- Notwithstanding anything contained in this Act or 'Rules made thereunder, the Registrar shall ensure the implementation of regulatory prescriptions of the Reserve Bank in case of State Co-operative Bank and Central Co-operative Banks.

44BQ. Exemption by the State Government-No society in the short term Co-operative Credit Structure shall be exempted under Section 62(2) of this Act in any manner from the application of the provisions of this chapter without prior consultation with the Reserve Bank or the National Bank."

CHAPTER VII

Penalties and Procedure

[1]**["45. Offences and Penalties.--(1)** It shall be an offence under this Act if-

(a) a Co-operative Society or an officer or member thereof willfully makes a false return or furnishes false information, or willfully not furnishes any information required from him by a person authorised in this behalf or a Registrar under the provisions of this Act;

(b) any person willfully or without any reasonable cause disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of this Act;

(c) any employer who, without sufficient cause, fails to pay to a Co-operative Society amount deducted by him from its employee within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made;

(d) any officer or custodian who willfully fails to handover custody of books, accounts, documents, records, cash, security and other property belonging to a Co-operative Society of which he is an officer or custodian, to an authorised person; and

(e) any person who indulges in the corrupt practices before, during or after the election of the Office-Bearer or member of the Board of the Co-operative Society,

(2) Any offence under sub-section (1) of this Section shall be punishable with imprisonment for a period which may extend up to one year or with a fine which may amount to rupees two thousand or both:

Provided that where a person is guilty of misappropriation, fraud, breach of trust, cheating or any other act involving moral turpitude, resulting in a loss to the Co-operative Society, he shall also be punishable under the relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860."

1. Subs. by Act 6 of 2018

any rule; or

(b) an officer or member of a registered society [1][or any person appointed under sub-section (2) of section 41] wilfully makes a false return or furnishes false information.

(2) Any officer or member of a registered society [1][or any person appointed under sub-section (2) of section 41] guilty of an offence under sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

[2][**45A.** (1) On election of new secretary or on supersession of co-operative society or on expiry of the term of the office bearers of a co-operative society, the outgoing secretary or the person holding charge of the office of the co-operative society shall hand over charge of his office and all papers and properties in his possession as secretary or incharge of the said society to the new secretary or the officer directed by the prescribed authority to take charge of the affairs of the said society.

(2) If the outgoing secretary of a co-operative society or the person holding charge of the office of secretary fails or refuses to hand over charge of his office as required under sub-section (1) above, the prescribed authority or any officer empowered by it in this behalf, may by an order in writing direct the outgoing Secretary or the person holding charge of the office of Secretary to hand over immediately the charge of his office and all papers and properties in his possession as such secretary to the new secretary in case of fresh election, and in case of supersession or on expiry of the term of office to the officer appointed to manage the affairs of the society.

(3) If the person to whom a direction has been issued under sub-section (2) fails to comply with the said direction he shall be punishable with the imprisonment which may extend up to the period of six months or a fine of Rs. 500, or with both.

(4) The offence under sub-section (3) shall be cognizable.

(5) If it is so required, the prescribed authority may, by order in writing, authorise any officer to forcibly take possession with the help of local police and Magistrate, of all papers and properties from the outgoing secretary or the person holding charge of the office of secretary and hand them over to the new secretary in case of fresh election and to the officer of the State Government appointed to run the affairs of the society in case of its supersession or expiry of the term of office bearers where fresh election in still to be held.

Comments & case-law

[Where managing committee of a society has been superseded, and a committee of Administrators appointed, on tenure for members of committee of Administrators is fixed. This committee can be reconstituted. by dropping some of the members without the dropped members being entitled to a hearing before order of removal by the Registrar. *Padma Charan Samantsighar vs. Registrar,* AIR 1981 Orissa 150. *See also Parmeshwara Bagh vs. State of Orissa,* AIR 1981 Orissa. 154. .

Where written consent of financing Bank has been obtained prior to the passing of order of supersession of managing committee of a Co-operative society, the order of supersession is not vitiated on account of any defect in notice to the Bank, since no further notice was required under law. *Durga Shankar Kar vs. State of Orissa,* AIR 1982 Orissa 20.

1. Ins. by Act 29 of 1956.
2. Ins. by Act 39 of 1982.

Order of supersession passed by Assistant Registrar by virtue of powers of Deputy Registrar delegated to him, cannot be said to be without jurisdiction *ibid.*

Removal of office bearers of a society without opportunity of hearing is violative of principles of natural justice. *Narsingha Charan Acharya vs. State of Orissa,* AIR 1985 Orissa 62]

[1]**[45B. Production of records by the Secretary or person incharge of the office of a Co-operative Society.-(1)** The Secretary of a Co-operative Society shall, on direction by Registrar or by any other Gazetted officer of Co-operative department, forthwith hand all records and documents of the Society as the Registrar or the officer mentioned above may require for inspection or enquiry relating to the affairs of the said Co-operative Society.

(2) If the Secretary or the person incharge of the office of the Co-operative Society fails, refuses or avoids to hand over the documents as required under foregoing sub-section (1) he shall be punishable with imprisonment for a period which may extend up to six months or with a fine of Rs. 500/- or with both; and such an offence shall be cognizable. • '

(3) When a person to whom a direction has been issued under sub-section (1) of this section fails, refuses or avoids to furnish all records and documents of that Society with the help of police and magistrate.]

Comments & case-law

[Offence under section 402 of Indian Penal Code committed by officer of society- Sanction for prosecution, whether necessary, See AIR 1957 Orissa 165: 1957 Cr. LJ 899.]

46. Prohibition of the use of the word 'co-operative'.-(1) No person or society other than a registered society shall trade or carry on business under any name or title of which the word co-operative ls part without the sanction of the State Government:

Provided that nothing in this section shall apply to the use by any person or his successor in interest of any name or title under which he traded or carried on business at the date on which

the Co-operative Society Act, 1912, came into operation.

(2) Any officer or member of a society or any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees, and, in the case of a continuing offence, with a further fine of five rupees for each day on which the offence is continued after conviction therefor.

47. Cognizance of offences.-(1) No Court inferior to that of a Magistrate of the second class shall try any offence under this Act.

[2]["(2) Every offence under this Act, except the offence under sub-section (1) (c) of Section 45 shall, for the purpose of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 197 4) be deemed to be a cognizable offence."

(3) No prosecution for an offence under this Act shall be instituted without the previous sanction of the Registrar, and the Registrar shall not sanction **the** prosecution of any person unless he has given such person an opportunity of being heard.

Comments & case-law

[A person against whom a complaint is filed does not become an accused members

1. Ins. by Act 39 of 1982.
2. Subs. by Act 6 of 2013

unless it is decided to issue process against him. There is no legal bar based on the principle of issue of estoppel to proceed against a person complained against on the same material in subsequent proceedings, after dismissal of an earlier complaint. *Dr. S.S. Khanna vs. Chief Secretary,* 1983 PLJR (SC) 107: AIR 1983 SC 595.]

48. Disputes.-(1) If any dispute touching the business of a registered society (other than a dispute regarding disciplinary action taken by the society or its. managing committee against a paid servant of the society) arises-

(a) amongst members, past members, persons claiming through members, past members or deceased members, and sureties of members, past members or deceased members, whether such sureties are members or non-members; or

(b) between a member, past member, persons claiming through a member, past member or deceased member, or sureties of members, past members or deceased member, whether such sureties are members or non-members and the society, its managing committee or any officer, agent or servant of the society; or

(c) between the society or its managing committee and any past or present officer, agent or servant of the society; or

(d) between the society and any other registered society; '[or]

[1] [(e) between a financing bank authorised under the provisions of subsection (1) of section 16 and a person who is not a member of a registered society;

'such dispute shall be referred to the Registrar:

Provided that no claim. against a past member or the estate of a deceased member shall be treated as a dispute if the liability of the past member or of the estate of the deceased member has been extinguished by virtue of section 32 or section 63.

Explanation.--(1) A claim by a registered society for any debt or demand due to it from a member, '[non-member], past member or the nominee, heir or legal representative of a deceased member or '[non-member] or from sureties or members, past members or deceased members, whether such sureties are members or nonmembers, shall be a dispute touching the business of the society within the meaning of this sub-section even in case such debt or demand is admitted and the only point at issue is the ability to pay or the manner of enforcement of payment.

Explanation.--(1) The question whether a person is or was a member of a registered society or not shall be a dispute within the meaning of this sub-section.

(2)The Registrar may on receipt of such reference.-

(a) decide the dispute himself; or

(b) transfer it for disposal to any person exercising the powers of a Registrar in this behalf; or

(c) subject to any rules refer it for disposal to an arbitrator or arbitrators.

(3) Subject to any rules, the Registrar may withdraw any reference transterred under clause (b) of sub-section (2) or referred under clause (C) of the said subsection and deal with it in the manner provided in the said sub-section.

(4) The appointment of an arbitrator or arbitrators and the procedure to be

1. Ins. by Act 16 of 1948.

followed in proceedings before the Registrar or such arbitrators shall be regulated by rule.

(5) In the case of dispute involving property which is given as collateral security, it shall be competent to the person deciding such dispute to issue mortgage award which shall have the same force as a mortgage decree of a competent Civil Court..

(6) Any person aggrieved by any decision given in dispute transferred or referred under clause (b) or (c) of sub-section (2) may, within three months from the date of such decision, appeal to the Registrar.

(7) The Registrar, in the case of dispute under this section, shall have the power of review vested in a Civil Court under section 144 and under Order **XL VII,** rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908, and shall also have the inherent jurisdiction specified in section 151 of the said Code.

(8) The Registrar may where it appears to him advisable, either of application or of his own motion, state a case and refer it to the District Judge for decision, and the decision of the District Judge shall be final.

(9) Save as expressly provided in this section, a decision of the Registrar under this section, and subject to the orders of the Registrar on appeal or review, a decision given in a dispute transferred or referred under clause (b) or (c) of subsection (2) shall be final.

Comments & case-law

[Effect of amendment of this section in 1948. AIR 1962 SC 1394: 1962 BLJR 687.

In a suit to set aside an award, the copy of award is necessary to decide as to whether the Secretary, Central Co-operative Bank is a necessary party and so entitled to notice under section 80 of C.P.C. ILR 1904. Cut, 86:

Dispute on the point as to whether the mortgage was on behalf of joint familyFor burden of proof. 30 Cut. LT 509.

Dispute in regard to list of Secretaries is different from dispute referable under section 84 of this Act. AIR 1965 Pat 459.

Assistant Registrar exercising powers of Registrar under section 48 of this Act is a court subordinate to High Court. AIR 1965 Pat. 226.

Registrar-whether has power to issue injunction. (1962) ILR 41 Pat. 325: 1962 BRLJ (Rev.) 62.

Words "Dispute touching the "business of registered society"-Scope of Election disputes-Section 48 (1) applies, 1962 ILR 41 Pat. 325: *See also Abdul Gaffor vs. State of Bihar,* 1983 PLJR 169.

The Expression "election" will also cover "election dispute" where an election has been challenged. In the same way, a dispute that can be raised under section 48 of the Act, covers a dispute as to election. *Hare Krishna Upadhya vs. State of Bihar,* 1976 BLJ 141.

A dispute between the Co-operative Bank and a registered Co-operative Society, is a disptue "touching the business of the Co-operative society". *Naya graph Co-operative Central Bank Ltd. vs. Narayan Rath,* AIR 1975 SC 1895: (1975) 2 SCC 445.

Election dispute also come squarely within the ambit of the provisions of

section 48. *Chandeshwar Prasad vs. State of Bihar,* 1987 PLJR 159 (FB): AIR 1987 Pat. 208.

The power conferred by section 48 are judicial in nature *ibid.*

The various stages of election of Committee of Management are clearly demarcated in the Act and the rules framed thereunder. Mere holding of pool does not complete the election process. *Ram Pyare Choudhary vs. State of U.P.,* AIR 1982 SC 831: (1982) 1 SCC 571.

The failure to hold election of members of the Board of Directors of a specified society in accordance with the provisions of the Act, will virtue the whole election programme from the commencement till the end. *B.K. Gayad vs. Nasik Merchants Co-op. Bank Ltd.,* AIR 1984 SC 192.

No election of Board of Directors can be set aside except by filing a petition under section 48. The election held at the Annual General Meeting will remain valid until this is done. The validity of an election, whether legal or factual has to be decided in an election petition. The Registrar of co-operative societies cannot declare elections invalid and the government should not dissolve the Board of Director on the basis of such report. *Abdul Gaffar vs. State of Bihar,* 1988 PLJR 196:
AIR 1983 Pat. 114.

The controversy about the date of election, when two different dates are claimed by the rival parties, is an election dispute and fall within the provision of section 48 (1). *Abdul Gaffor vs. State of Bihar, ibid.*

A petition having been filed before the election has taken place can by no stretch of imagination, be said to be an election dispute after the election is held. Once the election is held and candidates comprising the managing committee are declared as successful once, the election has come to an end. Any application filed with regard to any dispute of convening the general meeting on particular date will not fall within the ambit of an election dispute. *ibid.*

Term "demand"-scope 0f 1968 BRLJ (Rev.) 18.

Election disputes are also disputes referable to the Registrar under this section. *Pt. Raghav Jha vs. Co-operative Societies,* 1962 BRLJ (Rev.) 62: ILR 41 Pat. 25.

Appeal against rejection of nominaton of candidate for election of Directors of Co-operative Bank by the Dy. Registrar is maintainable. *Kapilendra Pothai vs. Dy. Registrar,* AIR 1981 Orissa 194.

Deputy Registrar exercising jurisdiction in election dispute is a court. The expression "election" also covers "election dispute" where the election has been challneged. Minister is an executive functionary and the expression "State Government" includes Minister. Minister, therefore has jurisdiction conferred under section 65A to call for any records of any proceeding of any matter pending before the Registrar or his sub-ordinate, or any person acting under his authority and examine and pass such orders as he may deem fit. *Lachandeo Sahni vs. State of Bihar,* 1982 PLJR (NOC) 7: AIR 1982 Pat. 48: 1981 BRLJ 239.

The expression "election dispute" means a disptue touching the business of Co-operative Society and such dispute can be decided under section 48. *Sri Narain Misra vs. State,* 1985 PLJR 572: AIR 1985 Pat. 9.

Registrar should not pass orders merely on basis of report of District Magistrate

regarding the elections held at the annual general meeting of a society. Even an order passed in the Registrar's administrative capacity should not be passed without affording an opportunity of hearing to parties who are being deprived of their right to run the administration of the society according to the claim made by them. *ibid.*

Rule 68 does not prescribe any particular form for reference of election dispute to the Registrar. The rule is not exhaustive and does not control section 48 of the Act. Reference of an election dispute by the District Magistrate, after holding of annual general meeting is a valid reference. *ibid.*

Where an employee has been discharged by the managing committee at the direction of Joint Registrar, an appeal lies to the Registrar. The appeal is a matter of right of the concerned employee in such cases. *Narkatiaganj G.D. & C.M. Union Ltd. vs. Registrar Co-op. Societies,* 1970 BLJR 351: 1971 BRLJ (Rev.) 62.

Dispute regarding service conditions of employees of society cannot be said to be a dispute touching the business of a society and so the registrar has no jurisdiction to try such cases. *Bihar State Co-op. Marketing Union Ltd. vs. Registrar. Co-op. Societies,* 1973 BRLJ 553: 197 4 BLJR 185: AIR 197 4 Pat. 177; *Tisco Oriya Co-op. Society Ltd. vs. Assistant Registrar, Co-op. Societies,* AIR 1975 Pat. 208: 1974 BBCJ 930. *Bihar State Co-op. Bank Ltd. vs. Registrar,* Co-op. Societies, AIR 1975 Pat. 187.

Thie jurisdiction of the ordinary civil and revenue courts of the land is ousted under section 57 of the Act in case of disputes which fall under section 48. A Registrar of Co-operative Societies exercising powers under section 48 must, therefore, be filed to discharge the duties which would otherwise have fallen on the ordinary civil and revenue courts of the land. In adjudicating up on a dispute referred under section 48, the Registrar is to all intents and purposes, a court discharging the same functions and duties in the same manner as a court of law is expected to do. *Thakur Yuga/ Kishore Sinha vs. Sitamarhi Central Co-op. Bank,* AIR 1967 SC 1494.

A dispute raised against the Co-operative society by its discharged employee claiming relief such as reinstatment in service is outside the scope of the expression "touching the management of the society "and the Registrar of Co-operative societies has no jurisdiction to deal with and determine such disputes. Such disputes squarely fall within the jurisdiction of Courts. *Gujarat State Co-operative Land Development Bank Ltd. vs. PR. Mankad,* AIR 1979 SC 1230: (1979) 2 SCC 123.

Where after the filing of application for review the Registrar who passed the order is transferred to another place, the Joint Registrar who is invested with the powers of review, would be legally competent to hear the review application. 1959 BLJR 291: ICR 38 Pat. 877.

Assistant Registrar, acting under section 48 of the Act, can go behind an earlier decision of his predecessor in respect of the dispute, 1956 BLJR 627.

Even when the Registrar comes to the conclusion that a person is not a member of the society, he, by virtue of explanation (1) to sub-section 48 of this Act, has got the power to decide about the ability to pay, or the manner of enforcement of payment, between the society and such non-member. 1956 BLJR 627.

Under Sec. 48 (7) the Registrar has been specifically granted the power of review vested in civil court under Section 114 and Order 47 rule 1 of the Code of Civil Procedure and has been given inherent power in most genera! terms to deal effectively with alll the matters validly referred to, and pending before him. *Pt.*

Raghav Jha vs. Registrar, Co-operative Societies, 1962 BRLJ (Rev.) 62: ILR 41 Pat 25.

There is no second appeal when the dispute is decided by the Registrar himself. The term "Registrar" in this context includes Dy. Registrar or Asstt. Registrar appointed to assist the Registrar. *Md. Islam vs. Dist. Co-operative Officer,* 1979 BBCJ 101: 1979 BLJ 82.

But where the Dy. Registrar or Asstt. Registrar has not been appointed to assist the Registrar, appeal before the Registrar lies. *ibid.*

Section 56 has got no application to orders passed by a person exercising the powers of a Registrar u/s 48 of the Act. *Din Dayal Singh vs. Biscomaun,* AIR 1976 Pat 179: 1976 PLJR 130.

Orders passed by Registrar and Assistant Registrar in appeal are final unless they are out of jurisdiction. 1956 BLJR 627.

The "Registrar" Includes such persons as the Registrar himself appointed by the State Government u/s 6 (1) of the Act or any person appointed under sub-section {!) of section 6 to assist the Registrar who has been conferred on by the State Government by general or special order published in the official gazette all or any of the powers u/s 26. Therefore, although there may be only one Registrar of Cooperative Societies appointed by the State Government u/s 6 (1), even such persons who have been appointed to assist the Registrar u/s 6 (1) of the Act may be conferred on all the powers of the Registrar in respect of matters not falling u/s 26 by a general or special order of the State Government published in the official gazette. *Abdul Gafoor vs. State of Bihar,* 1983 PLJR 196: AIR 1983 Pat. 114.

Section 48 is all pervasive. Therefore, whenever a dispute (including an election dispute) is raised, a reference has to be made to the Registrar. If a dispute is decided u/s 48 (1), read with section 48 (2) (b), the appellate forum is the Registrar himself under section 48 (6). *ibid.*

If no dispute has been raised by way of reference before the Registrar u/s 48 (1) of the Act or for the matter, when such a dispute has not been decided by a person acting as the Registrar by viture of section 6 (2) of Act and no appeal is preferred under sub-section (6) of section 48 of the Act, the State Government would not be entitled to entertain such a dispute u/s 65A of the Act overriding the provision of section 48. *ibid.*

Debts due to society from a member who ceased to be member on his retirement from service-Claim from past member-Limitation-In the circumstances of the case, claim held barred. *P.M.G. Officers Co-op. Society vs. Abdul Quddus,* 1963 BLJR 969.

An award under the Co-operative Societies Act is not a decree, although it resembles a decree. Where an award is made against the estate of deceased member of Co-operative Society under section 48 of the Act, it is not a nullity because the Act makes definte provision tor an award against the estate of a deceased member. Such an award cannot be held to be a nullity on the analogy of a decree against a dead man being nullity. *Ram Chandra Singh vs. Central Co-operative Bank Nawada,* 1941 PWN 536.

Where the plaintiff sued a Co-operative Union of which he was a member to recover arrears of rent on deposit made by him and the dispute related to the rate of interest, it was held that the suit did not lie in the Civil Court as it was barred by

section 57 of the Act read with section 48 of the Act. *Central Co-operative Union vs. Kamla Prasad,* AIR 1937 Pat. 531: 18 PLT 255.

Assistant Registrar has jurisdiction to determine the dispute u/s 48 (2). There is nothing in Secs. 15 and 16 which warrant a restricted meaning to be given to the language of the Explanation to Sec. 48 (1). *Union of India vs. Registrar, Co-operative Societies,* 1963 BRLJ (Rev.) 18. This case has been overruled by Supreme Court, see AIR 1962 SC 1367: 1962 BLJR 68 (SC).

This section puts no bar on transfer and authorises the. Registrar to transfer such of the cases as he may deem fit and proper. *Hare Krishna Upadhaya vs. State of Bihar,* 1979 BLJ 141.

Registrar has the same power of review as vested in the civil court under C.PC. The Registrar can always interfere in exercise of this power, where earlier order were passed without referring to many material facts on record. If an order differing with the earlier order is passed in such a case, the Registrar cannot be said to have transgressed the limitations of review jurisdiction and to have acted as a Court of Appeal. *Paras Nath Thakur vs. State of Bihar,* 1986 PLJR 168 see also. *Pandit Raghav Jha vs. Registrar,* 1962 BRLJ (Rev.) 62.

There is a clear distinction between a dismissal ir'J Ii mine and a dismissal with a speaking order. A dismissal in limine does not constitute a bar of the principle analogous to *res judicata* to a subsequent petition. The theory of merger does not apply to such a case. *ibid.*

A dispute referred to the Registrar under section 48 (c) can be either disposed of by the Registrar himself under section 48 (2) (a) or transferred for disposal under clauses (b) and (c) of section 48 (2). A right of appeal to the Registrar is given to person aggrieved by decisions given in disputes transferred or referred by the Registrar. Registrar can revise under section 56, only the cases decided by him under section 48 (2) (a). Section 46 is not attracted in case of appellate orders passed by Joint Registrar, and a revision application against order passed by another officer under section 48 (6) exercising powers of Registrar is not maintainable. *Raghav Jha vs. Registrar, Co-operative Societies,* AIR 1983 Pat. 137: 1983 BRLJ 75.

Acquisition of land for execution of scheme to provide houses cannot be recognised as vesting any right in the Co-operative Society if there has been failure. on the' Society's part relating to the most essential part of the transaction, that is the payment of the price of the. land being acquired. A right of ownership would have arisen only when the price would have been paid and in the absence of that, no claim can be said to have accrued. Government will not be duty bound to settle the land with that society only and non else. Settlement of some part of acquired land with another society is not hit by doctrine of promissory estoppel. *Postal Co-op. Home Construction Society Ltd. vs. Secretary to Government,* 1984 PLJR 1 : AIR 1981 Pat. 133.

The expression "save as expressly provided in this section" in sub-section (9) of Section 48 is of special significance. By use of the expression the legislature appears to have clearly laid down that provisions of other sections of the Act do not affect the finality of the order passed under Section 41. An order passed by the Deputy Registrar u/s 48 (6) of the Act cannot be revised by the Registrar u/s 56. *Din Dayal Singh vs. Biscomaun,* AIR 1976 Pat. 179: 1976 PLJR 130.

Where the society is in default or in arrears of Government revenue the settlement of sairat may be done with other societies or even individuals and the society in arrear cannot claim any priority in the matter on the ground that it operates in the area in which sairat lies. *Daudpur Fisherman Co-operative Society Ltd. vs. State of Bihar,* 1981 BRLJ 219: AIR 1981 Pat. 294.

Notice to the society must be deemed as notice to all its members. Notice to individual members is opposed to the very status of a co-operative society as a body corporate and is, therefore, unnecessary, lack of express provisions for issue of notice to individual members cannot be said to be violative of the principles of natural justice. *Daman Singh vs. State of Punjab,* AIR 1985 SC 973.

When a matter falls under any specific provision, then it must be governed by that provision and not by other general provisions. Therefore where the society held its employee liable for shortage of assets put under his custody and charge by reason on his negligence or misconduct, the matter being fully covered by section 40 (1) (b), must mean that section 48 is not applicable. *Uma Shankar Sharan Shrivastava vs. Biscomaun,* 1985 PLJR 19: 1984 BBCJ 905: AIR 1985 Pat. 46.

The scope of the dispute contemplated under section 48 is entirely different from one relating to a society's tiling a demand for misappropration, fraud and negligence etc. Every claim or demand cannot be put under the cover of section 48. ***ibid.***

Sections 40 and 48 are mutually exclusive and operate in altogether different field. While action under section 40 must be preceded by a proceeding uhder sections 33 to 37 no such pre-requisite or pre-condition is necessary for action under section 48. *Kinjer Vyapar Manda/ Sahyog Samiti Ltd. vs. Deputy Registrar,* 1986 PLJR 264 (FB); AIR 1968 Pat. 206 *(Uma Shankar Shrivastava vs. Biscomaun,* 1985 PLJR 19-- Overruled).

Section 40 pertains to administrative power of the Registrar flowing only as a precondition from the results of an audit, inquiry, inspection or winding up-Section 40 is not attracted or applicable to reference of a disptue under section 48 by a society against its officer, agent or servant for defalcation of funds. *ibid.*

Where appeal against the award of the Assistant Registrar has been filed before the Deputy Registrar and also simultaneously challenged before the High Court by invoking its writ jurisdiction, the Deputy Registrar has no jurisdiction to deal with matter during pendency of the writ petition. *ibid.*

The flat in a Tenant Co-partnership Housing Society registered under the Cooperative Societies Act can be attached and sold in execution of a decree against the allottee. *Ramesh Himmat Lal Shah vs. H.J. Joshi,* AIR 1975 SC 1470: (1975) 2 sec 105.

Where the Registrar of Co-operative Societies has acquiesced in the appointment and has allowed the incumbent Secretary of the Co-operative Society to work for a very long period, it will not be open to the Registrar to set aside the appointment of the incumbent officer-bearer. *Nayagarh Co-operative Central Bank Ltd. vs. Narayana Rath,* AIR 1977 SC 112: (1977) 3 sec 576.

After a Co-operative society has communicated a resolution for the expulsion of one of its members to the Registrar of Co-operative Societies tor his approval, a duty is cast upon the Registrar to exercise his power of according approval or disapp:val within the prescribed statutory period. If no action is taken by the

Registrar within the period provided by statute, his power to accord approval or disapproval to the resolution of the Co-operative Society lapses. *Balasinar Nagrik Co-operative Bank vs. B.S. Pandya,* AIR 1987 SC 849: (1987) 1 SCC 606.

An election can only be invalidated in an election petition under this Section of the Act. If the same has not been done by any authority, even the government can proceed on the assumption that the election is *ipsofacto* void *ab initio. Vijay Kumar Mishra vs. State of Bihar,* PLJR 846: 1989 (1) BLJ 636.

The proceedings under this section are in the nature of a civil suit, other wise cognizable by a civil court u/s 9 of the C.P.C. The statute has taken out the jurisdiction of the civil court and has conferred the same on the Registrar or a person exercising the power of the Registrar to decide the dispute touching the business or management of the society between its members, past members, their office bearers, agent, and officers or servants of the society. *Yogendra Prasad vs. Additional Registrar,* 1992 (1) PLJR 9 (SC).

Validity of plural remedies, if available under the law, cannot be doubted. It is not correct to say that whenever a specific remedy is made available in law, the other remedy (more general in nature) necessarily gets excluded. If plural remedies are available to a person, he is tree to choose, until he elects one of them. Provisions of section 48 may be availed of for recovery of loss in preference to provisions of section 4 or vice-versa. *Biscomaun vs. Uma Sankar Sharan,* 1992 (2) PLJR (SC) 42.

No electon of a Board of Directors can be set aside except by filing an election petition under Section 48 of the Act. Until that is done, the election held by the Annual General Meeting shall remain valid. The *ipso dixit* of the authority that the election is invalid in law would not warrant the dissolution of an election body. It is now well settled that no election can be said to be void *ab initio* merely on the *suo motu* assessment of a party or the Government. Validity of an election legal or factural has to be decided in the election petition.

The non-consideration of these important documents and materials led to the passing of wrong order on the earlier occasion in favour of the petitioners and others. On this occasion when a review petition was filed, on referring to the relevant materials it was detected that a mistake apparent on the face of the record was committed.

In this view of the matter, it cannot be accepted that the Registrar has transgressed the limitations of the reveiw jurisdiction and has acted as a court of appeal. *Paras Nath Thakur vs. State of Bihiar,* 1986 BLJ 673.

The delay in filing election petition challenging the validity of election of office bearers of a Co-operative Society cannot be condoned because the provisions of Limitation Act, 1993 apply only to proceeding in "Courts" and not to appeals and applications before Statutory Bodies other than "Courts" such as quasijudicial Tribunals or Executive Authorities. *Sita Ram Sah vs. State of Bihar,* 1995 (1) PLJR 396.

Where an order has been passed by the Registrar in respect of enrolment of a Co-operative society without full consideration of all relevant materials, the High Court may quash the order and remit the case for reconsideration of the Registrar for passing a fresh order. Managing Committee of M.G.M. *Co-operative Society vs. Yogendra Sharma,* 1996 (1) PLJR 882.

The prescribed procedure under the Act must be strictly followed in case of expulsion of a Member, and notice to show cause must also be given. *Smt. Sarladevi vs. Sailesh,* AIR 1996 Bom, 98.]

[Section 48- dispute regarding reduction in house rent allowance of the

employees of the Co-operative Bank falls within the ambit of the word "dispute" under this section-the term "business" in the section will also include "affairs of the society"-writ does not lie and dispute has to be decided first u/s 48 before coming to High Court. *Bihar Co-op. Bank Emp. Union vs. Ranchi Khunti Central Co-op. Bank Ltd.,* 2000(4) PLJR 179.

Section 48-word "business" occurring in this section has to be given a wide construction-principle of statutory construction *"expressio unius exclusio alterius"* applies. *ibid.*'

Section 48 read with section 54 and rule 68-sum of central society due from primary society can be recovered also from individual members of primary society but only after the property of the society is insufficient to discharge the liability under the award-the recovery is to be made at the first instance from the property of the defaulting society and only thereafter from the concerned individual members. *Sheo Shankar Prasad vs. Dy. Registrar Co-op. Society,* 2000(1) PLJR 1057.

Sections 48 and 54 read with Rule 68-Chairman and Secretary of a Weavers Society obtaining loan from Co-operative Bank for functioning of the Society-Debt Relief Scheme of 1990 announced by the Central Government which was implemented by the State also for waiver of loans upto Rs. 10,000/-- Society applying to the Assistant Registrar for waiver of loans to its members out of the ioans received from Co-operative Bank which was rejected by him and appellate authorities-subsequent certificate case for recovery of outstanding amount from Chairman and Secretary in their personal capacity---a mere reading of Section 54 makes it clear that an amount recoverable from a society u/s 48, apart from the property of the Society, the members may also be held liable to the extent of their limited liability---therefore in this case the members of the Managing Committee and the debtor-member ought to have been made opposite parties-Chairman and Secretary cannot be held personally liable for the dues which can be recovered by the Bank in accordance with Section 54 read with Rule 68. *Mohammad Faizan vs. State of Bihar,* 1997(1) PLJR 1028.

Sections 48 and 54 read with Rule 68-- Chairman and Secretary obtaining a loan from Co-operative Bank for functioning of society after executing Bonds and documents-Chairman and Secretary not liable in their personal capacity for such loan in absence of any case of misappropriation of the funds by them and no proceeding u/s 40 of the Act having been taken up. *ibid.*

Section 48-claim for enrolment of 452 members of a Society whose strength and nominal capital, as per its bye-laws was fixed as 800 and Rs. 20,000/- with each share valued at Rs. 25/- -eventhough the authorities to whom the dispute was referred by the High Court to determine the validity of membership of new 452 applicants who had filled and submitted their application forms held that they should be regarded as members of the Society, they were not enrolled as members on the ground that there are no shares left to be allotted as all the 800 shares have been purchased by existing 211 members---since the question whether no share is there to be allotted or there was any raise in the nominal capital of the Society from existing Rs. 20,000/- subsequently, are questions of facts which could not be decided in the writ application, matter remanded back to authority under the Act for hearing and a fresh decision. *Mg. Committee of Munger Gun Manufacturer's Co-op.Society vs. Yogendra Sharma,* 1996(1) PLJR 882.

Section 48 read with Articles 226 and 227 of the Constitution-alternative remedy-normally the existence of an alternative remedy does not oust the jurisdiction of the writ court-however, a writ court must act under self imposed restraint having regard to the existence of alternative remedy especially in matters of election dispute-only existence of extraordinary circumstances will justify by passing of alternative remedy. *Vishwanath Sahni vs, State of Bihar,* 1995(1) PLJR 535.

Section 48-allotment of lands for members of a society-some members left out by society-High Court ordered re-carving of some plots as well as from small part to accommodate the remaining members-instead of recarving and using small park, office bearers allotted portions from big park-cancellation of plots of such members by P.R.D.A.-cancellation valid-big park cannot be touched-no sympathetic consideration can be available to such members-no order now can be issued cancelling the earlier proceedings. *Shaikh Mohd. Ali vs. Bihar State Housing Board,* 1989 PLJR 477.

Section 48-- Termination simpliciter of employees' service reference to Assistant Registrar on the question of such termination, not permissible. *Tisco Oriya Co-op. Credit Society vs. Asstt. Registrar,* 1975 PLJR 290 (FB).

Section 48- Expression 'election dispute'-meaning of-dispute touching the business of co-operative society, is an election dispute, *Narain Mishra vs. State of Bihar,* 1985 PLJR 579.

Section 48--Election disputes also come squarely within the ambit of this section. *Chandeshwar Prasad vs. State of Bihar,* 1987 PLJR 159 (FB).

Section 48 - The powers are judicial in nature. *ibid.*

Section 48-- Registrar of Co-operative Societies cannot give directions to a Co-operative Society to admit a particular heir of deceased member of that Society as its member. To become a member one must be the holder of at least one share either by valid transfer or devolution of interest. *Patliputra Co-operative House Construction Society vs. State of Bihar,* 1972 PLJR 481.

Section 48(1)-- Question regarding irregular appointment of Accountant of the Society could be a dispute within Section 48(1), but it did not fall within Cl. (a} or (b} of sub-section (1). *Rama Shankar Tewari vs. Gopal Banerjee,* 1971 PLJR 377.

Section 48(1)---observance of Natural Justice-where order of Assistant Registrar affected question of appointment of the petitioner, he was entitled to a notice to show cause. *ibid.*

Section 48 & Bihar and Orissa Co-operative Societies Rules, 1959-- Rule 68, sub-rule 13(a)-Rule 68, sub-rule 13(a) does not prescribe any particular form for reference of election dispute to the Registrar-such Rule, not exhaustive and does not control Section 48 of the Act-reference of an election dispute by the District Magistrate is a valid reference. *Sri Narain Mishra vs. State of Bihar,* 1985 PLJR 579.

Section 48 r/w rule 33 a dispute between Co-operative Bank and its employees is not amenable to writ jurisdiction where the Bank is completely privately managed and controlled by its Board of Directors-the situation may be different where a society has been superseded and special officer has been appointed by the *Registrar. S. Itrat Hussain vs. Registrar Co. op Societies,* 2001 (2) PLJR 253.

Cancellation of allotment. Non-observance of principles of natural justice.

Although the Registration Act, 1908 does not specifically provide any mode or manner in which a deed of transfer earlier registered before the Registrar of Document could be cancelled by a subsequent deed of annulment but even if the Registrar of Document had the power to admit such a deed of annulment for registration, it had to be done as per the requirement of principles of natural justice and cannot be done to the detriment of the person in whose favour the earlier deed of transfer was registered. Once a property is transferred by a registered document, a vested civil right devolves upon the transferee and to nullify such vested right only a civil court of competent jurisdiction has the authority and the Registrar has no such power or authority of a civil court to decide right and title of a party. *Swati Pande vs. Registrar, Co-operative Societies,* 2007(2) PLJR 525.]

49., Registrar liquidators and arbitrators to have certain powers of Civil Court.--Subject to any rules, the Registrar, any person authorised to hold an inquiry under section 35 or an inspection under section 36, any liquidator, any person exercising the powers of a Registrar, or any arbitrator or arbitrators appointed under section 48, shall in so far as such powers are necessary for carrying out any of the purposes of this Act, have power to summon and enforce the attendance of witnesses and parties cancerned and to examine them upon oath and to compel the production of any books, accounts, documents or property by the same means and, so far as may be, in the same manner as if provided in the case of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

50. Attachment of property.--(1) Where the Registrar is satisfied on the application of the liquidator or of a society that any person with intent to defeat or delay the execution of any order that may be passed against him under section 44 or 48.

(a) is about to dispose of the whole or any part of his property, or

(b) is about to remove the whole or any part of his property from the local limits of the jurisdiction of the Registrar,

the Registrar may, unless adequate security is furnished to his satisfaction, direct the attachment of the said property or such part thereof, as he thinks, necessary, any such attachment shall have the same effect as if it had been made by a competent Court.

(2) An order of attachment passed under sub-section (1) shall, on the application of the Registrar, be executed by the Collector in whose jurisdiction the property lies, in the same manner as an order of a Revenue Court.

51. Enforcement of orders.-Orders passed under sections 44, 48 and 50 shall in addition to any other method of enforcement provided under this Act, on application be enforced as follows:--

(a) when passed by the Registrar, a liquidator or by an arbitrator or arbitrators, by any Civil Court having local jurisdiction in the same manner as a decree of such Court:

(b) when passed by the District Judge, in the same manner as a decree of the District Judge made in the suit pending before him.

52. Recovery of sums due.--Any sum payable by any person or by any registered society-

(a) as fees for an audit held under section 33,

(b) in accordance with an order of the Registrar under section 39 apportioning the costs of an inquiry or inspections,

(c) in accordance with an order passed under Section 40,

(d) in accordance with an order of the Registrar or of a liquidator passed under section 44, or

(e) in accordance with an order, decision or award passed or made under section 48,

[1][(f) As an amount due from member, past member or the nominee, heirs, or legal representative of the deceased member of a primary co-operative society.]

1. Ins. by (Amdt.) Act 5 of 1989.

shall be recoverable, as a public demand in any area, in which the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (B. & O. Act 4 of 1914),,is in force or as an arrear of land revenue throughout the whole of the State and the Registrar or other person authorised by him in this behalf, shall be deemed to be the person to whom such public demand is due or to whom such arrear of land revenue is payable.

Comments & case-law

[In a suit to set aside award, copy of award is necessary to decide as to whether Secretary of Central Co-operative Bank, is a necessary party and so whether notice under section 80, C.P.C. is necessary. lLR (1964) Cut. 86.

The certificate court cannot go behind the award given by the Assistant Registrar, Co-operative Societies u/s 6 which was upheld in appeal. *Ram Pratap Singh vs. Bihar Bakhtiarpur Fatwah Central Co-operative Bank, Bihar-shariff,* 1975 PLJR 6 (Rev.)

Section 52 of the Act contains five clauses (a) to (e). By section 7 o1 the amending Ordinance, another clause (f) has been added. Section 52 provides for recovery of sums due. It lays down categories of dues which may be recovered as public demand. Clause (f) introduces another category of dues which may be realised as public demand. No serious objection can be raised to such a provision. Clause (f) does not lay down that the dues may be realised without an adjudication. It is, therefore, neither unfair nor unjust nor unreasonable by any statutory imagination nor it violates Article 14 of the Constituton. Consequently there can be no serious challenge to the inclusion of clause (f) to Section 52 of the Parent Act. *Sheetal Prasad Gupta vs. State of Bihar,* (1990) 1 BLJ 493 (FB).

In interpreting a deeming provision creating legal fiction the Court is required to ascertain the purpose fo: which the fiction has been created and after ascertaining the same to assume the facts and consequences which are incidental or inevitable corrolary the fiction Section 52 merely vests the Registrar (or the person authorised by the Registrar) with the legal competence to send requisition by creating legal fiction in his favour as the person to whom the money is deemed to be due and payable. *Bindesh Kumar Singh vs. State of Bihar,* 1995 (1) PLJR 86.]

53. Recovery of sums due. to the Government.- All sums due from a registered society or from an officer or member, past or present of from his sureties or from the estate of a deceased member of a registered society or from his sureties as such to the Government including any costs awarded to the Government may be recovered in the same manner as arrears of land-revenue.

54. Property from which sums due from a society can be recovered.-All sums due from a registered society to the Government and all sums recoverable from a registered society under sections 33, 39, 44 or 48 may be recovered firstly, from the property of the society, secondly, in the case of a society, the liability of the members of which is limited, from the members, past members or estates of deceased members, or their sureties subject to the limit of their liability; and thirdly, in the case of other societies from the members, past members, or estates of deceased members or their sureties to such extent or in such proportion as may be determined by the Registrar.

55. Liability of past members.-Notwithstanding anything contained in sections 53 and 54, the liability of past members and of the estates of deceased members shall in all cases be subject to the provisions of sections 32 and 63.

[56. **Power of revision by Registrar.**-The Registrar may, on application or of his own motion, revise any order passed by a person exercising the powers of a Registrar or by a liquidator under section 44 provided such order has been passed within a period not exceeding six months :

Provided that the Registrar shall have no power to revise any order against which appeal has been provided under provisions of this Act."

Comments & case-law

[There is no period of limitation provided for exercise of the power by the Registrar or for the filing of an application to this effect. *Sahebganj Motor Transport Coop. Societies Ltd. vs. Registrar, Co-op. Societies,* AIR 1973 Pat. 77; 1972 BLJR 455.

The provisions of section 56 are not in *pari materia* with those of section 65.A of the Act, and section 56 has not such an overriding effect, as section 65-A. Section 65-A does nothing more than instead of the Registrar deciding the election dispute by referring to an officer subordinate to him, the State Government has been given power to recall an election dispute from the Registrar in appropriate cases. Section 48 itself puts no bar on transfer and authorises the Registrar to transfer such of the cases as he may deem fit and proper. Similar power is being exercised under Section 65-A by the State Government of recalling such election disputes from the Registrar as the State Governments may consider proper. That will not amount to any discrimination under Article 14 of Constitution. *Hare Krishna Upadhyaya vs. State of Bihar,* 1979 BLJ 141 .

Section 56 has got no application to orders passed by a person exercising the powers of a Registrar u/s 48 of the Act. *Din Dayal Singh vs. Biscomaun,* AIR 1967 Pat. 179; 1976 PLJR 130.

A right of appeal to the Registrar is given to persons aggrieved by decisions given in disputes transferred or fererred by the Registrar. Registrar can revise under section 56, only the case decided by him under section 48 (2) (a). Section 56 is not attracted in case of appellate orders passed by Joint Registrar, and a revision application against order by another officer under section 48 (6) exercise rig powers of Registrar is not maintainable. *Raghav Jha vs. Registrar, Co-operative Societies,* AIR 1983 Pat. 137: 1983 BRLJ 75.

Order passed in exercise of revisional powers in absence of written notice to parties to make their representation is invalid and should be quashed under Article 226 of the Constitution of India. The requirement of written notice cannot be dispensed with by relying upon absence of prejudice and imputation of knowledge to affected party. *C.A. T.A. Sales Co-op. Society vs. Government of A.P.,* AIR 1977 SC 2313: (1977) 4 sec 337.

The Registrar of Co-operative Societies has no power to review his own order, passed earlier after due consideration, *Jai Mahabit Co-op. Housing Society Ltd. vs. P.K. Narbheram,* AIR 1987 SC 1513: (1987) 1 SCC 549.]

A bare reading of these relevant provision clearly manifests the legislative intent that the Registrar on reference, himself may decide the dispute or transfer it for disposal to a person exercising powers of the Registrar on his behalf. If he himself decides the dispute u/s 48 (3) the question of either appeal or revision does not arise except to revise his judgment. This dichotomy is to be maintained when revisional power is exercised by the Registrar. The power of revision is conferred expressly only on an application or *suo-moto* against any order passed by a person exercising the power of a Registrar. *Yogendra Prasad vs. Additional Registrar,* 1992 (1) PLJR 9 (SC).

The Additional Registrar as a delegate of the Registrar is clearly within his

1. Subs. by (Amdt.) Act 10 of 2002.

power to exercise his Revisional power over the appellate power, *ibid.*

Merely because the Assistant Registrar on reference by the Registrar exercised the power under sub-section (1) of section 48, the Registrar will *not* be denuded of the supervisory or revisional powers under section 56 of the Act. *Yogendra Prasad vs. Additional Registrar,* 1992 (1) BLJ 1 (SC).

Where the out going Managing Committee of the Co-operative Society fails to hold elections for electing members of the succeeding Managing Committee before expiry of its term of office, the Registrar, Co-operative Societies is empowered under the Act to order removal of the outgoing Managing Committee and assume charge of management till elections are held and the new committee constituted. *Ram Swaroop Pathak vs. State of M.P,* AIR 1996 M.P 110.

-Section 56 read with Sections 48(6) & (9)-0rder passed by the Deputy Registrar (Judicial) under Section 48 (6) cannot be revised by the Registrar under Section 56. *M/s. Purtabpore Co. Ltd. vs. State of Bihar,* 1976 PLJR 130.]

57. Bar of jurisdiction of Court.--[1][(1) Save in so far as expressly provided in this Act., no Civil or Revenue Court shall have any jurisdiction in respect of any matter concerned with the winding up or dissolution of the registered society or suspension of the Managing Committee of a registered society under its act, or of any dispute required by section 48 to be referred to the Registrar or of any proceedings, under ChapterVII A.]

(2) While a society is in liquidation, no suit or other legal proceeding shall be proceeded with or instituted against the liquidator as such or against the society or any member thereof on any matter touching the affairs of the society, except by leave of the Registrar and subject to such terms as he may impose.

(3) No order of the State Government, District Judge, Registrar, a person appointed to assist the Registrar, liquidator, or an arbitrator or arbitrators purporting to be one, which under any provision of this Act is declared to be final shall be liable to be challenged, set aside, modified. revised, or declared void in any Court upon merits or upon any ground whatsoever except want of jurisdiction.

Comments & case-law

[Where the plaintiff used the Co-operative union of which he was a member to recover arrears of interest on deposit made by him, and the dispute was about rate of interest, it was held, that the suit did not lie in the Civil Court, as the cognizance of the dispute by it was barred by section 57 of this Act, AIR 1937 Pat. 531 : 16 PLT 255: 69 IC 689.

Sub-section (3) of this section cannot be interpreted to mean that where an order passed by a liquidator is challenged on the ground that it was passed without jurisdiction, no leave of the Registrar is necessary under sub-section (2), reading sub-sections (2) and (3) together, it is clear that whatever may be the scope of the suit or legal proceeding that may be instituted against a liquidator as such the leave of the Registrar will be necessary.

Thus, where a person institutes a suit against a liquidator as such for declaration that an award passed by the liquidator to the effect that the person who was a- surety for one of the members of the society under liquidation was liable for the amount for which he was a surety was *ultra vires* and ineffective, leave of the

1. Subs. by (Amdt.) Act 5 of 1989.

Registrar under sub-section (2) is necessary and sub-section (3) can be of no avail. AIR 1948 Pat. 337.

The exclusion of the jurisdicton of the civil court is not to be readily in ferred but such exclusion must be either explicitly expressed or clearly implied, Section 57 (3) clearly vests jurisdiction in the Civil Court in cases where an award is passed without jurisdiction .(1964) 30 Cut LT 509.

A Civil suit for declaration that the dismissal order of the employee of a Cooperative Society as a result of disciplinary proceedings is invalid, is not barred. *U.P Co-operative Cane Union Federation Ltd. vs. Liladhar,* AIR 1981 SC 152: 1980 (Supp.) SCC 61o.

A suit by an employee of a Co-operative society for declaration that retrenchment of his services is illegal does not relate to "business of Co-operative Society". Bar of jurisdiction of Courts will not apply to such a suit. *Allahabad District Co-op. Ltd. vs. Hanuman Dutt Tewari,* AIR 1982 SC 120: (1981) 4 SCC 431.

Co-operative Societies Act cannot be challenged on the ground that the protection afforded by Article 31 A (1) (c) was not available to co-operative societies. Protection of Article 31 A (1) (c) cannot be said to be not available on the ground that interest of co-operative society may not necessarily be in public interest. *Daman Singh vs. State of Punjab,* AIR 1985 SC 973.

Power to order amalgamation of a co-operative society of which an individual is member, with another society cannot be remotely held to offend the dignity of a human being so as to offend the basic structure of the Construction within the meaning of Article 20. *ibid.*

Once it is found that the award is without jurisdiction, the matter comes under sub-section (3) and under the jurisdiction of the Civil Court to entertain the suit. Subsection (2) has no application to such cases. *ibid.*

The object of enacting section 57 is the matters of detail relating to the affairs of a society should be disposed of the Fegistrar. Liquidator should not be dragged into court to explain the reasons for his decision. AIR 1953 Orissa 300.

The payment of debts of a society whether decretal or otherwise, is clearly "a matter touching the affairs of a society" within the meaning of sub-section (2) of this section, and proceedings to realise such debts are barred except by the leave of Registrar. An application to execute a decree for costs against a society can, therefore, lie only with leave of the Registrar under section 57 (2). AIR 1940 Pat. 253: **21 PLT** 217: 1940 PWN 155: 6 BR 776.

A dispute between the parties as to the manner or enforcement of payment (a certificate having been obtained under the Public Demands Recovery Act for enforcing an award made by Registrar) is a dispute touching the business affairs of a society. AIR 1942 Pat. 148: 22 Pat. LT 947: 8 BR 172: 197 IC 115.

The liquidator is empowered under section 43 (3) to take proceedings to execute an award issued by the Registrar against a member of the Co-operative Society in liquidation. If the member is aggrieved by the liquidator's action, he may apply to the Registrar to interfere with the liquidator's act under section 56 or to grant leave for the institution of the suit under section 57 (2) of this Act. A suit by him against liquidator is not maintainable in the absence of Registrar's sanction for its institution. AIR 1941 Pat. 428: 1941 PWN 373: 7 BR 585: 193 IC 142.

Pending an appeal from a decree in a suit against a Co-operative Bank, the

Bank went into liquidation. The liquidator was made a party respondent on the application of the applicant who also applied to the Registrar for leave to proceed with the appeal under section 57 (2), but received no such leave. It was held that the appeal was not maintainable and was therefore liable to be dismissed. 1944 PWN 172.

A wrong decision on a question of limitation may not amount to a defect of jurisdiction under section 57 (3), but an order determining a liability after expiry of the period provided by law, is an order without jurisdiction and therefore can be declared void and ignored. 10 BR 546.

Reference to the Registrar is not barred because of the pendency of a civil suit in regard to the same matter or some common matters. *Pt. Raghav Jha vs. Registrar,* Co-op. Society. 1962 BLJR (Rev.) 62: ILR 41 Pat. 325.

Agreement between parties cannot confer jurisdiction where jurisdiction of civil courts is ousted under the Act. *Orissa State Co-op. Mty. Federation vs. Association Mktg.* Co., AIR 1982 Orissa 1.

If the langauge of the statute is clear and unambiguous, it is not open to the Court to put any other interpretation which may violate the phraseology used therein. The width of the expression used in the statute cannot be narrowed down or cut down by courts. *Smt. Pratibha Singh vs. State of Bihar,* 1988 PLJR 646.

Supreme Court will not interfere where refusal of permission by competent Authority to a Co-operative Housing Society to develop its land in accordance with its layout plans is based on relevant and cogent reasons. *Kendriya Karamchari Grih Nirman Samiti Ltd. vs. New Okhla Industrial Development Authority,* (1988) 1 SCC 63.]

[1][CHAPTERVII-A

Distraint

57 A. Cases in which application for distraint may be made.-Where any debt or outstanding demand is due to a registered society from any member, past member or estate of deceased member or is due to a registered society which is duly authorised by the Registrar under any of the provisions of sub-section (1) of section 16 of this Act to grant loans to non-members, from any person who is not a member of a registered society or from the estate of such person if he is dead the society may, in addition to any other remedy to which it is entitled by law, present an application to the Registrar requesting him to recover the debt or outstanding demand by distraining, while in the possession of the **defaulter.**

(1) any crops or other products of the earth standing **or** ungathered on the holding of the defaulter;

(2) any crops or other products of the earth which **have** been grown on the holding of the defaulter and have been reaped or gathered and are deposited on the holding or on a threshing floor or place for treading out grain whether in the fields or within a homestead.

57B. Form of application.--(1) Every application under the last foregoing section shall specify-

(a) the holding of the defaulter and the boundaries thereof or such other particulars as may suffice for its identification:

1. Ins. by Act 16 of 1948.

(b) the name of the defaulter;

(c) the detailed account of the dues;

(d) the nature and approximate value of the produce to be distrained;

(e) the place where it is to be found, or such other particulars as may suffice for its identification; and

(f) if it is standing or ungathered at the time at which it is likely to be cut or gathered.

(2)The application shall be signed and verified in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for the signing and verification of plaints.

57C. Procedure on receipt of application.--(1) The applicant shall at the time of filing an application under the foregoing sections, file before the Registrar such documentary evidence (if any) as he may consider necessary for the purposes of the application.

(2) The Registrar may, after taking such evidence as he thinks, fit, admit the application or reject it.

(3) Where the Registrar cannot forthwtih admit or reject an application he may, if he thinks fit make an order prohibiting the removal of the produce specified in the application, pending the execution of an order for distraining the same or the rejection of the application.

(4) When an order for distraining any produce is made under the section at a considerable time before the produce is likely to be cut or gathered, the Registrar may suspend the execution of the order for such time as he thinks fit, and may, if he . thinks, fit, make a further order prohibiting the removal of the produce pending the execution of the order for distraint.

(5) An order under sub-section (3) or under sub-section (4) shall be served and published in such manner as the State Government may by rules prescribe.

57D. Execution of order for distraint.-(1) If an application is admitted under the last foregoing section and an order for distraining any produce is made the Registrar shall send a copy of the order containing the prescribed particu! rs to the Collector for execution.

(2)The Collector shall, upon receipt of the order referred to in sub-section (1), depute an officer to distrain the produce specified therein or such portion of that produce as he thinks fit, and the officer shall proceed to the place where the produce is, and distrain the produce by taking charge of it in this behalf and publishing a notification of the distraint in accordance with rules to that effect made by the State Government.

Provided that produce, which from its nature does not admit of being stored, shall not be distrained under this section at any time less than twenty days before the time when it would be fit for reaping or gathering.

57E. Service of demand and account.-(1) The distraining officer, shall at the time of making the distraint, serve on the defaulter a written demand for the amount due and the costs incurred in making the distraint, with an account exhibiting the grounds on which the distraint is made.

(2) Where the distraining officer has reason to believe that a person other than the defaulter is the owner of the property distrained, he shall serve copies of the demand and account on that person likewise.

3 The demand and account shall, if practicable be served personally but, if a person on whom they are to be served absconds or conceals himself or cannot otherwise be found, the officer shall affix copies of the demand and account on a conspicuous part of the outside of the house in which he usually resides.

57F. Rights to reap etc., produce.-(1) A distraint under this Chapter shall not prevent any person from reaping, gathering or storing any produce or doing any ther act necessary for its due preservation.

(2) If the person entitled to do so fails to do so at the proper time, the distraining *officer* shall cause any standing crops or ungathered products distrained to be reaped or gathered when ripe, and stored in such granaries or other places as are commonly used for the purpose or in some other convenient place in the neighbourhood or shall to whatever else may be necessary for the due preservation of the same.

(3) In either case the distrained property shall remain in the charge of the distraining officer or of some other person appointed by him in this behalf.

57G. Sale proclamation to be issued unless demand is satisfied.---(1) Unless the demand with all costs of distraint, be.immediately satisfied that distraining officer shall issue a proclamation specifying the particulars of the property distrained and the demand for which distrained, and notifying that he will, at a place and on a day specified not being less than three or more than seven days after the time making the distraint, sell the distraint property by public auction:

Provided that when the crops or products distrained from their nature admit of being stored but have not yet been stored, the day of the sale shall be so fixed as to admit of their being made ready for storing before its arrival.

(2) The proclamation shall be struck up on a conspicuous place in the village in which the land of the defaulter is situate.

57H. Place of sale.-The sale shall be held at the, place where the distrained property is, or at the nearest place of public resort if the distraining officer is of opinion that it is likely to sell there to better advantage.

571. When produce may be sold standing.--(1) Crops or products which from their nature admit of being stored shall not be sold before they are reaped or gathered and are ready for storing.

(2) Crops or products which from their nature do not admit of being stored may be sold before they are reaped or gathered, and the purchaser shall be entitled to enter on the land by himself, or by any person appointed by him in this behalf and do all that is necessary for the purposes of tending and reaping or gathering them.

57 J. Manner of sale.-The property shall be sold by public auction, in one or more lots as the officer holding the sale may think advisable, and if the demand with the costs of distraint and sale, is satisfied by the sale of a portion of the property, the order of distraint shall not be executed with respect to the remainder.

57K. Postponement of sale.--f, on the property being put for sale, a fair price (in the estimation of the officer holding the sale) is not offered for it, and if the owner of the property, or a person authorised to act in his behalf, applies to have the sale postponed till the next day or (if a market is held at the place of sale) the next market day, the sale shall be postponed until that day and shall be then completed, whatever price may be offered for the property.

57L. Payment of purchase money.--The price of every lot shall be paid at the time of sale, or as soon thereafter as the officer holding the sale direct, and in

default of such payment the property shall be put up again and sold.

57M. Certificate to be given to purchaser.--When the purchase money has been paid in full, the officer holding the sale shall give the purchaser a certificate describing the property purchased by him and the price paid.

57N. Proceeds of sale how to be applied.--(1) From the proceeds of every sale of distrained property under this Chapter, the officer holding the sale shall pay the costs of the distraint and sale, calculated on a scale of charges prescribed by rules to be made, from time to time, by the State Government in this behalf.

(2) The remainder shall be applied to the discharge of the amount due for which the distress was made, with interest thereon up to the day of sale; and the surplus (if any) shall be paid to the person whose property. has been sold.

57O. Certain persons may not purchase.-Officers holding sales of property under this Chapter and all persons employed by, or subordinate to such officers and all officers and members of the staff of registered societies are prohibited from purchasing either directly or indirectly, any property sold by such officers.

57P. Procedure where demand is paid before the sale.-(1) If at any time after a distraint has been made under this Chapter, and before the sale of the distrained property, the defaulter, or any person making a *bonafide* claim as the owner of the distrained property, where he is not the defaulter deposits with the Collector executing the order of distraint or in the hands of the distraining officer, the amount specified in the demand served under section 57-E, with all costs which may have been incurred after the service of the demand, the Collector, or officer, as the case may be, shall grant a receipt for the same, and the order of distraint shall not be executed.

(2) When the distraining officer receives the deposit, he shall forthwith pay it to the Collector.

(3) After the expiration of one month from the date of a deposit being made under this section, the Collector shall pay therefrom to the applicant for distrain the amount due to him, unless in the mean while the person making a bona fide claim as the owner of the property distrained has instituted a suit against the applicant contesting the legality of the distraint and claiming compensation in respect of the same.

57Q. Distraint of property which is under attachment.-When any conflict arises between an order for distraint issued under this Chapter and an order issued by a Civil Court for the attachment or sale of the property, which is the subject of the distraint, the order for distraint shall prevail; but if the property is sold under that order, the surplus proceeds of the sale shall not be paid under section 57-N, to the owner of the property without the sanction of the Court to which the order of attachment of sale was issued.

57R. Suit for corripensation for wrongful distraint and appeals. INO appeal shall lie from any order passed by the Registrar or a Collector under the Chapter, but any person whose property is distrained on an application made under section 57-A, in any case in which such an application is not permitted by that section, may institute a suit against the application for the recovery of compensaton:

Provided that, if such an order is passed by an Assistant Registrar or Deputy Registrar exercising the power of a Registrar, an appeal shall lie to the Registrar and his decision on such appeal shall be final.

57S. Power to make rules.-The State Government may from time to time, make rules for regulating the procedure in all cases under the foregoing provisions of this Chapter.

57T. Interpretation.-In this Chapter, unless there is anything repugnant in the subject or context –

(a) Collector" includes an officer appointed by the State Government to discharge any of the functions of a Collector under this Chapter;

(b) defaulter" means a person (including his legal representative if he is dead) from

(c) whom any such debt or outstanding demand as is referred to in section 57-A, is recoverable; and

(d) "holding" means any land used for agricultural or horticultural purposes.]

CHAPTER VIII

Miscellaneous

58. Registrar and other officers to be public servants:-The Registrar, a person exercising the powers of a Registrar, a person authorised to make an inspection under section 34 or 36 or to hold an inquiry under section 35, a liquidator and an arbitrator or arbitrators to whom any dispute is referred under section 48, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

59. Proof of entries in societies book.--(1) A copy of an entry in a book, register or list of a registered society regularly kept in the course of business, shall, if certified in such manner as may be prescribed by the rules, be admissible in evidence of the existence of such entry, and shall be admitted as evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry would, if produced, have been admissible to prove such matters, transactions and accounts.

(2) In the case of such societies as the State Government may, by general or special order, direct, no officer of a society shall in any legal proceeding to which the society is not a party, be compelled to produce any of the society's books, the contents of which can be proved under sub-section (1), or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded unless by order of the Courts or a Judge made for special cause.

60. Delegation of power to hear appeals.--The State Government may, by general or special order, delegate its power of hearing appeals under the provisions of this Act, '[x x x] to any authority specified in such order.

[61. Compulsory affiliation of registered societies to a Co-operative Federation.-(1) The registered co-operative society in accordance with the provisions of Rules framed under this Act shall be affiliated to Bihar Cooperative Federation in such manner and on such condition as has been directed by the Rules for the purpose.

(2) The organisation and activities of Bihar Cooperative Federation shall',be regulated, under rules framed under the provisions of this Act, and for which affiliation under sub-section (1) is compulsory.]

62. Exemptions from requirements as to registration.-(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by special order in each

1. Words "except the power of hearing appeals under Sections 26, 40 and 41" deleted by (Arndt.) Act 10 of 2002.
2. Subs. by ibid.

case and subject to such conditions, if any, as it may impose, exempt any society from any of the requirements of this Act as to registration.

(2) The State Government may by general or special order [] exempt any registered society from any of the provisions of this Act, or may direct that such provisions shall apply to such society with such modifications as may be specified in the order.

63. Limitation.-Notwithstanding any of the provisions of the [Indian Limitation Act, 1908 (9 of 1908), the period of limitation tor debt including interest due to a registered society by a member thereof shall be computed from the date on which such member dies or ceases to be a member of the society.

Comments & Case-law

[There can be no question of limitation at all under this section so long as the person from whom a debt is due to a society is still a member of the society. 21 PLT 343.

There is a period of limitation tor recovery of debt from past members-Claim against past member barred by limitation-Such dispute cannot be heard by Registrar-his award is without jurisdiction. *P.M.G. Officers Co-operative Society vs. Abdul Quddus,* 1963 PLJR 969.]

64. Power to exempt from income tax, stamp duty and registration fees.--(1) The Central Government, by notification in the official Gazette, may in the case of any registered society or class of registered societies, remit the income-tax payable in respect of the profits of the society, or of the dividends or other payments received by the member of the society on account of profits.

(2) The collecting Government may by notification remit, in the case of any registered society or class of registered societies-

(a) the stamp duty with which under any law for the time being in force, instruments executed by or on behalf of a registered society or by an officer or member thereof and relating to the business of such society or any class of such instruments or decisions, awards or orders of the Registrar or of any arbitrator or arbitrators under this Act, are respectively chargeable, and

(b) any fee payable under the law of registration tor the time being in force. In this sub-section "collecting Government" has the same meaning as in the Indian Stamp Act, 1899.

Comments & Case-law

[Reading Sec. 5 of the Act with item no. 27 of Appx V. of the Stamp Act it is anifest that a society registered under the Co-operative Society Act is exempted from payment of any stamp duty and as such a registered society is exempted from payment of any stamp duty in relation to any instrument executed by it or on behalf of it and relating to its business. *Patliputra Co-operative House Construction Society Ltd. vs. State of Bihar,* 1977 BBCJ 78.

Exemptions granted by the State Government in favour of building belonging to co-operative societies from the provisions of Rent Control Act is legitimate exercise of power. Such exemption cannot be discriminatory and violative of Article 14 of the

1. For an order under this sub-section, see the B.O.R.O. Vol I.Pt. VII.
2. See Limitation Act, 1963.

Constitution. *M/s S.M. Mahendra & Co. vs. State of Tamil Nadu,* AIR 1985 SC 270.

A co-operative society is entitled to the exemption of the profits and gains derived from the activities which is incidental and is to increase and promote cooperative societies under section 81 (i)(c) of the Income Tax Act 1961. *The Broach Distt. Co-operative Cotton Sales Ginning and Pressing Society Ltd. vs. The Commissioner of Income Tax Ahmedabad,* AIR 1989 SC 1493 : (1989) 2 sec 679 : (1989) 44 Taxman 489.

If the service rendered by a co-operative society is only incidental, it is entitled to deduction in income-tax.-Commissioner *of Income-Tax Madras V. South Arcot District Co-operative Marketing Society Ltd.,* AIR 1990 1249: (1989) 43Taxman 328.

Co-operative society making investments in security deposits for carrying on agency business interest or the security deposit received is not an investment thus no exemption can be claimed from income-tax. But if the loan advanced is to a member co-operative society by the apex co-operative society for carrying on business and the interest receiving on the same will be exempted from income-tax. *CIT V. U.P. Co-operative Federation Ltd.,* AIR 1989 SC 915 : (1989) 1 SCC 747: (1919) IUT 258.]

65. Exemption from compulsory registration of instrument relating to shares and debentures of a registered society---Nothing in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of Section 17 of the Indian Registration Act, 1908 shall apply to-

(1) any instrument relating to shares in registered society notwithstanding that the assests of such society consist in whole or in part·of immovable property; or

(2) any debenture by any such society and not creatinig, declaring, assigning or extinguishing any, right, title or interest to or in immovable property except in so far as it entitles the holders to the security afforded by a registered instrument where by the society has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holders of such debentures; or

(3) any endorsement upon or transfer of any debenture issued by any such society

[1][**x x x**]

Comments & case-law

[The State Government exercises supervisory jurisdiction only under section 65A. *Chandrika Jha • State of Bihar,* 1984 PLJR (SC) 1. see also *Abdul Gafoor v. State of Bihar,* 1983 PLJR 196 : AIR 1983 Pat. 114.

The provisions of section 56 are not in pari materia with those of section 65A of the Act, and section 65 has not such an overriding effect, as section 65A. Section 65A does nothing more than provide that instead of the Registrar deciding the

1. "Section 65A" repealed by (Amdt.) Act No. 10 of 2002.

election dispute by referring to an officer subordinate to him, the State Government has been given power to recall an election dispute from the Registrar in appropriate cases. Section 48 itself puts no bar on transfer and authorises the Registrar to transfer such of the cases as he may deem fit and prayed. Similar power is being exercised under section 65A by the State Government of recalling such election disputes from the Registrar as the State Government may consider proper. That will not' amount to any discrimination under Article 14 of the Constitution. Hare *Krishan Upadhyaya v. State of Bihar,* 1979 BLJ 141.

The exercise of special power of revision conferred by section 65A is a discretionary one and cannot be equated with the substantive right of appeal conferred by the statute u/s 48 of the Act. Therefore, merely becasue an aggrieved party files an application before the revisional authority, it cannot be said that it confers upon him any right to insist upon the revisional authority namely, the State Government to decide the matter one way or the other. *Abdul Gafoor v. State of* ***Bihar,*** 1983 PLJR 196 : AIR ·t983 Pat 114.

This section empowers the State Government of its own motion or on application to call for record of any proceeding of any matter pending before the Registrar or his subordinate or any person acting under his authority and examine and pass such orders as may deem fit. The section also lays down that orders may be passed by the State Government in regard to election of any society besides other matters. The expression "election" must cover all aspects of the election, including election disputes. Therefore, it is wrong to contend that the Minister, Co-operation, can pass orders in terms of section 65A of the Act only in regard to executive orders passed by the Registrar or his subordinate. *Lachandeo Singh v. State of Bihar,* 1982 PLJB **(NOC)** 7 : 1981 BRLJ 239 : 1981 BLJ 674 : 1982 BBCJ 14.

The scope of section 65A is very. limited. It cannot override the provisions of section 48(1) read with section 26(2) or sub-section (6) of section 48 read with section 48(2)(b). *Abdul Gafoor v. State of Bihar,* 1983 PLJR 196: AlR 1983 Pat. 114.

The question in what case power u/s 65A of the Act has to be exercised is a question of fact, to be determined in each individual case. But the exercise of power would be illegal where (i) no exceptional circumstances has been pointed out; (ii) the dispute with regard to the election was referred to the Registrar under sub-section (1) of section 48 and there was no dispute pending under the Act before any authority; (iii) there was no enquiry or investigation under the Act under challenge; and (iv) no such reference was decided either by a person acting as the Registrar himself either u/s 48(2)(a) or while exercising power under sub-section (6) section 48 of the Act. *ibid.* ·

The expression "State Government" occuring in this section includes the Minister of the Department of Co-operation. Accordingly the Minister has the jurisdiction to pass the orders staying the orders of the Dy. Registrar, Co-op. Societies. *Lachandeo Sahni v. State of Bihar,* 1982 PLJR (NOC) 7; 1981 BRLJ 239 : 1981 BLJR 674 : 1982 BBCJ 14.

The expression "pending before the Registrar" cannot be confined to the latter portion of the Section only. It governs the entire section and therefore the State Government can exercise power under the section only if a matter is pending. If a dispute has been finally considered and decided the section will have no application. *Saryug hgh v. State of Bihar,* 1982 PLJR (NOC) 17 : 1982 BBCJ 122 : *Sahjanand*

Sharma v. State of Bihar, 1983 PLJR 76.

An application was filed before the Registrar for taking action under Contempt of Court Act. The Registrar, passed order under Co-operative Societies Act restraining persons from acting as member of the managing committee. The order was reviewed by the Minister. The action of both, the Registrar and the Minister are justified, because the Registrar could have passed that order under power of review under the Cooperative Societies Act and in view of such order, Minister also has the competence to pass review order. *Sahjanand Sharma v. State of Bihar,* 1983 PLJR 76.

It is not necessary to give notice to the persons concerned while passing an interim order, *ibid.*

Where the bye-law empowered the Registrar to extend the tenure of committee of management, then it is he only who can do so. Neither the Chief Minister, nor Minister, Co-operative has the power to arrogate himself the statutory functions of Registrar. *Chandrika Jha v. State of Bihar,* 1984 PLJR (SC) 1 : AIR 1984 SC 322.

Where the bye-laws empower the Registrar to continue Board of Directors, he has to do so at his discretion. Constitution of Board of Directors not at his discretion but at the behest of Minister is invalid, *ibid.*

The power conferred by section 65A are devoid of any limitation or any guidelines. Section 65A, which purports to confer power on the State executive to totally override a Court and its judicial proceedings without any guidelines, is *per se* arbitrary and irrational. The blanket powers conferred on the State Government or Minister to call for any matter and decide it as it may deem fit are unguided and uncanalised power suffer from the voice of arbitrariness and consequently infract Article 14 of the Constitution of India. The High Court, therefore, struck down the provision. *Chandeshwar Prasad v. State of Bihar,* 1987 PLJR 159 (FB) : AIR 1987 Pat. 208.

The powers conferred on State Government by section 65A are neither revisional nor supervisory, *ibid.]*

[1][**658. Removal of difficulty.-lf** any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, as occasion may require, by order published in official Gazette, to anything not inconsistent with the provisions of this Act for purpose of removing the difficulty.]

66. Power to make rules.-The State Government may for the whole or any part of the State and for any registered society or a class of registered societies, make rules to carry out all or any of the purpose of this Act.

In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may-

(i) prescribes the forms to be used and the conditions to be compliec;I with in the making of application for the registration of a society and the procedure in the matter of such applications;

(ii) prescribe the conditions to be complied with by persons applying for admission or admitted as members and provide for the election and the admission of member and the payment to be made and the interests to be acquired before the exercise of the right of membership;

(iii) prescribe the extent to which a society may limit the number of its

1. Ins. by Act 21 of 1976

members and, subject to the provision of section 29, prescribe the maximum number of shares or portion of the capital of society, which may be held by a member;

(iv) prescribe the conditions of acceptance of registration of members and prescribe for the expulsion of member and for the payments, if any, to be made to members who withdraw or are expelled;

(v) provide for the general meetings of the members and for the procedure at such meetings and the powers to be exercised by such meeting;

(vi) prescribe the matters in respect of which is a society may or shall make bye-laws, and the procedure to be followed in making, altering and abrogating bye-laws and the conditions to be satisfied prior to such making, alteration or abrogation;

(vii) prescribe the manner in which managing committees and sub-committees thereof shall be constituted, [1] ["through election conducted by the authority constituted under sub-section (1) of section-14A or otherwise] and provide for the appointment, suspension and removal of members of managing committees and other officers, and for the procedure at meetings of managing committees and for the powers to be exercised and the duties to be performed by managing committees and other officers.

(viii) prescribe the conditions under which a society may be prohibited from appointing a defaulting member of any society to its managing committee or to the managing committee of any other society and from allowing him to exercise his right of membership in the society or to represent it in on other society :

(ix) prescribe the procedure to be followed when societies change the forum or extent of their liability, and provide for the amalgamation and division of societies and prescribe the conditions of such amalgamation and division;

(x) prescribe the conditions and terms under. which and regulate the manner in which funds may be raised by means of shares deposits or debentures or otherwise;

(xi) prescribe the conditions to be complied with by members applying for loans, the period for which loans may be made, the amount which may be lent and the manner of re payment;

(xii) provide for the deposit or investment of any funds under control of a society;

2**(xii)** prescribe the conditions, prohibitions and restrictions to which societies may-

(a) transact business with persons who are not members; or

(b) make advances against movable property;]

(xiv) prescribe the method of calculating the working capital and the net profits and the conditions under which such profits may be distributed, and the maximum rate of dividend which may be paid by any society or class of societies;

<u>(xv) provide for the formation an</u>d maintenance of reserve funds and the

1. Subs. by Act 16 of 1948.
2. Ins. by Act 18 of 2008

objects to which such funds may be applied and for the writing off of bad debts.

(xvi) prescribe the condition for refund of share money and transfer of shares;

(xvii) provide for the mode in which the value of a deceased member's interest shall be ascertained, and for the manner of nomination of a person to whom such interest may be paid or transferred;

(xviii) provide for the information and maintenance of a register of members and where the liability of members is limited by shares, of a register of shares and share-holders;

(xix) prescribe the forms to be used and the accounts and registers to be. kept and the reports and returns to be submitted by a society and provide for the persons by whom such reports and returns shall be submitted, and in case of failure to submit any such reports or returns, for the levy of the expenses of preparing them;

(xx) prescribe rules for audit under section 33, and for the periodical publication of balance-sheets showing the assets and liabilities of a society;

(xxi) provide for the persons by whom and the form in which copies of entries in records and registers of societies may be certified and for the charge to be levied for the supply of such copies;

(xxii) provide for the custody and destruction of records and registers;

(xxiii) provide for the procedure to be followed in the appointment or removal of and for the payment of remuneration to. a liquidator.

(xxiv) prescribe the procedure to be followed by the liquidator and provide for the manner of disposal of the surplus, if any, of the society;

(xxv) prescribe the procedure to be followed in presenting and disposing of appeals under this Act;

(xxvi) prescribe the procedure to be followed in the appointment of an arbitrator or arbitrators and in proceedings before the Registrar any person exercising the powers of a Registrar and an arbitrator or arbitrators including the transfer, reference and withdrawal of cases;

(xxvii) prescribe the procedure and condition for exercise of the powers conferred by section 49; [1][*]

[2]**[(xxviii)** prescribe the procedure for calling, holding and conducting meetings of creditors under section 24-A]; and

[3]**[(xxix)** provides for all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed by rules].

[5]**["(xxx)** prescribe the membership fee and provide for financial assistance for contribution towards such fee as well as minimum share capital to women, scheduled caste, scheduled tribe and backward class member belonging to a class or classes of registered societies which may be limited to maximum one member from a family."

(3) The power to make rules conferred by this section is subject to the condition to the rules being made after previous publication. [4]

(4) All rules made under this Section shall be published in the official Gazette <u>and on such publication shall have effect</u> as if enacted in this Act.

1. The word "and" re. by Act 8 of 1935.
2. Ins. by ibid.
3. The Original clause **(xxviii)** was re-numbred as clause **(xxix)** by ibid.
4. As to the procedure for previous publications see the Bihar and Orissa General Clauses Act, 1917 (B. & 0. Act 1 of 1917).
5. Ins by Act 18 of 2008

Comments & Case-law

[Normally the "Jalkars" should be settled with the Co-operative society in whose area of operation the "Jalkar" lies and the settlement may be made with any other Society only if the expediency of the situation so requires. A Co-operative society, which is a defaulter of Government dues, is not entitled to be given preference in the matter of settlement of sairats over other individuals. *Daudpur Fishermen Co-op. Societies Ltd. v. State,* 1981 BRLJ 229: AIR 1981 Pat. 294.

An Act beyond the object mentioned in the memorandum is ultra vires. But if the act done is fairly incidental, reasonably ancillary to its main business, conductive to the statement of objects, unless such an-act is expressly prohibited, it cannot be held to be ultra vires. The acquiring of land for cultivation and procuring good quality seeds by a Society carrying on business of distribution of seeds to agriculturists is not prohibited by bye-laws. *Gajadhar Prasad Choudhary v. State of Bihar,* AIR 1984 Pat. 105.

Rules have the status of subsidiary legislation or delegated legislation. Byelaws of a co-operative society, on the other hand, can at best have the status of an Article of a Company governed by the Companies Act, 1959. *B.K.k Gard v. Nasik Merchants Co-op. Bank,* Al R 1984 SC 192.

If there are two sets of Rules regulating the conditions of service of employees of Co-operative Societies the regulations framed under power conferred by the Act approved by the State Government shall prevail. *Om Prakash Maurya v. U.P. Sugar Factories Federation, AIR* 1986 SC 1984.

Where an employee continues in post after completion of maximum period of probation provided under regulations, he stands confirmed. Therefore his reversion to lower post by treating him as on probation is not legal. *ibid.]*

'[66A. Fixation of proportion of Co-operative Loans for schedule castes, scheduled tribes, small farme.rs, marginal farmers and other weaker sections of the community.- Subject to such directions as may be issued by the Reserve Bank of India, the primary agricultural co-operative societies shall during a co-operative year disburse to scheduled castes/scheduled tribes, small and marginal farmers and other weaker sections of the community, such proportion of their total lending as may be laid down by Registrar, Co-operative Societies from time to time having regard to the class of societies, the strength of membership of persons belonging to above classes.

Said societies shall maintain separate account in respect of their lending to the aforesaid classes in a manner to be prescribed by the Registrar.

[·66B. Personnel policy of Co-operative Societies.-{1) Co-operative Societies shall have autonomy in the formulation of the types of posts, their numbers and the procedure for recruitment of the personnel thereof. The Co-operative Society can frame personnel policy, for this purpose. Subject to provisions of its Bye-laws and personnel policy the Co-operative Society shall prescribe for the following, among
others:-

(1) eligibility, age and experience,

(2) pay scale and other emoluments,

(3) procedure of recruitment,

(4) service condition, and

1. Ins. by Act 39 of 1982.
2. Subs. by Act 6 of 2013

(5) disciplinary policy to be adopted.

(2) Any appointment made in contravention of the provisions of the Bye-laws and the personnel policy shall be void as if no such appointment ever existed and salary and other allowances paid, if any, shall be recoverable under Section 40."

Comments & Case-law

State acting either through the Registrar or the Secretary, Co-operative Department have the legal authority to issue directive. This directive has a statutory status and to that extent binding on various Co-operative Societies registered in the State.

Shyam Kishore Sinha vs. State of Bihar, 2007(3) PLJR 830.

Age of retirement of the employees of Co-operative Societies, enhanced from 58 to 60 years by the State subject to conditions that those employees who have suffered punishment due to the embezzlement, corruption, indiscipline, incompetence or forgery would be kept out of benefit of enhanced age of retirement. A person cannot be punished twice for the same charges. Petitioners are being retired at the age of 58 years because their service book reflect punishment imposed earlier. This the guarantee and protection given u/Art,20(2) of the Constitution of India. In absende of amendment in service regulations incorporating this 'punishment'l as a penalty the order cannot be permitted to have a pervasive effect in this area. When there is provision for compulsory retirement then there is no occasion of creating yet another clause of punishment by forcing an employee to retire at 58 years of age merely because in some distant past he had suffered some punishment. In the matter of superannuation of employees there cannot be two separate age of retirement. Impugned clause held to be-violative of Articles 14 and 20(2) of the Constitution of India and struck down. Direction issued to reinstate the petitioners in service with all benefits and they shall continue till they reach the age of 60 years. *Shyam Kishore Sinha vs. State of Bihar,* 2007(3) PLJR 830.

Enhancement of retirement age for employees of milk co-operative societies (COMFED). Refusal ot COMFED not to enhance the retirement age by defying the directives of State Government. Section 66B has been held to be a valid piece of legislation. As such State Govt. does have powers to issue directives to various cooperative societies in matters of appointment and service condition which shall govern the employees working under the societies. These directives are binding on all the co-operative societies including COMFED. Decision taken by Board of Directors of COMFED not to enhance the retirement age to 60 years is arbitrary and itlegal and accordingly, quashed. Directed to reinstate till they reach enhanced age of 60 years. COMFED given liberty to reconsider its decision if subsequently found that petitioners are not fulfilling any of the conditions as laid down by its Secretary.

Ram Narain Singh vs. State of Bihar, 2007(3) PLJR 214.

Salary to Paid Managers of PACS. No liability can be fastened on the State Government with respect to functioning of such societies as PACS. Such societies have to generate their own funds and Managers are to make recoveries and collections. *Shall Devi* vs. *State of Bihar,* 2007(1) PLJR 533.

GOVERNMENT OF BIHAR CO-OPERATION DEPARTMENT.

Notification

No. 14/3 Legal (Amend) - 07/89/526/ dated 9.2.1989.-In exercise of the powers conferred upon the State Government under Section 66B of the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 the following mode and method of recruitment is prescribed for recruitment of Personnel by the Cooper&tion Societies.

1. There shall be a Selection Authority for the recruitment of all grades of employees of all the State Level Cooperative Societies.

2. The Selection Authority shall consist of the following:-

(a) Member, Board of Revenue-	As Chairman
(b) Chairman of the concerned State Level Co-operative Societies	As Member
(c) One representative of Scheduled Caste or Scheduled Tribe to be nominated by the Secretary, Cooperative-	As Member
(d) Nominee of NABARD, Patna	As Member
(e) Managing Director of the concerned State Level Cooperative Society.	As Member-Secretary

3. (i) The Selection Authority shall prepare a panel of persons to be appointed in the different grades of the State-level Co-operative Societies.

(ii) Notwithstanding any thing contained in the bye-laws of any State-Level Cooperative Society or rules made thereunder, no appointment in any grade from outside the panel shall be valid.

4. The member-secretary shall provide the necessary secretariat assistance to the Selection Authority.

5. There shall be a Selection Authority at the District level for appointment of all grades of employees in the District Level Co-operative Societies.

6. The District Level Selection Authority shall consist of the following:-

(a) Collector/Deputy Commissioner-	As Chairman.
(b) Chairman/Honorary Secretary of the concerned District Level Co-operative Society-	As Member.
(c) One representative of Scheduled Caste or Scheduled. Tribe to be nominated by the Collector/Deputy Commissioner of the District.-	As Member
(d) Managing Director/Executive Officer of the District Level Co-operative Society.-	As Member-Secretary.

7. (i) The Selection Authority constituted for the District Level Co-operative Societies shall prepare a panel of persons to be appointed in the different grades of the District Level Co-operative Societies.

(ii) Notwithstanding any thing contained in the bye-laws of the District Level Co-operative Society or rules made thereunder, no appointment in any grade from. outside the panel shall be valid.

8. The Member Secretary shall provide the necessary secretariat- assistance to the Selection Authority constituted at the District Level Co-operative Society.

9. The rules framed by the State Government for the recruitment of various grades of Government employees and as amended from time to time, shall apply *mutatis-mutandis* to the preparation of panels by the Selection Authorities.

10. The rules relating to reservation as framed by the State Government and as amended from time to time, shall *mutatis-mutandis* apply to the preparation of panels by the Selection Authorities.

11. The State Level Cooperative Society shall mean a registered co-operative society functioning at the State Level.

12. The District Level Cooperative Society shall mean a registered co-operative society functioning at the District Level.

13. The term 'Registered Society' shall mean a registered society as defined by Section 2 (b} of the Bihar Co-operative Societies Act, 1935.

14. This order comes into force with immediate effect.

Comments & case-law

[The State Government has no power to cancel the appointments made by a Co-operative Bank. The provisions of section 66B only confer the power to lay down general policy with regard to recruitment etc. upon the State Government. *Sheo Shankar Prasad Sinha v. State of Bihar,* 1987 PLJR 270.

The direction to the Registrar to follow a uniform practice to superannuate the employees after the age of 58 should be strictly followed. So as that no employee can make any grievance of discrimination. *Md. Ali v. State of Bihar,* 1991 (1) BLJ 72 : (1991) 1 BLJR 111.

For further case-law, see under rules 6, 23 and 25.

Provisions of section 66B are not violative of Article 14 of the Constitution. Where the Legislature itself declares certain category of appointments to be void, nothing requires to be adjudicated, and principles of natural justice will have on application in case of cancellation of void appointments. Provisions of section 66B cannot be said to be arbitrary. *Teja Prasad v. State of Bihar,* 1992 (2) PLJR 56.

An order of termination of service of Branch Managers of Primary Agriculture Co-operative Societies passed without instituting departmental proceedings on their alleged failure to achieve norms for recovery of Co-operative loans set by the Cooperative Department will be liable to be set aside on ground of being violative of principles of natural Justice. The mere service of show cause notice without intiating disciplinary proceedings cannot be said to fully satisfy the mandatory requirement of providing effective opportunity of defence against proposed order of termination. *Kapileshwar Sharma vs. State of Bihar,* 1993 (2) PLJR 552.

In the face of the express bar provided under section 66B, it cannot be held that regular appointments could be made by a Co-operative Body registered under the Act without following the prescribed method and procedure or any form of selection merely because the "Selection Committee" had not been fully constituted. *Teja Prasad vs. State of Bihar,* 1992 (2) PLJR 568.

A notification under section 66B(1) providing for constituting a Selection Authority and creating an embargo against making any appointment from any source other than the "Panel" prepared by the Selection Authority can be validly issued by the State Government. Any appointment made in contravention of the Notification will be void *ab initio. ibid.*

It is only after the enactment of the 1989 Amendment Act (Act 5 of 1989) that certain Co-operative Bcdies such a Central Co-operative Bank became qualified to be treated' as "State" within the meaning of Article 12 of the constitution. Any appointment made prior to coming into force of the 1989 Amendment Act are no amenable to test on the touchstone of Articles 14 and 16 of the constitution for validity of appointment. *Ajay Kumar Mishra vs. Registrar,* 1995 (2) PLJR 397.

Restrictions imposed by Registrar, Co-operative on co-operative Societies, requiring purchases of machinery to be made through Regional Agro Industries Development Co-operative Ltd. are justifiable when in public interest. *George Kokkattumundayil vs. Joint Registrar,* AIR 1996 Ker 26.

Review.-Power of review has been given only to Registrar, Co-operative Societies, and is not vested in State Government under the Assam Act. *C.B.K. Fishery Co-operative Society Ltd. vs. State of Assam,* AIR 1996 Gau. 23.

Section 66B--change in manner of payment of salary to Managers of PACs by · opening of specified account in every Central Co-op. Bank to which the PACs may be attached is with a view of improve the functioning of PACs and does not amount to altering the service conditions. *Bihar Rajya Sahakarita Prabandak Sangh vs. State of Bihar,* 2000(3) PLJR 322.

Section 66B-State exercises pervasive control over co-operative societies and thus the co-operative societies virtually act as an extended arm of the State therefore, the State Government virtually controls the service conditions of the Managers of the PACs and their pay scale is also fixed by it---since their pay is fixed by the State Government and is at the subsistence level, the denial of protection from price rise by providing D.A. is violation of Articles 14 and 21 of the Constitution. *Bihar Rajya Sahkarita Prabandhak Sangh vs. State of Bihar,* 1999(3) PLJR 110.

Section 66B-Managers of PACs, even though not State Government employees cannot be denied just and reasonable pay as a citizen of India-their pay having been fixed by the State Government and not an expert body like Pay Commission, denial of D.A. to them amounts to exposing them to the vagaries of the market unlike State Government employees who enjoy such protection---a welfare State wedded to the principle of social justice cannot be allowed to do it, it being unreasonable, unfair and unconstitutional--Managers of PACs are entitled for D.A. at par with State Government employees. *ibid.* ·

Section 66B read with Rule 33 of Bihar and Orissa Co-operative Societies Rules, 1959-appointment of staff for Class Ill and Class IV posts by Vice-Chairman of Co-operative society any appointment made in Violation of Procedure prescribed for registered Societies by State Government Circular will be illegal. *Anjani Kumar Singh vs. Manager, Jamui Central Co-operative Bank Ltd.,* 1994(2) PLJR 761.]

67. Repeals.--The enactments specified in the schedule are hereby repealed in so far as they apply to the State to the extent specified in tile fourth column of the said schedule.

SCHEDULE

Enactments Repealed

(See Section 67)

Year	No.	Short title	Extent of repeal
1	2	3	4
1912	II	The Co-operative Societies Act, 1912	The whole
1920	XXXVIII	The Devolution Act, 1920	So much as relates to Act II of 1912.